भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अक्तूबर 2019

खंड 73 अंक 10

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया ''भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन'' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

चौथा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 — 1

मौद्रिक नीति रिपोर्ट – अक्तूबर 2019 — 9

भाषण

भारत के बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता के आयाम — 85
शक्तिकान्त दास

बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली संबंधी विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रत्याशाएं — 89
एम. के. जैन

लेख

भारत में आपूर्ति श्रृंखला गतिकी और खाद्य मुद्रास्फीति — 95

पूर्वी भारत में सुदूर तक ऋण पहुंचाने के वाहक — 113

वर्किंग पेपर की प्रेस प्रकाशनी

भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान: क्या मशीन लर्निंग के पास
बेहतर पूर्वानुमान की कुंजी है? — 123

वर्तमान सांख्यिकी — 125

हाल के प्रकाशन — 169

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

चौथा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

मौद्रिक नीति रिपोर्ट – अक्तूबर 2019

चौथा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज (4 अक्तूबर 2019) की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 5.15 प्रतिशत किया जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

- एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इसके लिए उदार रुख बरकरार रखा जाए।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अगस्त 2019 में एमपीसी की आखिरी बैठक के बाद से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि और कमजोर हो गई है। व्यापार और भू-राजनैतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण संभावनाओं पर अस्पष्टता बनी रही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बीच, 2019 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आयी जो 2019 की तीसरी तिमाही तक बढ़ी है, जो कि नरम औद्योगिक उत्पादन से प्रभावित है। सितंबर के लिए इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट इंडेक्स बताता है कि विनिर्माण क्षेत्र एक दशक के सबसे कम रीडिंग को छूते हुए संकुचित हो गया; निजी क्षेत्र भी धीमा बना रहा है। यूरो क्षेत्र में भी, आने वाले आंकड़ों से संकेत मिलता है कि खुदरा बिक्री में गिरावट और सितंबर में लगातार आठवें महीने पीएमआई संकुचन में रहने के साथ गतिविधि तीसरी तिमाही में पुनः मंद हो सकती है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में विघटित हुई; जुलाई में औद्योगिक उत्पादन और मंद खुदरा बिक्री में संकुचन से संकेत मिलता है कि हानि की गति तीसरी तिमाही में भी जारी रही है। जापान में, दूसरी तिमाही में हुई हानि की भरपाई तीसरी तिमाही में हुई, यद्यपि इसे राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा बचाया गया है और एक योजनाबद्ध बिक्री कर वृद्धि से उपभोक्ता खर्च को कम किया जा रहा है।

3. प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के समष्टि आर्थिक निष्पादन की तुलना तीसरी तिमाही में बिगड़ते वैश्विक वातावरण से की गयी है। जुलाई-अगस्त में खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी और अगस्त में निर्यात में कमी के साथ चीनी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में धीमी हो गई है, अब तेज मंदी को रोकने में राजकोषीय और मौद्रिक नीति उत्तेजनाओं की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित है। रूस में, आर्थिक गतिविधि में दूसरी तिमाही में विकास हुआ, यद्यपि अभी भी उपभोक्ता भावना और कमजोर औद्योगिक उत्पादन प्रतिरोध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील दोनों में आर्थिक गतिविधि दूसरी तिमाही में पलट गई, पिछली तिमाही में संकुचन से बाहर आई है; हालाँकि, यह नव सुधार घरेलू और बाहरी दोनों विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

4. अगस्त के शुरू में पर्याप्त आपूर्ति के बीच कच्चे तेल की कीमतों में मांग में कमी के कारण गिरावट आई। कीमतें सितंबर के मध्य तक सीमा बद्ध रहीं और भू-राजनीतिक संघर्ष बढ़ने के कारण आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप बढ़ी तथा उम्मीद से अधिक तेजी से कम हो गई है। सोने की कीमत सेफ हेवन (सुरक्षित स्थान) मांग पर ऊंची बनी रही। प्रमुख एई और ईएमई

* 04 अक्तूबर 2019 को जारी किया गया।

में लक्ष्य से नीचे बनी मुद्रास्फीति के साथ केंद्रीय बैंक अधिक उदार हो गए हैं।

5. अगस्त शुरुआत में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक वित्तीय बाजार संरक्षणवादी नीतियों और बिगड़ती वैश्विक विकास की संभावनाओं द्वारा फैली अस्थिरता के साथ अस्तव्यस्त हो गए है। अमेरिका में शेयर बाजार के अगस्त के नुकसानों को सितंबर की शुरूआत तक संभाल लिया गया- निवेशकों की भावना अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में ढील के संकेत से उत्साहित रही। ईएमई में शेयर बाजार गिर गया, चूंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर ने पूंजी बहिर्वाह को बढ़वा दिया, हालांकि सितंबर में उनमें आंशिक रूप से सुधार हुआ । अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की चिंताओं के कारण अगस्त तक ढील जारी रही, इससे पहले अमेरिकी खुदरा बिक्री के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों और अमेरिका और चीन के बीच सुगम व्यापार वार्ता से सितंबर की शुरुआत में थोड़ा सुधार हुआ। यूरो क्षेत्र में, बॉण्ड प्रतिफल पुनः नकारात्मक क्षेत्र में डूब गई, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा जमा दर में कटौती (-) 0.5 प्रतिशत और मात्रात्मक सहजता पुनर्सृजन से प्रेरित थे। ईएमई में, बॉण्ड प्रतिफल ने मिश्रित गति का प्रदर्शन किया, जो देश-विशिष्ट कारकों द्वारा संचालित है। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर अन्य एई की मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ। ईएमई मुद्राओं, जो अगस्त में मूल्यह्रास वाले पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर रही थीं, में सितंबर की शुरुआत में देश-विशिष्ट कारकों और वैश्विक जोखिम-आधारित धारणा के पुनरुद्धार पर मूल्यवृद्धि हुई।

घरेलू अर्थव्यवस्था

6. घरेलू मोर्चे पर 2019-20 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि 5.0 प्रतिशत तक गिर गई, जो लगातार पांचवीं तिमाही में अनुक्रमिक मंदी को बढ़ावा दे रही है। इसके घटकों में से निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 18-तिमाही के निचले स्तर पर आ गया। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने अनुक्रमिक आधार पर मामूली सुधार किया लेकिन पिछली तिमाही की तरह मंद रहा। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) ने समग्र हानि की गति को कुछ हद तक कम कर दिया।

7. आपूर्ति पक्ष पर, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि दर 2019-20 की पहली तिमाही में 4.9 प्रतिशत तक गिर गई, जिसे विनिर्माण विकास ने नीचे खींच लिया जो 0.6 प्रतिशत तक कम हो गई। 2018-19 के रबी मौसम के दौरान गेहूं और तिलहन के अधिक उत्पादन ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों को उन्नत किया था। विनिर्माण गतिविधि से सेवा क्षेत्र में विकास रुक गया ।

8. 2019-20 की दूसरी तिमाही की ओर बढ़ते हुए, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून शुरुआत में देरी के बाद जुलाई से तेजी से बढ़ी। 30 सितंबर 2019 तक संचयी अखिल भारतीय वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 10 प्रतिशत अधिक हुई। 2019-20 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमानों ने पिछले वर्ष के चौथे अग्रिम अनुमानों की तुलना में खाद्यान्नों का उत्पादन 0.8 प्रतिशत कम हुआ। रबी मौसम की ओर रुख करते हुए, प्रमुख जलाशयों में पानी का तत्कालीन भंडारण 26 सितंबर 2019 को पिछले वर्ष की तुलना में 115 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों में औसत संग्रहण स्तर का 121 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अगस्त और सितंबर में प्रचुर मात्रा में बारिश ने देश के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से मध्य भारत में मिट्टी की नमी की स्थिति में सुधार किया है। कुल मिलाकर, कृषि की संभावनाएं काफी उज्ज्वल हो गई हैं जो रोजगार और आय में वृद्धि और घरेलू मांग के पुनरुद्धार के लिए अनुकूल है ।

9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापी गई औद्योगिक गतिविधि जुलाई 2019 (वर्ष दर वर्ष) में मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कमी के कारण कमजोर हो गई । उपयोग के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन संकुचित रहा। खाद्य तेलों एवं मध्यवर्ती वस्तुओं, मुख्य रूप से हल्के स्टील के स्लैब, द्वारा संचालित उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में सतत विस्तार रहा है और वे संभावित विकास चालकों के रूप में उभरे हैं। पिछले महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर/ निर्माण क्षेत्र की गतिविधि में पिछले माह के (-) 1.9 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त में आठ मूल उद्योगों के सूचकांक कोयला, विद्युत, कच्चा तेल और सीमेंट के कारण संकुचित रहे। रिज़र्व बैंक के ओबीआईसीयूएस (रिज़र्व बैंक की आदेश बही, वस्तु सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण) द्वारा मापा गया विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 76.1 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही में 73.6 प्रतिशत तक कम हुआ। तथापि मौसमी समायोजित

सीयू, 2018-19 की चौथी तिमाही में 74.5 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही में 74.8 प्रतिशत तक बढ़ा । विनिर्माण कंपनियों ने औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के लिए 2019-20 की दूसरी तिमाही में क्षमता उपयोग में सुधार के अनुमान पर मत दिया। 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक (बीएआई) नए आदेशों में कमी, उत्पादन में संकुचन एवं सर्वेक्षणित फर्मों के लाभ मार्जिन में गिरावट के कारण कम हुआ । सितंबर 2019 में उत्पादन पीएमआई पिछले महीने की तुलना में अपरिवर्तित रही; नए आदेशों और रोजगार में मामूली वृद्धि हुई और नए निर्यात आदेशों में गिरावट आयी।

10. उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि जुलाई-अगस्त में सेवा क्षेत्र की गतिविधि कमजोर हुई। ग्रामीण मांग के संकेतक, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री संकुचित रहीं। शहरी मांग के अंतर्निहित संकेतकों में से, जुलाई-अगस्त में यात्री वाहन की बिक्री संकुचित हुई, जबकि अगस्त में घरेलू हवाई यात्री यातायात में तेजी आई। परिवहन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख संकेतक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जुलाई-अगस्त में दोहरे अंकों से संकुचित रही । निर्माण गतिविधि के दो संकेतकों में से, तैयार स्टील की खपत अगस्त में तेजी से कम हो गई और सीमेंट उत्पादन संकुचित हो गया। सितंबर 2019 में सेवा पीएमआई मुख्य रूप से नए व्यापार प्रवाह में गिरावट के कारण संकुचित रही।

11. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई, खुदरा मुद्रास्फीति, जून और अगस्त के बीच 3.1- 3.2 प्रतिशत की एक संकीर्ण सीमा में चली गई। जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई, ईंधन की कीमतों में गिरावट आई। अगस्त में खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति नरम हो गई।

12. अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी सब्जियों की कीमतों में वृद्धि, दालों की मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी और मांस और मछली मुद्रास्फीति में लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुई। दूसरी तरफ, अंडे, तेल और वसा, गैर-मादक पेय और तैयार भोजन की कीमतों में नरम वृद्धि हुई, और फलों और चीनी की कीमतों में गिरावट ने समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की।

13. अगस्त में ईंधन समूह में अपस्फीति और गहरी हो गई जो तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट के कारण थी। रियायती मिट्टी तेल की कीमतें, हालांकि, एक कैलिब्रेटेड ढंग से बढ़ रही थी क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी में एक क्रमिक कमी को जारी रखा था।

14. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़ी, लेकिन इसकी जड़ें काफी हद तक व्यक्तिगत देखभाल की कीमतों और प्रभावों तक - मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करनेवाली बुलियन कीमतों और परिवहन और संचार तक सीमित थीं । इसके विपरीत, अगस्त में नरमी रही, जो अधिकांश उप-समूहों में फैली हुई थी; हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में और तेजी आई।

15. रिज़र्व बैंक के सितंबर 2019 के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण के दौर से संकेत मिलता है कि परिवार प्रत्याशा मुद्रास्फीति में 3 माह आगामी होरीज़ोन में 40 आधार अंकों की वृद्धि और एक वर्ष आगामी होरीज़ोन में 20 आधार अंकों की वृद्धि होगी, जो कि संभवतः हाल के महीनों में खाद्य कीमतों में वृद्धि की अनुकूल प्रतिक्रिया है। रिज़र्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, कमजोर उपभोक्ता धारणा और कमजोर खपत मांग को दर्शाता है। विनिर्माण फर्मों ने 2019-20 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में मांग की स्थिति को कमजोर होते हुए देखा और उम्मीद की जा रही है कि वित्त और वेतन खर्चों के मद्देनजर उनकी उत्पादन कीमतें मौन रहेंगी।

16. रिज़र्व बैंक द्वारा सिस्टम से चलनिधि की निकासी करके परिचालन और विदेशी मुद्रा संचालन में मुद्रा को बढ़ाने के बावजूद अगस्त और सितंबर 2019 में समग्र चलनिधि अधिशेष में बनी रही। अगस्त में एलएएफ के तहत सकल दैनिक अनुपात अवशोषण ₹1,40,497 करोड़ था, जो अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा किए गए खर्च के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप महीने की शुरुआत से (25 अगस्त 2019 तक) अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और आंतरायिक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्राप्त की गई। सितंबर में, नकदी शेष के स्थिर निर्माण के साथ, विशेष रूप से 15 सितंबर के आसपास अग्रिम कर प्रवाह के कारण, अधिशेष चलनिधि नरम हुई, और सितंबर में रिज़र्व बैंक ने, ₹1,22,392 करोड़ की दैनिक सकल राशि अवशोषित की। आसान चलनिधि की स्थिति को दर्शाते हुए, अगस्त में 8 आधार अंकों (बीपीएस)

और सितंबर में 6 आधार अंकों द्वारा पॉलिसी रेपो दर (औसतन) से भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) नीचे लाया गया।

17. मौद्रिक संचरण विचलित और अधूरा रह गया है। फरवरी-अगस्त 2019 के दौरान संचयी नीति रेपो दर में 110 बीपीएस की कमी के बावजूद, वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपये के ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 29 बीपीएस की गिरावट आई। तथापि, इसी अवधि के दौरान बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में 7 बीपीएस की वृद्धि हुई।

18. निर्यात के मुकाबले आयात में गहरे संकुचन के कारण सकल निर्यात ने 2019-20 की पहली तिमाही में कुल मांग में योगदान दिया था। दूसरी तिमाही में, जुलाई और अगस्त 2019 में व्यापारिक माल का निर्यात कमजोर रहा, जिसका कारण इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण और कपास यार्न का कम लदान था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मुख्य रूप से तेल आयात बिल कम होने और आयातित सोने की मात्रा में कमी होने के कारण इस अवधि में आयात में तेजी से संकुचन हुआ। कोयला, मोती और जवाहारात और परिवहन उपकरण द्वारा गैर-तेल गैर सोना आयात को नीचे संकुचन में खींच लिया। इन गतिविधियों ने जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान व्यापार घाटे को कम किया। उच्च सकल सेवा प्राप्तियों और निजी हस्तांतरण प्राप्तियों ने 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी के चालू खाता घाटे को, एक साल पहले के 2.3 प्रतिशत से घटाकर 2.0 प्रतिशत किया। वित्त पोषण के मामले में, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक साल पहले के 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2019 में 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सकल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (स्वैच्छिक रिटेंशन रूट को छोड़कर) अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह की तुलना में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार का कुल वितरण एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध पुनर्भुगतान की तुलना में बढ़कर 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 1अक्टूबर 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 434.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था - मार्च 2019 के अंत तक 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

संभावनाएं

19. अगस्त 2019 के तीसरे द्विमासिक संकल्प में, सीपीआई मुद्रास्फीति को समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.1 प्रतिशत, 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 3.6 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। दूसरी तिमाही के लिए अब तक (जुलाई-अगस्त) महंगाई दर 3.2 प्रतिशत रही है जो मोटे तौर पर इन अनुमानों के अनुरूप है।

20. आगे, कई कारक मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र को आकार देने की संभावना रखते हैं। सबसे पहले, अगस्त द्वि-मासिक नीति के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना में काफी सुधार हुआ है। खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर के करीब अनुमानित है, जो समग्र खाद्य आपूर्ति की स्थिति के लिए अच्छा शकुन है। सब्जी की कीमतें तत्कालिक महीनों में बढ़ सकती हैं, लेकिन सर्दियों की आपूर्तियों के बाजार में प्रवेश करने के साथ उनके मध्यम हो जाने की संभावना है। दालों की कीमतों में पर्याप्त बफर स्टॉक के रहने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों को देखते हुए 2019-20 की तीसरी तिमाही में उत्पादन की कीमतों में नरमी के संकेत के साथ कमजोर मांग की स्थिति के बने रहने की ओर इशारा करते हैं। तदनुसार, भोजन और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में मूल्य दबाव कम हो जाने की संभावना है। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतें निकट अवधि में अस्थिर रह सकती हैं; जबकि वैश्विक मांग धीमी हो रही है, लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए कुछ उपरी ओर की जोखिम पैदा कर सकती है। चौथा, तीन महीने और एक साल आगे रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत परिवारों की मुद्रास्फीति की उम्मीदें मौजूदा दौर में बढ़ी हैं, जो निकट अवधि में मूल्य दबावों को दर्शाती हैं। अंत में, हाल के दौर में मूल्यह्रास प्रभावित कई उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के साथ वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। इन कारकों और हाल की नीति दर में कटौती के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.4 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जबकि 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली तिमाही के लिए अनुमानों को 3.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है (चार्ट 1)।

21. वृद्धि की ओर रुख करते हुए अगस्त पॉलिसी में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कुछ हद तक नीचे की ओर झुके हुए जोखिम के साथ 2019-20 की पहली छमाही के लिए

चार्ट 1: तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

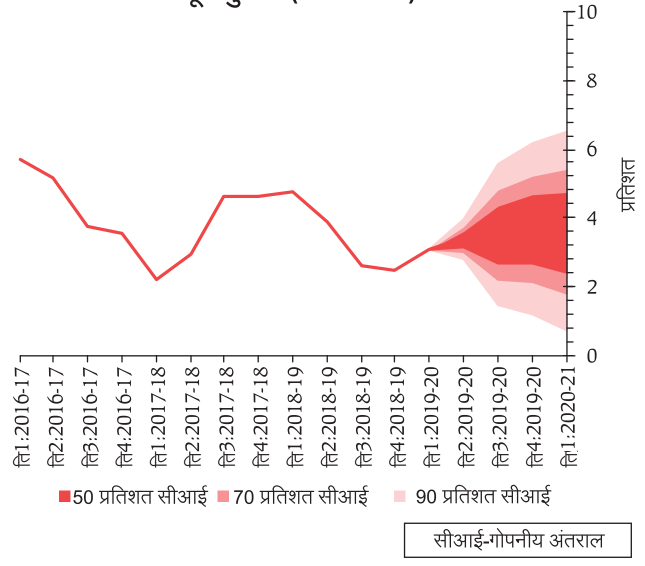

चार्ट 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का त्रैमासिक पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

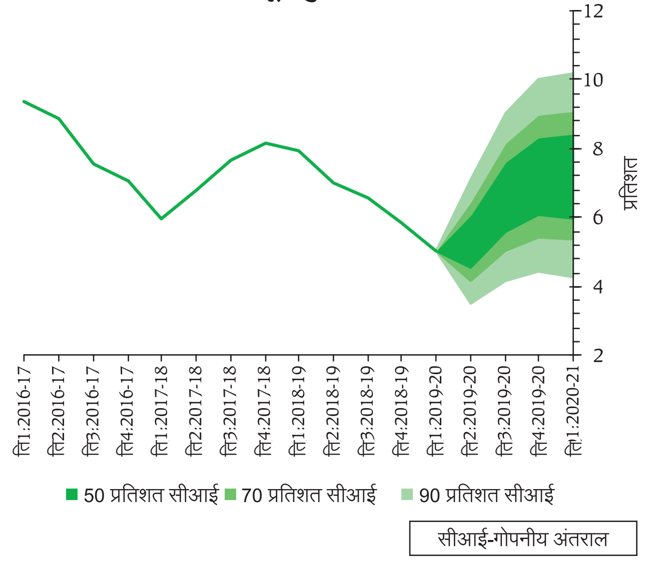

5.8-6.6 प्रतिशत की रेंज में और 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 7.3-7.5 प्रतिशत की रेंज में 6.9% और 2020-21 पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान की तुलना में काफी कम रहीं। विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि घरेलू मांग की स्थिति कमजोर बनी हुई है। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण की व्यावसायिक अपेक्षाओं का सूचकांक तीसरी तिमाही में मांग की स्थितियों में मूक विस्तार को दर्शाता है। वैश्विक विकास के धीमे हो जाने और व्यापार तनाव के जारी रहने से निर्यात की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं।हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर फरवरी 2019 के बाद से उदार मौद्रिक नीति के प्रभाव से धीरे-धीरे वास्तविक अर्थव्यवस्था के पोषक हो जाने और मांग को बढ़ाने की उम्मीद है। पिछले दो महीनों में सरकार द्वारा घोषित कई उपायों से भावना और घरेलू मांग, विशेषकर निजी खपत को पुनर्जीवित किए जाने की उम्मीद है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अगस्त की नीति में समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ 6.9 प्रतिशत से नीचे 6.1 प्रतिशत - 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 5.3 प्रतिशत और 2019-20 दूसरी छमाही के लिए 6.6-7.2 प्रतिशत की सीमा में संशोधित की गई और 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि भी नीचे की ओर 7.2 प्रतिशत के रूप में संशोधित हो गई है (चार्ट 2)।

22. एमपीसी द्वारा नोट किया गया है कि नकारात्मक आउटपुट अंतर विस्तृत हो गया है। हालांकि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए उपायों से निजी खपत को मजबूत करने और निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की संभावना है, निरंतर मंदी ने विकास की गति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास तेज करने की आवश्यकता को अधोरेखित किया है । 2019-20 की शेष अवधि में और 2020-21 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के लक्ष्य से नीचे रहने की उम्मीद है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के भीतर घरेलू मांग में मजबूती लाकर विकास चिंताओं को दूर करने के लिए नीतिगत अवसर है। एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इसके लिए उदार रुख बरकरार रखा जाए।

23. एमपीसी के सभी सदस्यों ने पॉलिसी रेपो दर को कम करने और मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को जारी रखने के लिए मतदान किया। डॉ.चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास ने रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया। डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया ने रेपो दर को 40 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया।

24. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 18 अक्टूबर 2019 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

25. एमपीसी की अगली बैठक 3-5 दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी ।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने; वित्तीय बाजारों को व्यापक और मजबूत करने और भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)

2010 में आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट को देखते हुए, एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम) का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनबीएफसी, अर्थात, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) की एक अलग श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया और दिसंबर 2011 में एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एक विस्तृत विनियामक ढांचा तैयार किया गया था। पात्र परिसंपत्ति के रूप में जोखिम को वर्गीकृत करने के लिए आय और ऋण सीमा को अंतिम बार 2015 में संशोधित किया गया था। गरीब तबके के लोगों तक ऋण पहुंचाने और उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु एमएफआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए इन मानदंडों को निम्नानुसार संशोधित करना प्रस्तावित है:

i. एनबीएफसी-एमएफआई के उधारकर्ताओं के वर्तमान स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1.00 लाख और शहरी / अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1.60 लाख को बढ़ाकर क्रमश: ₹1.25 लाख और ₹2.00 लाख किया जाए।

ii. पात्र उधारकर्ता के लिए ऋण सीमा को ₹1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹1.25 लाख की जाए।

इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

II. वित्तीय बाजार

2. ऑफशोर रुपया बाजार

ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्य बल (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) ने 30 जुलाई 2019 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में गैर-निवासियों को ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की सिफारिश की। रिजर्व बैंक ने सिफारिशों की जांच की है और निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करना प्रस्तावित किया है:

घरेलू बैंकों को स्वतंत्र रूप से किसी भी समय गैर-निवासियों को उनकी भारतीय बहियों के अलावा, घरेलू बिक्री टीम द्वारा या उनकी विदेशी शाखाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा कीमतों की पेशकश करने की अनुमति देना; तथा

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में कारोबार करने के लिए रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) को अनुमति देना।

केंद्र सरकार और अन्य विनियामकों के परामर्श से उपर्युक्त दोनों सिफारिशों को लागू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन पर निर्णय की घोषणा यथासमय की जाएगी।

3. अनिवासी रुपया खाता - नीति की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी), व्यापार ऋण और निर्यात और आयात के संबंध में सीमा-पार लेन-देन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए विनिमय जोखिम कम हो जाता है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि, ब्याज रहित वाले विशेष गैर-निवासी रुपये (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाने के लिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को रुपया मूल्यवर्ग ईसीबी की सुविधा, व्यापार ऋण और व्यापार चालान के लिए ऐसे खातों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा, एसएनआरआर खाते की अवधि पर प्रतिबंध, जो कि वर्तमान में 7 वर्ष है, को भी उपरोक्त उद्देश्यों के लिए हटाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में दिशानिर्देश एक महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।

III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

4. प्रस्तावित 24x7 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली के लिए चलनिधि सहायता

7 अगस्त 2019 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक दिसंबर 2019 से जनता के लिए 24x7 आधार पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा

उपलब्ध कराएगा। रिजर्व बैंक के पास रखे गए बैंकों के खातों में इन लेन-देन के सुचारू निपटान को सुकर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक संपार्श्विक चलनिधि सहायता को चौबीस घंटों के लिए विस्तारित करेगा, जो वर्तमान में एनईएफटी पर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 7.45 बजे तक उपलब्ध है। इससे बैंकों द्वारा निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

5. बड़े गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं द्वारा आंतरिक लोकपाल

ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए एक लोकपाल योजना की स्थापना की थी जैसा कि 5 दिसंबर 2018 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था। संस्थागत स्तर पर ही शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बड़े गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं (उन संस्थाओं के लिए जिनपर 10 मिलियन से अधिक प्री-पेड भुगतान लिखत बकाया है) वाली आंतरिक लोकपाल योजना को संस्थागत बनाया जाए। आंतरिक लोकपाल का उद्देश्य संस्था के भीतर एक तेज और किफ़ायती शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करना और शिकायत निवारण के लिए एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करना है। इस संबंध में निर्देश 15 अक्टूबर 2019 तक जारी किए जाएंगे।

6. भुगतान प्रणाली आंकडों का प्रसारण

रिज़र्व बैंक विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणाली संकेतकों पर आंकडे (रिज़र्व बैंक बुलेटिन और आरबीआई वेबसाइट पर) प्रकाशित करता है। डिजिटल भुगतान की गहनता संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणी) की सिफारिश के अनुरूप और डिजिटल भुगतान अवसरों में तेजी से विकास को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत भुगतान प्रणाली को शामिल करने वाले भुगतान के आंकडों संबंधी अधिक सूक्ष्म जानकारी प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ, भुगतान प्रणाली आंकडों का संपूर्ण विवरण बुलेटिन/ वेबसाइट में उपलब्ध होगा।

7. स्वीकृति विकास निधि (एडीएफ़)

देश में कार्ड जारी करने में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ देश भर में विशेष रूप से टियर III से टीयर VI केंद्रों में स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए जैसाकि आरबीआई के भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2021 में इंगित किया गया है और डिजिटल भुगतान की गहनता संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणी) द्वारा सिफारिश की गई है, हितधारकों के परामर्श से 'स्वीकृति विकास निधि' (एडीएफ़) बनाने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2019 तक ढांचे का परिचालन किया जाएगा।

8. डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार और गहनता

डिजिटल भुगतान तंत्र को विस्तृत और गहन करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश स्तरीय बैंकरों की समितियां (एसएलबीसी / यूटीएलबीसी) बैंकों और हितधारकों के परामर्श से पायलट आधार पर अपने संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में एक जिले की पहचान की जाएं। पहचान किए गए जिले को महत्वपूर्ण पदचिह्न वाले बैंक को आवंटित किया जा सकता है जो जिले को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। यह जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, सावधानीपूर्वक, त्वरित, सस्ती और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल रूप से भुगतान करने /राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संबंध में दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

I. समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण

घरेलू आर्थिक गतिविधियों में वर्ष 2018-19 में जो मंदी शुरू हुई थी वह वर्ष 2019-20 की पहली छमाही तक बनी रही। यह अनुमान है कि हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) वर्ष 2019-20 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2020-21 के प्रारम्भिक महीनों में लक्ष्य से नीचे बना रहेगा। यह उम्मीद की जाती है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में बहाल हो जाएगी,क्योंकि आधारगत प्रभाव अनुकूल था और गत मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई प्रसारित हो चुकी थी। सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से संवृद्धि की संभावना अच्छी बन गई है। अमरीका-चीन के बीच व्यापार संबंधी तनावों को लेकर विश्व में अनिश्चितता के तीव्र हो जाने, ब्रेक्सिट की मुश्किलें और भू-राजनैतिक तनाव बेसलाइन संवृद्धि पथ के प्रति नकारात्मक जोखिम हैं।

I.1 अप्रैल 2019 की एमपीआर के बाद से अब तक हुई मुख्य प्रगति

अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट(एमपीआर) के प्रकाशन के बाद की अवधि में जैसाकि उच्च आवृत्ति के संकेतकों से पता चलता है, वैश्विक आर्थिक गतिविधियां और भी कमज़ोर हो गयी हैं। अप्रैल की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में जिन नकारात्मक जोखिमों को चिह्नित किया गया था वे अब दिखाई देने लगे हैं जैसे-व्यापारगत तनावों का गहरा जाना, ब्रेक्सिट व्यतिक्रम की बढ़ती संभावनाएं, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, अशांत भू-राजनैतिक और आर्थिक घटनाओं के चलते वित्तीय बाज़ार में जोखिम-सहित एवं जोखिम–रहित मनोभावों का बने रहना। इन सब के होने से वैश्विक संवृद्धि ने 2019 की पहली तिमाही में जो गति पकड़ी थी, उसने उसे खो दिया है। इस चक्र के बचाव में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने जवाबी कार्रवाई के रूप में मौद्रिक नीति को सहज बनाना शुरू कर दिया है। वैश्विक व्यापार अधिक संकुचन में चला गया है, जिसकी चोट का प्रभाव निवेश एवं औद्योगिक उत्पादन, खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसकी अनुकम्पा से वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट आ गयी है, साथ ही अगस्त में कच्चे तेल की कीमतें डांवाडोल हो रही थीं और सुरक्षित स्थान पर पैसा लगाने की मांग की वजह से स्वर्ण की कीमतें तेज हो रही थीं। चीन की रेनमिनबी में अगस्त के प्रारम्भ से ही मूल्यह्रास होने के कारण विदेशी मुद्रा बाज़ार अस्थिर हो गए थे। लेकिन सऊदी अरब की तेल सुविधा पर हुए हमले एवं विश्व में तेल की आपूर्ति में अत्यधिक बाधा उत्पन्न होने से सितम्बर के मध्य तक कच्चे तेल की कीमतें संभली रहीं।

घरेलू स्तर पर, आर्थिक गतिविधियों में जो मंदी वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में शुरू हुई थी वह वर्ष 2019-20 की पहली छमाही तक जारी रही। वास्तविक जीडीपी वृद्धि की वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जो स्थिति थी वह पिछली 25 तिमाहियों से भी कम हो गई थी क्योंकि निजी उपभोग और निवेश कमज़ोर हो गए थे और दूसरी तिमाही के उच्च आवृत्ति संकेतक इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सकल मांग की गहनता के विभिन्न घटकों में धीमापन आ रहा था। हालांकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि के आसार पैदा हो रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून जो प्रारम्भ में देर से शुरू हुआ था उसकी कमी की भरपाई जुलाई-सितंबर में जमकर हुई वर्षा से पूरी हो गई। जलाशयों का स्तर बढ़कर संतोषजनक स्तर तक आ गया है जो रबी फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त है तथा खाद्यान्न का भंडार बफर मानदंड के स्तर से तीन गुना ज़्यादा है जो अत्यधिक मुद्रास्फीति के दबाव की हालत में राहत(कुशन) प्रदान करता है।इस बीच हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य के स्तर से नीचे बनी हुई है। मार्च 2019 से जहां खाद्य सामग्री की महंगाई बढ़ी हुई थी, वहीं खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर अन्य के लिए मुद्रास्फीति में बड़े पैमाने पर संतुलन पैदा हुआ है।

मौद्रिक नीति समिति : अप्रैल-अगस्त 2019

द्विमासिक कार्यक्रम के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान तीन बार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। अप्रैल की बैठक में जहां एमपीसी ने रेपो दर में 25 आधार अंक(बीपीएस) की कमी करते हुए उसे 6.0 प्रतिशत किया (4-2 के अनुपात में मतदान के साथ) ताकि निजी निवेश बढ़े और घरेलू संवृद्धि की रफ्तार को मजबूती मिल सके, वहीं मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ बनाए रखा (5-1 के अनुपात में मतदान के साथ)। संवृद्धि की गति में कमज़ोरी के आसार को, यहाँ तक कि ऋणात्मक उत्पादन–अंतर के और ज़्यादा बढ़ जाने एवं अगले 12 महीने में हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे बनी रहने के अनुमान को देखते हुए एमपीसी ने जून 2019 की अपनी बैठक में रेपो दर को और भी 25 आधार अंक कम करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया तथा मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ से निभावकारी कर दिया।

अगस्त की बैठक में एमपीसी ने इस आधार पर कि पूरे विश्व में संवृद्धि की दर घट रही है तथा बढ़ते हुए व्यापार संबंधी तनावों ने संपूर्ण परिदृश्य के प्रति नकारात्मक जोखिम का खतरा पैदा कर दिया है

[*] 04 अक्तूबर, 2019 को जारी किया गया।

जिससे घरेलू गतिविधियों में मंदी की स्थिति और प्रबल हो सकती है, नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंक और घटाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया। इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए कि दिए गए पूर्वानुमान की समय-सीमा में मुद्रास्फीति की संभावना नरम एवं लक्ष्य के भीतर बनी रहेगी, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सभी सदस्यों ने नीतिगत दर को सर्वसम्मति से कम करने के लिए (4 सदस्यों ने 35 आधार अंक और दो सदस्यों ने 25 आधार अंक की कमी के लिए मतदान किया) और नीति का रुख निभावकारी बनाए रखने के लिए मतदान किया। एमपीसी का यह विचार था कि विश्व में उभरती घरेलू एवं समष्टि–आर्थिक प्रगति के चलते 25 आधार अंक की कटौती संभवतः अपर्याप्त होगी, जबकि 50 आधार अंक की कटौती ज़्यादा हो जाएगी, खासतौर से इस संबंध में पहले की गई नई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए। समग्र रूप से, एमपीसी ने नीतिगत दर को फरवरी में 25 आधार अंक कम किया था, उसके साथ ही अप्रैल-अगस्त के दौरान कुल मिलाकर 85 आधार अंक की कटौती की गई।

एमपीसी के मतदान पैटर्न से पता चलता है कि प्रत्येक सदस्य के मूल्यांकन, प्रत्याशा तथा नीतिगत वरीयता में कितनी विविधता है, यह एक ऐसी विशेषता है जो अन्य केंद्रीय बैंकों की एमपीसी के मतदान पैटर्न से परिलक्षित होती है (सारणी I.1)।

समष्टि–आर्थिक दृष्टिकोण

अध्याय II और III में अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान हुई समष्टि-आर्थिक प्रगति का विश्लेषण दिया गया है और ये अध्याय स्टाफ द्वारा दिए गए अनुमानों की तुलना में मुद्रास्फीति तथा संवृद्धि के परिणामों में हुए विचलन को बताते हैं। इसकी संभावना की ओर देखें तो पता चलता है कि पिछले छह महीने में जो प्रमुख समष्टि-आर्थिक तथा वित्तीय चर उभरे हैं, वे यह अपेक्षा करते हैं कि बेसलाइन मान्यताओं को संशोधित किया जाए (सारणी I.2)।

सारणी I.1: मौद्रिक नीति समिति तथा मतदान पैटर्न

देश	नीति बैठकें : अप्रैल 2019 – सितंबर 2019		
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति के साथ बैठक	असहमति के साथ बैठक
ब्राज़ील	4	4	0
चिली	4	3	1
चेक गणराज्य	4	2	2
हंगरी	5	5	0
इजरायल	4	1	3
जापान	4	0	4
दक्षिण अफ्रीका	3	2	1
स्वीडन	3	3	0
थाईलैंड	4	3	1
यू के	4	4	0
यू एस	4	1	3

स्रोत: केन्द्रीय बैंक वेबसाइट।

सारणी I.2: निकट अवधि के पूर्वानुमानों के लिए आधारभूत अनुमान

संकेतक	एमपीआर (अप्रैल 2019)	वर्तमान एमपीआर (अक्तूबर 2019)
कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	2019-20 के दौरान प्रति बेरल यूएस $67.0	प्रति बेरल यूएस $62.6
विनिमय दर	रु.69/यूएस$	रु.71.3/यूएस$
मानसून	2019 के लिए सामान्य	दीर्घावधि औसत के 10 प्रतिशत ऊपर
वैश्विक संवृद्धि	2019 में 3.5 प्रतिशत 2020 में 3.6 प्रतिशत	2019 में 3.2 प्रतिशत 2020 में 3.5 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2019-20 के भीतर रहेगी केंद्र : 3.4 प्रतिशत संयुक्त: 5.9	बीई 2019-20 के भीतर रहेगी केंद्र : 3.3 संयुक्त: 5.9
पूर्वानुमान की अवधि के दौरान घरेलू समष्टि आर्थिक/ स्ट्रक्चरल नीतियां	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

टिप्पणियाँ :
1. कच्चे तेल का भारतीय बास्केट ऐसे व्युत्पन्न मूल्य मापन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सॉअर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट) कच्चा तेल शामिल है।
2. यहाँ अनुमानित विनिमय दर पथ स्टाफ के आधारभूत संवृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमान हासिल करने के उद्देश्य के लिए है तथा यह विनिमय दर के स्तर पर कोई "मत" प्रकट नहीं करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित है,न कि विनिमय दर के आसपास किसी भी विशिष्ट स्तर के और/या बैंड के उतार-चढ़ाव से।
3. विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (जनवरी और जुलाई 2019 अपडेट्स), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) से वैश्विक संवृद्धि अनुमान लिये गए हैं।
4. बीई : बजट अनुमान।
5. संयुक्त राजकोषीय घाटे में केंद्र और राज्यों को एक साथ लिया है।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान; बजट दस्तावेज़; और आईएमएफ।

प्रथम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें मई-मध्य और सितम्बर–मध्य में कम हो गईं जिससे यह पता चलता है कि तेल की बेशी आपूर्ति एवं भंडारण की स्थिति के चलते विश्व में मांग कमज़ोर हुई है, बावजूद इसके कि ईरान–संबंधी भू- राजनैतिक तनाव बने हुए थे और ओपेक ने उत्पादन में कटौती कर दी थी (चार्ट I.1)। लेकिन, कच्चे तेल की कीमतें सितम्बर के उत्तरार्ध में बढ़ गईं क्योंकि सऊदी अरब में तेल उत्पादन बाधित हो गया था। वर्तमान मांग-आपूर्ति की स्थिति के मूल्यांकन तथा बाज़ार की भावी स्थिति से ग्रहण किए गए संकेतों को देखते हुए बेसलाइन परिदृश्य से ऐसा लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें 2019-20 की दूसरी छमाही में औसतन 62.6 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रहेंगी।

चार्ट I.1: क्रूड ऑइल: मांग-आपूर्ति संतुलन और कीमतें

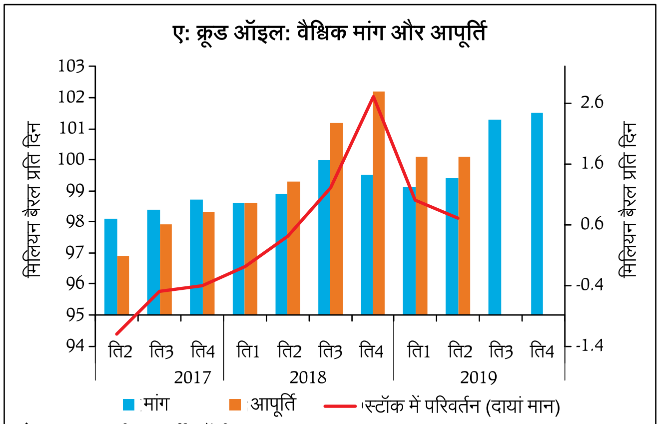

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी।

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

द्वितीय, सांकेतिक विनिमय दर(अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपया) अपने अप्रैल के स्तर से घट गई है, विशेष रूप से अगस्त के दौरान, क्योंकि अमरीका-चीन के व्यापार संबंधी कार्रवाइयों के गहरा जाने से चीन की रेनमिनबी प्रति अमरीकी डालर 7 यूआन मनोवैज्ञानिक स्तर नीचे चली गई जिससे होने वाली गिरावट का प्रभाव पड़ा है। आमतौर पर अमरीकी डालर आस्तियों तथा पोर्टफोलियो पूंजी बहिर्वाह के संबंध में सुरक्षित स्थान की ओर रुख ने भी रुपए पर दबाव को तेज़ कर दिया है। रुपए पर नया दबाव सितंबर के मध्य में पैदा हुआ क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार द्वारा निवेश और संवृद्धि तथा पूंजी बाज़ार में निधियों के प्रवाह को स्थिर बनाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा किए जाने से बाद के दिनों में रुपए के मूल्य पर हुए दबाव में बहाली पैदा हो गई।

तृतीय, वैश्विक आर्थिक गतिविधियां तथा व्यापार कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस बात की पुष्टि वैश्विक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक(पीएमआई) ने कर दी है जो सितंबर 2019 में 49.7 पर घटते हुए दायरे में बना रहा है। विश्व व्यापार संगठन के वस्तु व्यापार बैरोमीटर से संकेत मिलता है कि वणिक व्यापार कमज़ोर था जो 2019 की तीसरी तिमाही में क़ायम रहा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा वैश्विक संवृद्धि के अनुमान के ग्रेड को कम किया है। इस परिदृश्य में देखें तो वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में वैश्विक संवृद्धि अब अप्रैल बेसलाइन से नीचे रहने की उम्मीद है(सारणी I.2 और चार्ट I.2)।

I.2 मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण

वर्ष 2019-20 में अब तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे बनी रही है। खास बात यह है कि प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं में खाद्यान्न एवं ईंधन को छोड़कर अन्य में मुद्रास्फीति नरम बनी रही है जिससे घरेलू स्तर पर मांग के मंद बने रहने का पता चलता है। इसके आगे देखें तो मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं जो मूल्य और मज़दूरी में गिरावट के माध्यम से भावी मुद्रास्फीति में जुड़ती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर में किए गए सर्वेक्षण चक्र के अनुसार शहरी पारिवारिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं एक वर्ष आगे तक 20 आधार अंक तक बढ़ी, हालांकि इस अवधि में तीन महीने आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं 40 आधार अंक बढ़ गई हैं[1](चार्ट I.3)। रिज़र्व बैंक के सितंबर के उपभोक्ता विश्वसनीयता सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं पिछले सर्वेक्षण चक्र की तुलना में कम हुई हैं।

चार्ट I.2: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि

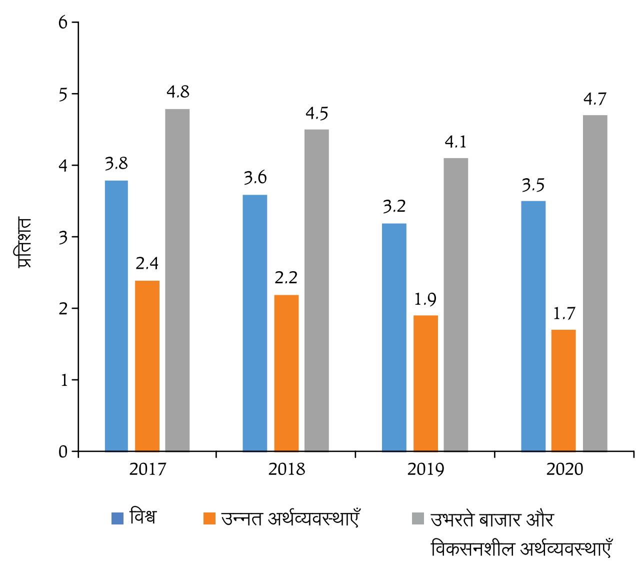

स्रोत : आईएमएफ।

[1] रिज़र्व बैंक का परिवार संबंधी मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण 18 शहरों में किया गया था और सितंबर 2019 के सर्वेक्षण के परिणाम (5,810) परिवारों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

चार्ट I.3: घरेलू वस्तुओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ

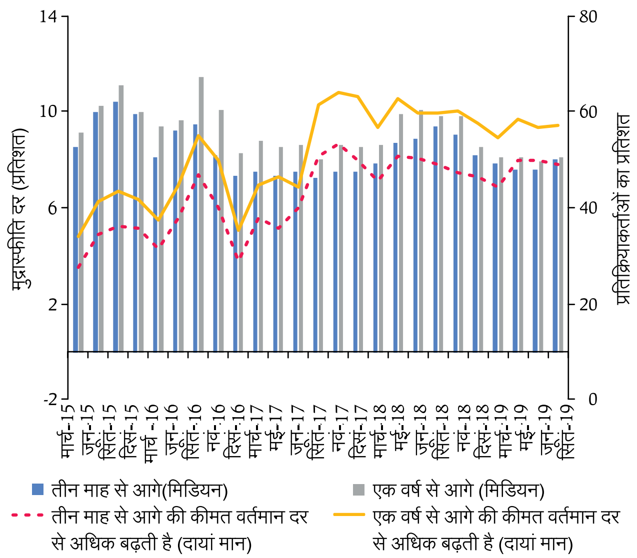

स्रोत: घरेलू वस्तुओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ सर्वेक्षण; आरबीआई।

चार्ट I.4: कच्चे माल की लागत और बिक्री कीमतों की अपेक्षाएँ

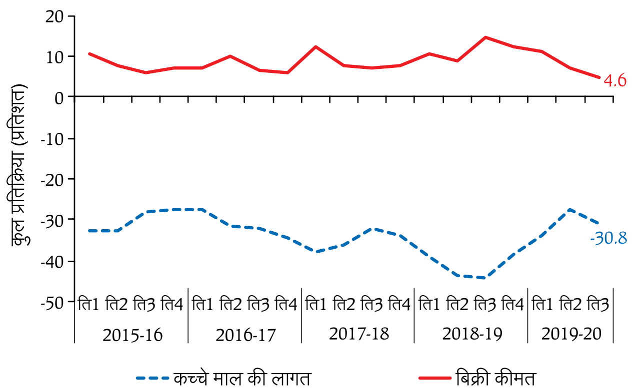

टिप्पणी : आशादायी और निराशाजनक सूचना देनेवाले उत्तरदाताओं के बीच का अंतर निवल प्रतिक्रिया हैं| यह रेंज -100 से 100 तक है | बिक्री कीमत के संबंध में निवल प्रतिक्रियाओं में वृद्धि /कमी आशादायी और निराशाजनक है, जबकि कच्चे माल की लागत के संबंध में निवल प्रतिक्रिया में वृद्धि / कमी उत्तरदाता कंपनी के दृष्टिकोण से आशादायी और निराशाजनक है | अतः कच्चे माल की लागत के उच्चतर/निम्नतर ऋणात्मक आंकड़ें उच्चतर/ निम्नतर इनपुट मूल्य दबावों को दर्शाते हैं |

स्रोत : औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई |

रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई-सितंबर 2019 में औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के चक्र में विनिर्माण फर्मों से यह अपेक्षित था कि कच्चे माल की लागत बढ़ेगी और 2019-20 की तीसरी तिमाही में बिक्री मूल्य शांत बने रहेंगे (चार्ट I.4)[2]। निक्केयी के विनिर्माण फर्मों के क्रय प्रबंधक सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादन के मूल्य कच्चे माल और अर्द्ध तैयार वस्तुओं की माँग कम होने से सितंबर में इनपुट मूल्य कम हो गए थे बावजूद इसके कि आउटपुट मूल्य कुछ बढ़ गए थे। लेकिन अगस्त में सेवा क्षेत्र की फर्मों में इनपुट मूल्य कम रिपोर्ट किए गए और उत्पादन मूल्य अधिक थे क्योंकि फर्मों ने अपने मार्जिन को बचाए रखा।

सितंबर 2019 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण में यह अपेक्षा की गई थी कि सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त 2019 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.9 प्रतिशत और 2020-21 की दूसरी तिमाही तक 4.0 प्रतिशत हो जाएगी (चार्ट I.5)[3]।

प्रारंभिक स्थितियों, आशावादी सर्वेक्षण के संकेतकों तथा समय-श्रृंखला एवं संरचनात्मक मॉडल्स के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया गया है कि सीपीआई मुद्रास्फीति 2019-20 की दूसरी तिमाही में 3.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 3.7 प्रतिशत रहेगी, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित रहेगा(चार्ट I.6)। हेडलाइन मुद्रास्फीति 2019-20 की चौथी तिमाही में 50 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत विश्वसनीयता अंतराल क्रमश: 2.7-4.7 प्रतिशत तथा 2.2-5.3 प्रतिशत होगा। वर्ष 2020-21 के लिए, यह मानते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा तथा बाह्य या नीतिगत कोई खास आघात नहीं पहुंचेगा, संरचनागत मॉडल के अनुमान यह बताते हैं कि मुद्रास्फीति 3.5-4.0 प्रतिशत के दायरे में बनी रहेगी। 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए 50 प्रतिशत

चार्ट I.5: व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ

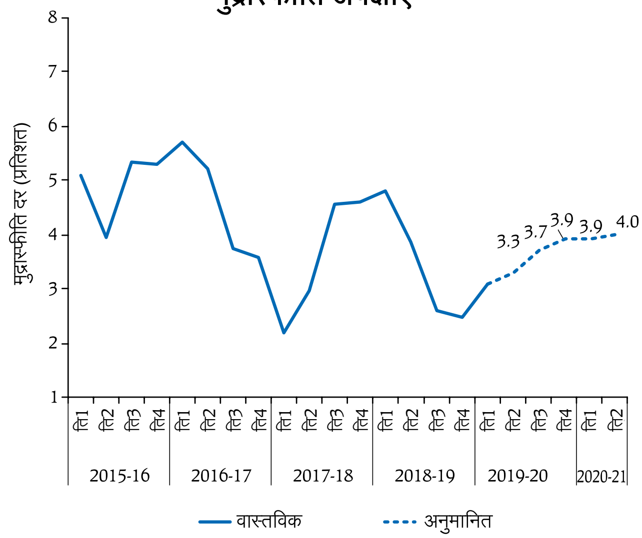

स्रोत : व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण,आरबीआई।

[2] जुलाई – सितंबर 2019 दौर के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के परिणाम 481 कंपनियो से प्राप्त उत्तर पर आधारित हैं।

[3] सितंबर 2019 में रिज़र्व बैंक के प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण के चक्र में 21 पैनलिस्ट ने भाग लिया था।

चार्ट I.6: सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान (वर्ष- दर वर्ष)

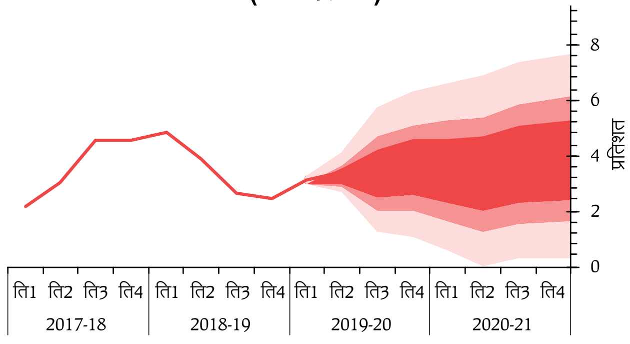

टिप्पणी : फ़ैन चार्ट बेसलाइन प्रोजेक्शन पथ के आस-पास अनिश्चितता दर्शाता है। बेसलाइन अनुमान तालिका I.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा लाल छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत आत्मविश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि वास्तविक परिणाम गहरे लाल छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होने की 50 प्रतिशत संभावना है । समान रूप से, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत आत्मविश्वास अंतराल के लिए, वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गयी सीमा के भीतर होने की क्रमश: 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है|

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान ।

चार्ट : 1.7 उपभोक्ता विश्वास

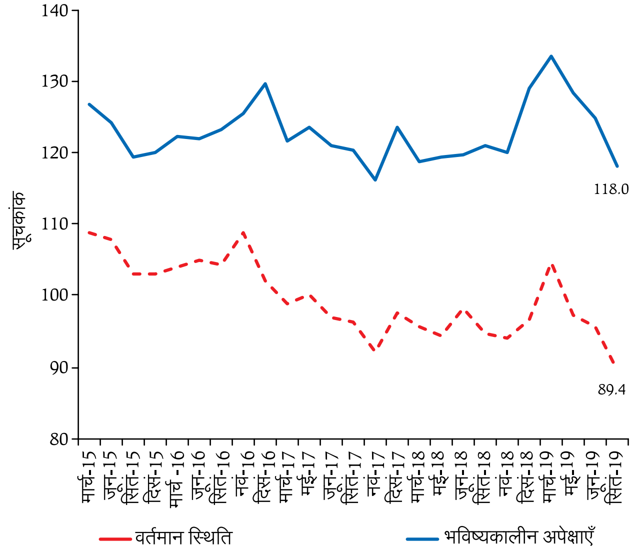

स्रोत : उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

और 70 प्रतिशत विश्वसनीयता अंतराल क्रमश: 2.5-5.4 प्रतिशत एवं 1.8-6.2 प्रतिशत रहेगा।

बेसलाइन मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दोनों प्रकार के जोखिम होते हैं। ऊर्ध्वमुखी जोखिम में अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू वित्तीय बाज़रों में ऐसी अस्थिरता शामिल होती है जो व्यापार तनाव, ब्रेक्सिट तथा प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीति रुझान, भू-राजनैतिक तनावों से पूरे विश्व में कच्चे तेल के बाज़ार में आपूर्ति संबंधी बाधा तथा नश्वर खाद्य सामग्रियों के मूल्य में अचानक उलटफेर से पैदा होती है। अधोमुखी जोखीम तब पैदा होते हैं जब विश्व में धीमी मांग के कारण कच्चे तेल एवं अन्य वस्तुओं की कीमतें मान्य कीमतों से ज़्यादा कम हो जाती हैं, तथा घरेलू स्तर पर मांग की दबी हुई स्थिति के कारण खाद्यान्न एवं ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति कमज़ोर बनी रहती है।

I.3 संवृद्धि के प्रति दृष्टिकोण

जैसाकि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दिए गए अनुमान की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में कमज़ोर बनी रही और यह ऐसा वातावरण था जो विश्व की प्रतिकूल स्थितियों से ग्रसित था। यह उम्मीद कि निजी उपभोग और निवेश दोनों बढ़ेंगे, पूरी नहीं हो पाई, और विश्व व्यापार में छाई मंदी के भार के नीचे निवल निर्यात ने अपनी गति खो दी। हालांकि इस मौसम में दक्षिण-पश्चिम मानसून औसत से अधिक बना रहा, किंतु इसके असमान बने रहने से अस्थायी रूप से तथा स्थानिक दोनों स्तर पर कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

संभावनाओं की ओर देखें तो रिज़र्व बैंक के मई, जुलाई और सितंबर के सर्वेक्षण चक्र में उपभोक्ता की विश्वसनीयता वर्ष में आगे चलकर कम होती गई है, क्योंकि सामान्य आर्थिक स्थितियों तथा रोज़गार परिदृश्य के प्रति मनोभाव क्षीण बना हुआ था(चार्ट I.7)[4]।

रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई-सितंबर 2019 में किए गए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण से विनिर्माण क्षेत्र के मनोभाव आगामी तिमाही में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्रत्याशित उत्पादन, आर्डर इनफ्लो, क्षमता उपयोग, रोज़गार स्थिति तथा निर्यात धीमा बना रहेगा(चार्ट I.8)।

भावी कारोबारी प्रत्याशाओं के बारे में अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं(सारणी I.3)। निक्केयी क्रय प्रबंधक सर्वेक्षण में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की फर्मों के बारे में एक-वर्ष आगे के उत्पादन की संभावनाएं आशावदी पाई गई हैं।

रिज़र्व बैंक सितंबर 2019 के सर्वेक्षण चक्र में प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं की उम्मीद है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सुधार होगा जो 2019-20 की पहली तिमाही के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर

[4] रिज़र्व बैंक ने 13 प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण किया और सितंबर 2019 का चरण 5,192 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर पर आधारित है।

चार्ट 1.8: व्यावसायिक मूल्यांकन और अपेक्षाएँ

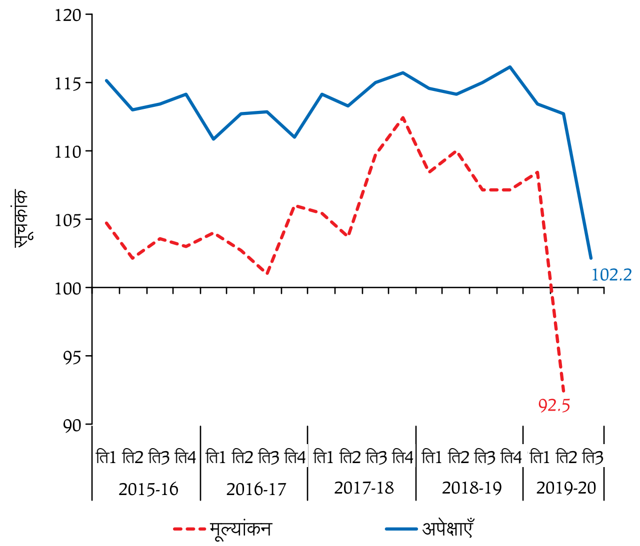

स्रोत : औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण,आरबीआई।

चार्ट 1.9 व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा वास्तविक जीडीपी में संवृद्धि का पूर्वानुमान

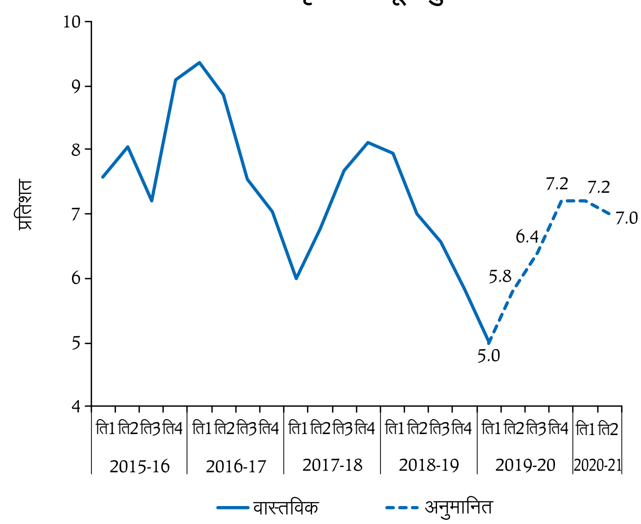

स्रोत : औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण,आरबीआई।

2019-20 की चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत और 2020-21 की दूसरी तिमाही में 7.0 हो जाएगी(चार्ट I.9)।

बेसलाइन मान्यताओं, सर्वेक्षण संकेतकों, फरवरी 2019 से नीतिगत रेपो दर में कमी, आधारगत प्रभाव तथा मॉडलगत पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2019-20 में 6.1 प्रतिशत अनुमानित की गई है – दूसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत – जिसमें जोखिम का रुख अधोमुखी होगा(सारणी I.4)। वर्ष 2020-21 के लिए संरचनागत मॉडल के अनुमान यह संकेत देते हैं कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0

सारणी I.3: कारोबारी प्रत्याशा सर्वे

मद	एनसीईएआर बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (जुलाई 2019)	फिक्की समग्र बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (जून 2019)	दून और ब्रेडस्ट्रीट कम्पोजीट बिजनेस आप्टिमिज्म इंडेक्स (जुलाई 2019)	सीआईआई बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (सितंबर 2019)
सूचकांक का वर्तमान स्तर	121.8	59.6	70.0	52.5
पिछले सर्वे के अनुसार सूचकांक	115.4	60.3	78.4	59.6
% परिवर्तन (ति-दर-ति)	5.5	-1.2	-10.7	-11.9
% परिवर्तन (वर्ष -दर -वर्ष)	6.5	-16.1	-13.2	-19.1

टिप्पणी : 1. एनसीईएआर : नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च।
2. एफआईसीसीआई : फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
3. सीआईआई : कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।

सारणी I.4: अनुमान - रिज़र्व बैंक और व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता

(प्रतिशत)

	2019-20	2020-21
रिज़र्व बैंक का बेसलाइन अनुमान		
मुद्रास्फीति,चौथी तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष)	3.7	4.0
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि	6.1	7.0
व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के माध्यिका अनुमान		
मुद्रास्फीति, चौथी तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष)	3.9	4.0#
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि	6.2	7.0
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	30.1	30.5
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	31.0	31.0
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में वृद्धि	12.0	12.9
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	6.1	6.0
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	3.3	3.3
रेपो रेट (समाप्त-अवधि)	5.0	-
91-दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	5.2	5.4
10-वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.3	6.5
समग्र भुगतान शेष (यूएस $ बिलियन)	15.1	10.0
पण्य निर्यात वृद्धि	1.5	6.3
पण्य आयात वृद्धि	0.5	7.1
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-1.9	-2.0

टिप्पणी : जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।
*: ति2:2020-21
स्रोत : रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान; व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (सितंबर 2019)।

चार्ट I.10: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि का पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

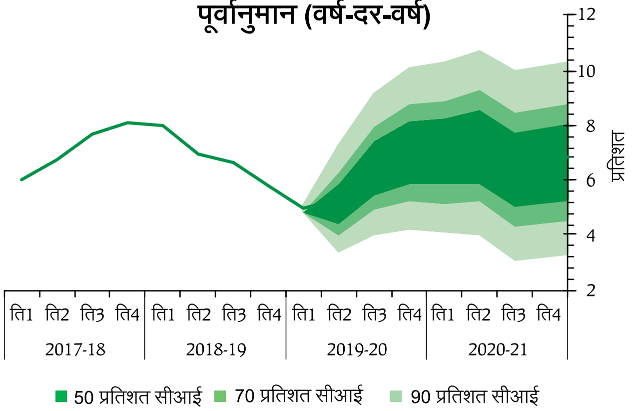

टिप्पणी : फ़ैन चार्ट बेसलाइन प्रोजेक्शन पथ के आस-पास अनिश्चितता दर्शाता है। बेसलाइन अनुमान तालिका I.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत आत्मविश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि वास्तविक परिणाम गहरे हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होने की 50 प्रतिशत संभावना है। समान रूप से, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत आत्मविश्वास अंतराल के लिए, वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गयी सीमा के भीतर होने की क्रमश: 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है|

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रतिशत की होगी – तिमाही वृद्धि की दर का दायरा 6.5-7.4 प्रतिशत होगा – यह मानते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा और किसी प्रकार का बाह्य या नीतिगत आघात नहीं पहुंचेगा।

बेसलाइन संवृद्धि परिदृश्य में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों जोखिम हैं (चार्ट I.10)। संवृद्धि और निवेश को तेज करने के लिए अगस्त-सितंबर में सरकार द्वारा घोषित उपायों– यथा- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) संबंधी नीतिगत सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु निधियों को सीधे जारी करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, निर्यात एवं भू-सम्पदा के लिए प्रोत्साहन, कॉर्पोरेट कर दर में कटौती- साथ ही, दबावग्रस्त आस्तियों के तीव्रतर समाधान और रेपो दर में की गयी पिछली कटौतियों का बैंकों द्वारा अपनी-अपनी उधार दरों में संचरित किए जाने की तीव्रतर गति ने बेसलाइन संवृद्धि अनुमान पथ को ऊपर उठाया है। तथापि, व्यापारिक तनावों में और वृद्धि तथा एक कठिन या नो-डील ब्रेक्सिट और वैश्विक वित्त बाज़ारों में तीव्रतर उतार-चढ़ाव, बेसलाइन संवृद्धि पथ के प्रमुख अधोगामी जोखिम हैं।

I.4 जोखिमों का संतुलन

पूर्ववर्ती खंडों में मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बेसलाइन पूर्वानुमान, सारणी I.2 में निर्धारित प्रमुख चरांकों संबंधी मान्यताओं पर निर्भर हैं। इन मान्यताओं को लेकर अनिश्चतताएँ, बेसलाइन पूर्वानुमानों में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी विचलन ला सकती हैं। यह खंड संभाव्य वैकल्पिक परिदृश्यों में बेसलाइन पूर्वानुमानों पर जोखिमों के संतुलन का आकलन करता है।

(i) वैश्विक संवृद्धि की अनिश्चितताएँ

बेसलाइन परिदृश्य में 2019 और 2020 में बाहरी मांग में कमी का अनुमान है। यदि व्यापारिक तनाव और बढ़ते हैं, या कठिन/नो-डील ब्रेक्जिट होता है, या निम्न ब्याज दर व्यवस्था के वर्षों का बाद उत्पन्न वित्तीय उतार-चढ़ाव या ऋण भुगतान में कठिनाइयों सहित अपस्फीति दबाव बढ़ते हैं, या चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अनुमान से अधिक मंदी आती है या इन सभी कारकों में तीव्रता आती है तो वैश्विक संवृद्धि और अधिक कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे परिदृश्य में, यदि वैश्विक संवृद्धि बेसलाइन से 50 बीपीएस नीचे खिसकती है तो घरेलू संवृद्धि और मुद्रास्फीति अपनी बेसलाइन ट्रेजेक्टरी से क्रमशः लगभग 20 बीपीएस और 10 बीपीएस और नीचे गिर सकती है। विलोमतः, व्यापारिक तनावों का त्वरित और व्यवस्थित समाधान, और/या सुलभ ब्रेक्जिट आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और

चार्ट I.11: आधारभूत मुद्रास्फीति पथ पर जोखिम परिदृश्य का प्रभाव

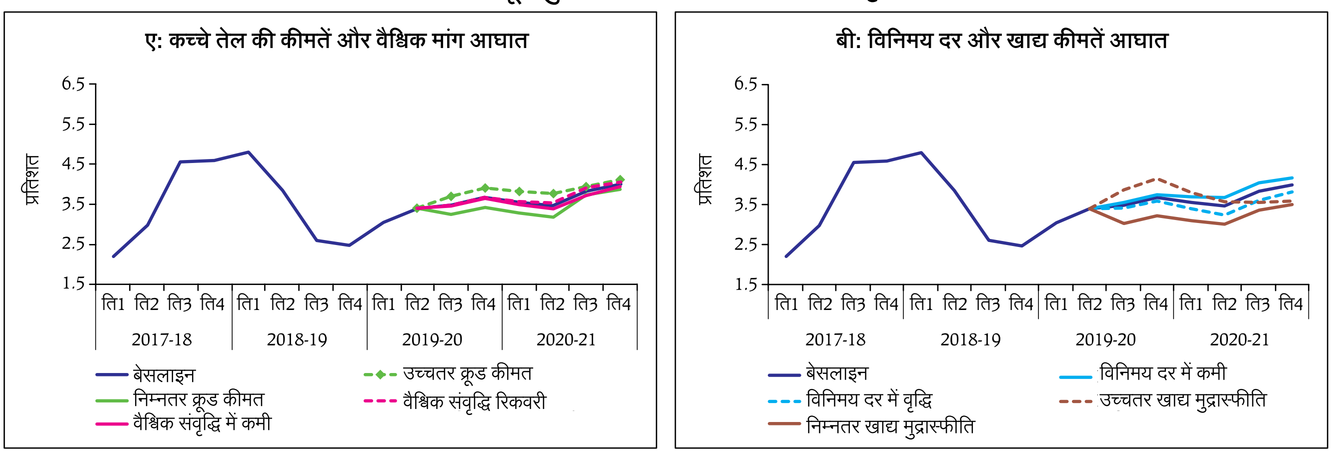

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बॉक्स I.1 क्या प्रतिफल लाभांतर से आउटपुट वृद्धि का पूर्वानुमान लग जाता है?

10 वर्ष और 3 माह यूएस खजाना प्रतिभूतियों के प्रतिफल के बीच का अंतराल – जो सावधि लाभांतर (टर्म स्प्रैड) के लिए करीब से देखा जाने वाला मीट्रिक है- 2007 के बाद पहली बार पलट गया है और जून 2019 में 13 आधार अंकों (बीपीएस) के साथ ऋणात्मक हो गया है। यह लाभांतर अगस्त में 35 बीपीएस के साथ लगातार तीन महीनों से ऋणात्मक बना हुआ है (एक वर्ष पूर्व 83 बीपीएस से)।

सन 1950 के बाद से यूएस की मंदियों से ठीक पहले प्रतिफल वक्र में महत्वपूर्ण व्युत्क्रम हुए। सितंबर 1966 में एकमात्र अवसर था जब 3 माह वाले खजाना प्रतिभूति के प्रतिफल अनुवर्ती मंदी के आए बिना 10 वर्षीय खजाना प्रतिफल से अधिक थे। इसके अलावा, प्रतिफल वर्क के ये व्युत्क्रम आनेवाले 18-24 महीनों में होनेवाली मंदी के साथ होते हैं (चार्ट I.1.ए)

प्रतिफल लाभांतर में व्युत्क्रम/कमी अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी हुई है। जर्मनी, यूके, जापान, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में प्रतिफलों में गिरावट आई है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को प्रदर्शित कर रही है। जर्मनी के मामले में 10 वर्षीय बांड प्रतिफल का लाभांतर 3 माह वाले बांड पर प्रतिफल की तुलना में अगस्त 2019 में 24 बीपीएस गिर गया है जो 1 वर्ष पहले 61 बीपीएस था। जर्मनी ने 1966, 1973, 1980, 1991, 2001 और 2008 के आरंभ में मंदी का अनुभव किया था। सन 1966 की मंदी को छोड़कर सभी मंदियों में पूर्वगामी अल्पावधिक प्रतिफलों के सापेक्ष दीर्घावधिक खजाना प्रतिभूति प्रतिफलों में तेज गिरावट थी। सन 1970 में एकमात्र व्युत्क्रम हुआ था जिसके बाद मंदी नहीं आई थी (चार्ट I.1.बी)।

प्रत्याशा अवधारणा के अनुसार दीर्घावधिक ब्याज दरें वर्तमान और अपेक्षित भविष्य की अल्पावधिक ब्याज दरों व टर्म प्रीमियम के योग के बराबर होती हैं। टर्म प्रीमियम से ज्ञात होता है कि प्रतिफल वर्क आमतौर पर क्यों उर्ध्वाकार होता है अर्थात दीर्घावधिक प्रतिभूतियों का प्रतिफल आमतौर पर अल्पावधिक प्रतिभूतियों से अधिक रहता है। जब जनता अल्पावधिक ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद करती है तो प्रतिफल वर्क सपाट या पलट/नीचे गिर जाता है। उक्त स्थिति में निवेशक दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के मूल्यों का बढा़ देते हैं जिससे अल्पावधिक प्रतिभूतियों के प्रतिफलों की तुलना में दीर्घावधिक प्रतिभूतियों का प्रतिफल कम हो जाता है। हालांकि, सावधि लाभांतर और आर्थिक गतिविधि के बीच सैद्धांतिक संबंध पर कोई एकराय नहीं है। बहुत हद तक, आर्थिक गतिविधि का पूर्वानुमान लगाने के लिए लाभांतर की उपयोगिता "सिद्धांत की खोज में एक शैलीगत तथ्य" बनी हुई है (बेनाटी और गुडहार्ट, 2008)। इसके अलावा, आउटपुट वृद्धि के लिए सावधि लाभांतर की पूर्वानुमानक शक्ति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों और उपयोग किए गए प्रतिक्रिया फलन पर निर्भर करती है। मौद्रिक नीति को संकुचित करने के मामलों में, उदाहरण के लिए, दीर्घावधिक दरों की तुलना में अल्पावधिक दरों के बढ़ने की संभावना ज्यादा है और जिस कारण प्रतिफल वर्क सपाट रहता है या संभवत: पलट सकता है (फेरोली, 2004)। यह भी तर्क दिया जाता है कि संभावनाओं की तुलना में आउटपुट में हुए विचलन के बारे में मौद्रिक प्राधिकरण जितना संवेदनशील होते हैं वे सावधि लाभांतर आउटपुट वृद्धि का उतना बेहतर पूर्वानुमान लगाते हैं। यदि मौद्रिक नीति विशेष तौर पर मुद्रास्फीति पर ध्यान देती है तो लाभांतर कम सटीकता से

चार्ट I.1.1: खजाना प्रतिफल लाभांतर और मंदी

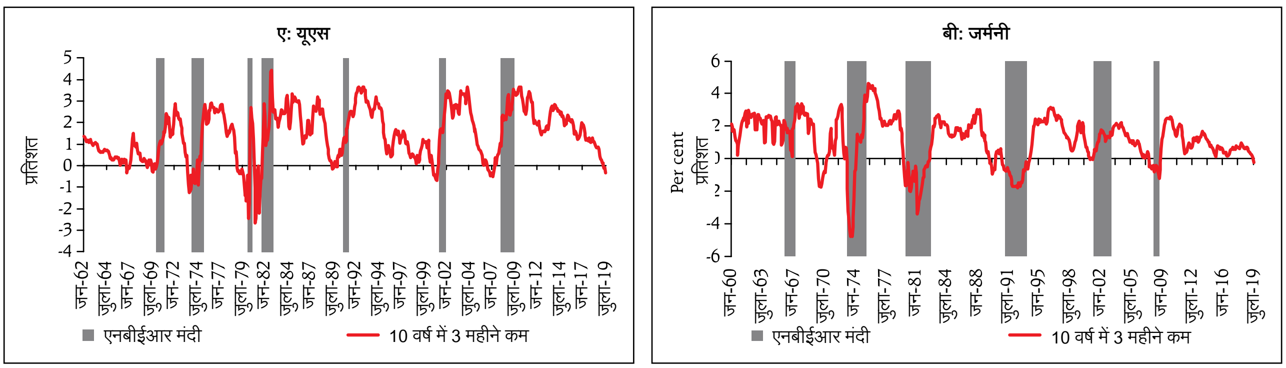

नोट: सावधि लाभांतर (टर्म स्प्रैड) की गणना 10 वर्षीय और 3 महीने वाली खजाना प्रतिभूतियों की निरंतर परिपक्वता के प्रतिफलों के अंतर के रूप में की जाती है। अंतिम आंकड़ा बिंदु अगस्त 2019 का है। छायांकित क्षेत्र नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनामिक रिसर्च (एनबीईआर) द्वारा पहचानी गई मंदी की अवधि को दर्शाता है। जर्मनी के लिए छायांकित क्षेत्र आर्थिक चक्र अनुसंधान संस्थान (ईसीआरआई) द्वारा पहचानी गई मंदी की अवधि को दर्शाता है।

स्रोत: फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेंट लुई; ईसीआरआई और ब्लुमबर्ग।

सारणी I.1: जीडीपी संवृद्धि और प्रतिफल लाभांतरों का सहसंबंध

	पश्च प्रतिफल लाभांतर							फ्यूचर प्रतिफल लाभांतर					
देश	t-6	t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6
यूएस	0.136 (0.042)	0.192 (0.004)	0.218 (0.001)	0.213 (0.001)	0.229 (0.001)	0.154 (0.021)	0.041 (0.545)	-0.073 (0.278)	-0.166 (0.013)	-0.204 (0.002)	-0.231 (0.001)	-0.341 (0.000)	-0.360 (0.000)
जर्मनी	0.268 (0.037)	0.272 (0.034)	0.307 (0.016)	0.291 (0.023)	0.322 (0.011)	0.119 (0.361)	-0.026 (0.843)	-0.207 (0.110)	-0.372 (0.003)	-0.385 (0.002)	-0.400 (0.001)	-0.418 (0.001)	-0.311 (0.015)

नोट: 1. 10 वर्षीय और 3 माह वाले खजाना प्रतिभूतियों के बीच प्रतिफल अंतराल को मासिक रिकार्डो के तिमाही औसत के रूप में मापा गया है।
2. यूएस और जर्मनी के आंकड़े क्रमश: 1962 की दूसरी तिमाही – 2019 की दूसरी तिमाही और 2002 की चौथी तिमाही-2019 की दूसरी तिमाही की अवधि से संबंधित हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए अंक मान - p को प्रदर्शित करते हैं।

स्रोत: ब्लुमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान

पूर्वानुमान लगाता है। कंजम्पशन स्मूदनिंग मॉडल प्रतिफल वर्क के ढलान और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों के बीच यह मानकर संबंध का पता लगाता है कि आय बढ़ने की अवधि के दौरान लोग उच्च उपभोग के बजाय स्थिर उपभोग को प्राथमिकता देते हैं व आय में गिरावट के दौरान कम उपभोग को प्राथमिकता देते हैं (हार्वे, 1988)। यदि वे भविष्य में मंदी की उम्मीद करते हैं, तो उपभोक्ता आय बढ़ाने के लिए अल्पावधिक वित्तीय लिखतों को बेच देते हैं और छूट पर बॉन्ड खरीदते हैं, परिणामस्वरूप प्रतिफल वक्र सपाट होता है या पलट जाता है।

अनुभवसिद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि प्रतिफल लाभांतर विभिन्न देशों और समय अनुसार काफी भिन्नता के साथ चार से छह तिमाहियों की अवधि पर आउटपुट वृद्धि का पूर्वानुमान लगाता है। हालांकि, 1980 के मध्य से सावधि लाभांतर की आउटपुट वृद्धि के पूर्वानुमान क्षमता में गिरावट आई है (व्हीलॉक और वोहार, 2009)। दूसरी ओर प्राबिट मॉडल बताता है कि मंदी की प्रत्याशा का पूर्वानुमान लगाते समय प्रतिफल लाभांतर का प्रदर्शन अन्य समष्टि आर्थिक व वित्तीय चरांकों के मुकाबले काफी बेहतर है (एस्ट्रेला और हार्डोवेलिस, 1991; एस्ट्रेला और मिस्किन, 1998)।

प्रतिफल लाभांतर और वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के बीच समकालीन सहसंबंध यूएस और जर्मनी दोनों के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाए गए हैं (सारणी I.1)। हालांकि, जीडीपी संवृद्धि और प्रतिफल लाभांतर के बीच एक से छह तिमाहियों का सहसंबंध दोनों देशों के लिए सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है,सिवाय जर्मनी t-1 की अवधि में जो अप्रभावी है। इन सहसंबंधों से ज्ञात होता है कि प्रतिफल वर्क में तीव्र ढ़लान होगी तो 3 माह वाली खजाना प्रतिभूतियों के मुकाबले 10 वर्षीय खजाना प्रतिभूतियों पर प्रतिफल भी उच्च होगा और भविष्य में जीडीपी संवृद्धि दर भी उच्च रहेगी। इसी तरह छह तिमाहियों तक जीडीपी संवृद्धि और फ्यूचर प्रतिफल लाभांतर के बीच संहसंबंध दोनों देशों के लिए नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है, t+1 अवधि को छोड़कर जहां यह दोनों देशों के लिए महत्वहीन है। जीडीपी संवृद्धि और प्रतिफल लाभांतर की मुख्य अवधि के बीच नकारात्मक संहसंबंध से ज्ञात होता है कि t अवधि में जीडीपी संवृद्धि उच्च रहती है तो आगामी तिमाहियों में प्रतिफल वक्र में कम ढलान होगी (साहू और गुप्ता, 2019)।

सारांशत: विशेष रूप से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिफल अंतराल, आउटपुट वृद्धि और मंदी का पूर्वानुमान लगाने में उपयोगी है। यद्यपि गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति के वर्तमान परिवेश में इसका संकेत प्रदान करने का महत्व कुछ हद तक धुंधला पड़ गया है। ऋणात्मक प्रतिफल अंतराल का वर्तमान चरण तदनुसार सतर्क करता है कि नीति निर्माता सचेत बने रहें।

संदर्भ:

बेनाटी, एल. और सी. गुडहार्ट (2008), “इन्वेस्टिगेटिंग टाइम-वेरिएशन इन द मार्जिनल प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द यील्ड स्प्रैड” *जर्नल ऑफ़ इकॉनामिक डायनामिक्स ऐन्ड कंट्रोल*, 32 (4), पीपी. 1236-72.

एस्ट्रेला, ए. और जी. ए. हार्डोवेलिस (1991), “द टर्म स्ट्रक्चर एज अ प्रेडिक्टर ऑफ़ रियल इकॉनामिक एक्टिविटी”, *जर्नल ऑफ़ फ़ाइनेन्स*, 46 (2), पीपी. 555-76.

एस्ट्रेला, ए. और एफ.एस. मिशकिन (1998), “प्रीडिक्टिंग यूएस रेसेशंस: फाइनेन्शियल वेरिएबल्स एज लीडिंग इंडिकेटर्स”,

रिव्यू ऑफ इकॉनामिक्स ऐन्ड स्टैटिस्टिक्स, 80 (1), पीपी. 45-61.

फेरोली, एम. (2004), ''मोनेटरी पॉलिसी एंड द इन्फर्मेशन कॉन्टेंट ऑफ द यील्ड स्प्रैड''. *टापिक्स इन मैक्रोइकॉनामिक्स, 4*(1), आर्टिकल 13

हार्वे, सी.आर. (1988), ''द रीयल टर्म स्ट्रक्चर एंड कंजम्पशन ग्रोथ,'' *जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकॉनामिक्स, 22*(2), पीपी. 305-33.

साहू एस एंड बी. गुप्ता (2019) "इज यिल्ड स्प्रेड प्रेडिक्ट आउटपुट ग्रोथ ?" भारतीय रिजर्व बैंक (मिमेयो)

व्हीकॉक, डी. सी. और एम. ई. वोहर (2009), "कैन दि टर्म स्प्रेड प्रेडिक्ट आउटपुट ग्रोथ एंड रिशेसंस? ए सर्वे ऑफ द लिटरेचर", फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस रिव्यू, सितंबर / अक्टूबर।

वैश्विक व्यापार और मांग को बल दे सकता है। यदि वैश्विक संवृद्धि आश्चर्यजनक रूप से 50 बीपीएस ऊपर बढ़ जाती है तो घरेलू संवृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 20 बीपीएस और 10 बीपीएस और ऊपर चढ़ सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों के भारतीय बास्केट ने 2019-20 के प्रथम पूर्वार्ध में बहुत उतार-चढ़ाव दर्शाये हैं और परिदृश्य अभी अनिश्चित ही बना हुआ है। भू-राजनीतिक हलचल से बेसलाइन अनुमान के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल वृद्धि मानते हुए, बेसलाइन से लगभग 30 बीपीएस ऊपर चढ़ सकती है और संवृद्धि बेसलाइन से लगभग 20 बीपीएस नीचे गिर सकती है। विलोमतः, यदि वैश्विक संवृद्धि, अनुमान से अधिक कमजोर पड़ जाती है तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है। यदि कच्चे तेल के भारतीय बास्केट में 53 अमेरिकी डॉलर की गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति लगभग 30 बीपीएस नरम होगी और संवृद्धि 20 बीपीएस बढ़ सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

(iii) विनिमय दर

अगस्त 2019 में यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में गिरावट हुई, जो वैश्विक हलचल को दर्शाता है। भविष्य में, बढ़ता हुआ व्यापारिक संरक्षणवाद और घटता हुआ वैश्विक कारोबार और वैश्विक उत्पादन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ा सकता है और मुद्रा पर और अधिक अधोगामी दबाव डाल सकता है। यदि आईएनआर बेसलाइन से 5 प्रतिशत गिरेगी तो मुद्रास्फीति 20 बीपीएस तेज होगी और निवल निर्यात और जीडीपी 15 बीपीएस तक बढ़ेगी। इसके उलट, उत्पादन और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए तमाम उपाय, एफ़डीआई व्यवस्था में नीतिगत सुधार और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में केंद्रीय बैंकों द्वारा उम्मीद से अधिक मौद्रिक नीति समायोजन, और अधिक पूंजी-अंतःप्रवाह आकर्षित कर सकता है और आईएनआर के मूल्य में तेजी ला सकता है। आईएनआर में 5 प्रतिशत की तेजी, बेसलाइन की तुलना में मुद्रास्फीति को लगभग 20 बीपीएस और जीडीपी संवृद्धि को लगभग 15 बीपीएस मंद कर सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

चार्ट III.12: आधारभूत संवृद्धि पथ पर जोखिम परिदृश्य का प्रभाव

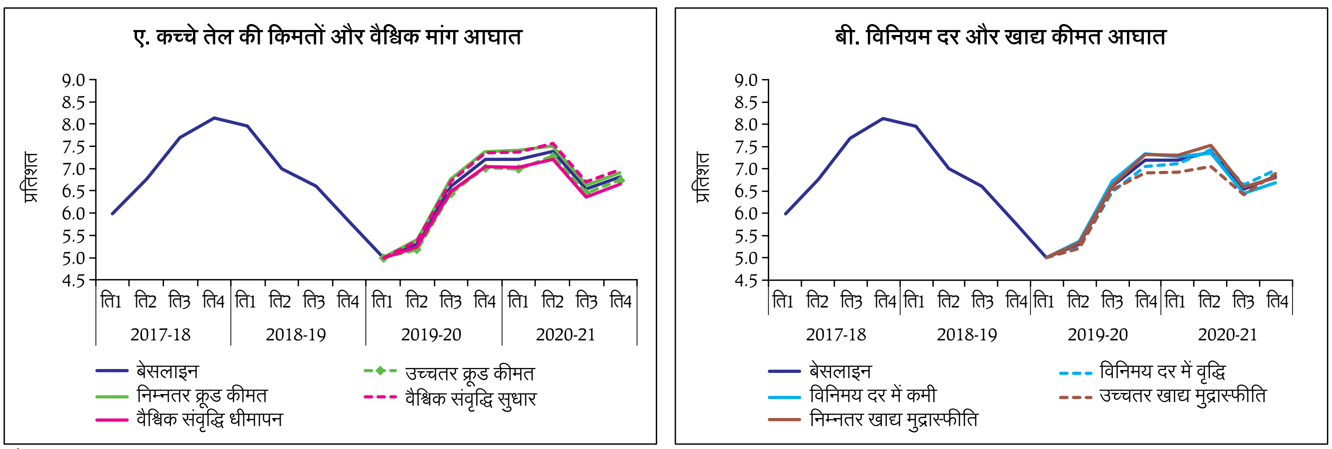

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान

(iv) खाद्य कीमतें

खाद्य कीमतें अप्रैल-अगस्त में सब्जियों और दलहनों की कीमतों के दबाव के कारण चढ़ गई थीं। तथापि, समग्र खाद्य स्फीति नरम ही बनी हुई है। बेसलाइन पथ यह मानता है कि खाद्य स्फीति वर्तमान स्तरों पर स्थिर रहेंगी और यह अन्य बातों के साथ-साथ, सब्जियों के दामों में मौसमी तेजी और दलहन के दामों में, मांग-आपूर्ति संतुलन के स्थिर होने से, आई आंशिक तेजी को दर्शाती है। यहाँ बेसलाइन को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी- दोनों जोखिम हैं। जुलाई- सितंबर में मॉनसून की जोरदार वापसी और इसके फलस्वरूप खरीफ बुआई में सुधार, बड़े बफर स्टॉक, और जल-भंडारों के बेहतर स्तरों के कारण रबी फसलों की बेहतर संभावना, खाद्य स्फीति को उम्मीद से कहीं अधिक नरम कर सकती है और परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन से 50 बीपीएस तक नीचे गिर सकती है। तथापि, कुछ इलाकों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खाद्य स्फीति पर ऊर्ध्वगामी दबाव पड़ सकता है और तदनुसार, हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 50 बीपीएस ऊपर चढ़ सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

I.5 निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 की शेष अवधि और 2020-21 के शुरुआती महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य से नीचे बने रहने का पूर्वानुमान है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय बाज़ारों में, साथ ही, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों और खराब हो जाने वाली खाद्य सामग्रियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, बेसलाइन मुद्रास्फीति पथ के लिए जोखिम पेश करते हैं। दूसरी ओर, पण्यों की वैश्विक कीमतों में नरमी की संभावना और बड़े बफर स्टॉक, हेडलाइन मुद्रास्फीति को बेसलाइन से नीचे बनाए रख सकते हैं।

सकारात्मक आधारभूत प्रभावों और पिछली मौद्रिक नीति पर की गई कार्रवाइयों के संचरण के कारण, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में 2019-20 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है। संवृद्धि को तेज करने के लिए अगस्त-सितंबर में सरकार द्वारा घोषित उपाय– यथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु निधियों को जारी करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, एफ़डीआई व्यवस्था में सुधार, निर्यात एवं भू-सम्पदा के लिए उढ़ाये गए कदम, कार्पोरेट आयकर दर में कटौती दबावग्रस्त आस्तियों के तीव्रतर समाधान संवृद्धि को बेसलाइन पथ से ऊपर उठा सकते हैं। यूएस-चीन व्यापारिक तनावों के इर्दगिर्द बनी हुई अनिश्चितताओं में वृद्धि, कठिन ब्रेक्जिट और भू-राजनीतिक तनाव बेसलाइन संवृद्धि पथ के लिए प्रमुख अधोगामी जोखिम हैं।

II. कीमतें और लागतें

खाद्य मुद्रास्फीति, विशेषकर सब्जियों तथा प्रोटीन युक्त पदार्थों, में तेजी के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में मार्च-अगस्त 2019 के कारण बढ़ोतरी दर्ज हुई। अप्रैल के बाद ईंधन समूह की मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से नरमी हुई और जुलाई तथा अगस्त 2019 में यह अपस्फीति में चली गई। सोने की कीमत में तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में मार्च से व्यापक रूप से नरमी रही है। ग्रामीण मजदूरी, कृषिगत तथा गैर-कृषिगत दोनों के लिए, असमायोजित वृद्धि में गिरावट बनी रही। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी लागत वृद्धि के उतार-चढ़ाव में भिन्नता रही - विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसमें वृद्धि थी और सेवा क्षेत्र के लिए यह एक दायरे में बनी रही। कृषि निविष्टियों (इनपुट) तथा औद्योगिक कच्चे माल में 2019-20 में अब तक गिरावट रही है।

पिछले छह माह अर्थात मार्च-अगस्त 2019 में, इस अवधि[1] के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे औसतन 3.1 प्रतिशत रही। इसके प्रमुख वाहक खाद्य कीमतें थीं जो मार्च 2019 में अपस्फीति से बाहर निकली और गर्मी के मौसम की सामान्य तेजी से आगामी महीनों में धीरे-धीरे बढ़ती रही। इसके विपरीत, ईंधन और बिजली संबंधी वस्तुओं की कीमतों में नरमी बनी रही और जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान अपस्फीति में चली गई। मार्च-जून 2019 के बीच खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में लगभग 100 आधार अंकों की गिरावट हुई और जून 2019 में 23 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई (चार्ट II.1)।

भारिबैं. अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) भारिबैं. को यह निदेश देता है कि वह अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक परिणामों में विचलन की पहचान करे, यदि कोई हो, और उसके अंतर्निहित कारणों की व्याख्या करे। अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) ने 2019-20 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.0 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था। वास्तविक मुद्रास्फीति निष्कर्ष ने भी कमोवेश इन्हीं अनुमानों का अनुसरण किया है (चार्ट II.2)।

जहां खाद्य कीमतें प्रत्याशा के अनुरूप अपस्फीति से बाहर निकलीं, सब्जियों की कीमतों में इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन तेजी हाल के समय में देखी गई तेजी से कहीं अधिक थी। दलहन की मुद्रास्फीति मई 2019 में दो वर्ष और छह महीनों की अपस्फीति से बाहर निकली। परिणामस्वरूप, मार्च और अगस्त 2019 के मध्य खाद्य मुद्रास्फीति में अनुमान से अधिक 230 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति प्रत्याशा से अधिक नरम हुई और इसने समायोजन किया। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित नरमी रही - 2019-20 (जो कि अप्रैल के एमपीआर के अनुमान का बेसलाइन था) के दौरान औसतन 67

चार्ट II.1: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष- दर -वर्ष)

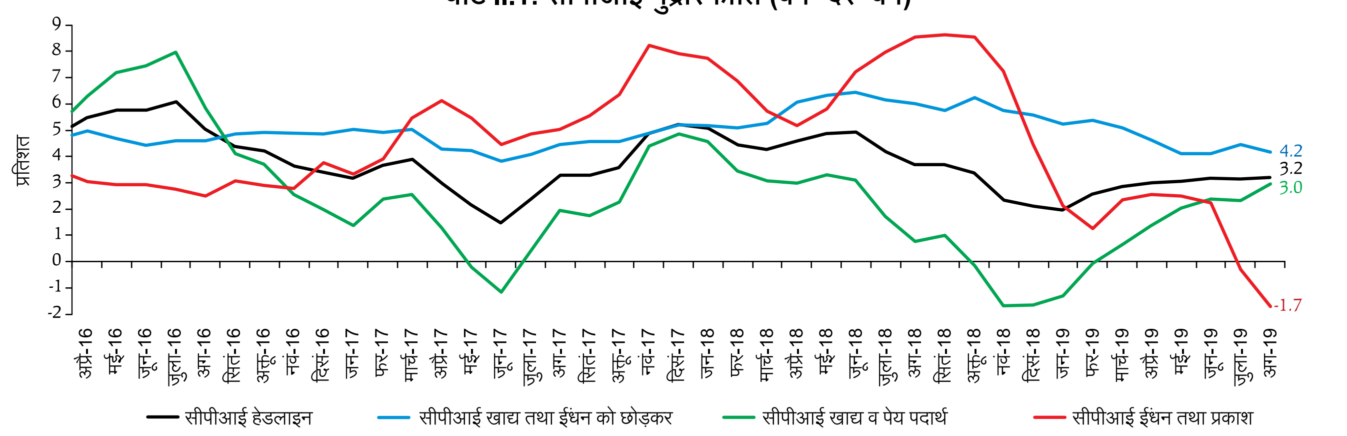

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[1] अखिल भारतीय संयुक्त सीपीआई (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तन के आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है।

चार्ट II 2: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष): वास्तविक बनाम पूर्वानुमान

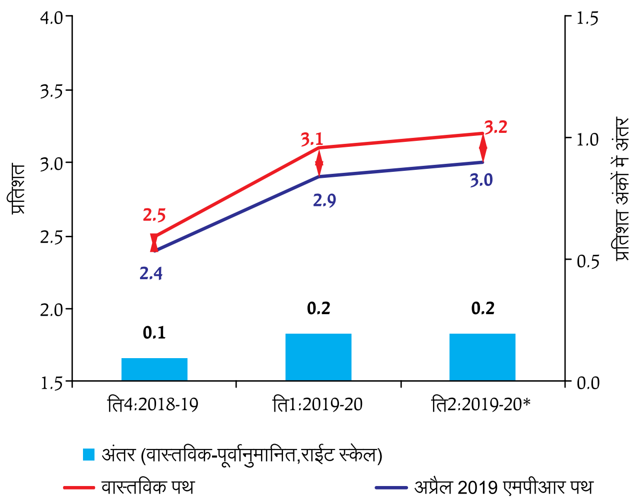

2019-20 की संपूर्ण दूसरी तिमाही के लिए पूर्वानुमान की तुलना में जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान के वास्तविक औसत मुद्रास्फीति

स्रोत : एनएसओ;और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से अगस्त में 60 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से कम। ईंधन समूह के भीतर ग्रामीण खपत की वस्तुएं जैसे जलावन तथा उपले और शहरी खपत जैसे तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) दोनों की कीमतों में अत्यधिक सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप, इस पूरा ईंधन समूह जुलाई में अपस्फीति में गया। कुल मिलाकर, इन भिन्न उतार-चढ़ावों की वजह से सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति का परिणाम मुद्रास्फीति अनुमानों को आंशिक रूप अर्थात 2019-20 की पहली तिमाही तथा 2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त) , प्रत्येक में 20 आधार अंक से पार कर गया (चार्ट II.2)।

II.1 उपभोक्ता मूल्य

वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) मुद्रास्फीति का विघटन यह दर्शाता है कि मार्च से जून 2019 के दौरान इसका उठता वक्रपथ कीमतों की चाल में निरंतर बढ़ोतरी से प्रेरित था (चार्ट II.3)। जुलाई में, अधिक अनुकूल आधार प्रभावों ने कीमत की ऊंची चाल को सामान्य करने में मदद की।[2]

चार्ट II.3: सीपीआई मुद्रास्फीति – गति तथा आधार प्रभाव

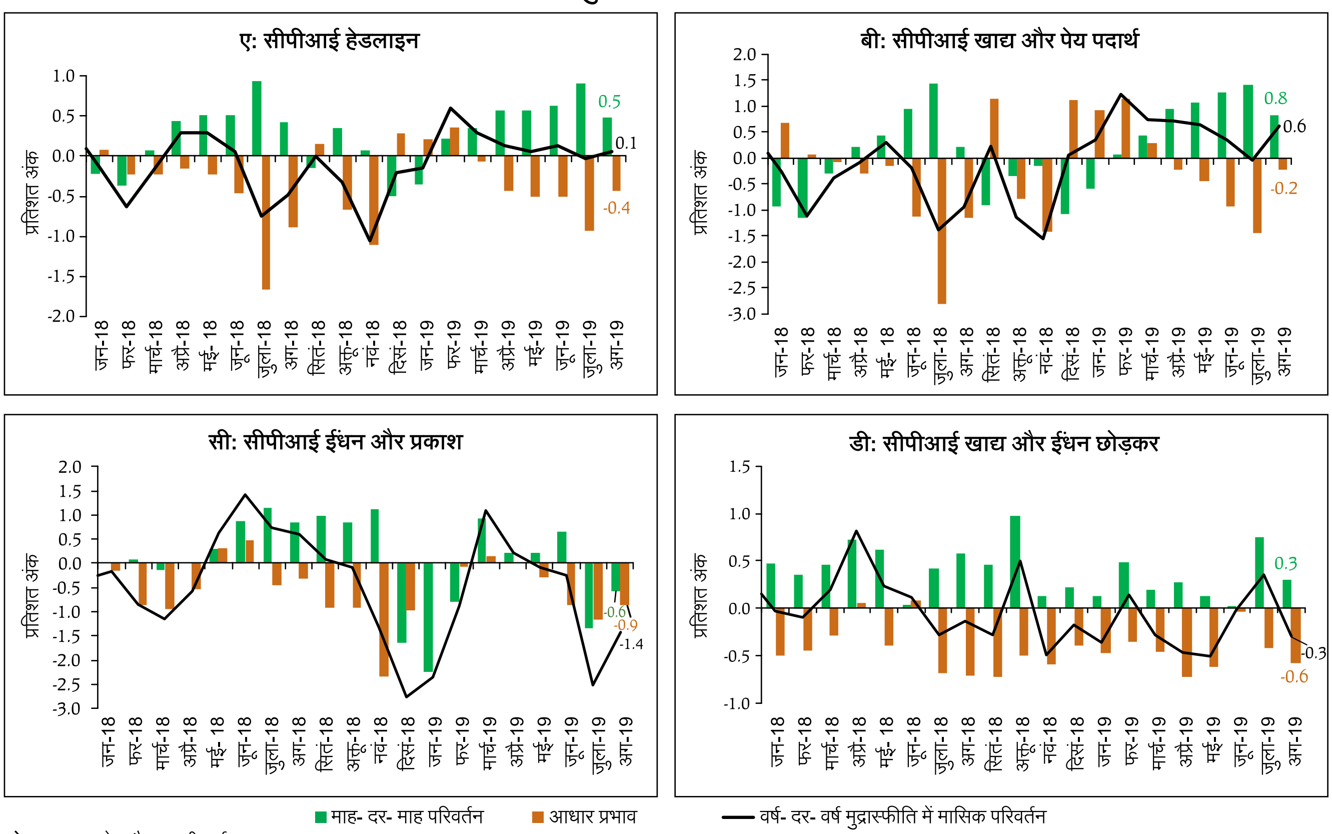

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[2] किसी भी दिए गए माह में मुद्रास्फीति (*अर्थात* सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन) पिछले माह की मुद्रास्फीति तथा मूल्य सूचकांक (गति) में वर्तमान माह-दर-माह परिवर्तन और 12 माह पहले (आधार प्रभाव) मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन के अंकगणितीय योग के बराबर होता है। एमपीआर, सितंबर 2014 का बॉक्स 1.1 देखें।

चार्ट II.4: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) (केरनेल घनत्व अनुमान)

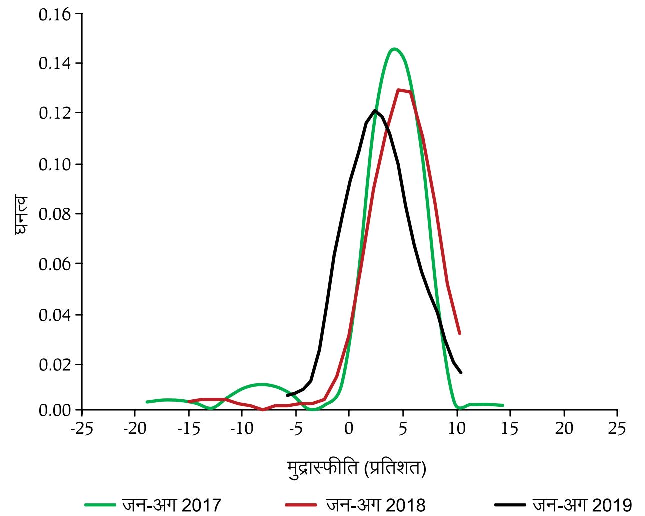

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5: सीपीआई डिफ्यूज़न सूचियाँ: (माह-दर-माह मौसमी समायोजित)

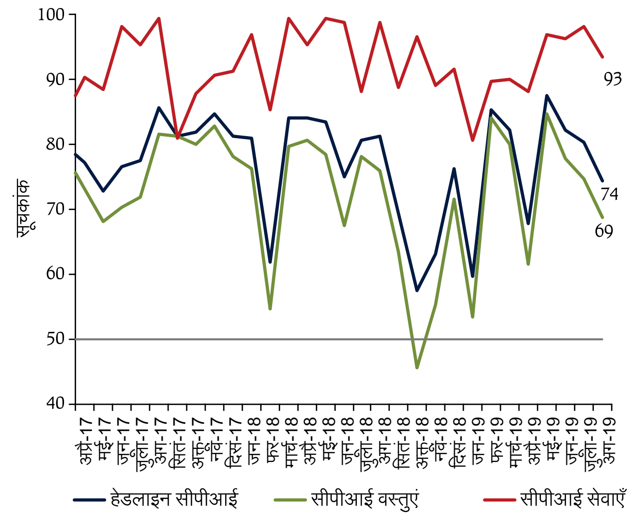

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हालांकि अगस्त में, कीमत की चाल कम आधार प्रभाव पर भारी रही और इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। 2019-20 की पहली छमाही में कीमतों की चाल में बढ़ोतरी खाद्य समूह, मुख्य रूप से सब्जियों, दलहन, मांस और मछली की कीमतों द्वारा संचालित थी। इसके विपरीत, ग्रामीण और शहरी ईंधन खपत की कीमतों में व्यापक आधार पर हुई गिरावट की वजह से जुलाई-अगस्त के दौरान ईंधन और बिजली की अंतर्निहित मुद्रास्फीति की चाल में भारी गिरावट रही। मार्च-अगस्त 2019 के दौरान खाद्य और ईंधन को छोड़कर वस्तुओं की कीमतों की चाल सामान्य रही और यह अनुकूल आधार प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित थी।

समूचे सीपीआई समूह की मुद्रास्फीति का संवितरण माध्यिका मुद्रास्फीति दरों में एक यथेष्ट गिरावट को दर्शाता है - 2018 में 4.8 प्रतिशत से 2019 में अब तक 2.1 प्रतिशत। इसके अलावा, खाद्य कीमतों की वजह से 2017 और 2018 में मुद्रास्फीति की ऋणात्मक ढलान वर्ष 2019 में नहीं थी जो यह दर्शाती है कि इस वर्ष मुद्रास्फीति की स्थिति समान्यतया मंद रहेगी (चार्ट II.4)। मौसमी समायोजित आधार पर सीपीआई मदों की कीमतों में बदलाव का प्रसार सूचकांक माह-दर-माह (एम-ओ-एम) वस्तुओं और सेवाओं दोनों ही श्रेणी में जून-अगस्त 2019 के दौरान संयमित रहा (चार्ट II.5)।[3]

II.2 मुद्रास्फीति के संचालक

मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक विघटन यह दर्शाता है कि 2019-20 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति धनात्मक आपूर्ति आघात से प्रभावित थी जिसने हल्की घरेलू मांग के संयोजन से हेडलाइन मुद्रास्फीति को नीचे और स्थिर रखा (चार्ट II.6ए)।[4]

समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति का वस्तु और सेवा घटकों में ब्योरा यह बताता है कि नाशवान वस्तुएं (7 दिनों की वापसी वाले गैर-टिकाऊ वस्तुएं) जैसे सब्जी और फल का अप्रैल-अगस्त के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में सबसे अधिक योगदान था (चार्ट II.6बी)। चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी तथा बिजली की कीमतों में अपस्फीति के कारण कम नाशवान वस्तुओं (30 दिनों की वापसी वाले गैर-टिकाऊ वस्तुएं) का सामान्य योगदान था। प्राथमिक रूप से सोने की कीमत में

[3] सीपीआई प्रसार सूचकांक कीमत में आए परिवर्तनों का एक मापक है, जो सीपीआई बास्केट में मदों को पिछले माह के दौरान उनकी कीमत बढ़ने, स्थिर रहने या गिरने के अनुसार श्रेणीबद्ध रखता है। प्रसार सूचकांक की 50 से ऊपर की रीडिंग कीमतों में बढ़ोतरी के सामान्यीकरण को इंगित करती है और 50 से नीचे की रीडिंग व्यापक-आधारित अपस्फीति को दर्शाती है।

[4] ऐतिहासिक विघटन को निम्नलिखित चरों (जो वेक्टर Y_t के रूप में दिए हैं) जैसे कि - कच्चे तेल के कीमतों की वार्षिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, उत्पादन अंतर, ग्रामीण मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर तथा नीतिगत रेपो दर के साथ वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) के आधार पर नमूना अवधि के दौरान मुद्रास्फीति में हुए उतार-चढ़ाव के प्रति प्रत्येक आघात के योगदान की माप करने की लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीएआर को संक्षेप रूप में $Y_t = c + A\,Y_{t-1} + e_t$ लिखा जा सकता है; जहां e_t वेक्टर आघातों [तेल कीमत आघात, आपूर्ति आघात (मुद्रास्फीति आघात), उत्पादन अंतर आघात, मजदूरी आघात तथा नीतिगत आघात] के रूप में दर्शाया गया है। वोल्ड विघटन Y_t के उपयोग को निर्धारकीय प्रवृत्ति के प्रयोजन तथा सभी आघातों के योग e_t के रूप में दर्शाया जा सकता है। इस निरूपण से विभिन्न आघातों से योगदानों के जोड़ के रूप में निर्धारकीय प्रवृत्ति से मुद्रास्फीति के विचलन को विघटित किया जा सकता है।

चार्ट II.6: मुद्रास्फीति के संचालक

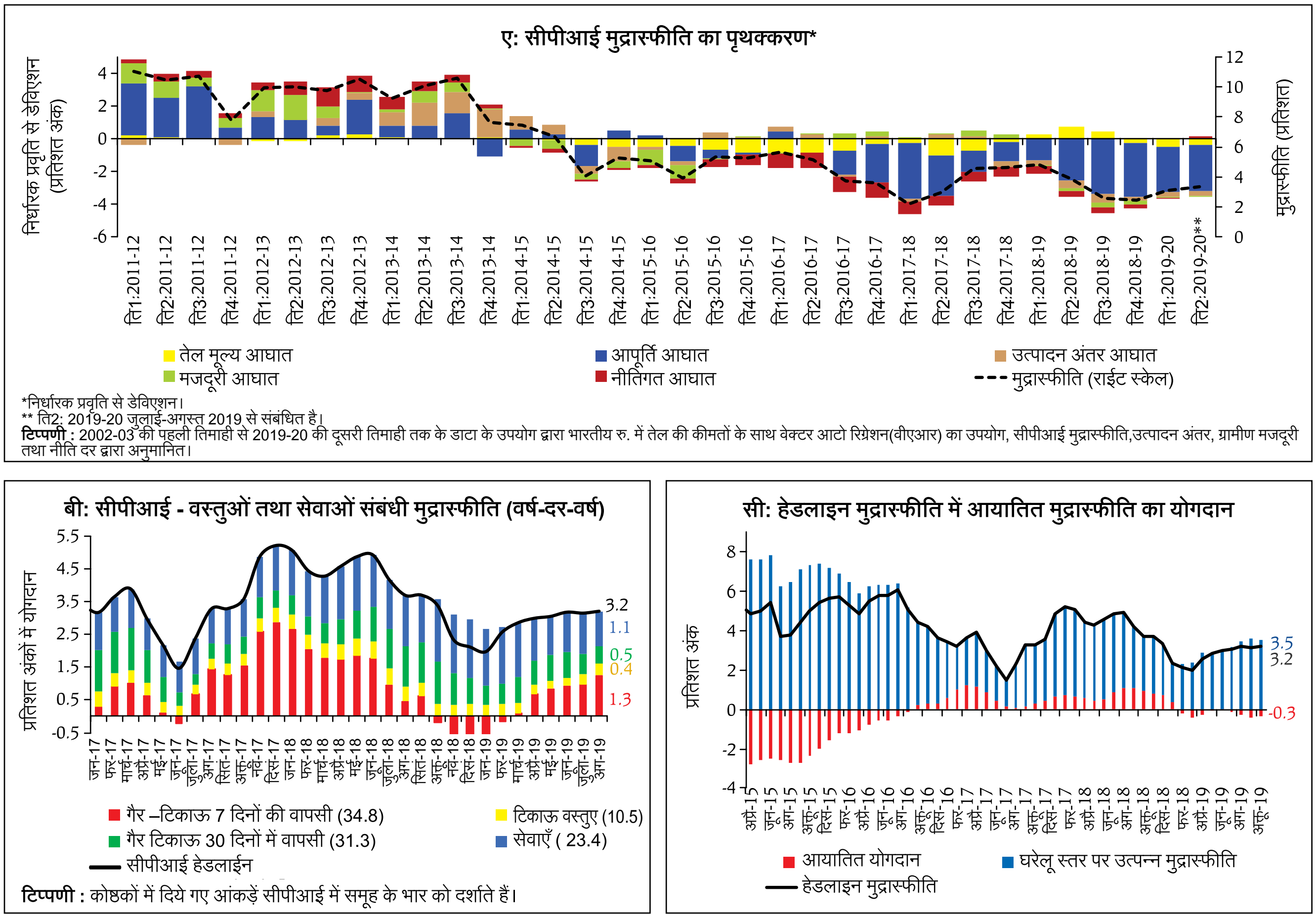

*निर्धारक प्रवृति से डेविएशन।
** ति2: 2019-20 जुलाई-अगस्त 2019 से संबंधित है।
टिप्पणी : 2002-03 की पहली तिमाही से 2019-20 की दूसरी तिमाही तक के डाटा के उपयोग द्वारा भारतीय रु. में तेल की कीमतों के साथ वेक्टर आटो रिग्रेशन(वीएआर) का उपयोग, सीपीआई मुद्रास्फीति,उत्पादन अंतर, ग्रामीण मजदूरी तथा नीति दर द्वारा अनुमानित।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में समूह के भार को दर्शाते हैं।

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तेज बढ़ोतरी और कुछ कम हद तक मोटर वाहन की कीमत में बढ़ोतरी के कारण जून-अगस्त 2019 के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में टिकाऊ वस्तुओं का योगदान बढ़ा। आयातित वस्तुओं (पेट्रोल; डीजल; एलपीजी; किरोसिन; इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं; सोना; चाँदी; रसायन और रासायनिक उत्पाद; धातु और धातु उत्पाद; तथा परिष्कृत वनस्पति तेल) ने मिलकर हाल की अवधि में समग्र मुद्रास्फीति में ऋणात्मक योगदान किया है (चार्ट II.6सी)। सेवाओं का समग्र मुद्रास्फीति में सामान्य योगदान रहा। यद्यपि, सेवा (समग्र सीपीआई में 23 प्रतिशत का भार) ने समग्र मुद्रास्फीति में लगभग एक तिहाई का योगदान किया (चार्ट II.6बी)।

सीपीआई खाद्य समूह

भारित अंशदान की बात करें तो अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य और पेय समूह (भार: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) का योगदान 32.9 प्रतिशत रहा जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 25.0 प्रतिशत था। अक्तूबर 2018-फरवरी 2019 के दौरान लगातार पाँच महीनों तक ऋणात्मक दायरे में रहने के बाद खाद्य समूह की मुद्रास्फीति मार्च 2019 के आरंभ से धनात्मक हुई और इसके बाद सब्जियों, फलों तथा प्रोटीन-युक्त वस्तुओं जैसे दाल, मांस, मछली और दूध की कीमतों के प्रभाव द्वारा इसमें नियमित रूप से बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7ए)।

खाद्य और पेय समूह के भीतर, वित्तीय वर्ष के दौरान सब्जियों की कीमतों में मजबूती बनी रही पर यह ऐतिहासिक ग्रीष्मकालीन कीमत बढ़ोतरी के निकट थी। फलों, दलहन, मांस और मछली की स्थिति में कीमतें वास्तव में ऐतिहासिक औसत (2011-2018) से अधिक रहीं। अन्य उप-समूह जैसे खाद्य समूह में अतीत के मुक़ाबले काफी कम रही (चार्ट II.7बी)।

चार्ट II.7: सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति

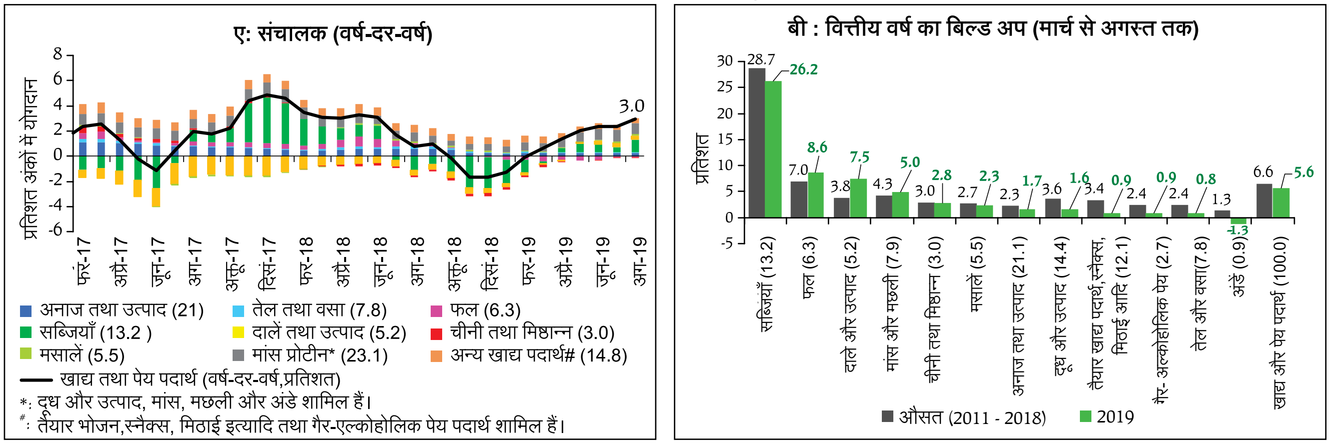

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई खाद्य पदार्थ और पेय में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत : एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चावल की कीमतों में अपस्फीति के साथ अनाज की मुद्रास्फीति (सीपीआई में 9.7 प्रतिशत तथा खाद्य और पेय समूह में 21.1 प्रतिशत का भार) अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान सामान्य रही और यह भरपूर उत्पादन तथा पर्याप्त भंडार को दर्शाता है। खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2018-19 में चावल का उत्पादन 1164 लाख टन था, यह 2017-18 में 1128 लाख टन उत्पादन से अधिक था जो कि हाल-फिलहाल तक का एक सार्वकालिक रिकॉर्ड है। भारत की पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत सरकार द्वारा चावल निर्यात को दिया जाने वाला 5 प्रतिशत का प्रोत्साहन 01 अप्रैल 2019 से वापस ले लिए जाने की वजह से अप्रैल-जुलाई 2019 के दौरान चावल के निर्यात में गिरावट रही और इसके फलस्वरूप घरेलू उपलब्धता अधिक रही। मई 2018 के 30 प्रतिशत से अप्रैल 2019 में गेहूं के आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर 40 प्रतिशत किए जाने से आयात में गिरावट से गेहूं की मुद्रास्फीति, यद्यपि, अप्रैल-अगस्त 2019 (2018-19 में 3.4 प्रतिशत) के दौरान औसत 6.8 प्रतिशत के साथ ऊपर बनी रही।

जहां तक सब्जियों (सीपीआई में जिसका 6.0 प्रतिशत तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में जिसका 13.2 प्रतिशत भार है) की बात है, प्याज, टमाटर एवं आलू (कुल सीपीआई-सब्जियों में जिनकी हिस्सेदारी 36.5 प्रतिशत है) की कीमतों में सुधार के कारण सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.8 ए)।

अप्रैल 2019 से ही आलू की कीमतों में दबाव बढ़ गया। पहले, फरवरी तथा मार्च के दौरान पश्चिम बंगाल में असमय बारिश ने कटाई योग्य फसल को प्रभावित किया। दूसरा, गर्मी के महीनों में तापमान में अचानक वृद्धि तथा उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों के कई भागों में अचानक आए आंधी-तूफान ने मार्गस्थ उत्पादों को बर्बाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंडी में आवक कम हो गई। इस कठिन अवस्था के बावजूद, आलू की कीमतें अनुकूल आधारभूत प्रभावों के कारण अप्रैल 2019 की शुरुआत में अपस्फीति में बदल गईं। प्याज की कीमतों में दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के दौरान कमी आई थी, परंतु अप्रैल माह से इनमें सुधार हुआ और ये जून-अगस्त के दौरान तेजी से बढ़ीं। मुख्यतः नासिक जैसे बड़े प्याज उत्पादक जिला में सूखा जैसे हालात के कारण महाराष्ट्र में रबी फसल 'प्याज' की पैदावार वाले रकबे में आई कमी जिससे मंडी में आवक कम हुई। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) द्वारा की जा रही खरीद संबंधी गतिविधियों के कारण भी प्याज की कीमतों को समर्थन मिला। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्याज आपूर्तिकर्ता राज्यों में जुलाई-अगस्त के दौरान अत्यधिक बारिश के साथ-साथ बाढ़ के कारण आपूर्ति में कमी आई। टमाटर की कीमतें मार्च 2019 से बढ़ने लगीं एवं इससे संबंधित मुद्रास्फीति नवंबर 2018 के (-) 52.2 प्रतिशत की तुलना में मई 2019 में तेजी से बढ़कर 70.1 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में देरी से की गई कटाई के साथ-साथ कर्नाटक में फफूंद से बर्बाद हुई फसल ने कीमतों में शुरुआती बढ़ोतरी को अंजाम दिया तथा मुख्य आपूर्तिकर्ता राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश एवं बाढ़ जैसे हालात के कारण पैदा हुई आपूर्ति बाधाओं द्वारा इसमें और बढ़ोतरी की गई। तथापि, टमाटर के मामले में मुद्रास्फीति मुख्यतः अनुकूल आधारभूत प्रभावों के कारण जुलाई में नरम होकर 28.4 प्रतिशत हो गई। यह प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण अगस्त में 39.4 प्रतिशत बढ़ गई।

चार्ट II.8: सीपीआई सब्जियाँ

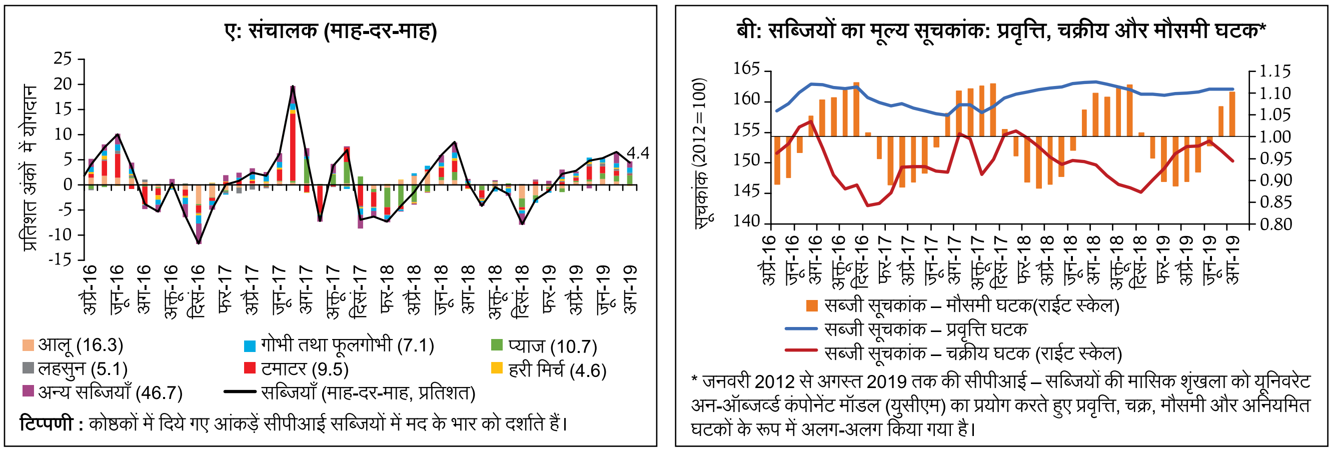

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रचलित सीपीआई-सब्जियों में अपघटन को ध्यान में रखते हुए चक्रीय और मौसमी घटक यह बताते हैं कि दिसंबर 2018 से शुरू होने वाले चक्रीय उत्थान, जिसके साथ प्रवृत्ति घटक एक समान रहा, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान (जुलाई 2019 तक) सब्जियों से संबंधित मुद्रास्फीति का प्रमुख संचालक था। ग्रीष्म ऋतु के दौरान मौसमी बढ़ोतरी पिछले वर्षों के अनुरूप रही (चार्ट II.8बी)।

फलों (जिनका सीपीआई में 2.9 प्रतिशत तथा खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 6.3 प्रतिशत भार है) की कीमतों के मामले में स्थिति दिसंबर 2018 में अवस्फीति में बदल गई। फरवरी 2019 से फलों की कीमतें बढ़ने लगीं अप्रैल और जुलाई में इसमें तीव्र वृद्धि हुई। हालांकि फल अगस्त 2019 तक अवस्फीति की अवस्था में बनी रहीं। केला एवं सेब के मामले में कीमतों में दबाव विशेष रूप से स्पष्ट थे जिनका एक-साथ फलों की श्रेणी में 35.6 प्रतिशत हिस्सा है। मंडी में कम आवक के कारण केला की कीमतें प्रभावित हुईं, जबकि सेब की कीमतों में पहले जैसी मौसमी बढ़त हुई। सेब की कीमतों को कम आयात के कारण भी समर्थन मिला, जो भारतीय उत्पादों पर यूएस द्वारा शुल्क लगाए जाने के क्रम में सेब पर आयात शुल्क में जून 2019 में 20 प्रतिशत तक की गई बढ़ोतरी का परिणाम था। हालांकि, मंडियों में अधिक घरेलू आवक के कारण केला एवं सेब दोनों के मामले में कीमतों में दबाव अगस्त में कम हुआ।

वर्ष 2019 के गर्मी के महीनों में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सब्जी तथा फलों की कीमतों में वृद्धि देखी गई। क्षेत्रवार विश्लेषण बताता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच फलों एवं सब्जियों की कीमतों में होने वाले माह-दर-माह बदलाव के आंकड़ों संबंधी कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सब्जियों तथा फलों की कीमतों में होने वाले माह-दर-माह बदलाव में आंकड़ा आधारित अधिक उतार-चढ़ाव विद्यमान है।[5]

दलहन सीपीआई (जिनका सीपीआई में 2.4 प्रतिशत तथा खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 5.2 प्रतिशत भार है) कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण 29 महीने अपस्फीति की स्थिति में रहने के उपरांत मई 2019 से बढ़ने लगीं एवं अगस्त 2019 में ये 35 महीने के मुद्रास्फीति के अधिकतम स्तर पर पहुंचकर 6.9 प्रतिशत हो गईं (चार्ट II.9.ए)। फिर भी, सीपीआई दाल सूचकांक प्रवृत्ति से नीचे रहा (चार्ट II.9.बी)। दलहन का उत्पादन वर्ष 2017-18 के 254 लाख टन की तुलना में वर्ष 2018-19 में कम होकर 234 लाख टन (चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार) रहा। इसके अतिरिक्त, दलहन का निर्यात वर्ष 2017-18 के 57 लाख टन की तुलना में वर्ष 2018-19 में कम होकर 26 लाख टन हो गया जिसके परिणामस्वरूप घरेलू आपूर्ति की प्रचुरता कम हुई। दलहन का एक बड़ा भाग, लगभग 40 लाख टन, उपलब्ध है जिसे कीमतों के दबाव को रोकने के लिए बाज़ार में प्रवाहित किया जा सकेगा।

मांस तथा मछली की कीमतों ने भी खाद्य पदार्थ संबंधी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया है जो आंशिक रूप से चारा और मुख्यतः मक्का, की कीमतों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। वास्तव में, मांस तथा मछली की कीमतों से संबंधित मुद्रास्फीति जुलाई 2019 में 62 महीने के उच्चतम स्तर पर थी। अंडे की कीमतें अपने पहले के पैटर्न के अनुरूप आगे बढ़ती रहीं, जबकि दूध एवं इसके उत्पादों की कीमतें मई- अगस्त 2019 के दौरान बढ़ीं, जो दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध के क्रय की कीमतों में ₹5-6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी के आंशिक प्रभाव के कारण मुख्यतः दूध की खुदरा कीमतों में ₹2 प्रति लीटर से ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

[5] एफ-परीक्षण और टी-परीक्षण फ्रेमवर्क पर आधारित. परिणामों की तेजी का परीक्षण मौसमी रूप से समायोजित और असमायोजित डाटा का प्रयोग करते हुए किया गया था।

चार्ट II.9: सीपीआई दालें

ए: सीपीआई -दालें तथा उत्पाद के संचालक - (माह-दर-माह)

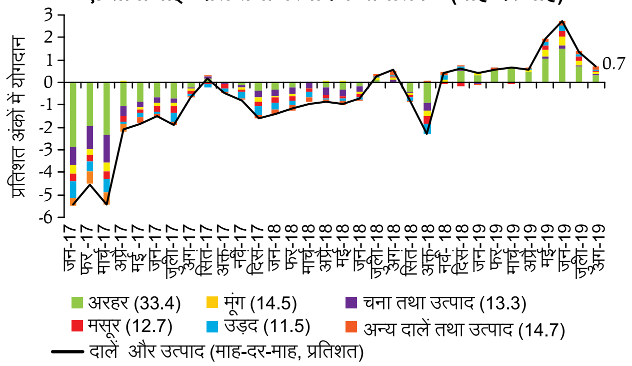

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई - दालें तथा उत्पाद में भार को दर्शाते हैं।

बी: वास्तविक बनाम प्रवृत्ति

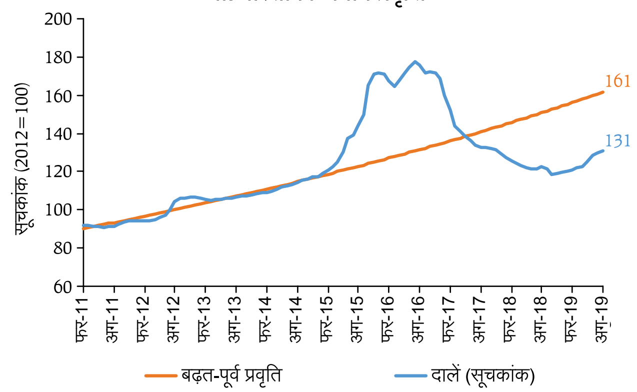

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चीनी की कीमतें लगातार 15 महीने के लिए नकारात्मक स्थिति में रहने के बाद मई 2019 में अवस्फीति की स्थिति से बाहर आई। हालांकि, जून-अगस्त 2019 के दौरान वे पुनः अवस्फीति की स्थिति में वापस लौट गई जो घरेलू आपूर्ति अधिशेष के साथ-साथ अनुकूल आधारभूत प्रभावों को दर्शाता है। इंडियन शुगर मिल्स एसोशिएसन (इस्मा) के अनुसार, चीनी का प्रारंभिक स्टॉक 01 अक्तूबर 2019 की स्थिति के अनुसार 145 लाख टन होने की अपेक्षा है जो अभी तक का सर्वाधिक स्तर है। चीनी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, जो लगातार अधिक वैश्विक आपूर्ति के कारण मई 2017-फरवरी 2019 के दौरान अवस्फीति की स्थिति में थीं, मार्च 2019 में सकारात्मक दायरे में आ गई। घरेलू बाज़ार में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में चीनी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जो संभवतः फरवरी 2019 में चीनी के विक्रय की न्यूनतम कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़त को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी के कारण तेल तथा वसा के मामले में मुद्रास्फीति अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान लगभग 0.8 प्रतिशत की निम्न स्थिति पर बनी रही तथा अधिक घरेलू उत्पादन ने कीमतों को नियंत्रित रखा। चौथे उन्नत आकलन के अनुसार वर्ष 2018-19 में तिलहन का उत्पादन 2.5 प्रतिशत बढ़ गया; तथापि, वर्ष के दौरान मूँगफली के उत्पादन में आई कमी ने वर्ष 2018-19 की अधिकांश अवधि में एवं वर्ष 2019-20 में अभी तक मूँगफली के तेल की कीमतों पर दबाव डाला है।

सीपीआई ईंधन समूह

ईंधन समूह मुद्रास्फीति अप्रैल के बाद जून तक क्रमवार कम हुई तथा यह जुलाई एवं अगस्त 2019 में अवस्फीति की स्थिति में बदल गई क्योंकि बड़े घटक जैसे बिजली, एलपीजी, उपले, जलावन की लकड़ी तथा चिप्स व कोयला ऋणात्मक दायरे में चले गए (चार्ट II.10ए)।

चार्ट II.10: सीपीआई ईंधन और प्रकाश समूह मुद्रास्फीति

ए: संचालक (वर्ष-दर-वर्ष)

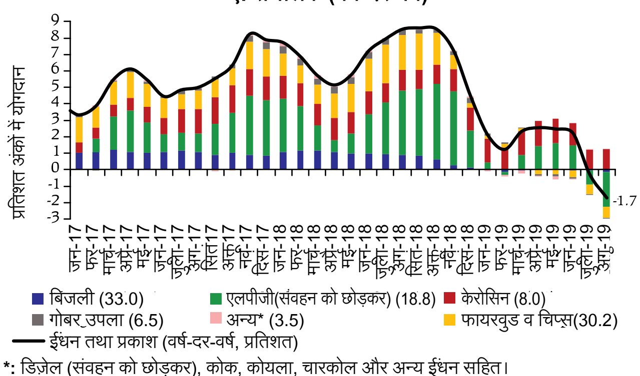

*: डिज़ेल (संवहन को छोड़कर), कोक, कोयला, चारकोल और अन्य ईंधन सहित।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई-ईंधन तथा प्रकाश में मद के भार को दर्शाते हैं।

बी: एलपीजी - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें

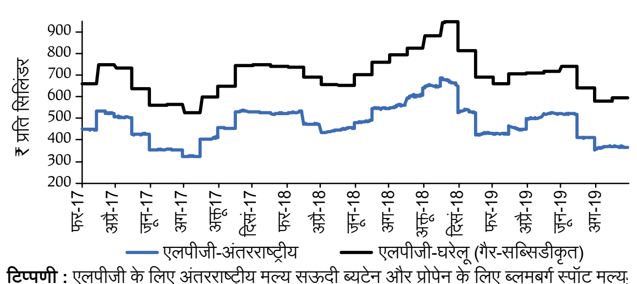

टिप्पणी : एलपीजी के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य सऊदी ब्यूटेन और प्रोपेन के लिए ब्लूमबर्ग स्पॉट मूल्य पर आधारित है, जो क्रमश: 60:40 के अनुपात में संयुक्त हैं ये अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्य संकेतक मूल्य हैं जो बेंचमार्क कीमतों के करीब हैं और आयात मूल्य निर्धारण के लिए तेल प्रमुखों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक बेंचमार्क उत्पादों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एलपीजी के लिए इस्तेमाल किए गए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क उत्पादों पर और जानकारी www.ppac.org.in पर उपलब्ध है| इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड(आईओसीएल) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार घरेलू कीमतें चार महानगरों की औसत पंप कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

स्रोत : (i) चार्ट II.10ए के लिए एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान|| (ii) चार्ट II.10बी के लिए ब्लूमबर्ग; इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड(आईओसीएल); एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मार्च से जून के बीच कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद घरेलू एलपीजी की कीमतें जुलाई एवं अगस्त में अचानक कम हो गई जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट का परिणाम है (चार्ट II.10बी)। बिजली की कीमतें, जो ईंधन एवं लाइट उप-समूह का एक-तिहाई हिस्सा है, जनवरी 2019 से अधिकांश महीनों में अवस्फीति की स्थिति में रही हैं। ग्रामीण उपभोग वाली वस्तुओं जैसे जलावन वाली लकड़ी एवं चिप्स, तथा उपले की कीमतें भी अप्रैल 2019 से अवस्फीति की स्थिति में हैं। आंशिक रूप से इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों[6] में एलपीजी के प्रयोग में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके विपरीत, तेल विपणन कंपनियों (ओएमओ) द्वारा नियंत्रित कीमतें बढ़ाई गई जिसके कारण मिट्टी के तेल की नियंत्रित कीमतों ने आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थों पर रियायत को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बाज़ार कीमतों के काफी नजदीक लाना था।

सीपीआई - खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर

खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च और जून 2019 के बीच कम होकर 100 आधार अंक के पास रही। उतार-चढ़ाव वाले घटकों जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, सोना एवं चाँदी को छोड़कर भी यह लगभग 70 आधार अंक तक कम हुई जो इस समूह में अवस्फीति की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है। तथापि, जुलाई 2019 में इसमें 35 आधार अंक तक की बढ़ोतरी हुई जो जारी नहीं रही तथा यह अगस्त में 30 आधार अंक तक कम हो गई (चार्ट II.11)।

चार्ट II.11: अपवाद-आधारित सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

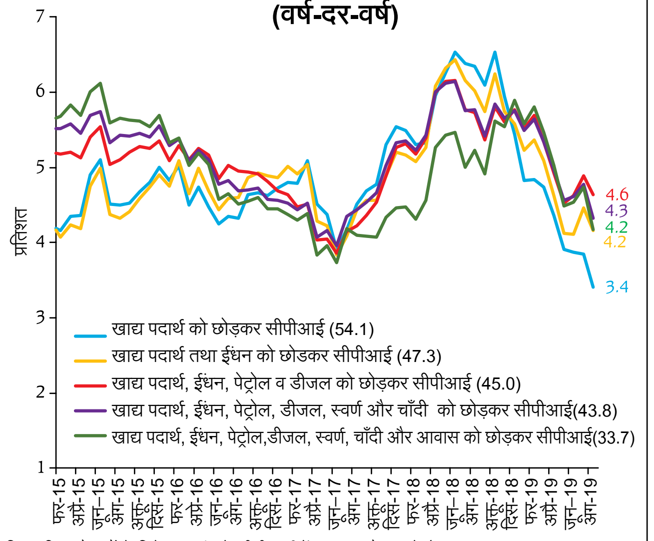

टिप्पणी : कोष्ठकों मे दिये गए आँकड़े सीपीआई में भारांक को दर्शाते हैं।
स्रोत : एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सीपीआई के भीतर खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक अधिकतम घटक उप-समूहों के मामले में कीमतों में वृद्धि ऐतिहासिक औसत से काफी कम रही है (चार्ट II.12)।

अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि खाद्य पदार्थ के मामले में निरंतर कम मुद्रास्फीति का खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई पर प्रभाव विस्तार रहा है (बॉक्स.II.1)।

चार्ट II.12: खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई

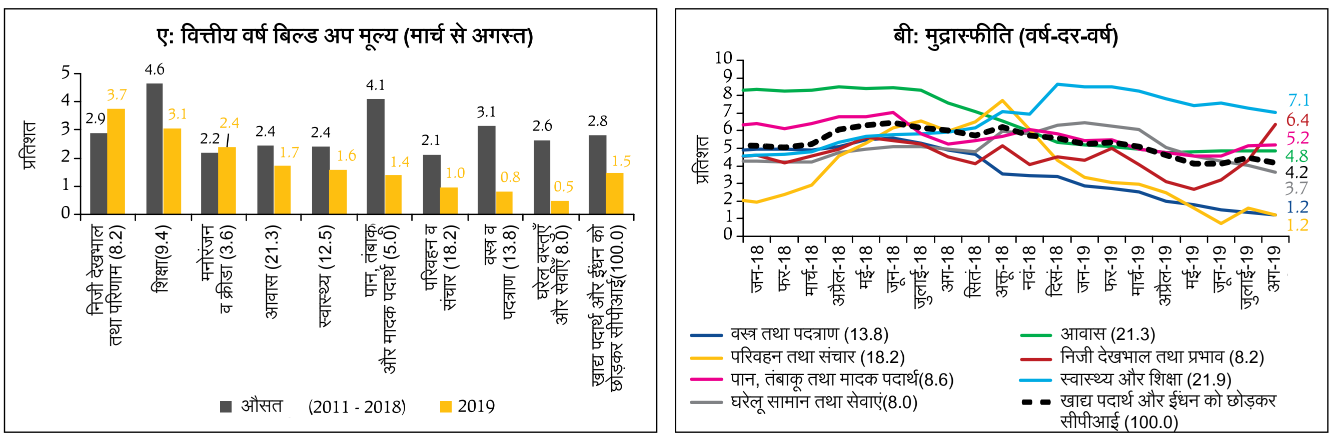

टिप्पणी : कोष्ठकों मे दिये गए आँकड़े खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[6] प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्सन दिए गए थे। इससे एलपीजी कवरेज (अखिल भारतीय) बेहतर होकर वर्ष 2015-16 के 62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 94 प्रतिशत हो गया। आकलन बताते हैं कि ये जलावन वाले परंपरागत ईंधन स्रोत जैसे लकड़ी एवं उपले से संबंधित मुद्रास्फीति में लगभग 1.60 प्रतिशत अंक की कमी लाने में योगदान दिए होंगे।

बॉक्स : II.1:खाद्य पदार्थ सहित मुद्रास्फीति से लेकर खाद्य पदार्थ एवं ईंधन रहित मुद्रास्फीति पर स्पिलओवर के समयांतर अनुमान

खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का हेडलाइन मुद्रास्फीति पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव रहता है। यह सीपीआई बास्केट में खाद्य पदार्थ के सापेक्ष भार पर प्रत्यक्ष रूप से एवं मुद्रास्फीति अनुमानों, वेतन और सापेक्ष कीमत समायोजन में बदलाव के माध्यम से दूसरे चक्र के प्रभावों पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है (सेसेटी और मोएनर, 2008)। सीमा-पार साक्ष्य पर अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि उतार-चढ़ाव और अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य पदार्थ के मामले में लगातार आघात, जिसका उपभोग बास्केट में खाद्य पदार्थ पर व्यय का बड़ा हिस्सा शामिल है, का खाद्य पदार्थ और गैर-खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति पर बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है (वाल्श, 2011)। ये स्पिलओवर समय पर निर्भर तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति द्वारा अनुकूलित हो सकते हैं। अनेक उतार-चढ़ाव वाली संभावनाओं (टीवीपी-वीएआर) - (प्राइमॅसरी, 2005) में से चुने गए विकल्प सहित समयांतर मानदंड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन को टाइम-वैरिंग पासथ्रू को-एफिसियंट के आकलन के लिए प्रयोग किया गया। यह वर्ष 1996-97 की पहली तिमाही से वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही[7] की नमूना अवधि में पाँच चरों जैसे आउटपुट गैप (अपने सामर्थ्य के स्तर से आउटपुट अंतर, y_t); खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति (π_t^f); खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति (π_t^c); नीतिगत ब्याज दर (i_t) (कॉल मनी दर द्वारा प्रोक्सी किया हुआ, जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है) एवं विनिमय दर (प्रति यूएसडी भारतीय रुपया) परिवर्तन (z_t), पर आधारित है।[7]

अनुमानित मॉडल को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :

Y_t को t समय पर 5 चरों को एक $n \times 1$ वेक्टर $\{y_t, \pi^f, \pi^c, i_t, z_t\}$ में परिभाषित करने दें।

तब,

$$Y_t = X_t\beta_t + A_t^{-1}\Sigma_t \varepsilon_t, \qquad t = s+1 \ldots n. \qquad (1)$$

$X_t = I_s \otimes (Y_{t-1}' \ldots Y_{t-s}')$; $a_t = (a_{21}, a_{31}, a_{32}, a_{41}, \ldots, a_{54})$ जहां βt को-एफिसिएंट का वेक्टर है तथा $j = 1, \ldots, k$, $t = s+1, \ldots, n$ के लिए $h_{jt} = \log\sigma^2_{jt}$ सहित A_t; $h_t = (h_{1t}, \ldots, h_{kt})$ में निम्न-त्रिकोणीय अंशों का एक स्टैकड वेक्टर है। यह मान लिया जाता है कि (1) में मानदंड एक रैंडम वॉक प्रासेस अपनाते हैं जैसा कि (2) बताया गया है:

$$\begin{aligned}\beta_{t+1} &= \beta_t + u_{\beta t}\\ a_{t+1} &= a_t + u_{at}\\ h_{t+1} &= h_t + u_{ht}\end{aligned} \text{ with } \begin{bmatrix}\varepsilon_t\\ u_{\hat{a}t}\\ u_{at}\\ u_{ht}\end{bmatrix} \sim N\left(0, \begin{bmatrix} I & 0 & 0 & 0\\ 0 & \Sigma_\beta & 0 & 0\\ 0 & 0 & \Sigma_a & 0\\ 0 & 0 & 0 & \Sigma_h\end{bmatrix}\right) \qquad (2)$$

अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि (i) को-एफ़िसिएंट पास-थ्रू समय के अनुसार बदलने वाले हैं – जो वर्ष 2003-04 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बीच रहे; (ii) यह पास-थ्रू तब अधिक होता है जब खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति अधिक एवं निरंतर बनी रहे, तथा खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति के कम रहने की स्थिति में यह कम रहे।

चार्ट II.1.1: सीपीआई खाद्य का खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई में पास-थ्रू

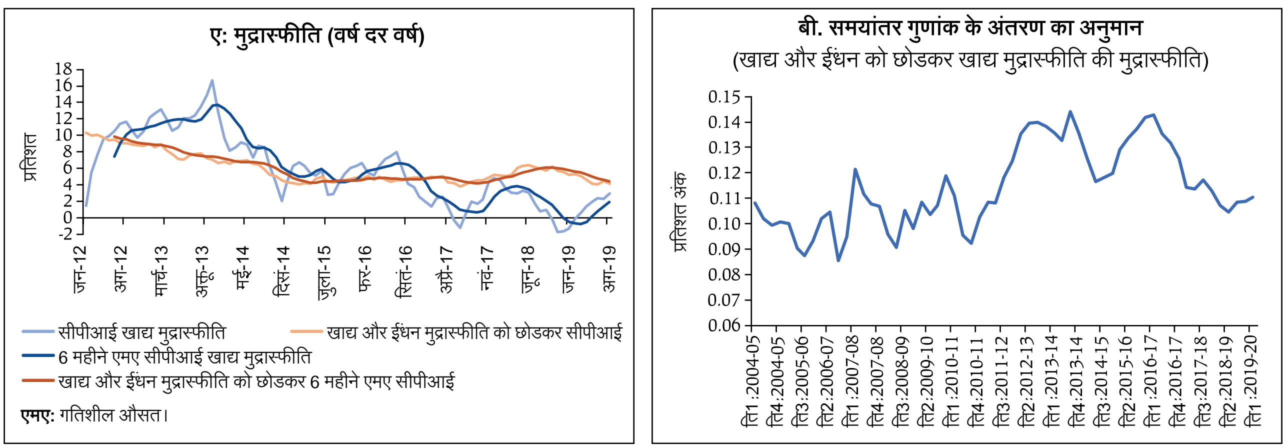

स्रोत : एनएसओ; और भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

(जारी.)

[7] वर्ष 2011 के पहले खाद्य पदार्थ की कीमतों सहित सीपीआई तथा खाद्य पदार्थ एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई के आकलन औद्योगिक कार्मिकों से संबंधित सीपीआई के समकक्ष सूचकांकों का प्रयोग करके किए जाते थे।

वर्तमान के खाद्य पदार्थ संबंधी निम्न मुद्रास्फीति के परिदृश्य में पास-थ्रू को-एफ़िसिएंट लगभग 10 प्रतिशत तक कम हुआ (चार्ट II.1.1 ए और बी)। खाद्य पदार्थ का मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर, पर विषम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की कम और स्थिर कीमतें बनाए रखना अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रण में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति की निरंतरता को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष में अनिवार्य सुधार करेगा।

संदर्भ:

बारदोलोई, एस. (2019), "स्पिल ओवर फ्राम फूड इन्फ़्लेशन टू कोर इन्फ़्लेशन इन इंडिया: ऐन एम्पिरिकल एनालिसिस" ।

सेसेटी, एस. और मोएनर, आर. (2008), "कोमोडिटी प्राइस एंड इन्फ़्लेशन डाईनमिक्स," बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटेलमेंट क्वाटर्ली रेव्यू , बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटेलमेंट, पीपी, 55-66 ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2014), *"रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथेन द मॉनीटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क* (चेयरमैन : डॉ. ऊर्जित आर. पटेल)" ।

प्रीमिसेरी, जी (2005), "टाइम वैरींग स्ट्रक्चर वेक्टर ऑटोरिग्रेशन एंड मॉनीटरी पॉलिसी", *रेव्यू ऑफ एकोनोमिक स्टडीज़*, 72, पीपी. 821-852 ।

वाल्श, जे. (2011), "रीकंसिडरींग द रोल ऑफ फूड प्राइसेस इन इन्फ़्लेशन", आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/11/71, इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड ।

अनुकूल आधार प्रभावों के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों में निरंतर अपस्फीति के चलते परिवहन और संचार उप-समूह में मुद्रास्फीति सामान्य रही (चार्ट II.13ए)। हालांकि, अधूरे पास-थ्रू (अंतरण) के कारण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के मध्य काफी अधिक अंतर रहा (चार्ट II.13बी)।

वस्तु और सेवाओं के संबंध में खाद्य, ईंधन, पेट्रोल तथा डीजल मुद्रास्फीति को छोडकर सीपीआई के घटकों की जांच से पता चलता है कि माल मुद्रास्फीति ने नरमी (फरवरी-मई) और इजाफ़ा (जून-अगस्त) इन दोनों चरणों को देखा जबकि सेवा संबंधी मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट हुई है (चार्ट II.14ए और बी)। मई के दौरान माल मुद्रास्फीति में हुई गिरावट के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, एक प्रमुख उप समूह कपड़े और फुटवियर का योगदान रहा। माल मुद्रास्फीति को सामान्य बनाए रखने वाले अन्य उप-समूहों में व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, विशेष रूप से सोना, चांदी तथा प्रसाधन के सामान और घरेलू सामान एवं सेवा संबंधी वस्तुएं रही। माल मुद्रास्फीति में जून से आई उछाल पूरी तरह से व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं और सोने की कीमतों में तीव्र वृद्धि के चलते उप-समूह की वस्तुओं के कारण उत्पन्न हुई है। सेवाओं में मुद्रास्फीति जो कि फरवरी 2019 में अपने उच्च स्तर पर थी वह अगस्त 2019 में 4.9 प्रतिशत पर सामान्य रही (चार्ट II.14बी)। यह नरमी ट्यूशन और कोचिंग जैसी शिक्षा सेवाओं, परिवहन किराया, विशेषरूप से बस किराया; चिकित्सा सेवाएं; सफाई और सिलाई शुल्क जैसी घरेलू सेवाओं में व्यापक रूप से आई।

चार्ट II.13: अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों में उतार-चढ़ाव

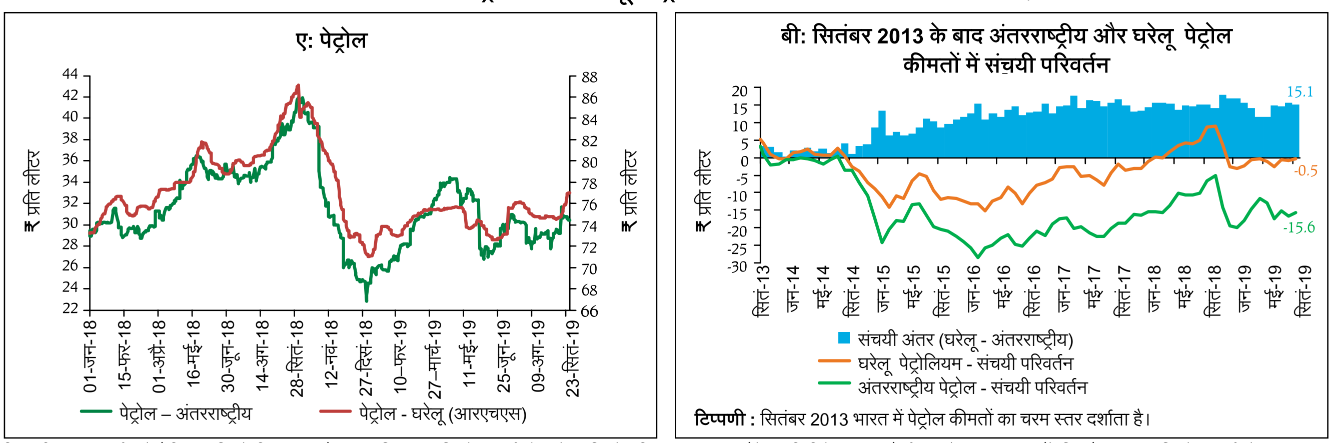

टिप्पणी: अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतें सिंगापुर गॅसोलाइन की स्पॉट कीमतें दर्शाती हैं। घरेलू कीमतें इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चार महानगरों की औसत पम्प कीमतें दर्शाती है।
स्रोत : ब्लूमबर्ग, आईओसीएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.14: खाद्य पदार्थ, ईंधन,पेट्रोल व डीजल को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान

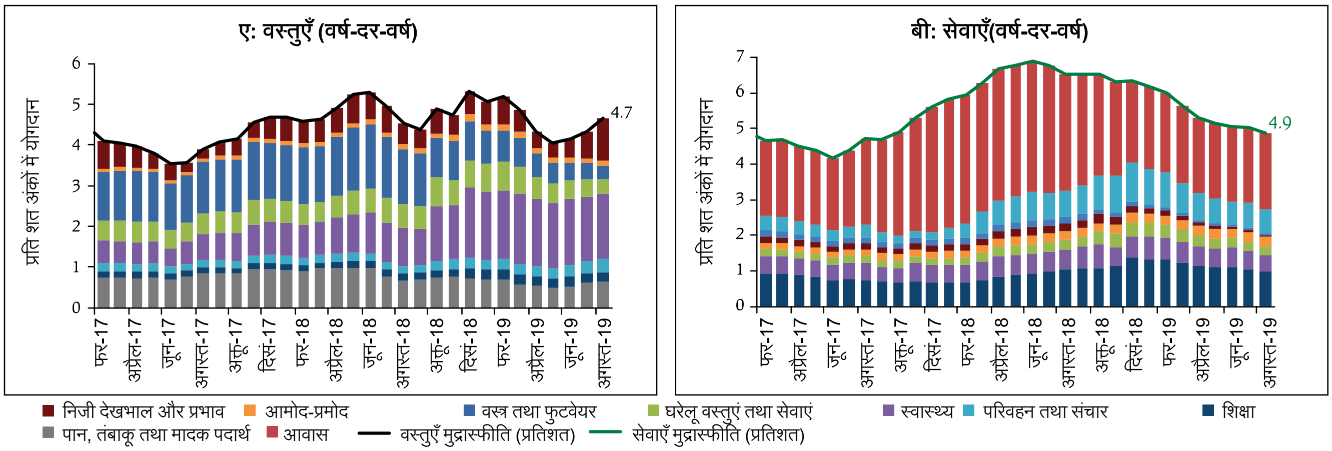

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मुद्रास्फीति के अन्य मापक

क्षेत्रीय सीपीआई अर्थात औद्योगिक कामगारों (सीपीआई-आईडबल्यू), कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) तथा ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) में मुद्रास्फीति, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में हुई मामूली वृद्धि की तुलना में मार्च और जून 2019 के बीच तेजी से बढ़ी। सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के खाद्य और ईंधन संबंधी घटकों में मुद्रास्फीति हेडलाइन सीपीआई की मुद्रास्फीति से अधिक थी तथा यह इन सूचकांकों में खाद्य के बड़े हिस्से द्वारा बढ़ी थी। सीपीआई-आईडबल्यू के मामले में, विचलन का प्रमुख स्रोत हाउसिंग घटक था। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अंतर्गत एचआरए में हुई वृद्धि के चलते सीपीआई-आईडबल्यू में हाउसिंग मुद्रास्फीति जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक रही, जिसके चलते मई 2019 तक सीपीआई-आईडबल्यू मुद्रास्फीति बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई। एचआरए में वृद्धि का प्रभाव कम होने के साथ सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति गिरकर अगस्त 6.3 प्रतिशत हो गई।

थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) में मुद्रास्फीति क्षेत्रीय सीपीआई के विपरीत लगातार गिरकर अगस्त, 2019 में 1.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गई। जहां एक ओर, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों का अनुसरण करते हुए ईंधन समूह की मुद्रास्फीति मार्च के 4.6 प्रतिशत से गिरकर अगस्त 2019 में (-) 4.0 प्रतिशत पर आ गई; गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों में भी मुद्रास्फीति सभी ओर गिर गई और अगस्त में संकुचित हो गई। वहीं दूसरी तरफ, डबल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में जून से तेजी आई और जुलाई में कुछ सुधार को छोडकर अगस्त तक उच्च स्तर पर बनी रही। पिछले छह महीनों के दौरान जीडीपी और जीवीए अपस्फीतिकारक सीपीआई मुद्रास्फीति के साथ व्यापक रूप से संरेखित रहे (चार्ट II.15ए)।

अंतर्निहित मुद्रास्फीति गतिशीलता को अपवर्जन-आधारित उपायों से मापा जा सकता है जो अस्थिर वस्तुओं / वस्तु समूहों अथवा ट्रिमिंग जैसे सांख्यिकी उपायों को हटाते हैं और आउटलायर्स की छटाई

चार्ट II.15: मुद्रास्फीति के वैकल्पिक मापन

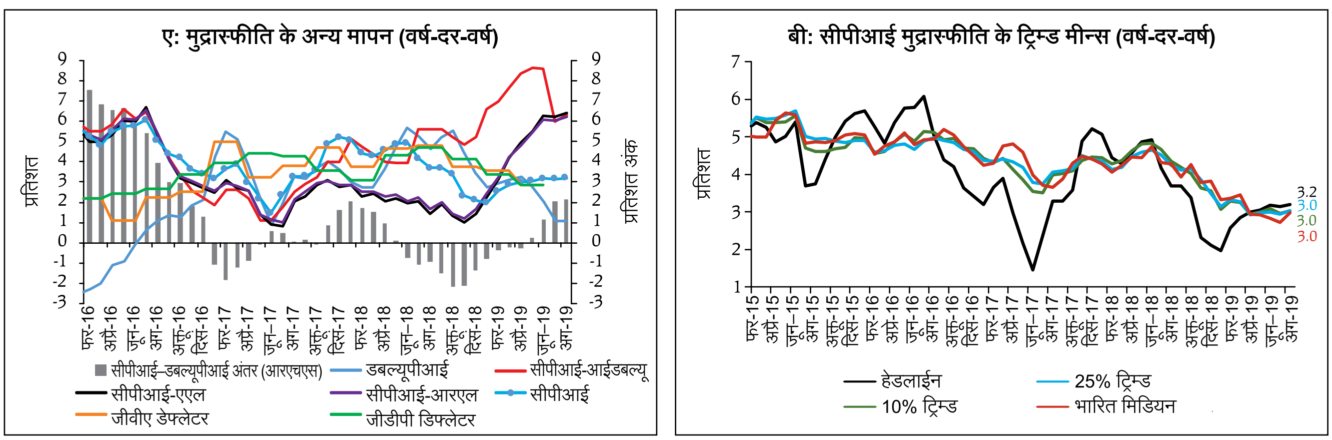

स्रोत : एनएसओ; श्रम ब्यूरो;वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

करके मुद्रास्फीति वितरण में धनात्मक और ऋणात्मक तिर्यक (स्क्यू) और चिरकालिक फैट टेल्स को समायोजित करते हैं। इन उपायों के द्वारा मुद्रास्फीति में पिछले छह माह में नरमी आई है (चार्ट II.11 और II.15बी)।

II.3 लागतें

अंतर्निहित लागत स्थितियों की गतिविधियां काफी हद तक डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति के तदनुरूप रहीं (चार्ट II.16)। 2019-20 में अब तक फार्म इनपुट्स और औद्योगिक कच्चे माल (डबल्यूपीआई से लिए गए) की लागत में कमी आई है। 2019-20 के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के सामान्य रहने से हाई स्पीड डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, नेप्था, बिटुमिन फरनेस ऑयल तथा पेट्रोलियम कोक जैसे इनपुट के संबंध में घरेलू कीमतों के दबाव का नियंत्रण रहा। इसके अलावा, खनिज की कीमतों में संकुचन के चलते भी औद्योगिक इनपुट लागतों में कमी आई है।

अन्य औद्योगिक कच्चे मालों में घरेलू कोयला मुद्रास्फीति 2019-20 के शुरुआत से काफी हद तक कम रही, जो अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान लगभग 0.7 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान घरेलू कोयले की कीमतें काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों के अनुरूप रही। कागज और कागज उत्पादों में भी मुद्रास्फीति लुगदी और कोयले जैसे कच्चे माल की लागत कम होने के कारण सामान्य बनी रही। रेशों के मामलें में, जून-अगस्त 2019 के दौरान मुद्रास्फीति में कमी आई, जो प्रमुख रूप से कच्चे जूट और कच्चे कपास की कीमतों में कमी को दर्शाती है।

कृषि क्षेत्र के इनपुटों में, उर्वरकों के संबंध में कीमत के दबाव कम रहे जो विशेष रूप से फॉस्फेट, डि-अमोनियम फॉस्फेट तथा ट्रिपल सुपरफॉस्फेट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के सामान्य रहने के चलते कीटनाशक और अन्य कृषि उत्पादों के संबंध में भी मुद्रास्फीति 2019-20 की पहली तिमाही में बड़े पैमाने पर कम हुई। बिजली की कीमत, जिसका औद्योगिक और कृषि दोनों इनपुटों में उच्च भारांक रहता है, जून-अगस्त 2019 के दौरान अपस्फीति में परिवर्तित हो गई। हालांकि, अगस्त 2016-दिसंबर 2018 (अगस्त 2017 को छोड़कर) के दौरान 28 महीनों तक अपस्फीति में रहने के बाद जनवरी 2019 में चारे की कीमतें सकारात्मक हो गई; और जुलाई 2019 में 37 महीनों के सबसे उच्च स्तर 16 प्रतिशत पर पहुँच गई। कृषि मशीनरी और उपकरणों की लागत के संबंध में भी मुद्रास्फीति 2018-19 की दूसरी छमाही से उच्च और निश्चल बनी रही।

कृषिगत तथा गैर-कृषिगत दोनों श्रमिकों के लिए ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि सामान्य तथा निश्चल बनी रही जो कि 2019-20 के दौरान अब तक क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत के आस-पास है। यह मध्यम ग्रामीण मुद्रास्फीति, निम्न खाद्य कीमतें तथा विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के देरी से हुए प्रभाव को दर्शाती है (चार्ट II.17)। हालांकि, फरवरी 2019 से सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल में मुद्रास्फीति बढ़ी

चार्ट II.16: कृषि कार्य तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

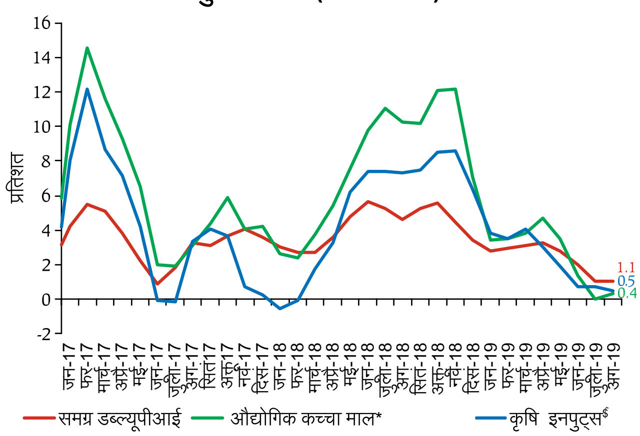

*: डब्ल्यूपीआई से प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएँ, खनिज, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च गति डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस तेल, चिकनाई तेल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, सूती धागे और कागज व लुगदी शामिल हैं।

$: डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।

स्रोत : वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.17: ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि और मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

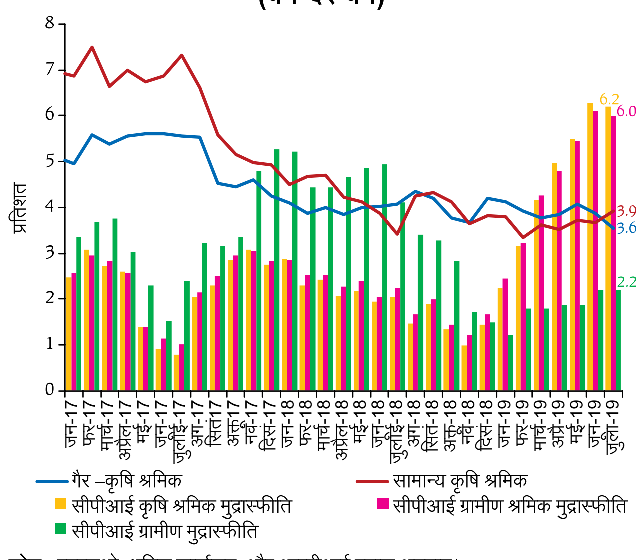

स्रोत : एनएसओ; श्रमिक कार्यालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

है लेकिन वास्तविक ग्रामीण मज़दूरी की वृद्धि इन सूचकांकों के आधार पर मार्च 2019 से नकारात्मक हो गई।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की लागत में वृद्धि ने सेवाओं और विनिर्माण संस्थाओं के लिए अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों को दर्शाया है। विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों के लिए इकाई श्रम लागत 2018-19 की चौथी तिमाही में मामूली रूप से गिर गई लेकिन बाद में कर्मचारियों की लागत में वृद्धि के साथ ही उत्पादन के मूल्य में गिरावट के कारण 2019-20 की पहली तिमाही में 6.3 प्रतिशत तक बढ़ गई।[8] सेवा क्षेत्र में कंपनियों के लिए इकाई श्रम लागत अंतिम तिमाही में मामूली रूप से बढ़ी, क्योंकि कर्मचारियों की लागत में उच्च वृद्धि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि से आगे निकल गई (चार्ट II.18)।

रिज़र्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भाग लेने वाली विनिर्माण कंपनियों ने कच्चे माल की कम लागत के कारण 2019-20 की दूसरी तिमाही में इनपुट लागत में गिरावट दर्ज की। दूसरी तिमाही में वित्त और वेतन पर कम व्यय होने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही में इनपुट कीमतों में गिरावट के चलते बिक्री कीमतों में गिरावट की संभावना है।

विनिर्माण क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के लिए सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों ने इनपुट लागत और बिक्री की कीमतों में 2018-19 की दूसरी तिमाही से लेकर 2019-20 की पहली तिमाही तक लगातार गिरावट दर्ज की। हालांकि, 2019-20 की पहली तिमाही में

चार्ट II.18: विनिर्माण तथा सेवाओं में श्रम लागत उत्पादन के प्रति यूनिट मूल्य कर्मचारी लागत

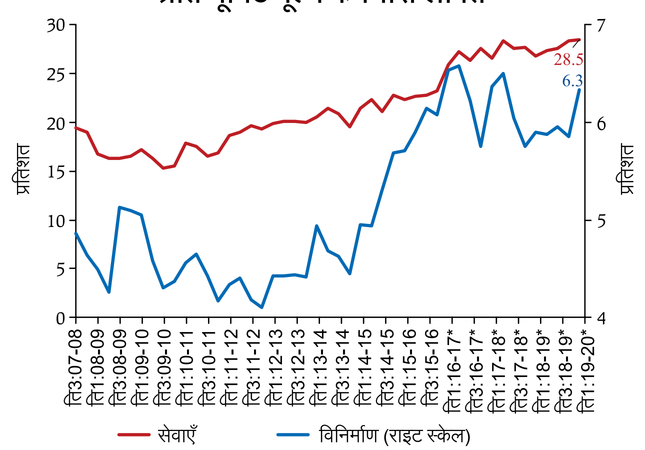

*: ₹500 करोड़ से अधिक की निवल मालियत की सूचीगत कंपनियों द्वारा 2016-17 की पहली तिमाही से नए लेखा मानक "आईएनडी-एएस तथा शेष अनुसूचित कंपनियों को यही मानक 2017-18 की पहली तिमाही से अपनाना कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा लागू है | इस परिवर्तन का प्रभाव संवृद्धि दर के मामले में समग्र स्तर पर हल्का है यद्यपि इसे अनुपात के लिए न लिया जाए|| तदनुसार डाटा को देखा जाए।

स्रोत : केपिटलाइन डाटा बेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बिक्री की कीमतें आउटपुट लागत की तुलना में अधिक थी। 2019-20 की दुसरी तिमाही के दौरान इनपुट लागत और बिक्री कीमत दोनों में तेजी आई। सेवा क्षेत्र पीएमआई में कंपनियों द्वारा दर्ज की गई इनपुट लागत मुद्रास्फीति भी 2018-19 की दूसरी तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक धीरे-धीरे घटी लेकिन 2019-20 की दूसरी तिमाही के प्रथम दो महीनों के दौरान यह बढ़ गई। सेवा क्षेत्र द्वारा लगाए गई कीमतें स्थिर रही।

II.4 निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 में अब तक मुद्रास्फीति की दिशा बढ़ती हुई खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा परिलक्षित है, जिसमें हाल के वर्षों में लगभग ऐतिहासिक और आम तौर पर रहने वाली कीमतों से अधिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि गरमी के मौसम के दौरान सब्जियों की कीमतों में आई अधिक तेजी के चलते हुई है। हालांकि, आगे चलकर, खरीफ की फसल और सर्दियों के मौसम में होने वाली आपूर्ति के साथ ही सब्जी की बढ़ी हुई कीमतों में नरमी आने की संभावना है। अच्छे मानसून और बुवाई के बाद अनाज की कीमतों के दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, अनाज के बफर स्टॉक निर्धारित मानदंडों से अधिक ही हैं। दालों के मामले में, बफर स्टॉक के साथ ही बाजार में ताजा उपज आने से कीमतें नियंत्रण में रहने की संभावना हैं। आगे चलकर, घरेलू ईंधन और पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक गतिविधियों के कारण काफी अनिश्चितता रह सकती है। कमजोर वैश्विक मांग के बावजूद कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के चलते एक बड़े जोखिम की संभावना बनी हुई है। हालांकि, कमजोर घरेलू मांग और कम इनपुट लागत को देखते हुए खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में मुद्रास्फीति सामान्य रहने की संभावना है।

रिज़र्व बैंक के आने वाले कल के सर्वेक्षणों को देखने से ज्ञात होता है कि खासकर गैर-आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ग्राहकों के कमजोर आत्मविश्वास और मांग में कमी के संकेत मिल रहे हैं। घरेलू वस्तुओं में मुद्रास्फीति मोटे तौर पर स्थिर बनी रहने की संभावना है। वित्त और वेतन व्यय पर लागत मंदित रहने के कारण विनिर्माण फर्म अभी भी इनपुट कीमतों में नरमी और मूल्य निर्धारण में वृद्धि को देख रहे हैं हालांकि, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा कुछ हद तक बढ गई है । कुल मिलाकर, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2019-20 के दौरान रिज़र्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रहने की उम्मीद है।

[8] इकाई श्रम लागत को उत्पादन के मूल्य पर स्टॉक लागत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

III. मांग और उत्पादन

पहली तिमाही में व्यक्तिगत उपभोग में कमी के कारण सकल मांग कमजोर हुई। आपूर्ति पक्ष की ओर, विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र मंदी संगठित क्षेत्र में कमजोरी को अनिवार्य रूप से दर्शाती है। 'वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएँ' तथा निर्माण गतिविधियों ने सेवा क्षेत्र की वृद्धि को नीचे की ओर खींच लिया है। सरकार द्वारा हाल में किए गए उपायों से पूंजीगत व्यय चक्र तुरंत शुरू होगा और इससे घरेलू मांग में सुदृढ़ता पैदा होगी ।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू आर्थिक गतिविधियों की गति में तीव्र गिरावट आई। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में व्यक्तिगत उपभोग में कमी के कारण सकल मांग कमजोर हुई। आपूर्ति के संबंध में पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवा क्षेत्रों में उत्पादन ज्यादा समय तक कमजोर रहने के कारण विनिर्माण संबंधी गतिविधियां धराशायी हो गईं और निर्माण गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। सामने आ रहे आंकड़े दर्शाते हैं कि यह गिरावट 2019-20 की दूसरी तिमाही में भी जारी रही।

III.1 सकल मांग

बाजार की कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) परिवर्तनों से मापे गए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में कुल मांग में गिरावट, वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत तक गहरी हो गई और 2018-19 की पहली तिमाही से आरंभ हुई अनुक्रमिक मंदी पांचवीं तिमाही तक लगातार (सारणी III.1 और चार्ट III.1ए) बनी रही। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर आंकी गई मौसमी समायोजित वार्षिकी जीडीपी वृद्धि दर (एसएएआर) वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के 5.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.1बी)।

जीडीपी के घटकों में से, निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई), जो सकल मांग का मुख्य आधार में गिरावट आई तथा उसकी संवृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही में चार प्रतिशत अंक से अधिक की तीव्र गिरावट के साथ अठारह-तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। सरकारी अंतिम खपत व्यय (जीएफसीई) ने सकल मांग की गिरावट को थाम लिया। जीएफसीई को छोड़कर, वास्तविक जीडीपी की संवृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही में घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई होती। पूंजीगत व्यय के ज़ोर न पकड़ पाने के कारण सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीई) 2019-20 की पहली तिमाही में कमजोर रहा। कारोबारी दबाव के कारण बाहरी व्यापार वातावरण प्रतिकूल रहा और 2019-20 की पहली तिमाही में निर्यात वृद्धि काफी कम हो गई। घरेलू मांग की स्थिति को दर्शाती आयात संवृद्धि और उसमें हुई तीव्र गिरावट से शुद्ध निर्यात ने नौ तिमाहियों के अंतराल के बाद वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया।

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (प्रतिशत)

मद	2017-18 (एफ़आरई)	2018-19 (पीई)	भारित योगदान*		2017-18 (एफ़आरई)				2018-19 (पीई)				2019-20
			2017-18	2018-19	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
निजी अंतिम उपभोग व्यय	7.4	8.1	4.2	4.5	10.1	6.0	5.0	8.8	7.3	9.8	8.1	7.2	3.1
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	15.0	9.2	1.5	1.0	21.9	7.6	10.8	21.1	6.6	10.9	6.5	13.1	8.8
सकल फिक्स्ड़ पूंजी निर्माण	9.3	10.0	2.9	3.1	3.9	9.3	12.2	11.8	13.3	11.8	11.7	3.6	4.0
निर्यात	4.7	12.5	1.0	2.5	4.9	5.8	5.3	2.8	10.2	12.7	16.7	10.6	5.7
आयात	17.6	15.4	3.8	3.6	23.9	15.0	15.8	16.2	11.0	22.9	14.5	13.3	4.2
बाज़ार मूल्यों पर जीडीपी	**7.2**	**6.8**	**7.2**	**6.8**	**6.0**	**6.8**	**7.7**	**8.1**	**8.0**	**7.0**	**6.6**	**5.8**	**5.0**

एफआरई: प्रथम संशोधित अनुमान पीई : अनंतिम अनुमान

*: संवृद्धि के लिए घटक-वार योगदान को सारणी में जीडीपी संवृद्धि के साथ नहीं जोड़ा है क्योंकि स्टाक में बदलाव, कीमती वस्तुए और विसगंतियों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), भारत सरकार।

चार्ट III.1: जीडीपी संवृद्धि और उसके घटक

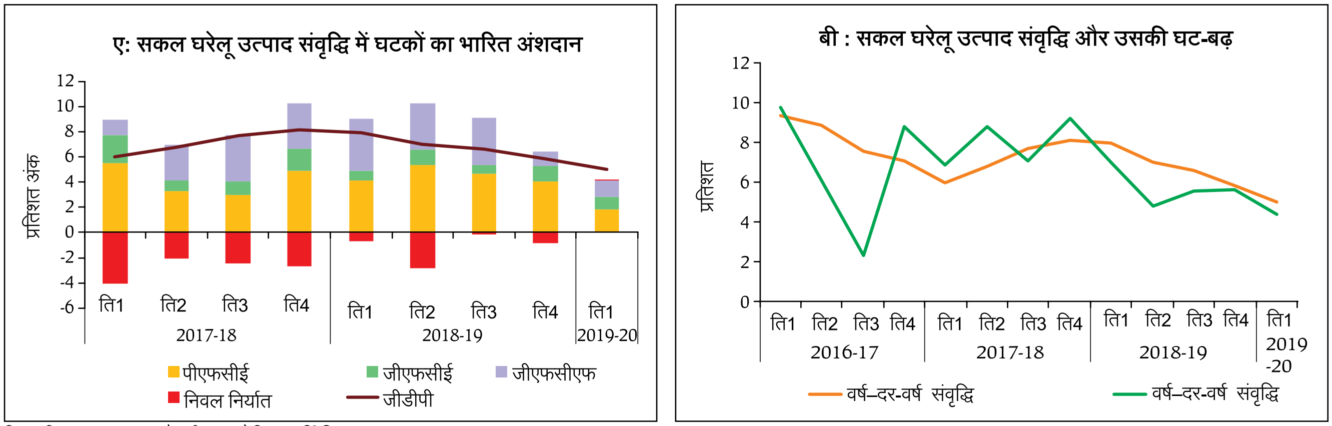

टिप्पणी : एसएएआर - मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत दर
स्रोत : एनएसओ,भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जीडीपी अनुमान के मुक़ाबले वास्तविक उत्पादन

अप्रैल 2019 में एमपीआर ने 2019-20 की पहली तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था, जिसमें बेसलाईन पथ के आस-पास समान रूप से संतुलित जोखिम था (चार्ट III.2)। तिमाही के लिए वास्तविक उत्पादन अनुमानों से 180 आधार अंक कम रहा। सबसे पहले, निजी उपभोग की मांग में वास्तविक वृद्धि ने नीचे गिरकर सब को चौका दिया जो यह दर्शाता है कि अप्रैल 2019 के अनुमानों ने ग्रामीण और शहरी दोनों खपत में व्यापक मंदी को कम आंका। दूसरा, जीएफसीएफ संवृद्धि भी अनुमान से कम रही क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और उनका आयात अपेक्षा से कम रहा तथा निर्माण मरणासन्न भी रहा।

III.1.1 निजी अंतिम खपत व्यय

पीएफसीई में अप्रत्याशित मंदी की वजह से इसका हिस्सा एक वर्ष पहले रहे 56.1 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2019-20 की पहली तिमाही में 55.1 प्रतिशत रह गया। रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा निर्माण और जूट निर्माण जैसे कुछ श्रम गहन निर्यात क्षेत्रों में कमजोर संवृद्धि के कारण निजी खपत में मंदी व्याप्त हो गई (चार्ट III.3)।

चार्ट III.2: सकल देशी उत्पाद संवृद्धि: अनुमानित बनाम वास्तविक (तिमाही1: 2019-20)

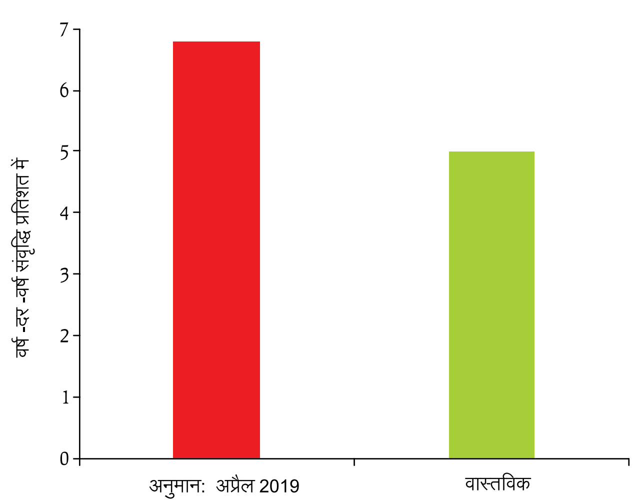

स्रोत: एनएसओ, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.3 चुनिन्दा संकेतक – श्रमिक- व्याप्त क्षेत्रों में निर्यात मांग

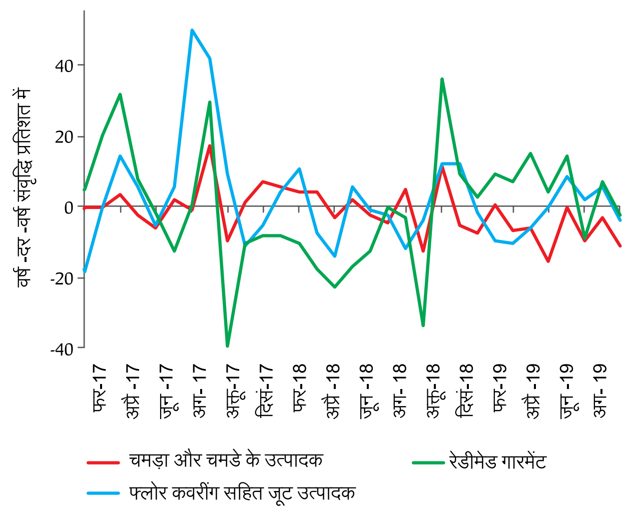

स्रोत: वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महा निदेशक(डीजीसीआई एण्ड एस)।

चार्ट III.4: उच्च आवृत्ति संकेतक - शहरी मांग

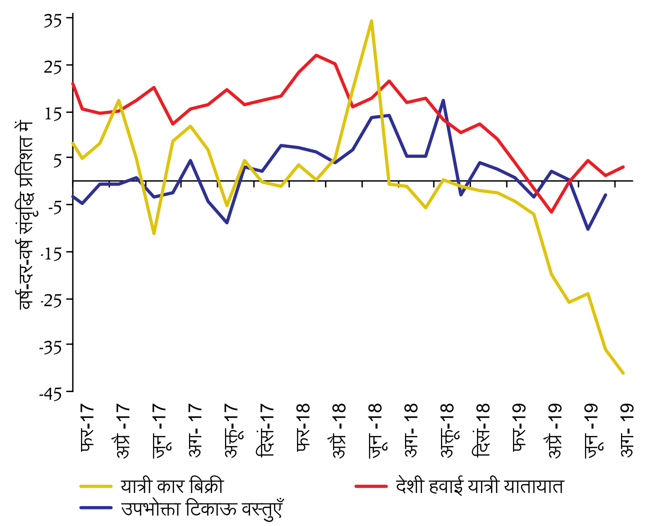

स्रोत: भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण; सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); और एनएसओ।

चार्ट III.5: घरेलू ऋण

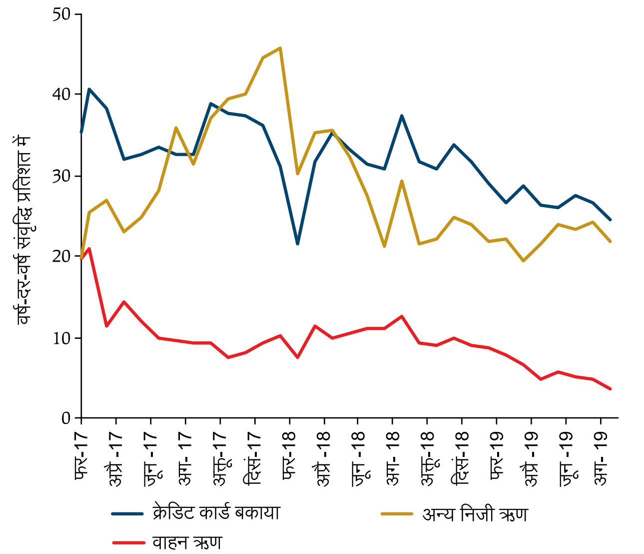

स्रोत : आरबीआई।

शहरी उपभोग के उच्च आवृत्ति संकेतक हाल के महीनों में कमजोर हो गए हैं जिसे यात्री वाहनों की बिक्री और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में संकुचन में देखा जा सकता है (चार्ट III.4)। इनमें से, अप्रैल 2019 के बाद से हर महीने यात्री कार की बिक्री में दोहरे अंकों की कमी आई है, परिणामस्वरूप प्रमुख कार उत्पादकों ने कारखाने के उत्पादन को बीच-बीच में रोक दिया। सख्त सुरक्षा मानदंडों के कारण उच्च कीमतों, नए उत्सर्जन मानदंडों के कारण व्याप्त अनिश्चितता और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रस्तावित स्विचिंग जैसे कारकों ने यात्री वाहनों की बिक्री को प्रभावित किया है (बॉक्स III.1)। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले वाहन के लिए घरेलू ऋण की संवृद्धि भी नरम रही (चार्ट III.5)। एक निजी एयरलाइन के बंद हो जाने के कारण घरेलू हवाई यात्री यातायात संवृद्धि जुलाई में मामूली रही, जिसने हवाई किराए को प्रभावित किया और मांग में कमी आई, हालांकि इसमें अगस्त में सुधार हुआ। यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में सरकार के हालिया समर्थन जैसे 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए भारत स्टेज (बीएस) IV वाहनों को पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए संचालन की अनुमति देना, सरकारी विभागों द्वारा नए वाहनों की खरीद पर लगे प्रतिबंध को हटाना और जून 2020 तक एकमुश्त पंजीकरण शुल्क लागू करने को स्थगित करना आदि के कारण यात्री वाहन बिक्री में सुधार हो सकता है।

ग्रामीण मांग के विभिन्न संकेतक भी कमजोर बने हुए हैं (चार्ट III.6)। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की बिक्री जुलाई और अगस्त में कम हुई। हालांकि गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि जुलाई में तेज हुई जो मुख्य रूप से सूरजमुखी के तेल द्वारा संचालित थी। तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं (एफएमसीजी) कंपनियों की बिक्री में संवृद्धि, जिसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, भी सुस्त रही है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमानों में अपेक्षाकृत मजबूत

चार्ट III.6: चुनिन्दा संकेतक - ग्रामीण मांग

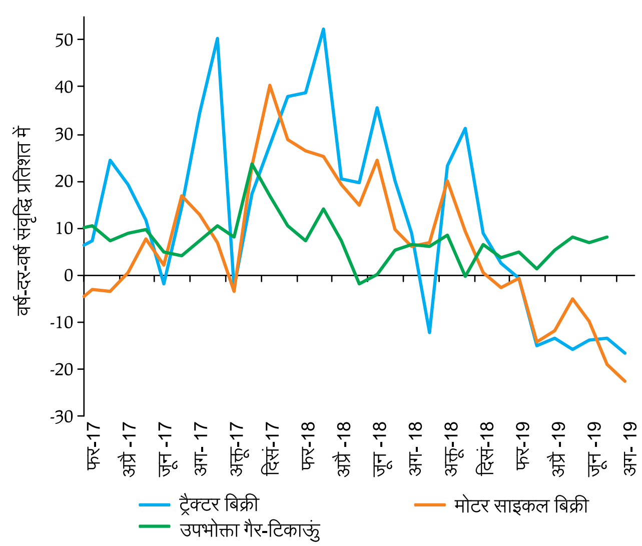

स्रोत : ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन; एसआईएएम; और एनएसओ।

बॉक्स III.1: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में धीमापन

भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में धीमापन कई विनियामकीय और संस्थागत कारकों के कारण मांग में कमी के रूप में परिलक्षित हुआ है। आर्थिक गतिविधि[1] में इस उद्योग की भूमिका को देखते हुए, इसने उल्लेखनीय रूप से ध्यान आकर्षित किया है।

2007-08 की पहली तिमाही से लेकर 2019-20 की पहली तिमाही तक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए ऑटो सेक्टर में मंदी के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित कारकों का आकलन करने के लिए बाह्य चर (लुडविगसन, 1998) (वीएआरएक्स) के साथ वेक्टर ऑटो रेग्रेशन का उपयोग करते हुए एक आकलन ढांचा तैयार किया गया। पहले वीएआरएक्स (1) में

$$Y = A\ (L)Y + CX + U, \qquad \text{.... (1)}$$

जहां $Y = [c_t, y_t, s_t, i_t]$ समकालिक प्रणाली के समीकरणों के लिए एक अंतर्जात चर का एक वेक्टर है। c_t दीर्घावधिक रुझान से ऑटोमोबाइल खरीद के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबीज़) द्वारा संवितरित क्रेडिट के बीच के अंतराल के रूप में मापी गई क्रेडिट मांग है। s_t उसके दीर्घकालिक रुझान से वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री का विचलन है। y_t उत्पादन अंतराल के रूप में मापी गई सकल मांग है और i_t एससीबीज़ की भारित औसत उधार दर है। सकल मांग और क्रेडिट मांग में वृद्धि से वाहन बिक्री के बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर, ब्याज दर में वृद्धि के कारण ऑटो की बिक्री के नरम पड़ने की संभावना है।

$X = [z_t, p_t, d_1, d_2]$ समकालिक प्रणाली के समीकरणों के बाहर एक बहिर्जात चर का एक वेक्टर है, p_t डीजल की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन है, d_1 एक डमी चर है जो अप्रैल 2017 से लागू बीएस IV को दर्शाता है. d_2 एक डमी वैरिएबल है जो 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान हुई तीन घटनाओं को दर्शाता है, अर्थात आईएलएंडएफएस डिफ़ॉल्ट के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़) में तरलता की समस्या, एक्सल लोड मानदंडों की घोषणा तथा बीमा और सुरक्षा मानदंडों का लागू होना। U_t एक विशेष प्रकृति की त्रुटियों का वेक्टर है।

इसी तरह के मॉडल का अनुमान (1) में वाणिज्यिक वाहनों (s_t) की बिक्री के बजाय उसके दीर्घकालिक रुझान से यात्री कारों की बिक्री के विचलन का उपयोग करके लगाया गया था।

दो वीएआरएक्स (चार्ट III.I.1) से आवेग प्रतिक्रिया कार्यों (आईआरएफ) से निकलने वाले प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

चार्ट III.I.1: आवेग प्रतिक्रिया क्रियाकलाप

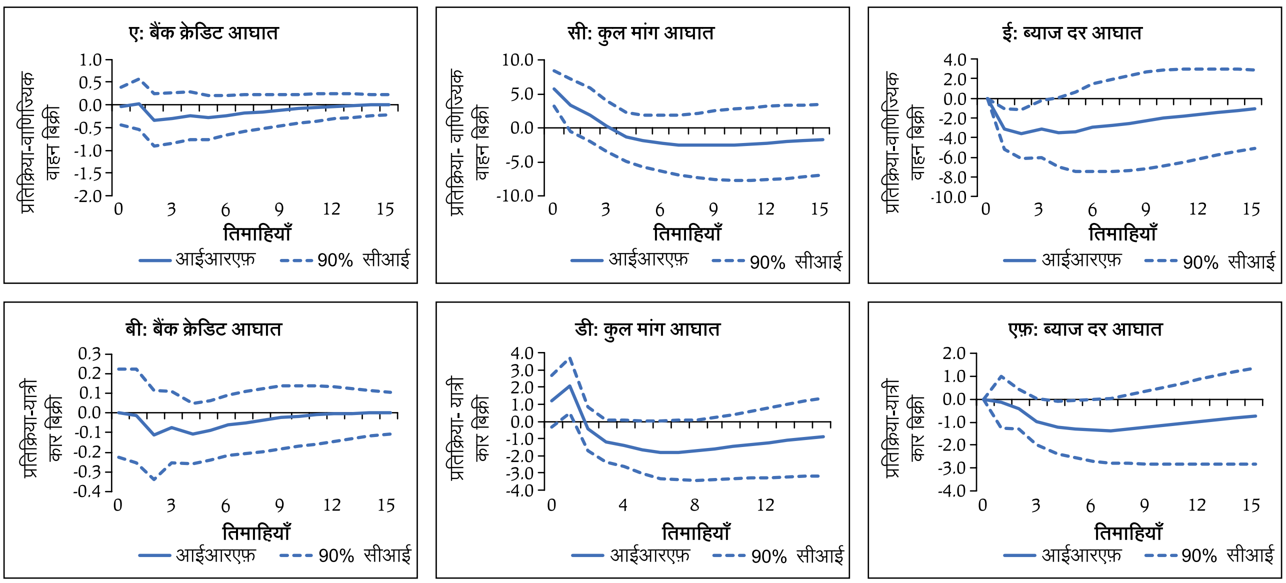

(जारी...)

[1] 2017-18 में विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में "परिवहन उपकरणों के निर्माण" का हिस्सा 12.0 प्रतिशत है और समग्र जीवीए का 2.1 प्रतिशत था।

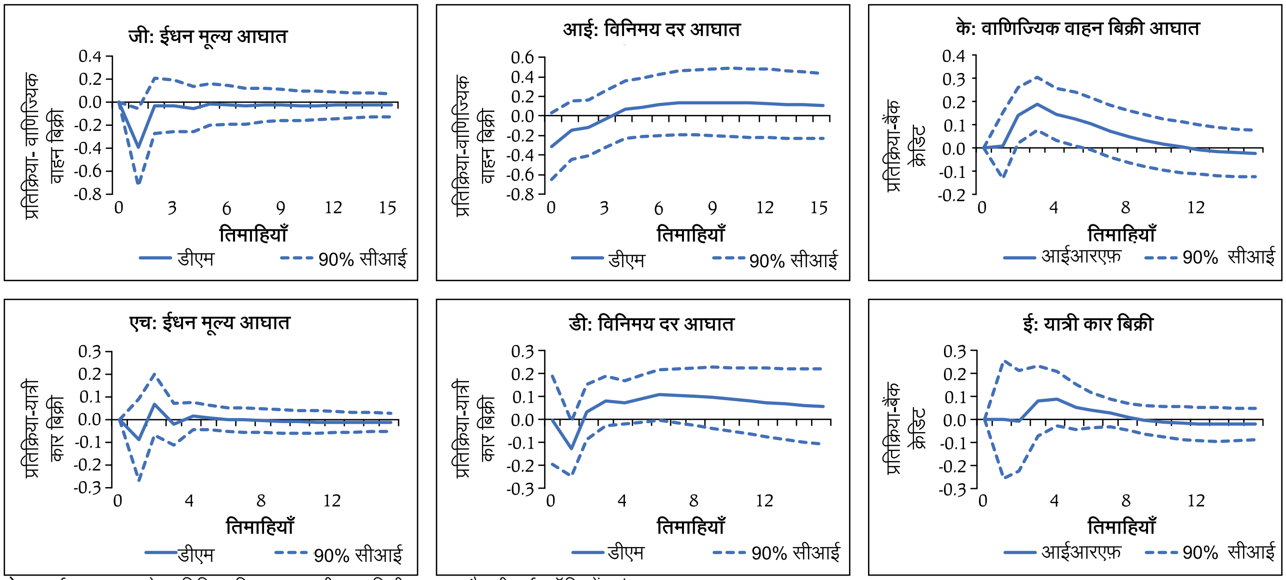

नोट: आईआरएफ़ - आवेग प्रतिक्रिया क्रियाकलाप, डीएम- गतिशील गुणक और सीआई- कॉन्फ़िडेंस इंटरवल

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(i) वाणिज्यिक वाहन और यात्री कार की बिक्री सकल मांग आघात के प्रति संवेदनशील हैं।

(ii) वाणिज्यिक वाहन और यात्री कार बिक्री दोनों ब्याज दरों में गिरावट के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।

(iii) ईंधन की कीमतों का वाणिज्यिक वाहन बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(iv) विनिमय दर मूल्यह्रास ऑटो बिक्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है ; और

(v) वाहन बिक्री पर बैंक ऋण का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है; हालाँकि, इसका उल्टा कारण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है अर्थात वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बैंक ऋण प्रवाह को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

चार्ट III.I.2: यात्री कार बिक्री - वैश्विक रुझान

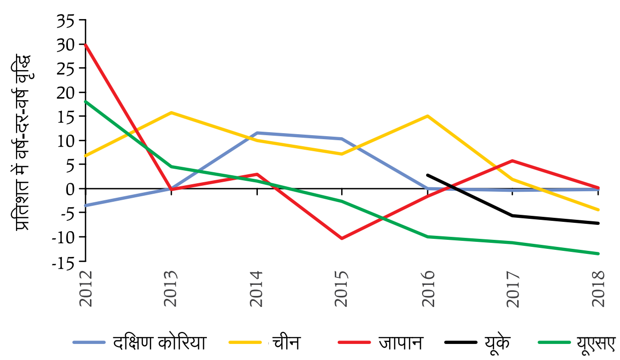

स्रोत : सीईआईसी।

तीन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए डमी (d_2) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं और वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में 10 प्रतिशत अंक और यात्री कार की बिक्री में 8 प्रतिशत अंक की गिरावट को स्पष्ट करती है।

मांग में गिरावट जैसे आघात, एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता संकट और सुरक्षा तथा बचाव मानदंडों को बढ़ाने के उपायों जैसे आघातों के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट आई है।

अमेरिका, यूरो क्षेत्र, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में विभिन्न कारणों से यात्री कार की बिक्री में सुस्ती देखी गई (चार्ट III.1.2)। वे हैं: (i) चीन और यूरो क्षेत्र में सख्त उत्सर्जन मानदंड; (ii) यूरो क्षेत्र में कार निर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्य बिक्री; (iii) धीमे वैश्विक विकास के कारण कमजोर मांग; और (iv) अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बढ़ने से डिगा उपभोक्ता विश्वास।

संदर्भ:

लुडविगसन, एस. (1998)। “द चैनल ऑफ मॉनीटरी ट्रांसमिशन टू डिमांड: ईविडेंस फ्राम द मार्केट फॉर ऑटोमोबाईल क्रेडिट”, जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग, 30 (3), पीपी. 365-383.

खरीफ खाद्यान्न उत्पादन - पिछले साल के स्तर से केवल 0.8 प्रतिशत नीचे - और आने वाले समय में मिट्टी में नमी की स्थिति और जलाशयों में अनुकूल स्तर के मद्देनजर रबी मौसम के लिए उज्ज्वल संभावनाएं ग्रामीण आय और मांग को उत्प्लावित कर सकती हैं।

III.1.2 सकल स्थिर पूंजी निर्माण

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में पिछली पांच तिमाहियों में जो दो अंकों में वृद्धि हुई थी वह वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही और वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में तेज़ी से घटी है। जीएफसीएफ में सकल मांग का हिस्सा जो एक वर्ष पहले 32.8 प्रतिशत था वह घटकर वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 32.5 प्रतिशत हो गया था। उच्च आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि निवेश संबंधी गतिविधियां दूसरी तिमाही में धीमी रही हैं। पूंजीगत वस्तुओं का आयात और उनका उत्पादन जुलाई में घट गया था (चार्ट III.7)। लेकिन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास के लिए दिए गए ऋण में तेज़ी बनी रही, जिससे यह ज्ञात होता है कि वहनीय आवास क्षेत्र के लिए नीति प्रेरक रही है।

रिज़र्व बैंक की आर्डर बुक, इन्वेंट्री तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) द्वारा की गई माप के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के 76.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 73.6 प्रतिशत हो गया है; लेकिन मौसम के हिसाब से समायोजित करके देखें तो चौथी तिमाही के 74.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 की पहली तिमाही में 74.8 प्रतिशत हो गया है (चार्ट III.8)। निजी क्षेत्र में रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घट गई है, जबकि पहली तिमाही में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की हालत थोड़ा और खराब हुई है (चार्ट III.9)।

निजी क्षेत्र में निवेश घट जाने के कारण 2011-12 से पूंजी निर्माण कम हो गया है (चार्ट III.10)। निजी क्षेत्र में निवेश की स्थिति को रेखांकित करके देखें तो ज्ञात होता है कि कारपोरेट डिलीवरेजिंग का सहारा ले रहे हैं जैसाकि बढ़ते हुए ब्याज-कवरेज अनुपात से पता चलता है (चार्ट III.11)।

चार्ट III.7: निवेश मांग के संकेतक

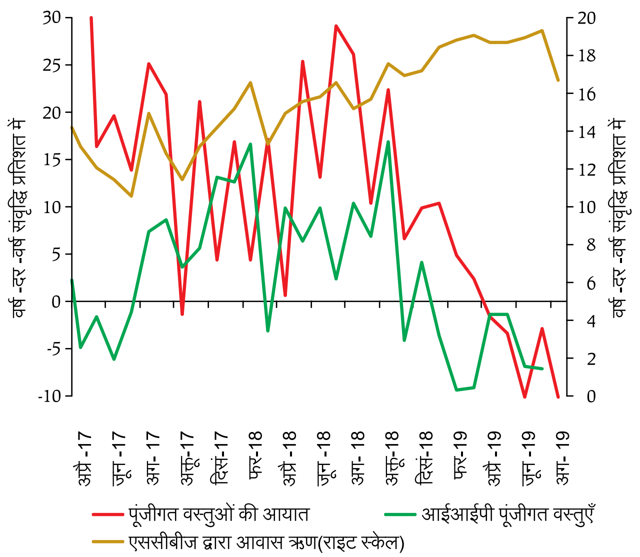

स्रोत : एनएसओ; डीजीसीआई एण्ड एस।

चार्ट III.8: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग

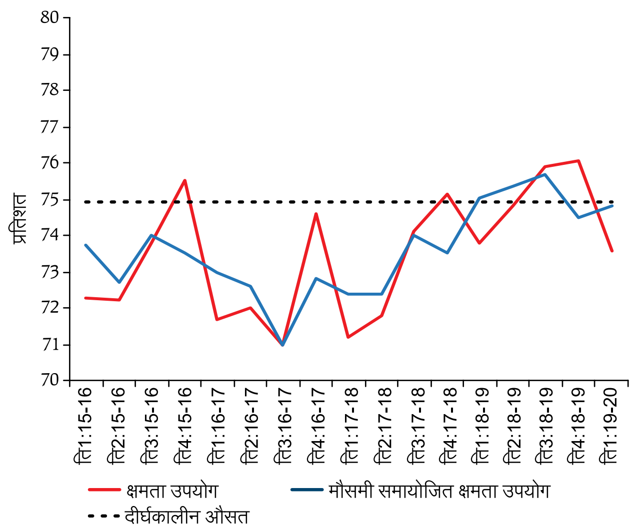

स्रोत : दीर्घकालीन औसत

चार्ट III.9 : ठप परियोजनाएं

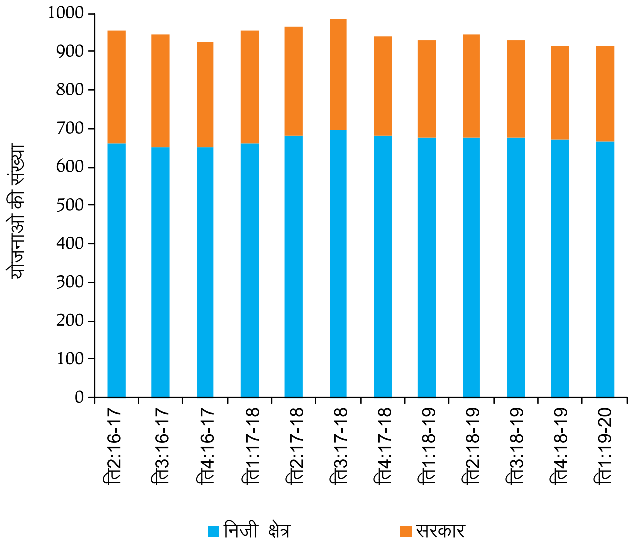

स्रोत : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई)।

चार्ट III.10: सकल पूँजी निर्माण – संस्थागत क्षेत्र विसमूहन

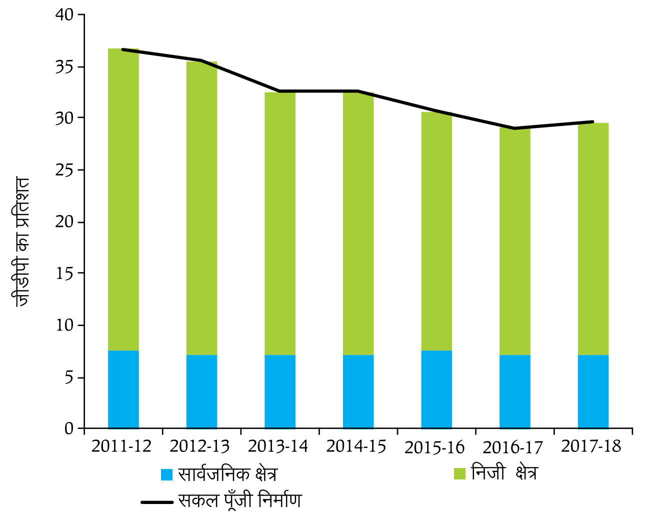

टिप्पणी : सकल पूंजी निर्माण में कीमती वस्तुएँ और त्रुटियां व चूक शामिल नहीं हैं|
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान |

चार्ट III.11: विनिर्माण और सेवा फर्मों में ब्याज कवरेज अनुपात(आईसीआर)

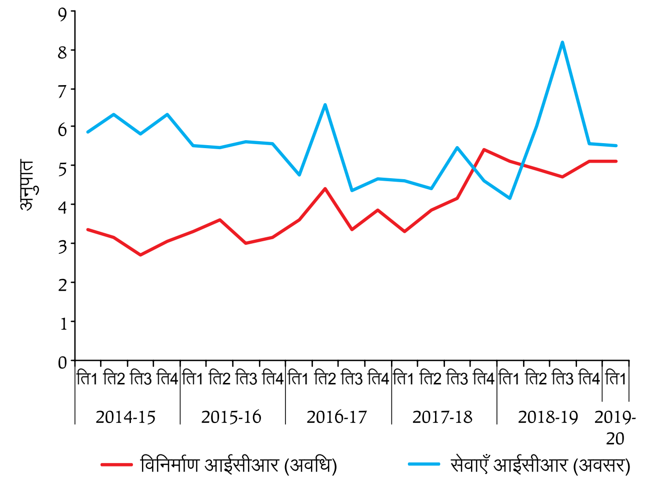

टिप्पणी: 2019-20 की पहली तिमाही का परिणाम 1723 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों और 660 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी सेवा कंपनियों पर आधारित है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान |

निवेश संबंधी गतिविधियों में पैदा हुई मंदी इस बात से भी पता चलती है कि बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर वित्तीय प्रवाह घट गया है (चार्ट III.12, विस्तृत जानकारी केलिए अध्याय IV देखें)।

III.1.3 सरकारी व्यय

सरकारी अंतिम उपभोक्ता व्यय (जीएफसीई) ने वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही और वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सकल मांग को सहारा प्रदान किया, जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। विशेष रूप से व्यय में वृद्धि में कमी के कारण अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि बजट अनुमान (बीई) के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) तथा राजस्व घाटा (आरडी) की स्थिति में सुधार हुआ है (सारणी III.2)। चालू राजकोषीय वर्ष में केंद्र सरकार का कुल व्यय अब तक राजस्व व्यय द्वारा संचालित रहा है।

चार्ट III.12: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

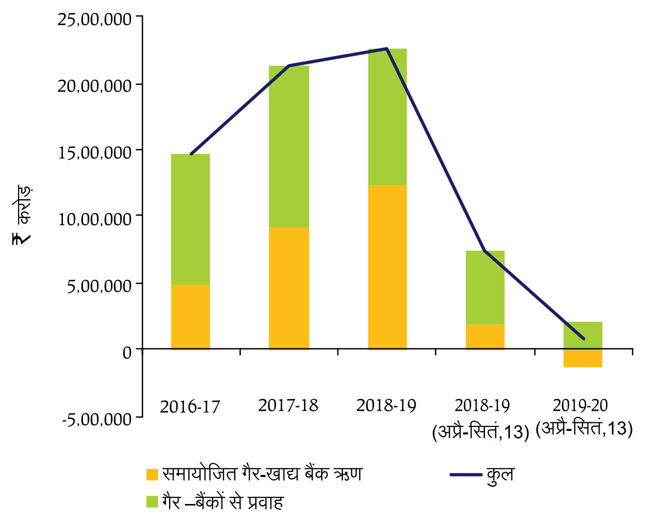

स्रोत : आरबीआई |

सारणी III.2: मुख्य राजकोषीय संकेतक – केंद्र सरकार (अप्रैल – अगस्त)

(प्रतिशत)

संकेतक	बीई के प्रतिशत के रूप में		वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि
	2018-19	2019-20	2019-20
1. राजस्व प्राप्तियाँ	26.9	30.7	29.8
a. कर राजस्व (निवल)	24.7	24.5	10.5
b. गैर-कर राजस्व	40.1	63.4	102.0
2. कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ	26.4	29.8	29.6
3. राजस्व व्यय	43.8	42.5	10.7
4. पूंजी व्यय	44.0	40.2	3.0
5. कुल व्यय	43.8	42.2	9.8
6. सकल राजकोषीय घाटा	94.7	78.7	-6.3
7. राजस्व घाटा	114.0	89.9	-8.1
8. प्राथमिक घाटा	767.7	773.4	-10.0

बीई : बजट अनुमान।
स्रोत : लेखा महानिदेशक;और संघीय बजट दस्तावेज़, 2019-20।

चार्ट III.13 : अप्रैल- अगस्त के दौरान कर वसूली

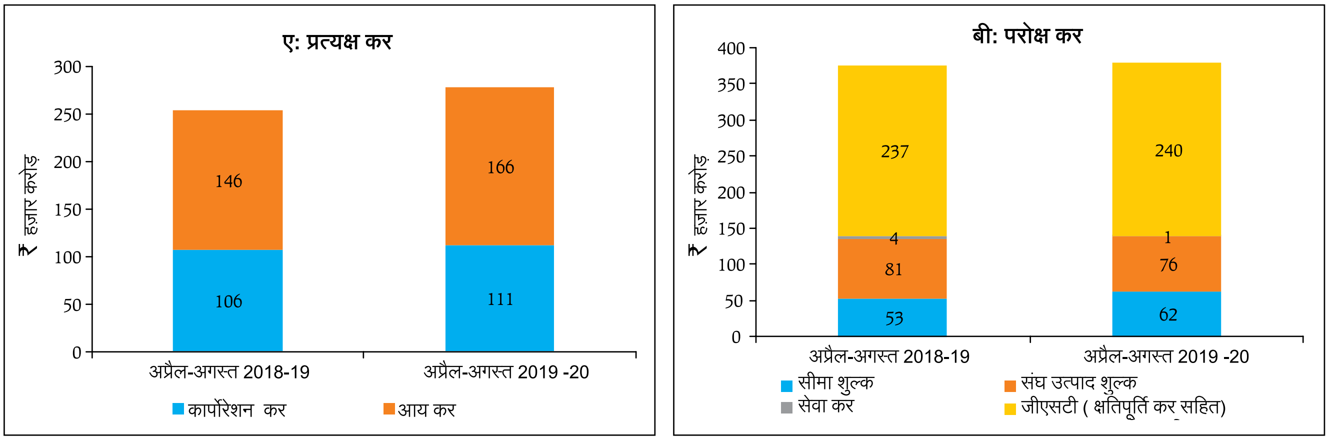

स्रोत : महालेखा नियंत्रक (सीजीए)|

व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने केलिए राजस्व का सृजन किया जाना महत्वपूर्ण है। प्राप्ति पक्ष की ओर, प्रत्यक्ष कर की वसूली के अंतर्गत – आय और कारपोरेशन कर दोनों – अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान खिंच से गए हैं (चार्ट III.3)।

महीना-दर-महीना उतार-चढ़ाव के बावजूद अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान जीएसटी की वसूली 4.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए समायोजन के कारण कुल जीएसटी राजस्व में राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से कहीं अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान आईजीएसटी वसूली के विभाजन के बाद भी सीजीएसटी वसूली का हिस्सा एसजीएसटी वसूली के हिस्से से काफी कम था। वे अगस्त 2019 में लक्ष्य प्राप्त करने से पहले लगातार आगे बढ़ता रहा (चार्ट III.14ए और 14बी)। हालांकि एसजीएसटी वसूली में राज्यवार काफी भिन्नता रही है, क्योंकि कुछ राज्यों में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है। इसकी खामियों को नियंत्रित करते हुए तथा आईटी संबंधी खराबी को दूर करते हुए जैसेकि सिस्टम द्वारा इनपुट कर जमा को विधिमान्य बनाने हेतु इनवाइस मैचिंग-सिस्टम लागू करने, भुगतान मॉड्यूल की परिचालनगत कमियों को दूर करके, जीएसटी अधिनियम तथा नियम के अनुरूप सिस्टम आधारित विधिमान्यीकरण और साथ ही सिस्टम डिज़ाइन की खामियों को दूर करते हुए जीएसटी की संभाव्यता को हासिल किया जा सकता है।[2]

चार्ट III.14: सीजीएसटी और एसजीएसटी का हिस्सा

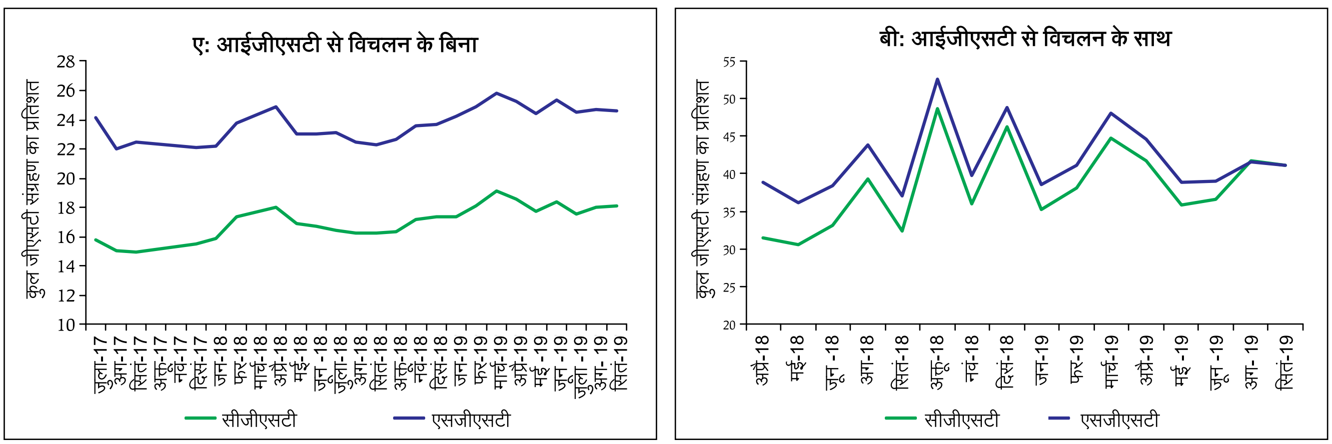

स्रोत : प्रेस आसूचना ब्यूरो, भारत सरकार|

2 प्रत्यक्ष कर से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट – मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वस्तु एवं सेवा कर, रिपोर्ट सं.11, जुलाई 2019।

गैर-कर राजस्व केंद्र सरकार के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान इस राजस्व में मजबूत वृद्धि देखी गई जब रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष का अंतरण किया गया। इसके अतिरिक्त विनिवेश के जरिये संसाधन जुटाने के प्रयासों से भी राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

व्यय पक्ष की ओर देखें तो 2019-20 की पहली तिमाही में राजस्व और पूंजी व्यय में थोड़ी सी कमी हुई है। हालांकि, चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में महत्वपूर्ण बढ़त हुई; बजट आबंटन का तकरीबन 40 प्रतिशत जुलाई 2019 माह में सड़कों और महामार्गों के संबंध में व्यय हुआ है। इसी तरह, 22 राज्यों की उपलब्ध जानकारी 2019-20 की पहली तिमाही में राजस्व व्यय में मंदी का संकेत देती है, जबकि जुलाई, 2019 में इसमें वृद्धि हुई।

राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटा के लक्ष्य का पालन करने केलिए अपने पूंजी खर्चों को घटा दिया है (चार्ट III.15)। इसके चलते निवेश पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, पूंजीगत व्यय गुणक की संवृद्धि दर को बढ़ाने वाली विशेषता को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि केंद्र और राज्य दोनों पूंजीगत खर्चों में तेज़ी लाएं। (भारिबैं, 2019)[3]। चालू वर्ष की शेष अवधि में सरकारी वित्त के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बजट किए गए पूंजी खर्चों तथा राजस्व-सृजन के लक्ष्यों का पालन करना रहेगा।

जहां तक राज्यों के प्रत्यक्ष करों का संबंध है, मुद्रांक-शुल्क की वसूली काफी हद तक निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है (चार्ट III.16)। इसलिए, निर्माण क्षेत्र में आने वाली मंदी, मुद्रांक-शुल्क की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

वर्ष 2008-09 से 2016-17 के दौरान जीडीपी 6 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद केंद्र और राज्यों की संयुक्त जीएफडी 2017-18 में 6.0 प्रतिशत से नीचे गिर गई। इसे 2018-19 (आरई) में 6.2 प्रतिशत और 2019-20 (बीई) में 5.9 प्रतिशत अनुमान किया गया है। केंद्र द्वारा संचालित सामान्य सरकार की बकाया देनदारियों को वर्ष 2018-19 में 69.8 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2019-20 तक सकल घरेलू उत्पाद का 69.6 प्रतिशत तक बजट करने का अनुमान है, हालांकि राज्यों में कर्ज बढ़ रहा है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में गिरावट दिखते हुए ब्याज भुगतान के साथ वर्ष 2018-19 में सामान्य सरकार की कर्ज चुकौती क्षमता में सुधार आया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान रिज़र्व बैंक ने योजनाबद्ध जारी कार्यक्रम के अनुसार अब तक केंद्र के बाजार उधार कार्यक्रम को प्रबंधित किया है। वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार का बजटीय बाजार उधार

चार्ट III.15: राज्यों के पूंजीगत परिव्यय

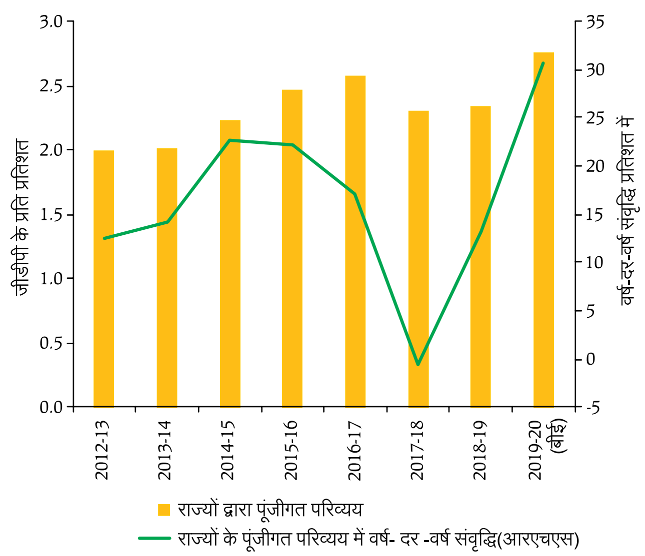

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज़; और एनएसओ।

चार्ट III.16: कंस्ट्रक्शन जी.वी.ए. और राज्य की स्टैम्प शुल्क वसूली

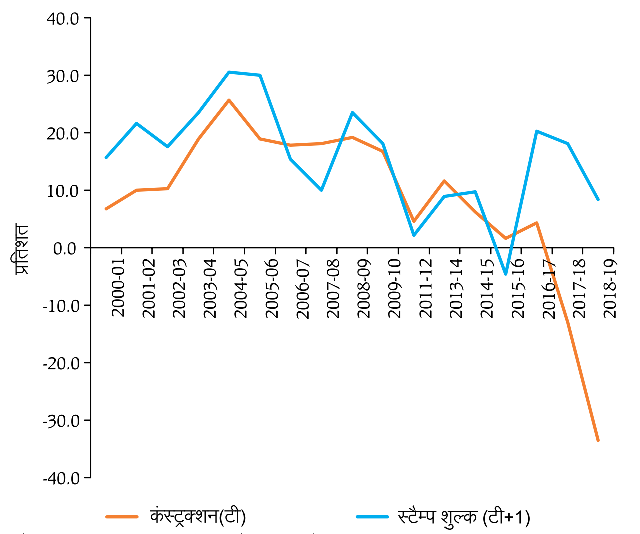

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज़; और एनएसओ।

3 भारतीय रिज़र्व बैंक (2019), "भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय गुणक", मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल पृ.सं. 35-37.

सारणी III.3: सरकारी बाज़ार उधार

(₹. बिलियन)

मद	2017-18			2018-19			2019-20 (सितंबर 30, 2019)		
	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
निवल उधार	4,48,410	3,40,281	7,88,691	4,22,737	3,48,643	7,71,380	3,40,972	1,56,447	4,97,419
सकल उधार	5,88,000	4,19,100	10,07,100	5,71,000	4,78,323	10,49,323	4,42,000	2,25,445	6,67,445

स्रोत : भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

₹7,10,000 करोड़ का है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24.3 प्रतिशत अधिक है। 30 सितंबर, 2019 (वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में 50.4 प्रतिशत) की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने बजटीय सकल उधार का 62.3 प्रतिशत पूरा किया (सारणी III.3)। केंद्रीय बजट 2019-20 में ₹ 50,000 करोड़ के बजट में प्रतिभूतियों की अदला-बदली जैसे समेकन के उपाय किए गए हैं, जिनमें से ₹ 40,109 करोड़ की प्रतिभूतियों को पहले ही स्विच किया जा चुका है। 30 सितंबर, 2019 तक राज्यों ने अपने बजटीय सकल उधार का 35.6 प्रतिशत पूरा किया है जबकि यह 2018-19 की इसी अवधि में 27.6 प्रतिशत था। राज्यों द्वारा बाजार उधार का एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है।

III.1.4 बाह्य मांग

पहली बार वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के उपरांत वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शुद्ध निर्यात का सकारात्मक योगदान रहा, क्योंकि आयात वृद्धि में धीमी गति निर्यात की तुलना में अधिक सुस्पष्ट थी।

वैश्विक व्यापार गति में निरंतर नुकसान ने भारत के व्यापारिक निर्यात को प्रभावित किया, जिससे कि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही और जुलाई-अगस्त 2019-20 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) और गैर-पीओएल श्रेणियों (चार्ट III.17ए) में संकुचन हुआ है। जिन सेक्टरों ने समग्र गिरावट में योगदान दिया है उनमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और गहने और चावल शामिल हैं। पीओएल निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है। इसके अतिरिक्त, जून 2019 में प्रमुख रिफाइनरियों के नियमित रखरखाव के संबंधित कामबंदी ने निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला (चार्ट III.18ए)।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में पीओएल संवृद्धि की गति में कमी और गैर-पीओएल गैर-स्वर्ण आयात में गिरावट के कारण आयात में कमी आई। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही (चार्ट III.18 बी) के दौरान सोने की कीमतों में कमी, शादी और त्योहारी सीजन की मांग में गिरावट के कारण सोने के आयात में उछाल देखा गया। गैर-पीओएल गैर-सोने के आयात में गिरावट परिवहन उपकरण, मोती और कीमती पत्थरों, धातु के अयस्क और वनस्पति तेल के आयात के रूप में व्यापक रूप से आधारित थी। जुलाई-अगस्त 2019 में

चार्ट III.17 माल और सेवाएँ व्यापार में संवृद्धि

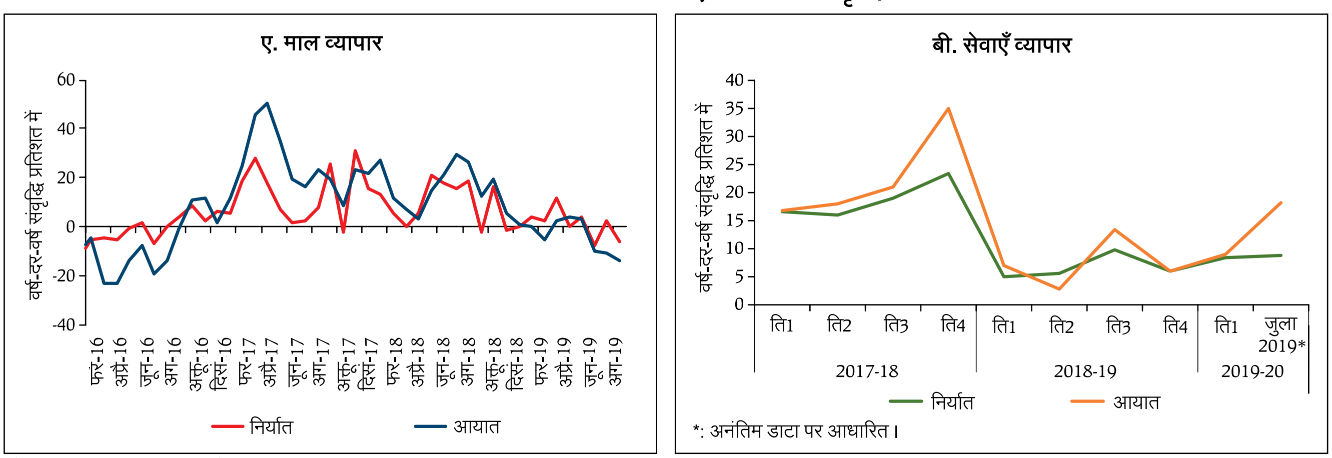

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस; और आरबीआई।

चार्ट III.18: माल निर्यात व आयात संवृद्धि के प्रति संबन्धित अंशदान

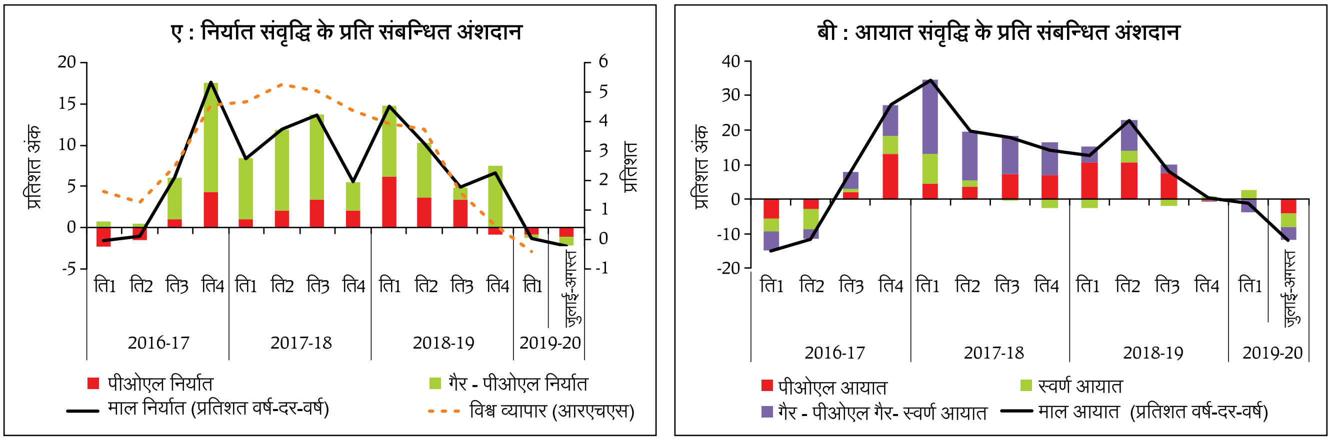

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान

आयात में व्यापक आधार पर संकुचन जारी रहा। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही 46.7 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 46.2 बिलियन अमरीकी डालर पर मॉडरेट रहा, हालांकि क्रमिक आधार पर अर्थात् वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में मामूली बढ़त देखी गई। निर्यात की तुलना में आयात में तेज गिरावट आई, हालांकि व्यापार घाटा जुलाई-अगस्त 2018-19 में 36.5 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में कम होकर 26.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यद्यपि चालू खाते में घाटे से वर्ष-दर-वर्ष और अनुक्रमिक दोनों ही आधारों पर व्यापार घाटे के चलन दिखाई दिए, तथापि 2018-19 की चौथी तिमाही में यह जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर एक प्रतिशत से भी नीचे था लेकिन 2019-20 की पहली तिमाही में यह बढ़कर जीडीपी के 2 प्रतिशत पर आ गया। व्यापार घाटे के 80 प्रतिशत से भी अधिक का वित्तपोषण अदृश्य मदों से हुआ, अर्थात सेवाओं का निवल निर्यात और धनप्रेषण। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2019-20 की पहली तिमाही में सेवाओं के निवल निर्यातों में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई – मुख्यतया इनका संचालन सॉफ्टवेयर, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं में हुआ (चार्ट III.17बी)। प्रमुख सूचना –प्रौद्योगिकी कम्पनियों के राजस्व में 2019-20 की पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सुधार हुआ वर्ष 2019 में कुल वैश्विक आई टी व्यय में 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। सन 2019-20 की पहली तिमाही में धनप्रेषण में मजबूती रही यद्यपि 2019-20 की पहली तिमाही में विदेशी निवेश पर उच्चतर लाभांशों के कारण आय-खाते के तहत भुगतानों का निवल बहिर्वाह बढ़ गया।

2019-20 की पहली तिमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के मिश्रण ने चालू खाते के घाटे को सहजता से पूरा कर दिया और आरक्षित निधियों में 14.0 बिलियन अमरीकी डालर का संचय हुआ। मार्च 2019 में आरंभ किए गए स्वैच्छिक प्रतिधारणा मार्ग (वीआरआर) के तहत आए प्रवाह सहित उच्चतर एफपीआई प्रवाहों ने बाह्य वित्तपोषण स्थितियों को सहज बना दिया। 2019-20 की पहली तिमाही में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के तहत सकल अन्तर्वाह 6.3 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि इसकी तुलना में यह एक साल पहले 1.5 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्वाह था। 2019-20 की पहली तिमाही में 13.9 बिलियन अमरीकी डालर का निवल एफडीआई भी एक वर्ष पहले के 9.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अधिक रहा। एकल ब्रान्ड की खुदरा बिक्री, संविदागत विनिर्माण और कोयला खनन क्षेत्रों में एफडीआई के लिए मानदंडों को सहज बनाने से एफडीआई के अन्तर्वाह को समर्थन संभावित है और यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की सहभागिता को मजबूत करेगा। जुलाई और अगस्त 2019 में इक्विटी खंड से बहिर्वाहों के बावजूद अप्रैल सितंबर 2019 के दौरान हमारे घरेलू पूंजी बाजार में निवल एफपीआई खरीददारी 3.3 बिलियन अमरीकी डालर रही, इसकी तुलना में एक साल पहले 11.5 बिलियन अमरीकी डालर बाहर गए थे। 2019-20 की पहली तिमाही में अनिवासी डिपॉजिटों के तहत निवल प्रवाह में बहुत मजबूती रही। भारत की फोरेक्स विनिमय आरक्षित निधियां 1 अक्तूबर 2019 को 434.6 बिलियन अमरीकी डालर पर रही जो मार्च 2019 के अंत में वर्ष 21.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़ोतरी है।

III.2 सकल आपूर्ति

आपूर्ति पक्ष को देखें तो 2018-19 की चौथी तिमाही में सकल मूल्यवर्धित संवृद्धि गिरकर 5.7 प्रतिशत पर रही और इसके बाद 2019-20 की पहली तिमाही में और भी गिरकर इक्कीस तिमाहियों में न्यूनतम 4.9 प्रतिशत पर आ गई (तालिका III.4)। मौसमी आधार पर समायोजित तिमाही-दर तिमाही की वार्षिकीकृत संवृद्धि के रूप में आकालित जीवीए की गति भी पहली तिमाही में तेजी से कम हुई (चार्ट III.19)।

जीवीए संवृद्धि की गति में कमी का कारण (वर्ष-दर-वर्ष) रहा 2019-20 की पहली तिमाही में सेवाओं की संवृद्धि में महत्वपूर्ण गिरावट होकर इसका 6.7 प्रतिशत रह जाना, जबकि 2018-19 की चौथी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत पर था, यह गिरावट भवन-निर्माण और 'वित्तीय, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवाओं' के कारण रही। 2011-12 की श्रृंखला[4] में विनिर्माण क्षेत्र ने द्वितीय न्यूनतम संवृद्धि दर्ज की। कुछ गिरावट के बावजूद लोक-प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में अच्छी दर से बढ़ोतरी हुई। यदि पीएडीओ को छोड़ते तो जीवीए संवृद्धि गिरकर 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.0 प्रतिशत और 2019-20 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर रह गई होती (चार्ट III.20)। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबद्ध सेवाओं की संवृद्धि में अनुक्रमिक रूप से बढ़ोतरी रही।

चार्ट III.19: जीवीए संवृद्धि - वर्ष-दर-वर्ष और तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर

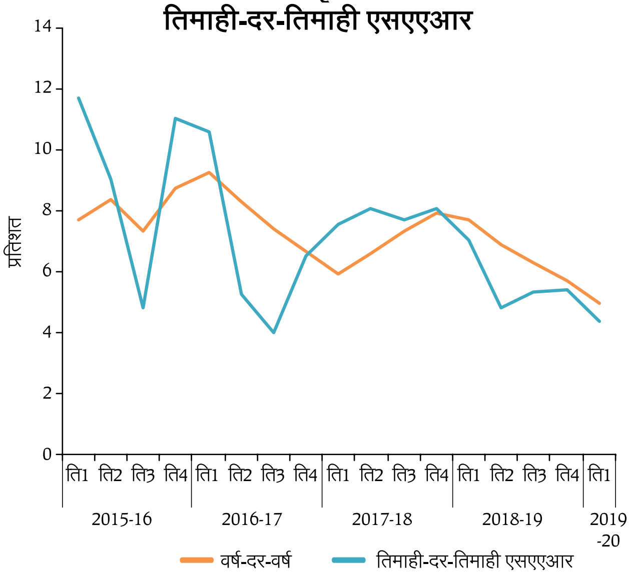

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.2.1 कृषि

2019-20 की पहली तिमाही में रबी की मौसम में गेहूं और तिलहनों के उच्चतर उत्पादन के बलबूते पर कृषि और सहायक क्रियाकलापों का मूल्य-वर्धन विगत तिमाही के संकुचन से बाहर निकला। सन 2018-19 के लिए तृतीय उन्नत अनुमानों के अनुसार इसे उच्चतर बागवानी उत्पादन में 0.7 प्रतिशत की

सारणी III.4: जीवीए में क्षेत्र-वार संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18 (एफआरई)	2018-19 (पीई)	भारित योगदान		2017-18 (एफआरई)				2018-19 (पीई)				2019-20
			2017-18	2018-19	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
कृषि,फोरेस्टरी और फिशिंग	**5.0**	**2.9**	0.8	**0.4**	**4.2**	**4.5**	**4.6**	**6.5**	**5.1**	**4.9**	**2.8**	**-0.1**	**2.0**
उद्योग	**6.1**	**6.2**	**1.4**	**1.4**	**-0.1**	**7.7**	**8.0**	**8.6**	**9.9**	**6.1**	**6.0**	**3.4**	**1.7**
खनन तथा उत्खनन	5.1	1.3	0.2	0.0	2.9	10.8	4.5	3.8	0.4	-2.2	1.8	4.2	2.7
विनिर्माण	5.9	6.9	1.1	1.2	-1.7	7.1	8.6	9.5	12.1	6.9	6.4	3.1	0.6
विद्युत,गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोज्यता	8.6	7.0	0.2	0.2	8.6	9.2	7.5	9.2	6.7	8.7	8.3	4.3	8.6
सेवाएँ	**7.8**	**7.7**	**4.8**	**4.8**	**8.6**	**6.5**	**8.0**	**8.0**	**7.5**	**7.5**	**7.6**	**8.2**	**6.7**
निर्माण	5.6	8.7	0.5	0.7	3.3	4.8	8.0	6.4	9.6	8.5	9.7	7.1	5.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	7.8	6.9	1.5	1.3	8.3	8.3	8.3	6.4	7.8	6.9	6.9	6.0	7.1
वित्त, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ	6.2	7.4	1.4	1.6	7.8	4.8	6.8	5.5	6.5	7.0	7.2	9.5	5.9
लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	11.9	8.6	1.5	1.1	14.8	8.8	9.2	15.2	7.5	8.6	7.5	10.7	8.5
मूल कीमतों पर जीवीए	**6.9**	**6.6**	**6.9**	**6.6**	**5.9**	**6.6**	**7.3**	**7.9**	**7.7**	**6.9**	**6.3**	**5.7**	**4.9**

एफआरई : पहला संशोधित अनुमान; पीई: अनंतिम अनुमान।
स्रोत: एनसओ।

[4] विनिर्माण में सबसे कम वृद्धि 2017-18 की पहली तिमाही में दर्ज की गई, संभवत: यह वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू करने का संक्रमणकाल प्रभाव था।

चार्ट III.20: जीवीए संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर)

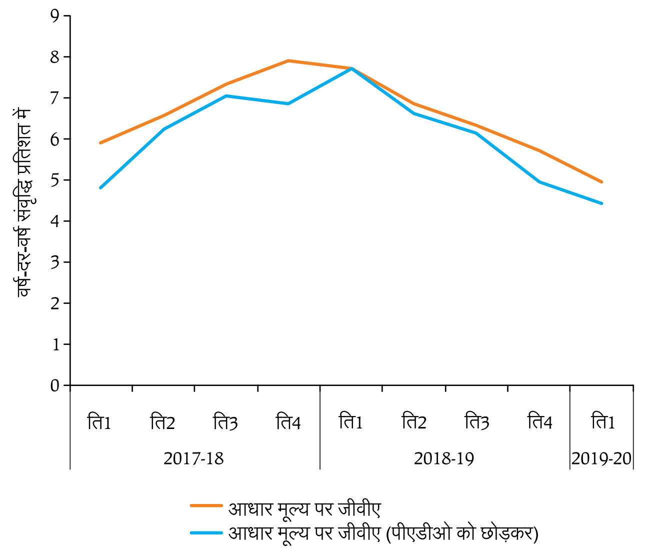

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.21: दक्षिण-पश्चिमी मानसून वर्षा की संचयी साप्ताहिक प्रगति (प्रतिशत)

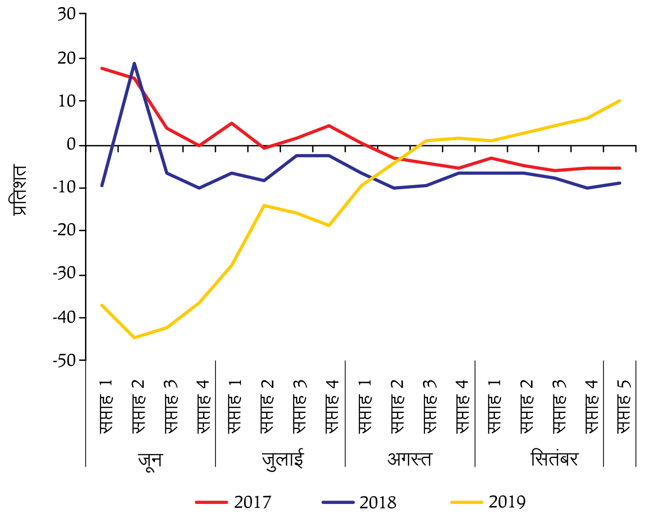

स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी)।

बढ़ोतरी से 3,138 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन का समर्थन भी मिला।

वर्ष 2018-19 के लिए कृषि उत्पादन के संबंध में अगस्त में जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन 2850 लाख टन बताया गया था – यही अनुमान पिछले वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम रूप से किया गया अनुमान था, लेकिन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 2903 लाख टन से कम था। दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्व मानसून खराब रहने के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ था, खास तौर से *रबी* मौसम की फसलों के लिए क्योंकि इनमें से अधिकांश फसलों ने उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य खो दिया था। जो भी हो, चावल, गेहूं और गन्ने का उत्पादन वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक हुआ था।

वर्ष 2019 में, दक्षिण-पश्चिम मानसून एक सप्ताह विलंब से शुरू हुआ था और *वायु* तूफान की वजह से मानसून पूरे दक्षिणी एवं मध्य भारत में बढ़ने से बाधित रहा। फलस्वरूप, जून में दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 36 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी। मानसून ने जुलाई से रफ्तार पकड़ा। महीने की शुरुआत में हुई भारी वर्षा ने उसकी कुल कमी को महीने के अंत तक एलपीए से 9 प्रतिशत कम के स्तर तक ला दिया (चार्ट III.21)। सम्पूर्ण भारत में 30 सितंबर, 2019 को हुई कुल वर्षा एलपीए से 10 प्रतिशत अधिक थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कुल वर्षा एलपीए स्तर से 9 प्रतिशत कम हुई थी। वर्षा के वितरण की दृष्टि से देखें तो 12 उप-प्रभागीय क्षेत्रों (पिछले वर्ष के 1 उप-प्रभागीय क्षेत्र की तुलना में) में बेशी वर्षा हुई, 19 में (पिछले वर्ष के 23 उप-प्रभागीय क्षेत्र की तुलना में) सामान्य वर्षा हुई, और 5 उप-प्रभागीय क्षेत्र (पिछले वर्ष के 12 उप-प्रभागीय क्षेत्र) में कम वर्षा हुई (चार्ट III.22)। अगस्त मध्य से लेकर सितम्बर तक हुई प्रचुर वर्षा ने (26 सितम्बर 2019 तक) 113 जलाशयों के भर जाने के भंडारण स्तर को और भी बढ़ा दिया था और पिछले वर्ष की इसी

चार्ट III.22: उप-प्रभाग वार तुलनात्मक वर्षा स्थिति (सितंबर 30, 2019 तक)

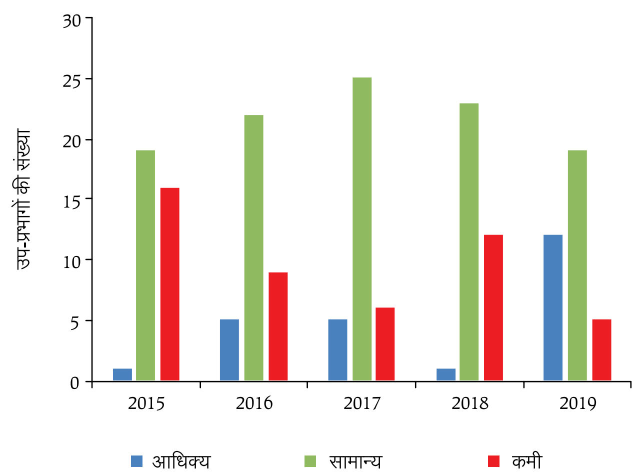

स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी)|

चार्ट III.23: उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) – कुल और फसल-वार

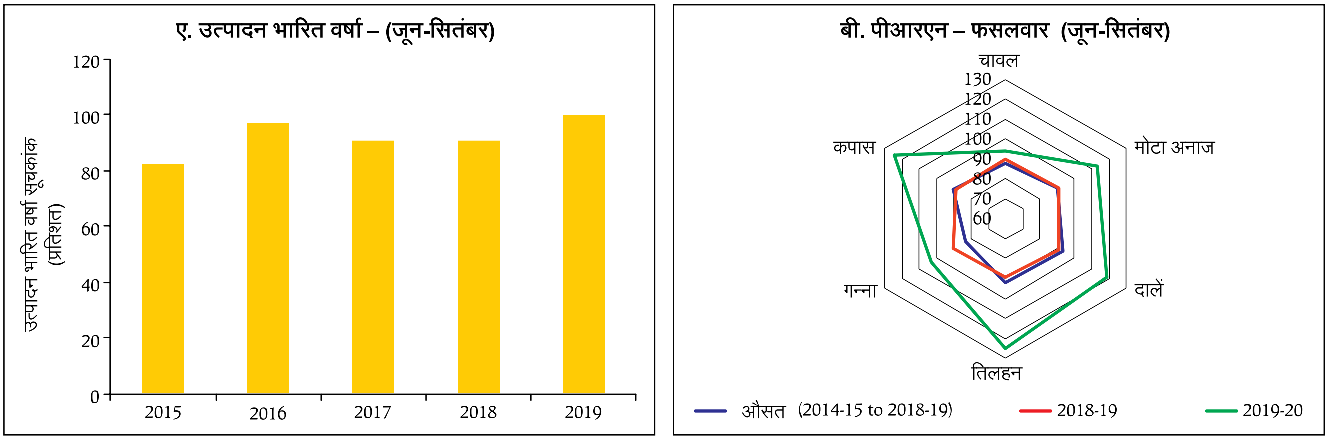

स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अवधि की तुलना में जल-भंडारण का स्तर कुल जलाशयों में 115 प्रतिशत अधिक था।

उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक[5] (पी आर एन) भी एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक था और चावल को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख फसलों के लिए 'सामान्य' अथवा 'सामान्य से अधिक' था (चार्ट III.23)।

मानसून शुरू होने में प्रारम्भ में जो देरी हुई उसके कारण खरीफ की बुवाई धीमी रही और अधिकांश फसलों की बुवाई का एकड़ पिछले वर्ष बुवाई किए गए क्षेत्र से कम था। 28 जून 2019 तक खरीफ फासला के अंतर्गत बुवाई का कुल क्षेत्र एक वर्ष पहले की तुलना में 9.5 प्रतिशत कम था। लेकिन उसके बाद, पूरे देश में अप्रत्याशित तेज़ी आई और खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा के चलते बुवाई में सुधार आया। फलस्वरूप, 27 सितम्बर 2019 को कुल बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष के औसत बुवाई क्षेत्र से आगे निकल गया (चार्ट III.24ए)। अलग-अलग स्तर पर देखें तो सभी फसलों में बुवाई क्षेत्र बढ़ गया था तथा कपास और दालों के संबंध में बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई थी (चार्ट III.24बी)।

खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए पहले अग्रिम अनुमान ने खाद्यान्न उत्पादन 1406 लाख टन रखा

चार्ट III.24: खरीफ फसलों की बुवाई प्रगति

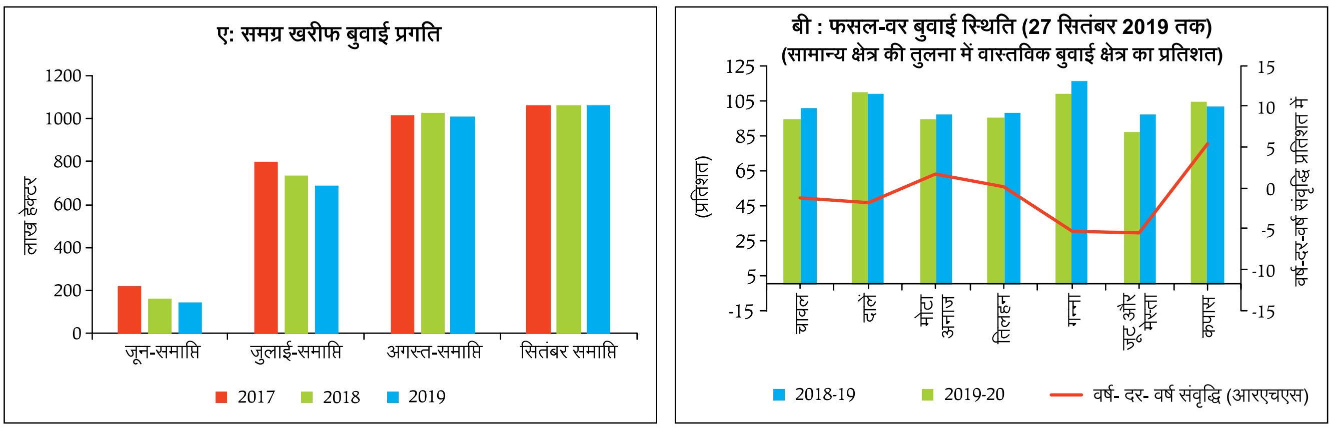

स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

[5] फसल के लिए (कुल खाद्यान्न) अखिल भारतीय उत्पादन-भारित सूचकांक (पी आर एन) का आकलन राज्यवार वास्तविक वर्षा और आईएमडी सामान्य वर्षा के भारित औसत के अनुपात के रूप में किया जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस्तेमाल किए गए भारांक पाँच वर्ष के राज्यवार फसल (कुल खाद्यान्न) उत्पादन के औसत हिस्से पर आधारित होता है।

है, जो पिछले वर्ष के स्तर से 0.8 प्रतिशत कम है, जिससे मानसून के विलंब से शुरू होने एवं विभिन्न राज्यों में तीव्र वर्षा तथा सैलाब का होना परिलक्षित होता है। लेकिन, कमर्शियल फसलों में तिलहन, कपास, जूट, तथा मेस्ता का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक हुआ है।

वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम के लिए घोषित एमएसपी से यह सुनिश्चित हो सकेगा की सभी फसलों के उत्पादन लागत (ए2 और एफएल6 का योग) का कम से कम 50 प्रतिशत वापस मिल जाएगा (सारणी III.5)। लेकिन, वर्ष 2019-20 में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य की तुलना में कम था (1.1-9.2 प्रतिशत के दायरे में) इसकी तुलना में वर्ष 2018-19 में यह दायरा 3.7-52.5 प्रतिशत था। जहां एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सोयाबीन (9.2 प्रतिशत), उसके बाद रागी के लिए (8.7 प्रतिशत) थी, वहीं नाइजर बीजों (1.1 प्रतिशत) तथा मूंग के लिए (1.1 प्रतिशत) सबसे कम थी।

III.2.2 उद्योग

औद्योगिक गतिविधियों में जो मंदी वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में आ गई थी वह वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में और गहरा गई (चार्ट III.25)। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में विनिर्माण जीवीए में आई तीव्र गिरावट निश्चित रूप से संगठित क्षेत्र की कमज़ोरियों को प्रदर्शित करती है। लेकिन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन पिछली तिमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बेहतर हुआ है। जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन और बढ़ा है (चार्ट III. 26)।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार अर्धनिर्मित वस्तु क्षेत्र लगातार तीन महीने जुलाई 2019 तक दो अंकों में बढ़ता रहा है, यह बढ़त विशेष रूप से हलकी इस्पात की शिलाओं के उत्पादन से संचालित रही है। उपभोक्ता की गैर-टिकाऊ वस्तुओं में भी वृद्धि हुई है जिसे सूर्यमुखी बीज के तेल का सहारा प्राप्त हुआ है लेकिन पूंजीगत वस्तुओं में भी वृद्धि हुई है जिसे सूर्यमुखी बीज के तेल का सहारा प्राप्त हुआ है।

सारणी III.5: न्यूनतम समर्थन मूल्य - *खरीफ* मौसम की फसलें

फसलें	₹/क्विंटल)			संवृद्धि दर (प्रतिशत)		लागत पर 2018-19 में लाभ (प्रतिशत)	लागत पर 2019-20 में लाभ (प्रतिशत)
	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 से ऊपर 2017-18	2019-20 से ऊपर 2018-19		
धान सामान्य	1550	1750	1815	12.9	3.7	50.1	50.2
धान (एफ) / ग्रेड 'ए'	1590	1770	1835	11.3	3.7	51.8	51.9
ज्वार–हाइब्रिड	1700	2430	2550	42.9	4.9	50.1	50.2
ज्वार-मालदंडी	1725	2450	2570	42.0	4.9	51.3	51.4
बाजरा	1425	1950	2000	36.8	2.6	97.0	84.7
रागी	1900	2897	3150	52.5	8.7	50.0	50.0
मक्का	1425	1700	1760	19.3	3.5	50.3	50.3
तूर (अरहर)	5450	5675	5800	4.1	2.2	65.4	59.5
मूंग	5575	6975	7050	25.1	1.1	50.0	50.0
उड़द	5400	5600	5700	3.7	1.8	62.9	63.9
मूंगफली	4450	4890	5090	9.9	4.1	50.0	50.0
सूरजमुखी के बीज	4100	5388	5650	31.4	4.9	50.0	50.0
सोयाबीन पीला	3050	3399	3710	11.4	9.2	50.0	50.0
तिल	5300	6249	6485	17.9	3.8	50.0	50.0
निगरसीड	4050	5877	5940	45.1	1.1	50.0	50.0
मीडियम स्टेपल कपास	4020	5150	5255	28.1	2.0	50.0	50.1
लोंग स्टेपल कपास	4320	5450	5550	26.2	1.8	58.8	58.5

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

[6] ए2 एवं एफ एल के योग में शामिल हैं सभी प्रकार की अदा की गई लागतें जैसे किराये पर लिए गए श्रमिक, मशीनें, पट्टे पर ली गई ज़मीन का अदा किया गया किराया, बीज, खाद, सिंचाई प्रभार, मूल्यह्रास तथा अधिरोपित पारिवारिक श्रम मूल्य।

[7] असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में तिमाही जीवीए अनुमान दर्शाने के लिए आईआईपी उपयुक्त गणक स्तर का इस्तेमाल किया गया है।

चार्ट III.25: उद्योग जीवीए की संवृद्धि में भारित अंशदान

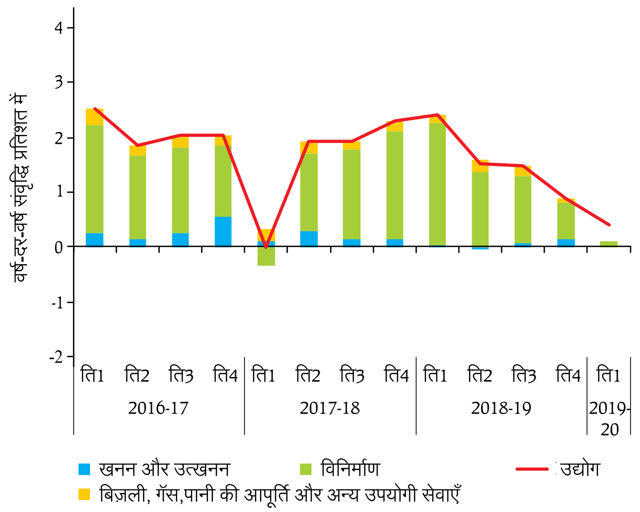

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.26: आईआईपी संवृद्धि के प्रति क्षेत्रीय योगदान

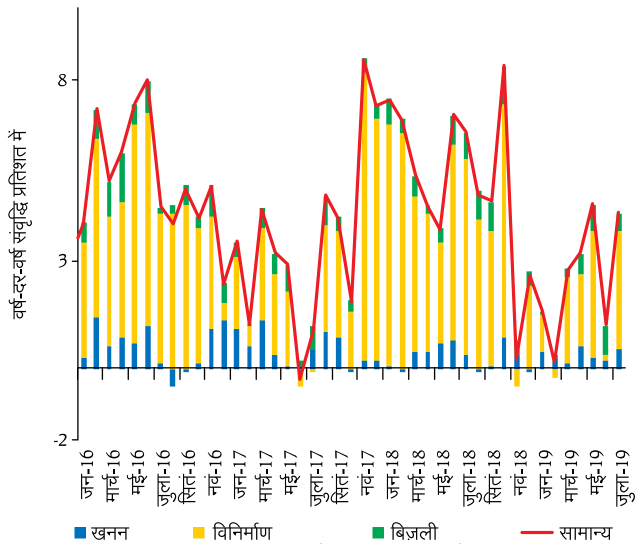

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान | खनन

लेकिन, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन लगातार नौ महीने से घटता रहा है, जिसका कारण कमर्शियल वाहन, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर्स, प्रिंटिंग मशीनरी,जनरेटर तथा ब्वायलर के उत्पादन में गिरावट रही है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में लगातार दो महीने से गिरावट होती रही है, जो ऑटो उपकरणों तथा दुपहिया वाहनों के उत्पादन में कमी होने से हुई है (चार्ट III. 27)।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन बढ़ गया क्योंकि गर्मी में मांग अधिक थी और मानसून विलंब से शुरू हुआ था। मौसमी दबाव कम होने के साथ विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखा जाए तो जुलाई में कम था (चार्ट III. 28)।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में विनिर्माण जीवीए में गिरावट विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि में भी दिखाई दी, जो मुख्यतया ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम तथा लोहा और इस्पात की कम बिक्री द्वारा नीचे की ओर खिंच गई (चार्ट III. 29)। बिक्री में धीमापन कर के पहले होने वाले लाभ में तीव्र गिरावट में भी दिखाई दी (चार्ट III.30)। सीमेंट, फार्मास्युटिकल्स तथा रसायन कंपनियों की बिक्री में कुछ आशा जगी जो 2019-20 की पहली तिमाही में जारी रही।

हाल के समय में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का समग्र कारोबारी मनोभाव क्षीण हुआ है। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आई

चार्ट III.27: आईआईपी और उपयोग-आधारित वर्गीकरण

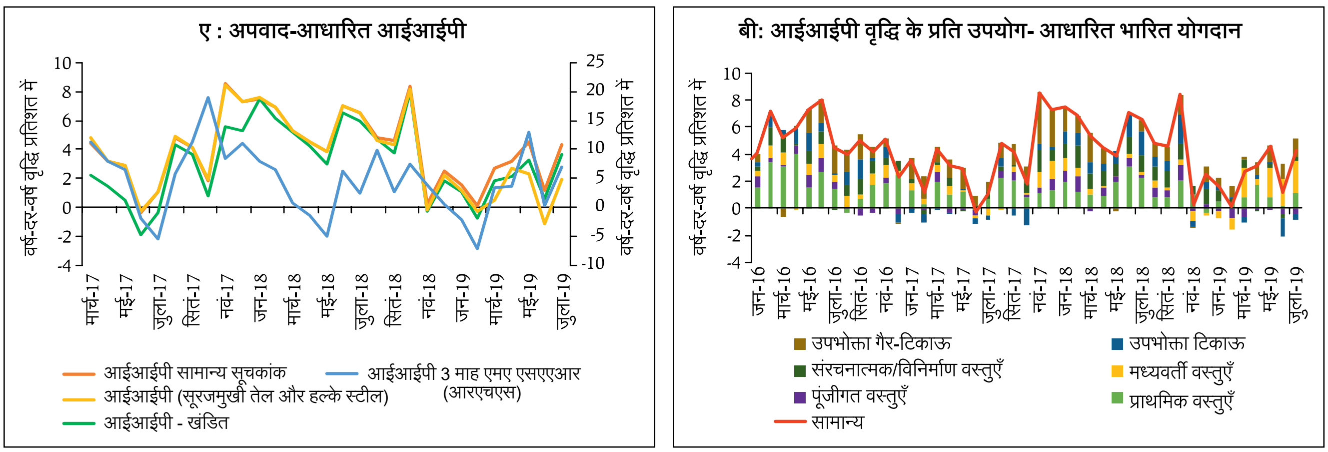

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.28: विभिन्न स्रोतों द्वारा बिजली निर्माण

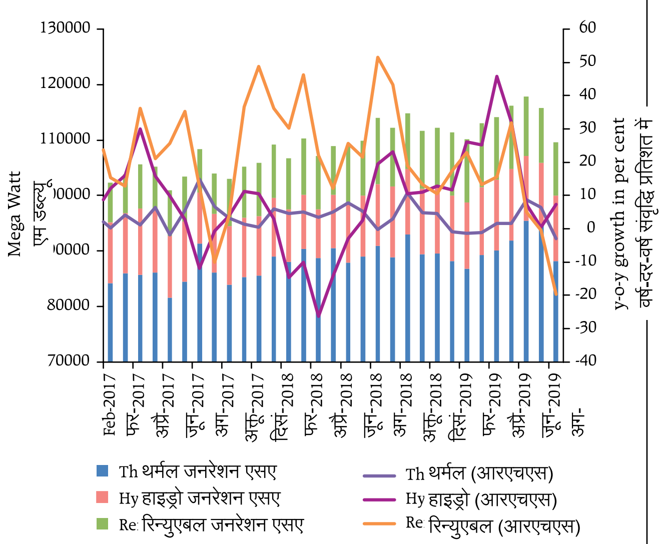

स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए)।

चार्ट III.29: औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में सांकेतिक बिक्री वृद्धि

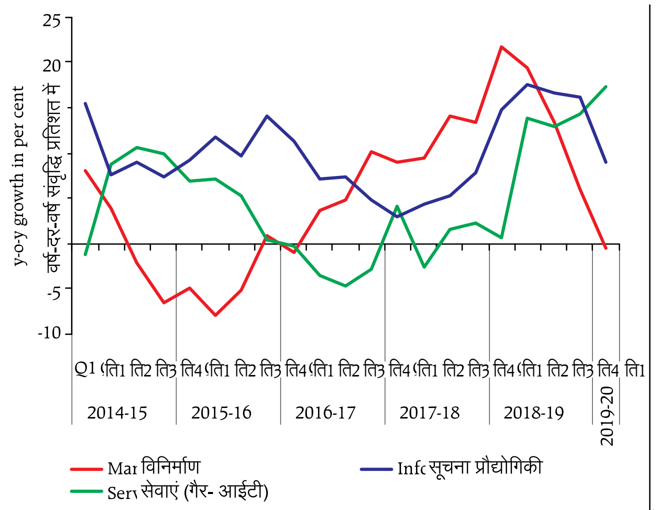

टिप्पणी : 2019-20 की पहली तिमाही का परिणाम 1,723 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों और 660 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी सेवा कंपनियों पर आधारित है।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान|

ओ एस) के 87 वें चक्र में कारोबारी मूल्यांकन सूचकांक (बीईआई) 2018-19 की दूसरी तिमाही में गिरकर 92.5 (2019-20 की पहली तिमाही में 108.4 से) हो गया, ऐसा नए क्रम में गिरावट, उत्पादन में कमी, क्षमता से कम उपयोग और सर्वे की गई फार्मों की लाभ मार्जिन में गिरावट के कारण हुआ। लेकिन, कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 102.2 (2019-20 की दूसरी तिमाही में 112.8 से) हो गया था। सितम्बर 2019 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अपने पिछले महीने के स्तर पर बना रहा जबकि नया क्रम और रोजगार में सुधार हुआ यद्यपि नए आयात क्रम में मामूली गिरावट आई।

चार्ट III.30: विनिर्माण जीवीए के घटक

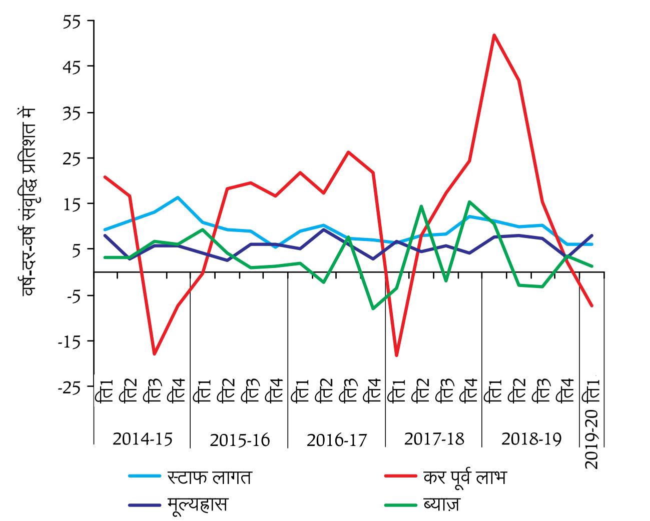

टिप्पणी : 2019-20 की पहली तिमाही का परिणाम 1,723 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों पर आधारित है|
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.2.3 सेवाएं

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में वृद्धि पिछली सात तिमाहियों में सबसे कम थी, जो वित्तीय, स्थावर संपदा एवं प्रोफेशनल सेवाओं, निर्माण गतिविधियों द्वारा नीचे खींच ली गई। पीएडीओ वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सुदृढ़ दर से बढ़ी और समग्र सेवाओं में जीवीए की खोई हुई गति को सहारा प्रदान किया। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाओं ने गति बनाए रखी, हालांकि हाल के समय में परिवहन सेवा संकेतक अत्यधिक कमज़ोर पड़ गए हैं। जुलाई-अगस्त में कमर्शियल वाहन, सवारी वाहन तथा दुपहिया वाहन की बिक्री में तीव्र गिरावट पैदा हुई है। घरेलू वायु सवारी की स्थिति अगस्त में बढ़ गई। जहां जुलाई में रेल यात्रियों की संख्या घट गई थी,वहीं घरेलू वायु कार्गो की वृद्धि में अगस्त में सुधार हुआ (चार्ट III. 31 ए व बी)। लेकिन, सेवा पीएमआई की जून में गिरावट की स्थिति उलट गई और जुलाई तथा अगस्त में उसने विस्तार पैदा हुआ।

चार्ट III 31: परिवहन संकेतकों का कार्य

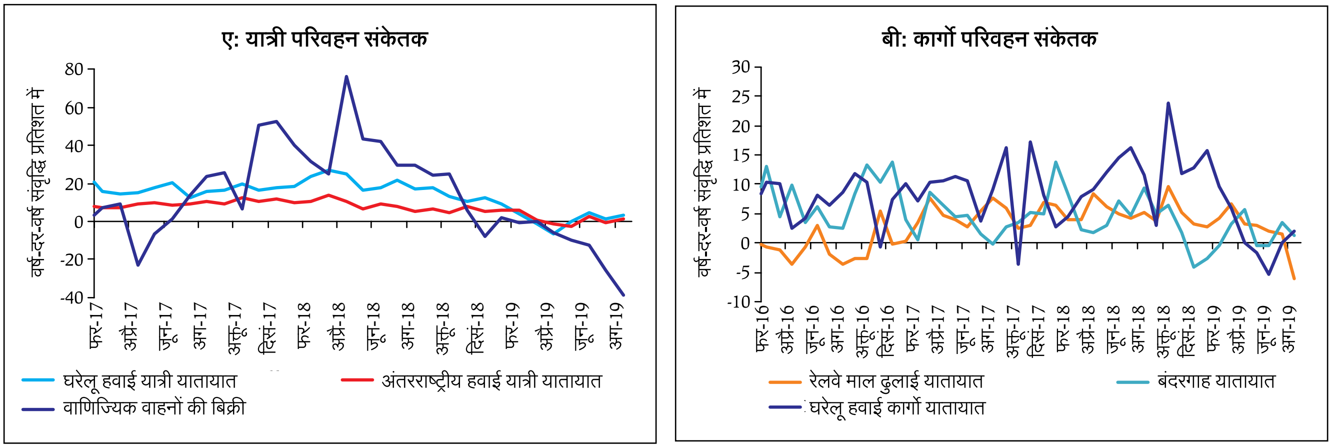

स्रोत: एसआईएएम; रेल मंत्रालय; इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण।

निर्माण गतिविधियों के दो प्रमुख संकेतकों में से, सीमेंट का उत्पादन अगस्त में कम होने से पूर्व जुलाई में तेजी से बढ़ा जिससे पिछले महीने की गिरावट की स्थिति उलट गई। जबकि, तैयार इस्पात का उपभोग जुलाई-अगस्त में मंद पड़ गया था (चार्ट III. 32)। आगे चलकर, घरेलू स्तर पर इस्पात की नरम कीमतों के कारण इस्पात का उपभोग मज़बूत होने की संभावना है।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में पीएडीओ वृद्धि क्रमश: मंद पड़ती गई, जिससे यह पता चलता है कि चुनाव से पूर्व संघ और राज्य सरकारों का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को घटाकर) धीमा था। "वित्तीय, स्थावर संपदा तथा प्रोफेशनल सेवाओं में वृद्धि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कम हो गई थी, जिसका मुख्य कारण सूचीबद्ध स्थावर संपदा कंपनियों का खराब निष्पादन तथा बैंक जमा एवं क्रेडिट में धीमापन रहा है (चार्ट III.33)।

आवासीय स्थावर संपदा क्षेत्र में, बिक्री और नई पेशकश दोनों ही वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घट गए थे, जो यह दर्शाता है

चार्ट III.32 : विनिर्माण संकेतक

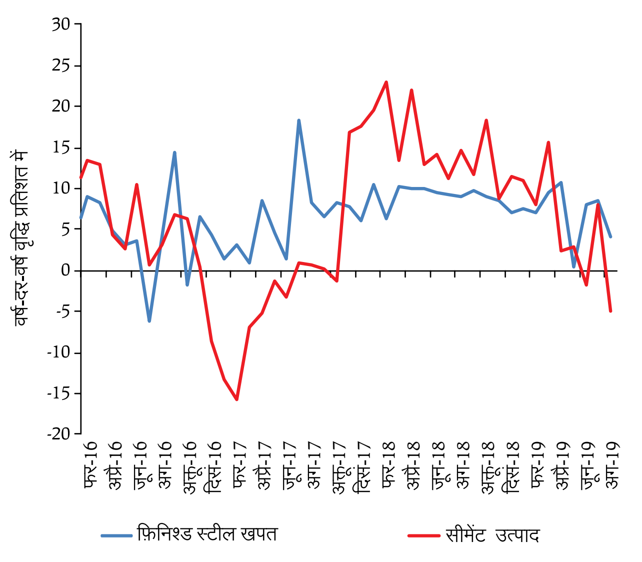

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

चार्ट III.33: वित्तीय सेवाओं में वृद्धि

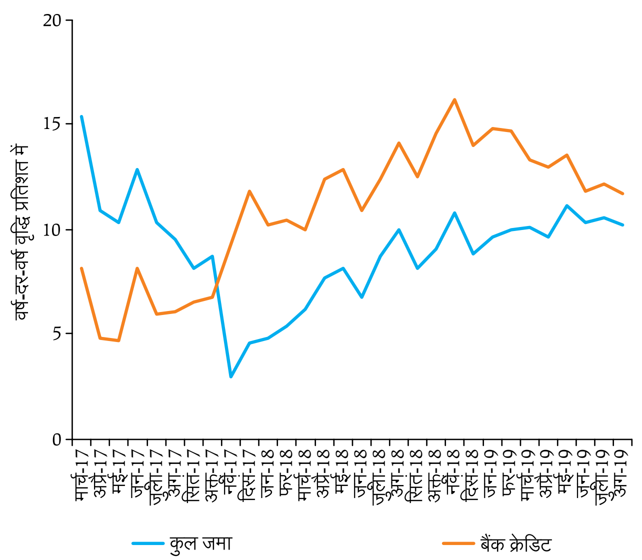

स्रोत :आरबीआई।

चार्ट III.34: आवास क्षेत्र – प्रारंभ, बिक्री और कीमतें

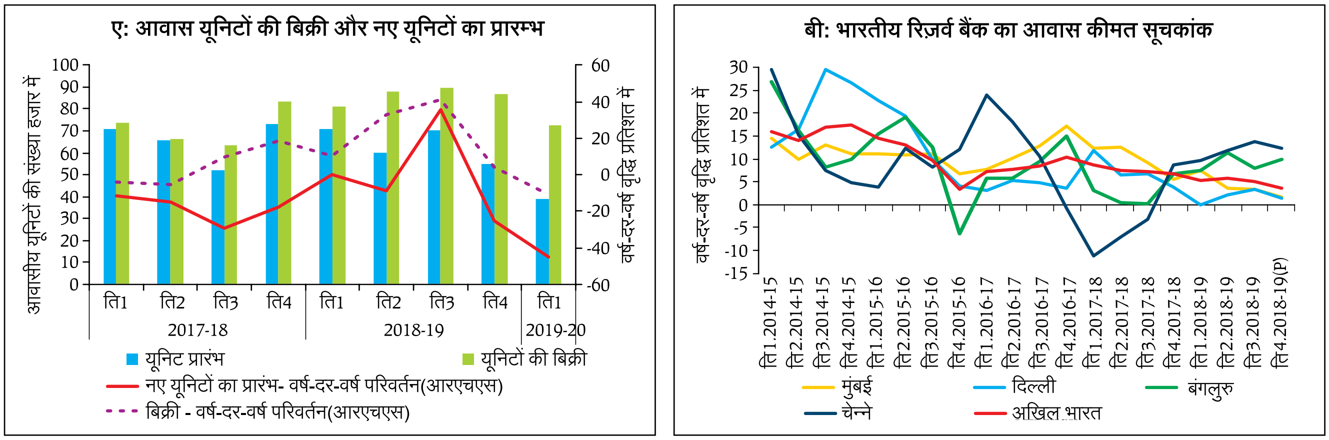

स्रोत : प्रोप टाइगर और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कि मांग धीमी थी (चार्ट III.34 ए)। नई पेशकश को पीछे छोड़ती बिक्री से इंवेंट्री का ओवरहैंग कुछ हद तक कम हो गया है, हालांकि अभी भी इसका आवासीय गृह मूल्यों पर थोड़ा प्रभाव बना हुआ है (चार्ट III.34 बी)।

III.3 उत्पादन अंतराल

उपर्युक्त भाग में सकल मांग और सकल आपूर्ति का विस्तृत विश्लेषण वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन प्रदान करता है। उत्पादन अंतराल -जिसे इसके संभाव्य स्तर से वास्तविक उत्पादन में हुए विचलन द्वारा मापा जाता है

चार्ट III.35 : आउटपुट अंतराल अनुमान

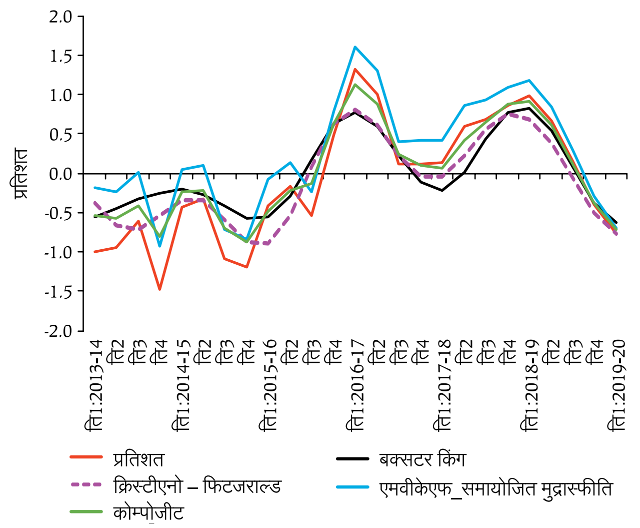

टिप्पणी : एमवीकेएफ मल्टीवेरियट कलमान फ़िल्टर।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

और जिसे संभाव्य उत्पाद अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है- अर्थव्यवस्था में माँग-आपूर्ति की स्थिति के बारे में सारांशित माप प्रदान करता है। चूकि संभाव्य उत्पादन और उत्पादन अंतराल दोनों अलक्ष्य होते हैं और उनके आकलन कार्य -पद्धति के चयन और डाटा उपलब्धता के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए संभाव्य उत्पादन के आकलन के लिए अनेक पद्धतियों का उपयोग करते हुए प्रयोजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपनाई गई पद्धति में समानचर फिल्टर है जैसे एक ओर हाड्रीक प्रेसकॉट (एचपी)फिल्टर और क्रिस्टियानो फिटजराल्ड (सी एफ) फिल्टर और दूसरी और बहुचरीय कालमन फिल्टर्स (एमवीकेएफ) को लिया गया है, जो मुद्रास्फीति में होने वाली प्रगति को गणना में लेता है ताकि कारोबारी चक्र की स्थिति के संबंध में तीव्र निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें (चार्ट III. 35)। इन समस्त उपायों को मिलाकर जो संयुक्त रूप से अनुमान प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि उत्पादन अंतराल और भी नकारात्मक हो गया है।

III.4 निष्कर्ष

घरेलू और वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों ने मिलकर आर्थिक गतिविधियों को, खासतौर से सकल मांग के संबंध में दबाया है। निकट समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य यह है कि उसे अनेक जोखिमों का दबाव सहना पड़ सकता है। पहला, निजी उपभोग, जो अन्य समस्त चीजों के साथ आर्थिक गतिविधियों को सहारा प्रदान करता है, वह अब अनेक कारकों की वजह से मंद पड़ने लगा है। इस संदर्भ में देखें तो भारी संख्या में रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल और स्थावर संपदा की स्थिति चिंताजनक बन गई है।

हाल में जो उपाय शुरू किए गए हैं जैसे कारपोरेट कर की दरों में तीव्र कमी, आवासीय क्षेत्र के लिए दबावग्रस्त आस्ति निधि, अवसंरचना निवेश नीधि, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी धन-वापसी प्रणाली लागू किया जाना तथा निर्यात गारंटी हेतु निधि की व्यवस्था इसमे सहायक होगी। दूसरा, बैंकों में क्रेडिट-वृद्धि धीमी पड़ गई है तथा कमर्शियल क्षेत्र को जाने वाली समग्र निधि घट गई है, जिसका आंशिक कारण जोखिम न उठाना है तथा आंशिक कारण मांग में कमी आना है। हाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दुबारा पूंजी दिये जाने से क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा मिला है, ये निजी निवेश गतिविधियों को फिर से जीवित करने के लिए जरूरी है। इस बीच, वैश्विक स्तर पर उत्पन्न अनिश्चितताओ ने घरेलू स्तर पर निवेश गतिविधियों को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा, व्यापार संबंधी तनाव पैदा होने से निवेश में बढ़ोतरी आने में विलंब होने के अलावा निर्यात की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निजी कारपोरेट क्षेत्र भी नई क्षमताए नहीं पैदा कर रहा है,यद्यपि वर्तमान क्षमता उपयोग की स्थिति अनेक तिमाहियों से इसके दीर्घकालिक-औसत के निकट पहुंच चुकी है। हालिया उपाय पूंजी व्यय चक्र को झटके से शुरू करने में मदद करेंगे जिससे नई क्षमताओं का प्रवाह बढ़ेगा और जो अल्पकाल में घरेलू मांग को मजबूती प्रदान करेंगे तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि क्षमता को मध्यावधि में प्रोत्साहन देंगे।

IV. वित्तीय बाजारों और चलनिधि की स्थितियां

घरेलू वित्तीय बाजार खंडों ने बदली हुई घरेलू और विश्वव्यापी गतिविधियों के प्रति सन 2019-20 की पहली छमाही में विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया की। यद्यपि मुद्रा बाजारों ने नीति के प्रभाव के सहज और संपूर्ण प्रसार का अनुभव किया जबकि सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजार खंड स्वदेशी आर्थिक मंदी और विश्वव्यापी अतिरेकों से प्रभावित हुए। भू-राजनीतिक तनावों के कारण भारी बिकवाली के दबावों के बीच भी स्टॉक मार्केट ने समय-समय पर नई ऊंचाइयों को छुआ। क्रेडिट बाजार में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधारों में गिरावट रही जो कि कमजोर मांग और जोखिम से विमुखता को प्रकट करता है।

अग्रणी केंद्रीय बैंकों के सहज नीतिगत रुख के बावजूद, व्यापारिक तनावों के कारण उथल-पुथल के छिटपुट आघातों, भू-राजनैतिक आक्रोशों, अव्यवस्थित ब्रेक्जिट से जुड़े संशय और वैश्विक समृद्धि के शिथिल परिदृश्य के कारण सन 2019-20 के पूर्वार्ध (2019-20 की पहली छमाही) में वैश्विक बाजारों में व्यग्रता रही। इक्विटी बाजारों ने खासतौर पर अत्यधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव किया क्योंकि हांगकांग में अशांति और अर्जेंटीना में देनदारियों में चूक होने की चिंताओं के कारण उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के स्टॉकों में बिकवाली का दौर रहा। बॉन्ड बाजारों में कॉर्पोरेट क्रेडिट से सम्बद्ध कीमत-लागत अंतराल बढ़ गए क्योंकि वैश्विक समृद्धि के अनुमान धूमिल हो गए थे; दूसरी तरफ जोखिम उठाने की घटती हुई क्षमता ने समायोजनकारी मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप समस्त उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी उपार्जनों को कम कर दिया। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर का मूल्य अन्य सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में बढ़ता रहा जो सापेक्षतया मजबूत अमेरिकी समष्टि आर्थिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। व्यापारिक तनावों और बाजार में उथल-पुथल से बढ़ते हुए अतिरेकी जोखिमों के बीच उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के मूल्यों में गिरावट आई।

IV.1 घरेलू वित्तीय बाजार

घरेलू वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों ने बदलती हुई घरेलू और वैश्विक गतिविधियों के प्रतिसाद में सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान अलग-अलग रवैया दिखाया। अगस्त में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों के व्यवधान से बॉन्ड बाजारों से उपार्जन में शिथिलता रही जबकि मुद्रा बाजारों ने तीव्र और संपूर्ण पारगमन दिखाया। चुनाव से जुड़े हुए संशयों का अंत होने के साथ ही पहली तिमाही में इक्विटी बाजारों ने काफी अच्छा लाभ उठाया लेकिन दूसरी तिमाही में भू-राजनैतिक गतिविधियों, कमजोर कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन और समष्टि आर्थिक संकेतकों में कमजोरी के कारण इसे हानि उठानी पड़ी। भू-राजनैतिक तनावों और अर्थव्यवस्था में घरेलू चक्रीय मंदी के बीच वैश्विक तनावों के बढ़ने से विदेशी मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों से ऋण उठाने में कमी के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का समग्र प्रवाह शिथिल रहा जो मुख्य रूप से कमजोर मांग और जोखिम से बचने की वृति दर्शाते हैं।

IV.1.1 मुद्रा बाजार

सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, मुद्रा बाजार के विभिन्न खंड आरबीआई की मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों, रुख और चलनिधि की स्थितियों से प्रभावित हुए। ओवरनाइट मनी मार्केट में भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) 2019-20 की पहली छमाही के दौरान नीतिगत रेपो दर से समान्यतः नीचे बनी रही तथा इसमें गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही (विवरण के लिए खंड IV.3 देखें)। डबल्यूएसीआर और नीतिगत रेपो दर के बीच का अंतर जून से बढ़ा और सितंबर में 6 बीपीएस के औसत पर रहा। संपार्श्वीकृत खंड में ओवरनाइट मनी मार्केट में अन्य दरें, यानी, त्रि-पक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर, काफी हद तक डबल्यूएसीआर के साथ मिलकर चलती रहीं। सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान त्रि-पक्षीय रेपो दर और मार्केट रेपो दर डब्ल्यूएसीआर से औसतन 7 बीपीएस नीचे रहीं।

सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान (अगस्त तक) अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में कारोबार की मात्रा गैर- संपार्श्वीकृत से संपार्श्वीकृत खंड में स्थानांतरित हो गई। चलनिधि की स्थिति में बढ़ती हुई सहजता के कारण कॉल मनी टर्नओवर (कुल ओवरनाइट मार्केट की मात्रा में) की हिस्सेदारी में गिरावट आई। नतीजतन, मुद्रा बाजार की कुल

चार्ट IV.1: ओवरनाइट मुद्रा बाज़ार मात्रा में शेयर

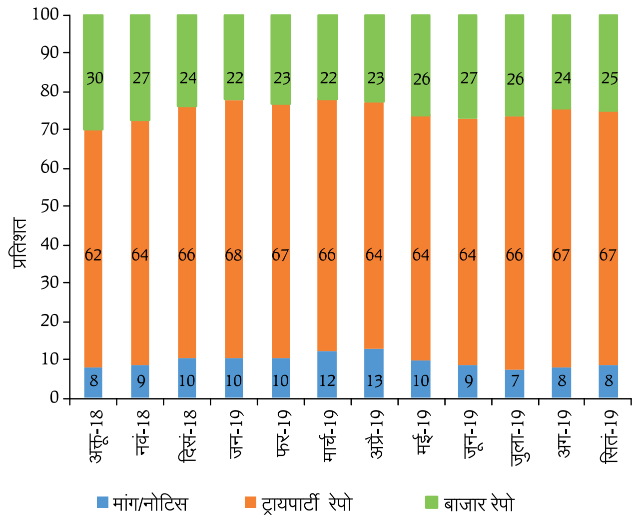

स्रोत : आरबीआई; और सीसीआईएल।

चार्ट IV.2: मुद्रा बाज़ार दरें

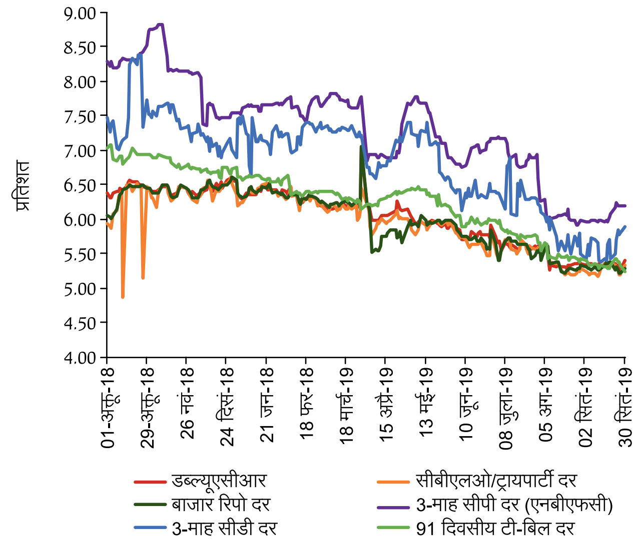

स्रोत : आरबीआई; सीसीआईएल; एफबीआईएल और ब्लूमबर्ग।

मात्रा में त्रि-पक्षीय रेपो और मार्केट रेपो टर्नओवर की हिस्सेदारी बढ़ी (चार्ट IV.1)[1]।

सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान (अगस्त तक) बाजार के माइक्रोस्ट्रक्चर के संदर्भ में, म्यूचुअल फंड (एमएफ) क्रमशः 59 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी के साथ त्रि-पक्षीय रेपो और मार्केट रेपो खंड में प्रमुख उधारदाताओं के रूप में बने रहे। त्रि-पक्षीय रेपो खंड में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और मुद्रा रेपो खंड में प्राथमिक डीलर (पीडी) प्रमुख उधारकर्ता थे। अप्रैल और मई में चलनिधि कमी की स्थिति को देखते हुए, इन दो महीनों के दौरान संपार्श्वीकृत खंड में म्यूचुअल फंडों द्वारा दी जाने वाली उधारियों में गिरावट आई और म्यूचुअल फंडों द्वारा ली जाने वाली उधारियों में वृद्धि हुई। जून से प्रणालीगत चलनिधि में वृद्धि के कारण, जून-सितंबर के दौरान संपार्श्वीकृत खंड म्यूचुअल फंडों द्वारा दी जाने वाली उधारियों में वृद्धि हुई जबकि म्यूचुअल फंडों द्वारा ली जाने वाली उधारियों में मामूली गिरावट आई।

सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, लंबी अवधि के मुद्रा बाजार लिखतों यथा- डिपॉजिट सर्टिफिकेट (सीडी), कमर्शियल पेपर (सीपी) और 91-दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिल्स) पर ब्याज दरों ने नीतिगत दरों में कटौती और नीतिगत रुख के निरपेक्ष से समायोजनकारी होने पर अलग-अलग अंशों में प्रतिक्रिया दी (चार्ट IV.2)। प्रथम छमाही के दौरान विशेष रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी कमर्शियल पेपर (सीपीसी) पर ब्याज दरें काफी संयमित रहीं, हालांकि सीपी की दरें सीडी दरों से ऊपर कारोबार करती रहीं। इसकी तुलना में, इस अवधि के दौरान 3-महीने टी-बिल पर प्रतिफल काफी हद तक संयमित रहे।

बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की सहज स्थितियों के मद्देनजर,2019-20 की पहली छमाही (13 सितंबर, 2019 तक) के दौरान, सीडी के नए निर्गम गिरकर 1,75,305 करोड़ रूपये हो गए, जो 2018-19 के दौरान 1,98,829 करोड़ रूपये थे। सीपी के प्राथमिक निर्गम भी 2018-19 की पहली छमाही के दौरान रहे 13,58,117 करोड़ रुपए से गिरकर, 2019-20 की पहली छमाही के दौरान 11,92,277 करोड़ रुपए हो गए और इनमें 99 प्रतिशत से अधिक निर्गम A1+ रेटिंग वाली कंपनियों के थे। जुलाई से सीपी निर्गम मंद हो गए जो जून और जुलाई 2019 में कुछेक सीपी निर्गमकर्ताओं की ग्रेडिंग नीचे जाने के मद्देनजर बढ़े हुए जोखिम परहेज को दर्शाता है। फिर भी, 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, प्राथमिक सीपी बाजार में ब्याज दरों में, जो भारित औसत डिसकाउंट दर (डबल्यूएडीआर) में परिलक्षित होती हैं – चलनिधि स्थितियों में सहजता आने से 130 बीपीएस तक तीव्र गिरावट हुई (चार्ट IV.3ए)। इस अवधि के दौरान, गैर-

[1] मांग मुद्रा बाजार के सहभागियों में केवल बैंक और प्राथमिक डीलर शामिल है, जबकि बाजार के अन्य सहभागी यथा म्यूचुअल फंड, बीमा कम्पनियाँ और अन्य वित्तीय संस्थाएं त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो खंडों के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं।

चार्ट IV.3: वाणिज्यिक पत्र का प्राथमिक निर्गम

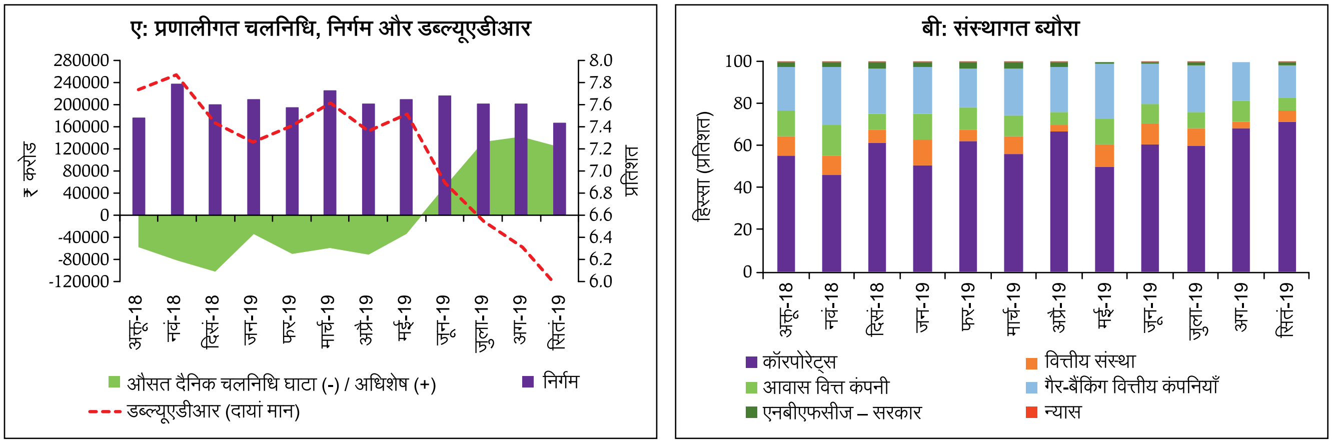

स्रोत : आरबीआई; एफ-ट्रैक; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वित्तीय कोरपोरट और एनबीएफ़सी सीपी बाजार में प्रमुख जारीकर्ता रहे ((चार्ट IV.3 बी)।

मुद्रा बाजार में जोखिम प्रीमियम (अर्थात 3-माह वाले सीपी और 3-माह टी-बिल के बीच लाभांतर) अप्रैल–जुलाई के दौरान औसतन 99 बीपीएस के साथ उच्च बना रहा जो जून-जुलाई के दौरान कुछ सीपी निर्गमकर्ताओं को डाउनग्रेड करने और अप्रैल-मई के दौरान चलनिधि की संकुचित स्थितियों को दर्शाता है (चार्ट IV.4ए)। अगस्त-सितंबर में जोखिम प्रीमियम में औसतन 64 बीपीएस की तेज गिरावट हुई, जिसके निम्नलिखित कारण थे (i) जून 2019 की शुरुआत से ही चलनिधि स्थितियों के घाटे से अधिशेष की तरफ जाने के कारण उत्पन्न चलनिधि प्रभाव; (ii) प्रतिस्पर्धी दरों पर निधि जुटाने वाले शीर्ष रेटेड निर्गमकर्ताओं द्वारा निर्गमों की अधिकता; और (iii) एनबीएफसी को चलनिधि संबधी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम[2]। एनबीएफ़सी और गैर-एनबीएफ़सी के 3-माह वाली सीपी दर के बीच के स्प्रेड, कुछेक तेजी के बावजूद, संकुचित हुआ (2018-19 की दूसरी छमाही के 44 बीपीएस की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में 23 बीपीएस का औसत) (चार्ट IV.4बी)।

चार्ट IV.4: जोखिम प्रीमियम और सीपी बाजार में स्प्रेड

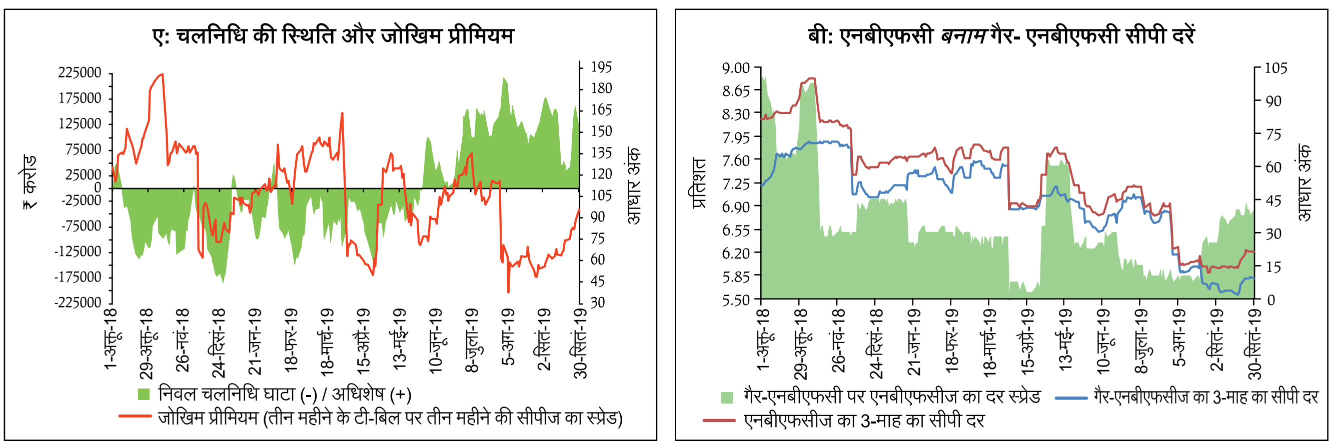

स्रोत : आरबीआई; ब्लूमबर्ग; एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[2] 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ₹1 लाख करोड़ मूल्य की उच्च-रेटेड साझी आस्तियां खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट की एकबारगी गारंटी प्रदान करेगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2019 की अपनी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति में कृषि, सूक्ष्म व लघु उद्यमों और आवास क्षेत्रों को, जिसे निर्दिष्ट सीमा तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, आगे ऋण देने के लिए एनबीएफसी को बैंक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई। आरबीआई ने बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के फ्रेमवर्क को भी उदार बनाया, जिससे एनबीएफसी को आगे ऋण देने और रुपया ऋणों की चुकौती हेतु निधि जुटाने की सुविधा मिल गई।

सारणी IV.1: मुद्रा बाजार में नीति संचरण

(आधार बिंदु)

एच1: 2019-20	दरों में परिवर्तन						
	रेपो	डब्ल्यूएसीआर	ट्राय-पार्टी रेपो	बाजार रेपो	3-माह सीडी	91-दिवसीय टी-बिल	3-माह सीपी (एनबीएफसीज)
अप्रैल 3 से जून 4	-25	-32	-43	-37	-33	-16	-5
जून 6 से अगस्त 6	-25	-24	-18	-25	-48	-44	-80
अगस्त 7 से सितंबर 30	-35	-23	-28	-32	-6	-38	20
संचयी (अप्रैल 3 - सितंबर 30)	**-85**	**-79**	**-89**	**-94**	**-87**	**-98**	**-65**

स्रोत: आरबीआई;सीसीआईएल;एफबीआईएल; ब्लूमबर्ग।

2019-20 की पहली छमाही के दौरान, मुद्रा बाजार के सभी खंडों में नीति का संचरण लगभग पूरा हो गया था। इस अवधि के दौरान तीन नीतिगत घोषणाओं में से जून की नीति के बाद से सर्वाधिक प्रभाव महसूस किया गया, विशेष तौर पर मुद्रा बाजार स्पैक्ट्रम के दीर्घकालिक सिरे पर, क्योंकि जून की नीति ने दरों में कटौती और निरपेक्ष से उदार रुख की ओर मुड़ने के संकेत दिए (सारणी IV.1)। इस प्रकार, रेपो दर कटौतियों की घोषणा का प्रभाव और अधिशेष स्थितियों का चलनिधि प्रभाव, दोनों ही नीतिगत संचरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साधन रहे।

IV.1.2 सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

सन 2018-19 की चौथी तिमाही के दौरान हुई सकारात्मक गतिविधियों, यथा- मौद्रिक नीति में ढील और नीतिगत रुख को जांची-परखी सख्ती से बदलकर निरपेक्ष बनाने; टिकाऊ चलनिधि का प्रवाह; स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग की घोषणा (वीआरआर); मुद्रास्फीति की लगातार हितकारी स्थितियों से संकेत लेते हुए, 2019-20 की पहली तिमाही में सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफलों के कारोबार में नरमी रही। हालांकि प्रतिफलों में नरमी अल्पकालिक थी और उनमें अप्रैल 2019 से आंशिक रूप से तेजी आरंभ हो गई क्योंकि (i) नीतिगत रुख में वैसा कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा बाजार सहभागियों को उम्मीद थी (ii) अमेरिका द्वारा ईरान से आयात पर रोक लगाने और लीबिया व वेनेजुएला में आपूर्ति बाधित होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रही; और (iii) भारतीय रुपये (आईएनआर)का मूल्यह्रास हुआ। इसके परिणास्वरूप, यूएस डॉलर क्रय/ विक्रय स्वैप के माध्यम से टिकाऊ चलनिधि को प्रवाहित करने के बावजूद, बेंचमार्क प्रतिफल में अप्रैल 2019 में 6 बीपीएस की मजबूती रही।

बढ़ते व्यापार तनावों के बीच व राजनैतिक स्थिरता संबंधी संकेतों से युक्त चुनाव परिणामों की संभावना के मद्देनजर मई में प्रतिफलों में 38 बीपीएस की नरमी रही। इसे, खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीदियों के माध्यम से चलनिधि के प्रवाहित किए जाने और कच्चे तेल की कीमतें कम रहने का लाभ मिला। नरमी का यह रुझान जून तक जारी रहा और इस माह बेंचमार्क प्रतिफल में 15 बीपीएस की गिरावट रही क्योंकि नीतिगत दरों में आगे और कटौती, नीतिगत रुखों में बदलाव और आरबीआई द्वारा लगातार ओएमओ खरीदियों से बाजार मनोभाव में उछाल आ गया था।

प्रतिफलों में नरमी दूसरी तिमाही तक भी जारी रही जबकि लिखतों की अत्यधिक आपूर्ति के डर से बाजार का रुख अशांत था। वास्तव में, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ जुलाई 2019 तक अस्थिर रहा। तथापि, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तक रहना और अन्तरिम बजट के समक्ष उधारी की अपरिवर्तित मात्रा जैसी सकारात्मक बजट घोषणाओं से बाजार को उछाल मिला। यह ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा नवीकृत खरीदारी में भी परिलक्षित होता है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति में हितकारी स्थिति के संकेतों ने आगे और दर कटौती की उम्मीदों को बढ़ा दिया। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप, जुलाई के दौरान बेंचमार्क प्रतिफल में 50 बीपीएस की और भी कमी आई तथा यह 16 जुलाई 2019 को 6.33 प्रतिशत के निचले स्तर तक चला गया, जो 2019-20 की पहली छमाही में न्यूनतम स्तर था। एमपीसी द्वारा अपेक्षा से अधिक 35 बीपीएस की दर कटौती, एपीआई पर सरचार्ज लगाने के निर्णय की वापसी, आरबीआई द्वारा उम्मीद से अधिक अधिशेष का अंतरण जैसी सकारात्मक गतिविधियों के बावजूद, प्रोत्साहन की प्रत्याशा से होनेवाली राजकोषीय गिरावट एवं घरेलू/भू-राजनैतिक तनावों की चिंता

चार्ट IV.5: 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड, रेपो दर और चलनिधि स्थितियाँ

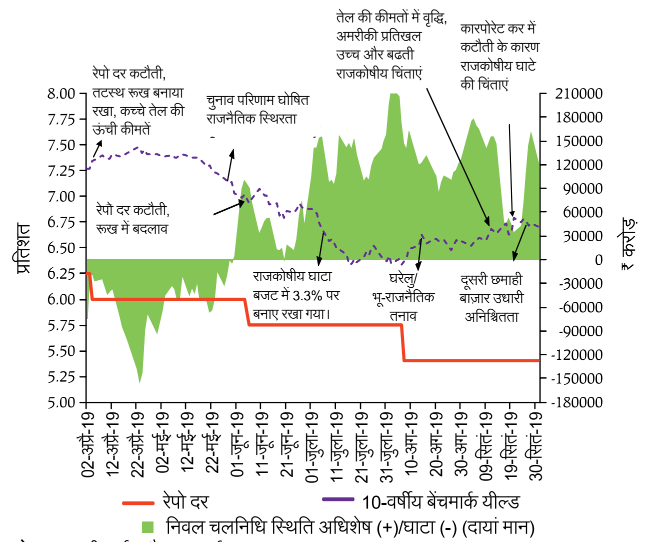

स्रोत : आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

के कारण सरकारी प्रतिभूति बाजार अगस्त में चौकस रहा। तदनुसार अगस्त 2019 में बेंचमार्क प्रतिफल में 19 बीपीएस की तेजी रही जिससे पूर्ववर्ती लाभ कम हो गया (चार्ट IV.5)।

बेंचमार्क प्रतिफल का तेजी की ओर झुकाव सितंबर में भी जारी रहा जिसके निम्न कारण थे (i) सऊदी तेल रिफाइनरियों पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी (ii) राजकोषीय चिंताओं का बने रहना; और (iii) यूएस बॉन्ड प्रतिफलों में वृद्धि के कारण ओवरनाइट इन्डेक्स्ड़ स्वैप (ओईएस) दरों में तेजी। इसके बाद सउदी अधिकारियों द्वारा दिए गए सामान्य बहाली के आश्वासनों से कुछ हद तक बाजार की आशंकाएं खत्म हुई और उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। इसके अलावा, राज्यों के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में की गई खरीदी की सहायता, आगे भी दर-कटौती की बाजार को उम्मीद और गिल्ट्स में विदेशी निवेश की सीमा में ढील से सितंबर के अंत तक प्रतिफल और नरम हो गया। समग्र तौर पर, 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, बेंचमार्क प्रतिफल 65 बीपीएस नरम होकर, 30 सितंबर, 2019 को 6.70 प्रतिशत पर पहुंच गया।

प्रतिफल वक्र, जिसके स्तर में 2019-20 की पहली छमाही में परिवर्तन हुआ था, का वर्णन उसके स्तर तथा ढलान के आधार पर किया गया है (चार्ट IV.6ए)[3]। अप्रैल माह में मौद्रिक नीति घोषणा के बाद, प्रतिफल के औसत स्तर में 50 आधार अंकों की नरमी आई है, जो इन बिन्दुओं द्वारा संचालित हुई : i) मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ, नीति में 85 बीपीएस की संचयी नरमी; (ii) ओएमओ और विदेशी मुद्रा खरीद / बिक्री के माध्यम से चलनिधि डालते हुए अधिशेष चलनिधि की स्थिति पैदा करना; (iii) एनबीएफसी को सतत आधार पर चलनिधि सहायता के उपाय करना; और (iv) सौम्य घरेलू मुद्रास्फीति स्थिति। लेकिन अगस्त माह में नीति की घोषणा के बाद से ही (30 सितंबर, 2019 तक), इसका औसत स्तर 24 आधार अंक बढ़कर और मजबूत हो गया और प्रतिफल वक्र भी और अधिक तीक्ष्ण हो गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा कारपोरेट कर की दरों में कटौती की घोषणा के बाद सरकारी राजस्व में भारी गिरावट, कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधाओं और कतिपय ईएमई में

चार्ट IV.6: जी-सेक प्रतिफल वक्र

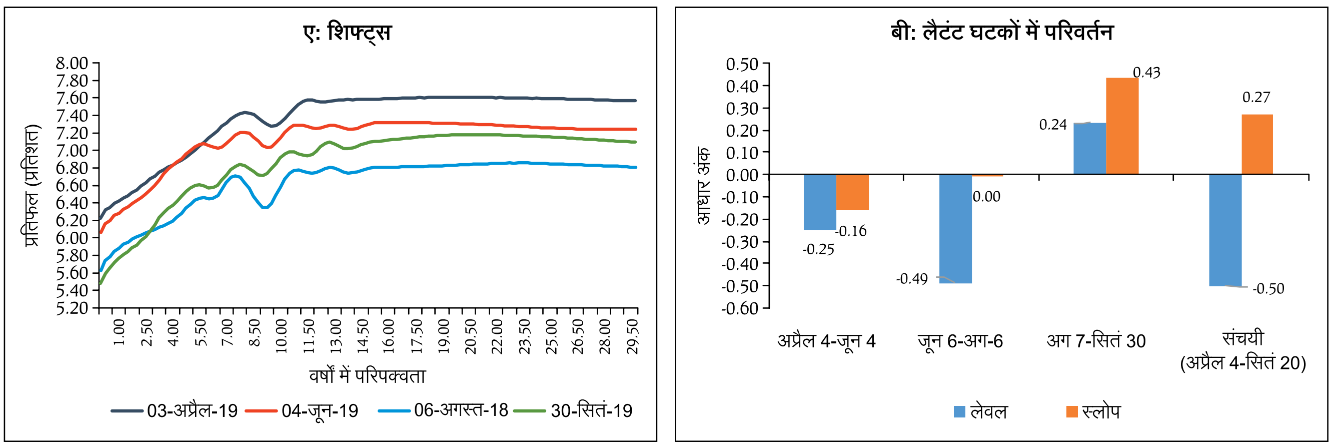

स्रोत : एफबीआईएल; और आरबीआई।

[3] जहां यह स्तर समस्त परिपक्वताओं में सभी अर्जन का औसत है, वहीं उसमें ढलान को दीर्घावधि एवं अल्पावधि परिपक्वता के बीच अर्जन में अंतर(अवधि स्प्रेड) द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

अत्यधिक बढ़ती हुई भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं/वित्तीय बाज़ारों में खलबली की आशंकाओं को प्रकट करता है (चार्ट IV.6बी)।

वीआरआर की शुरुआत तथा सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ी हुई निवेश सीमा से, 2019-20 के आरंभ में ऋण लिखतों में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी। अनुकूल मुद्रास्फीति संकेतों के साथ-साथ राजनैतिक स्थिरता से, निवेशकों की रुचि में तेजी आई। 2019-20 की पहली छमाही के दौरान सरकारी-प्रतिभूति बाजार में विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) निवल खरीदार रहे, तथापि, भू-राजनैतिक तनावों तथा सुस्त आर्थिक परिदृश्य के कारण सितंबर में वे निवल बिकवाल बन गए (चार्ट IV.7)। प्राथमिक क्षेत्र में, अल्पावधि में, बेंचमार्क प्रतिफल का अनुसरण करते हुए, खजाना-बिल प्रतिफल 2019-20 की पहली छमाही के दौरान नरम पड़े (चार्ट IV.8)।

दीर्घावधि में, 2019-20 की पहली छमाही के दौरान भारत सरकार के निर्गमों की फ्रंट-लोडिंग के विपरीत, राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के निर्गमों में नरमी आई। एसडीएल का भारित औसत संचयी स्प्रेड का कट-ऑफ 2019-20 की पहली छमाही में (30 सितंबर की स्थिति के अनुसार) संबन्धित अवधि के जी-सेक ले लिए 52 आधार अंक रहा, जबकि 2018-19 की पहली छमाही में इसी अवधि के लिए यह 54 आधार अंक था (चार्ट IV.9)। 2019-20 की पहली छमाही के दौरान 10-वर्ष अवधि की प्रतिभूतियों का औसत अंतर-राज्य स्प्रेड 4 आधार अंक था जो 2018-19 की पहली छमाही में दर्ज किए गए स्तर के समान ही बना हुआ था।

चार्ट IV.8: एफबीआईएल: ट्रेज़री बिल बेंचमार्क
(परिपक्वता पर प्रतिफल)

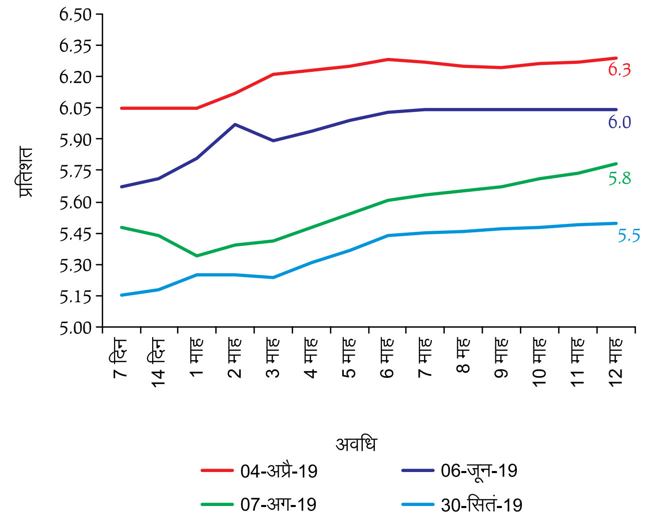

स्रोत : एफबीआईएल।

IV.1.3 कारपोरेट बॉण्ड बाजार

कारपोरेट बॉण्ड से होने वाले प्रतिलाभ 2019-20 की पहली छमाही के दौरान तेजी से शिथिल हुए। यह काफी हद तक सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ का अनुसरण था जिससे नीतिगत रेपो दर में की गई कटौतियों के प्रसारण का पता चलता है (चार्ट IV.10 ए)। इस अवधि के दौरान 5 वर्षीय-एएए कारपोरेट बॉण्ड से होने वाले प्रतिलाभ 66 आधार अंक कम हुए और मार्च 2019 के अंत में 8.10 प्रतिशत से गिरकर सितंबर 2019 अंत में 7.44 प्रतिशत हो गए। इसका कारण

चार्ट IV.7: इक्विटी तथा ऋण में एफ़पीआई निवेश

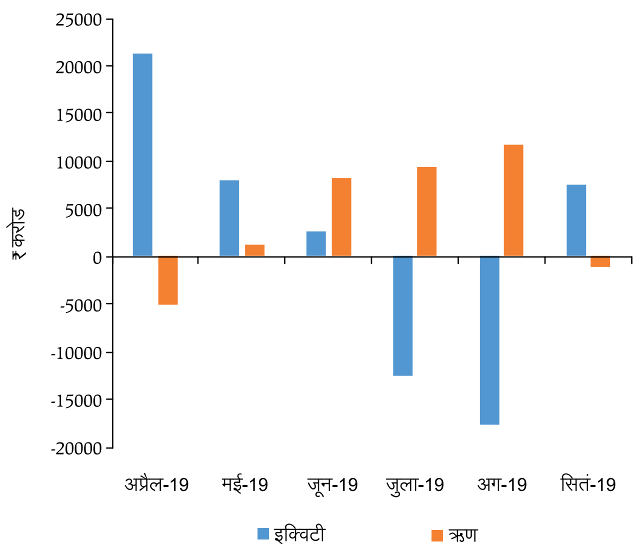

स्रोत : एनएसडीएल।

चार्ट IV.9: एसडीएल - उगाही गई राशि और स्प्रेड

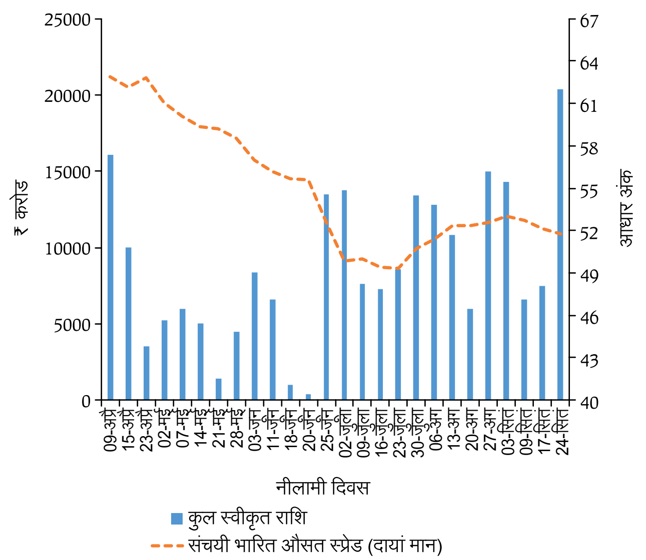

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.10: कॉर्पोरेट बॉन्ड

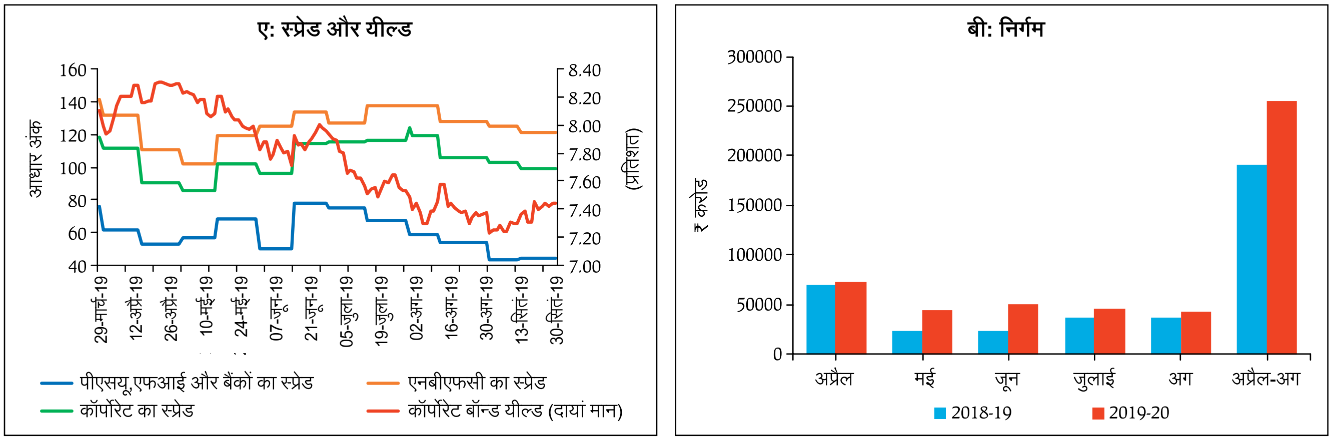

स्रोत : ब्लूमबर्ग; और सेबी।

संचयी नीति दर में 85 आधार अंकों की कटौती रहा(वर्तमान सहजता चक्र के दौरान फरवरी 2019 में की गई कटौती इसमें शामिल नहीं है)। इसके अलावा, सहज चलनिधि स्थितियों के कारण भी जोखिम प्रीमिया में कमी हुई है। उदाहरण के तौर पर, सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों, एनबीएफसी और कार्पोरेट्स द्वारा जारी बॉण्डों पर (5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की तुलना में 5 वर्षीय-एएए कारपोरेट बॉण्ड) प्रतिलाभ स्प्रेड में इस अवधि के दौरान क्रमशः 32 आधार अंक, 20 आधार अंक और 19 आधार अंक की गिरावट रही। भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के 5-वर्षीय क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप – जो ऋण चूक जोखिम दर्शाते हैं- में भी क्रमशः 23 आधार अंकों और 21 आधार अंकों की गिरावट रही।

प्राथमिक बाजार में कारपोरेट बॉण्डों के निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाने का कार्य अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान तेजी से 34.4 प्रतिशत बढ़कर ₹2.6 लाख करोड़ हो गया जो कि 1 वर्ष पहले ₹1.9 लाख करोड़ था(चार्ट IV.10 बी)। कारपोरेट बॉण्ड बाजार में लगभग समस्त संसाधान संग्रहण (97.3 प्रतिशत) निजी प्लेसमेंट मार्ग से होना जारी रहा। कारपोरेट बॉण्डों में एफपीआई द्वारा किया जाने वाला निवेश मार्च 2019 के अंत के ₹2.19 लाख करोड़ से घटकर सितंबर 2019 अंत को ₹2.03 लाख करोड़ पर आ गया। इसके परिणामस्वरूप कारपोरेट बॉण्डों में निवेश के लिए एफ़पीआई की अनुमोदित सीमा का उपयोग सितंबर 2019 अंत को कम होकर 64.0 प्रतिशत पर आ गया जबकि मार्च 2019 के अंत में यह 75.9 प्रतिशत था। 2019-20 की पहली छमाही के दौरान (27 सितंबर, 2019 के अंत तक), कारपोरेट बॉण्ड बाजार का औसत दैनिक टर्नओवर बढ़कर ₹ 8,261 करोड़ हो गया जबकि 2018-19 की पहली छमाही के दौरान यह ₹7,131 करोड़ था।

IV.1.4 इक्विटी बाज़ार

2019 के आम चुनावों के तत्काल बाद इक्विटी बाज़ारों ने रिकार्ड खड़े कर दिए। इसके पश्चात घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोग से 2019-20 की दूसरी तिमाही में इनमें संशोधन हुए जिसने बाजार के मनोभाव को शिथिल कर दिया और यह वर्षारंभ में रहे उसी स्तर के करीब वापस आ गया (चार्ट IV.11ए)।

कारपोरेट अर्जनों के परिणाम कमजोर रहने के बावजूद, बीएसई सेन्सेक्स ने निरंतर एफ़पीआई अंतर्वाहों, रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में कटौती और सकारात्मक वैश्विक संकेतों की मदद से अप्रैल 2019 में हल्की बढ़त हासिल की। मई 2019 के आरंभ में बाज़ारों में तेज गिरावट का दौर रहा क्योंकि यूएस और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गए थे। हालांकि इसी माह में आगे चलकर स्थायी सरकार की संभावनाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में और अधिक ढील दिए जाने के अनुमानों के कारण निवेशकों के मनोभाव सकारात्मक हो गए।

बाजार के उल्लास ने बीएसई सेन्सेक्स को 3 जून 2019 को 40268 की रिकार्ड ऊँचाई पर पहुँचा दिया लेकिन यह दौर अस्थायी ही रहा क्योंकि एक आवासीय वित्त कंपनी द्वारा चूक करने के कारण एनबीएफसी क्षेत्र में चलनिधि की चिंता पैदा होने के बाद बाजार में मंदड़िया मनोभाव पैदा हो गया। बजट के कुछ प्रस्तावों यथा (i) अत्यधिक धनाड्यों पर टैक्स: (ii) वापसी खरीद पर टैक्स; और (iii)

चार्ट IV.11: स्टॉक बाज़ार सूचकांक और निवेश

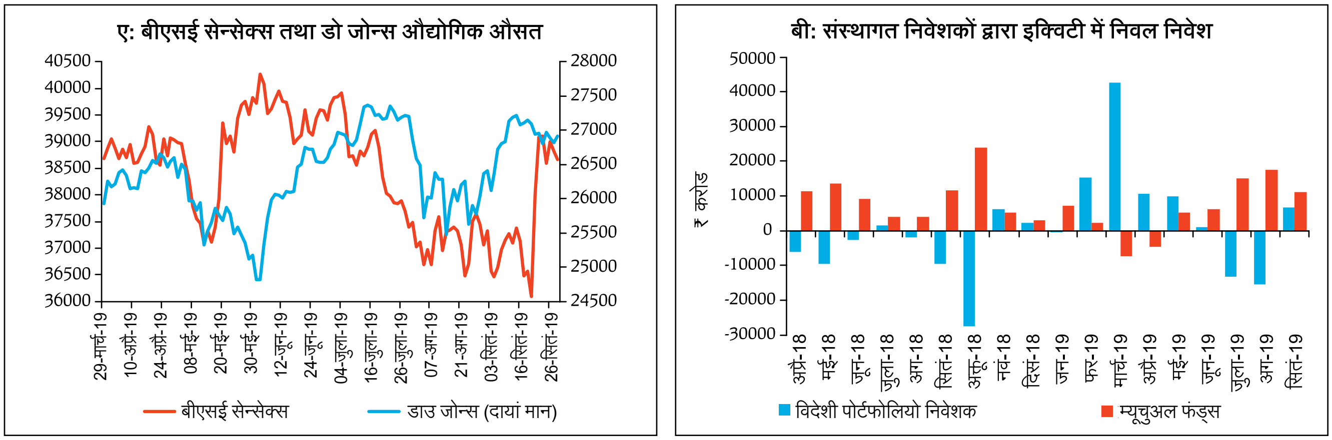

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता में बढ़ोतरी की अपेक्षा में यह गिरावट जुलाई में और भी बढ़ गई। वैश्विक इक्विटी बाज़ारों से नकारात्मक संकेतों, सरकारी क्षेत्र के एक बैंक में उधारियों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट मिलने, 2019-20 की पहली तिमाही में कारपोरेट उपार्जनों में कमी की चिंताओं, मानसून की धीमी प्रगति और गैर-कारपोरेट के रूप में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलोयो निवेशकों पर टैक्स सरचार्ज की प्रस्तावित बढ़ोतरी के कारण एफपीआई के निरंतर बहिर्वाह ने इस गिरावट को जुलाई 2019 में और भी बदतर कर दिया।

अगस्त 2019 में इक्विटी बाजार में मामूली गिरावट हुई। प्रतिकूल घरेलू गतिविधियों यथा 2019-20 की पहली तिमाही के लिए मंद कॉर्पोरेट अर्जन परिणाम, निरुत्साही औद्योगिक क्रियाकलाप और ऑटो बिक्री, और नकारात्मक वैश्विक संकेतों – अर्थात हांगकांग में राजनीतिक अशांति, अर्जेंटीना में ऋण चुकौती में चूक और अमरीका-चीन व्यापारिक वार्ताओं में अनिश्चय ने सरकार के उपायों यथा एफपीआई पर सुपर रिच टैक्स को वापस लेने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की फ्रंटलोडिंग और मोटर-वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी के स्थगन के सकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती से प्रेरित होकर बीएसई सेन्सेक्स में 20 सितंबर को लगभग 5 प्रतिशत का उछाल आया जो पूरे दशक में उछल का सबसे बड़ा दौर था। बाद में, घरेलू बैंकिंग क्षेत्र की सेहत की चिंताओं और यूएस में राजनीति अनिश्चितता के कारण बीएसई में गिरावट आयी। समग्र तौर पर, बीएसई ने सितंबर 2019 के दौरान 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।

यद्यपि इक्विटी बाजार में एफपीआई ने 605 करोड़ रुपये की निवल बिक्री की, तथापि घरेलू संस्थागत निवेशकों खासकर, म्यूचुअल फन्डों ने 2019-20 की पहली छमाही के दौरान ₹50,316 करोड़ की भारी खरीद की (चार्ट IV.11बी)। इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, इक्विटी के सार्वजनिक निर्गमों (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और अधिकार निर्गम) के माध्यम से संसाधन जुटाने में अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान ₹ 59,618 करोड़ की लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में ₹12,028 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

IV.1.5 विदेशी मुद्रा बाजार

अप्रैल, 2019 के बाद से,भारतीय रुपये का मूल्य अपने निचले स्तर पर गिरकर 03 सितम्बर 2019 को ₹72.19 प्रति अमेरिकी डालर(संदर्भ दर) पर पहुंच गया। भारतीय रूपये में गिरावट कई ईएमई मुद्राओं के साथ अमेरिकी डॉलर के गिरावट के अनुरूप थी, जिसे अगस्त और सितम्बर में बतलाया गया था। समग्र रूप से अप्रैल-सितम्बर 2019 में भारतीय रुपये में गिरावट, अमेरिका-चीन के बढ़ते व्यापार तनावों और वैश्विक विकास में वृद्धि की चिंता के कारण निवेशकों के बढ़ते जोखिम से प्रभावित होने, एफ़पीआई द्वारा इक्विटी बेच देने और अमेरिकी डालर के मजबूत होने की वजह से हुई। मार्च 2019 के अंत की स्थिति के सापेक्ष 30 सितम्बर 2019 को अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य 2.1 प्रतिशत कम हुआ, जबकि इसके समकक्ष ईएमई मुद्राओं यथा मलेशिया के रींगिट, दक्षिण अफ्रीका के रांड, चीन के युआन और

चार्ट IV.12: विभिन्न मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव

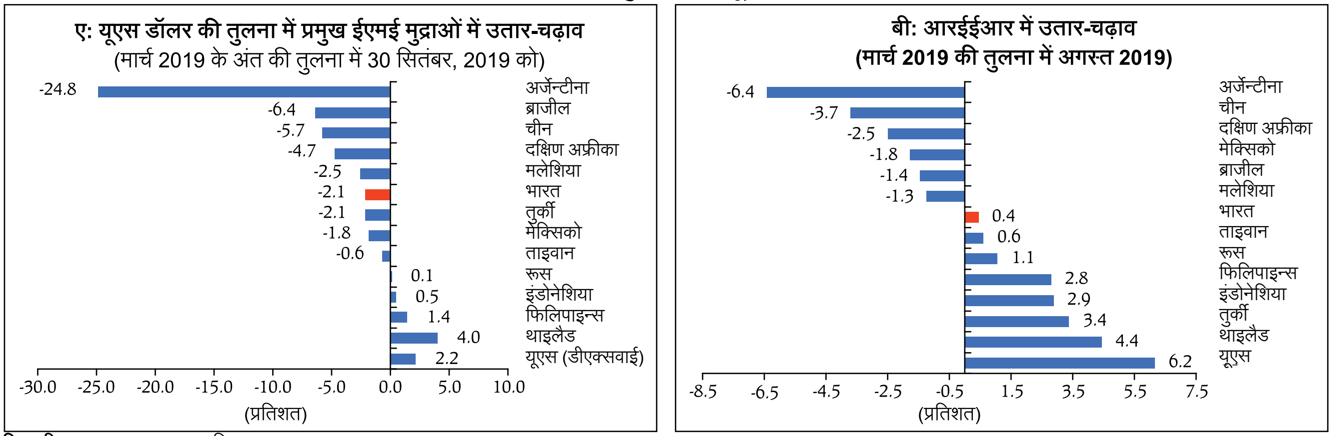

टिप्पणी : मूल्यह्रास (-) / मूल्यवृद्धि (+)
स्रोत : आरबीआई;एफबीआईएल; आईएमएफ; ब्लूमबर्ग; थॉमसन रूटर्स; और बीआईएस

ब्राज़ील के रियाल में हुए मूल्यह्रास की तुलना में यह गिरावट मामूली थी (चार्ट VI.12ए)।

36-मुद्रा और 6-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर(एनईईआर) के संदर्भ में मार्च (औसत) 2019 के समक्ष भारतीय रुपये में क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की मजबूती आयी। भारतीय रुपये में दोनों 36-मुद्रा और 6-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में इसी अवधि के दौरान मजबूती आयी (सारणी IV.2)।

ताइवान डालर, रूसी रूबल, फिलीपीन पेसो, इंडोनेशियन रुपिया, तुर्की लीरा और थाई बाट की तुलना में मार्च और अगस्त 2019 में भारतीय आरईईआर में मामूली मजबूती आयी (चार्ट IV.12 बी)।

सारणी IV.2: सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दरें– व्यापार-आधारित भार

(आधार : 2004-05=100)

मद	सूचकांक : सितंबर, 2019 (पी)	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत)	
		मार्च 2019 की तुलना में सितंबर, 2019 को	मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019 को
36-करेंसी आरईईआर	116.7	1.3	-1.2
36-करेंसी एनईईआर	73.9	0.4	-1.7
6- करेंसी आरईईआर	126.6	2.7	-0.9
6- करेंसी एनईईआर	64.6	1.1	-1.9
₹/यूएस$	70.69	-1.7	-6.4

पी: अनंतिम।
स्रोत: आरबीआई; और एफबीआईएल।

V.1.6 क्रेडिट बाजार

क्रेडिट बाजार में, वर्ष के दौरान (सितम्बर के मध्य तक) कोई क्रेडिट मांग नहीं थी। इस प्रकार, धीमी गति और प्रतिकूल आधार प्रभावों - दोनों से खाद्येतर क्रेडिट वृद्धि में कमी आई (चार्ट IV.13)। 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान क्रेडिट में सामयिक गिरावट पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में ज्यादा थी। पिछले दो वर्षों की इसी तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में (सितम्बर के मध्य तक) क्रेडिट नियंत्रित रही।

चार्ट IV.13 एससीबीज की गैर- खाद्य ऋण संवृद्धि (मासिक औसत)

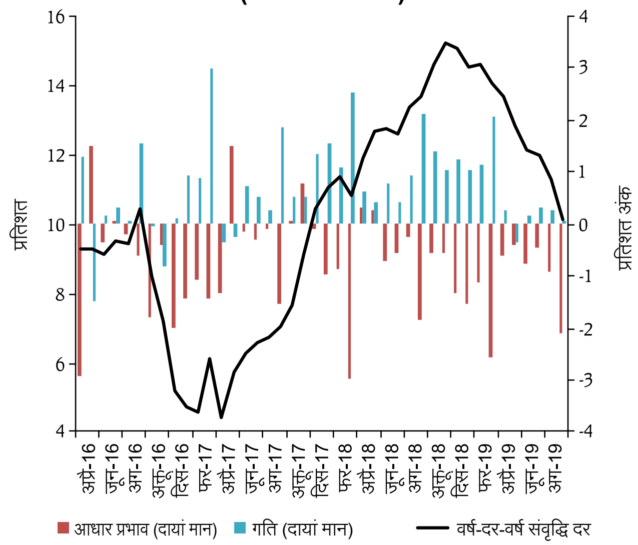

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.14: बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि

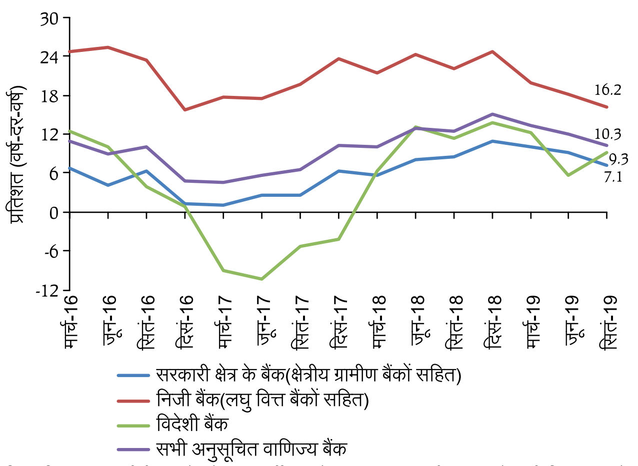

टिप्पणी : 1. आईडीबीआई बैंक के पुनः वर्गीकरण के साथ, 21 जनवरी, 2019 से सभी विकास दर में आईडीबीआई बैंक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में शामिल हैं। इसलिए, आईडीबीआई बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आधार अवधि के आंकड़ों से हटा दिया जाता है और विकास दर के आधार पर गणना के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों में जोड़ा जाता है।
2. सितंबर, 2019 के लिए डाटा सितंबर 13, 2019 का है जो अनंतिम है।

स्रोत : आरबीआई।

सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए क्रेडिट में वृद्धि सुस्त रहीं जबकि विदेशी बैंकों की क्रेडिट वृद्धि में हाल की अवधि में कुछ बढ़त के बावजूद, स्थिति साधारण बनी रही (चार्ट IV.14)।

कृषि क्रेडिट वृद्धि और व्यक्तिगत ऋण पिछले एक साल में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहे जबकि औद्योगिक क्रेडिट वृद्धि अगस्त 2018 और अप्रैल 2019 के दौरान लगातार बढ़त के बाद पिछले चार महीने में मंद रही। जनवरी 2019 के दौरान सेवा क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि में तेज गिरावट आई थी (चार्ट IV.15ए)। वर्ष के दौरान (अगस्त 2018 से अगस्त 2019), वृद्धिशील खाद्येतर क्रेडिट प्रवाह में, सेवाएँ और उद्योग क्षेत्रों के बाद व्यक्तिगत ऋणों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही(चार्ट IV.15बी)। व्यक्तिगत ऋणों के अंतर्गत, क्रेडिट मांग व्यापक तौर पर दो हिस्सों - आवास और क्रेडिट कार्ड बकाया पर केन्द्रित रही। उद्योगों के अंतर्गत, पेय पदार्थ और तंबाकू, रसायन, रबड़ और प्लास्टिक, सीमेंट, इंजीनियरिंग, वाहन, निर्माण और अवसंरचना (ऊर्जा, दूरसंचार और सड़क) की क्रेडिट वृद्धि में तेजी आई।

लगातार चार तिमाहियों में गिरावट के बाद, जून 2019 में दवाबग्रस्त आस्तियां अनुपात और अनर्जक आस्तियां(एनपीए) अनुपात दोनों में मामूली वृद्धि के बाद, क्रेडिट गुणवत्ता और भी खराब हुई(चार्ट IV.16ए)। क्षेत्र-वार विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि उद्योग को छोड़कर जून 2019 में सभी क्षेत्रों में एनपीए अनुपात गिरा है (चार्ट IV.16बी)।

बैंक ने 2019-20 (13 सितम्बर तक) में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसआरएल) पोर्टफोलियो में अपना निवेश 35,000 करोड़ रुपए तक घटा दिया। तथापि, इसमें 2018-19 की दूसरी छमाही में गिरावट के विपरीत, सीपी के प्रति एक्सपोजर में आंशिक बढ़त हुई। गैर-सांविधिक चलनिधि निवेश और खाद्येतर क्रेडिट- दोनों में गिरावट के साथ, वर्ष के दौरान अब तक समायोजित खाद्येतर क्रेडिट[4] वृद्धि में गिरावट आई (चार्ट IV.17)।

चार्ट IV.15: क्रेडिट का क्षेत्रीय परिनियोजन

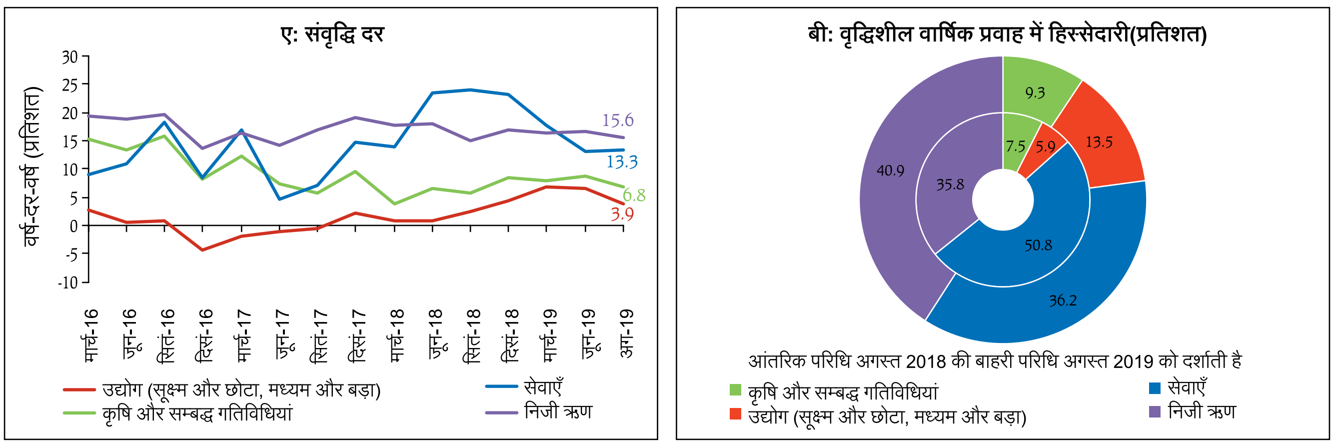

स्रोत : आरबीआई।

[4] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विस्तारित खाद्येतर क्रेडिट और वाणिज्यिक पत्र में उनके निवेश के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा जारी किए गए बॉन्ड/ शेयर/ डिबेंचर भी शामिल हैं।

चार्ट IV.16: दबावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां

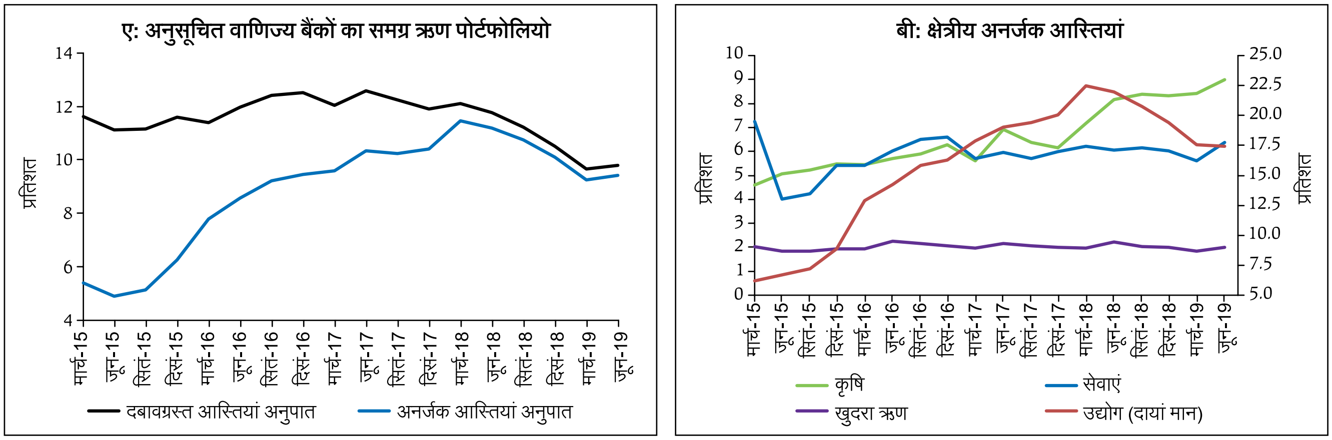

स्रोत : आरबीआई।

मंद ऋण उठाव और गैर-एसएलआर निवेश में गिरावट के साथ बैंकों ने आरबीआई द्वारा एसएलआर में कटौती के बावजूद अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में वृद्धि की है। बैंकों ने मार्च 2019 के अंत के 6.3 प्रतिशत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की तुलना में, 30 अगस्त 2019 को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 6.9 प्रतिशत अतिरिक्त एसएलआर रखा (चार्ट IV.18)।

समग्रतः, बैंकों से निधीयन में कमी और गैर-बैंक स्रोतों से कम निधीयन के चलते, वर्ष 2019-20 में वाणिज्यिक क्षेत्र को अब तक (मध्य सितंबर तक) किया गया कुल वित्तीय प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है। निधीयन के घरेलू गैर-बैंक स्रोतों में, इक्विटी के सार्वजनिक निर्गमों और निजी प्लेसमेंट में काफी अधिक वृद्धि हुई। विदेशी स्रोतों में, बाह्य वाणिज्यिक उधारियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) दोनों में तीव्र वृद्धि हुई है (सारणी IV.3)। कारोबारी सुगमता में सुधार करने के लिए जनवरी 2019 में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के लिए विशेषरूप से एक नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई; तदनंतर, जुलाई 2019 में अंतिम उपयोग से संबंधित प्रावधानों को भी युक्तिसंगत बनाया गया।

चार्ट IV.17: समायोजित गैर–खाद्य ऋण (तिमाही परिवर्तन)

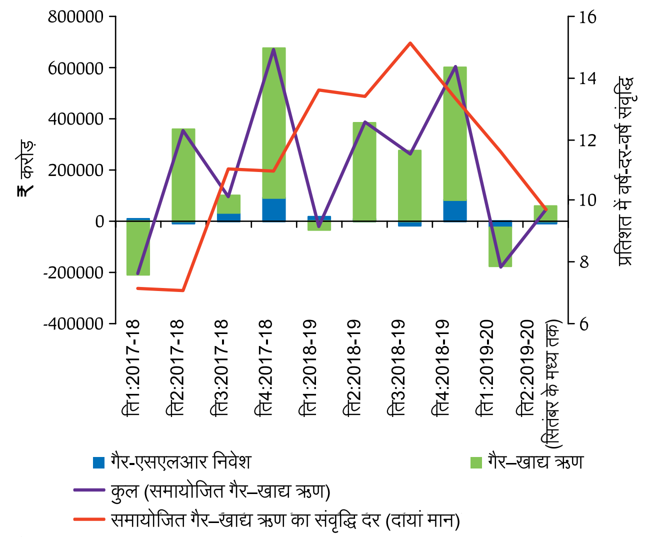

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.18: बैंकों का अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात

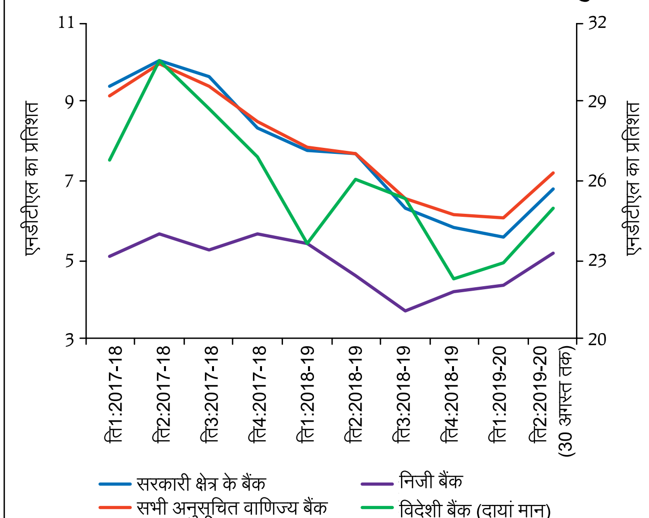

टिप्पणी : एक तिमाही में बेशी एसएलआर की गणना उस तिमाही के सभी रिपोर्टिंग शुक्रवार के औसत के रूप में की गई है।
स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.3 वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए निधीयन का प्रवाह

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अप्रैल से मध्य -सितंबर			
	2018-19		2019-20	
	राशि	कुल से प्रतिशत	राशि	कुल से प्रतिशत
ए. बैंकों से प्रवाह, अर्थात, समायोजित गैर-खाद्य ऋण (ए1+ए2)	**1,85,083**	**25.1**	**-1,28,760**	**-141.5**
ए1. गैर-खाद्य ऋण	*1,65,187*	*22.4*	*-93,688*	*-103.0*
ए2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर निवेश	*19,896*	*2.7*	*-35,072*	*-38.5*
बी. गैर-बैंकों से प्रवाह (बी1+बी2)	**5,51,004**	**74.9**	**2,19,755**	**241.5**
बी1. घरेलू स्रोत	*4,44,696*	60.4	*13,562*	14.9
1. गैर- वित्तीय कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यू *	6,253	0.8	58,326	64.1
2. गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा सकल निजी प्लेसमेंट*	47,379	6.4	62,495	68.7
3. गैर- बैंकों द्वारा सबस्क्राइब किए वाणिज्य पत्रों का निवल निर्गम	2,53,669	34.5	19,118	21.0
4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण$	52,181	7.1	-6,003	-6.6
5. आरबीआई द्वारा विनियमित 4 एआईएफ़आई द्वारा कुल अकोमोडेशन*	40,032	5.4	-4,774	-5.2
6. एनबीएफ़सीज-एनडी-एसआई और जमाराशि लेनेवाले एनबीएफ़सीज (बैंक ऋण का निवल)$	41,200	5.6	-1,25,600	-138.0
7. कॉर्पोरेट कर्ज, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश ^	3,982	0.5	10,000	11.0
बी2. विदेशी स्रोत	*1,06,308*	*14.4*	*2,06,193*	*226.6*
1. बाह्य वाणिज्यिक उधार / एफ़सीसीबी *	-653	-0.1	54,073	59.4
2. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ^	1,06,961	14.5	1,52,119	167.2
सी. बैंकों और गैर-बैंकों से कुल प्रवाह (ए + बी)	**7,36,087**	**100.0**	**90,995**	**100.0**

$: जून तक ^: जुलाई तक *: अगस्त तक

स्रोत: आरबीआई; सेबी; बीएसई; एनएसई; एनएचबी; एलआईसी; और व्यापारी बैंक।

IV.2 मौद्रिक नीति संचरण

फरवरी 2019 से आरंभ हुए मौद्रिक नीति के सुगमता चक्र से नीतिगत रिपो दर में 110 आधार अंक की संचयी कटौती के प्रति वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधारी दरों की प्रतिक्रिया अब तक धीमी रही है (सारणी IV.4)। जबकि रुपए में दिए गए नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) में केवल 29 आधार अंक (फरवरी-अगस्त 2019) की गिरावट आई, इसके विपरीत, इसी अवधि में रुपए में दिए गए बकाया ऋण पर डबल्यूएएलआर में 7 आधार अंक की वृद्धि हुई। अपर्याप्त संचरण बैंक मियादी जमा दरों में धीमे समायोजन को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। यह नियत

सारणी IV.4: जमा तथा उधार दरों की ओर संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मियादी जमा दरें		उधार दरें		
		माध्यिका मियादी जमा दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर	1-वर्षीय माध्यिका एमसीएलआर	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपए ऋण	डब्ल्यूएएलआर - नए रुपए ऋण
फर-मार्च 2019	-25	-1	-2	-5	-3	-24
अप्रैल-मई 2019	-25	-6	0	0	7	13
जून –जुलाई 2019	-25	-4	-4	-15	2	-9
अगस्त-सितंबर 2019	-35	-15	2	-15	1	-9
फरवरी – सितंबर, 2019	**-110**	**-26**	**-4**	**-35**	**7**	**-29**

*: डब्लूएएलआर तथा डब्लूएडीटीआर पर अद्यतन डाटा अगस्त 2019 से संबंधित है।
डब्लूएडीटीआर : भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर। डब्लूएएलआर : भारित औसत उधार दर।
एमसीएलआर : निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.19: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर में परिवर्तन (फरवरी–अगस्त 2019)

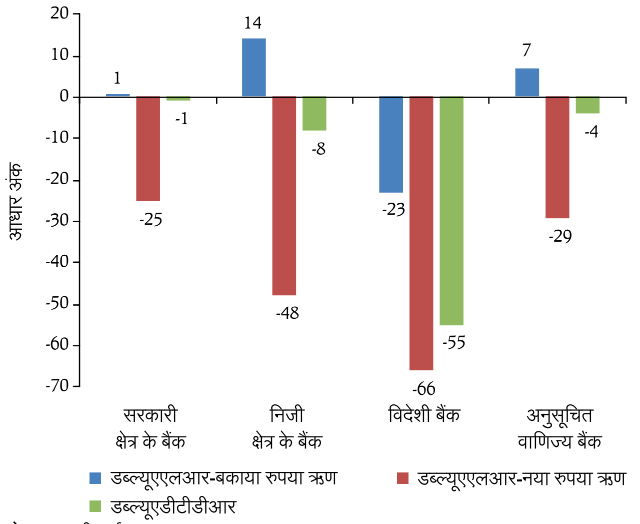

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.20: नया रुपया ऋण का बैंक समूह-वार शेअर

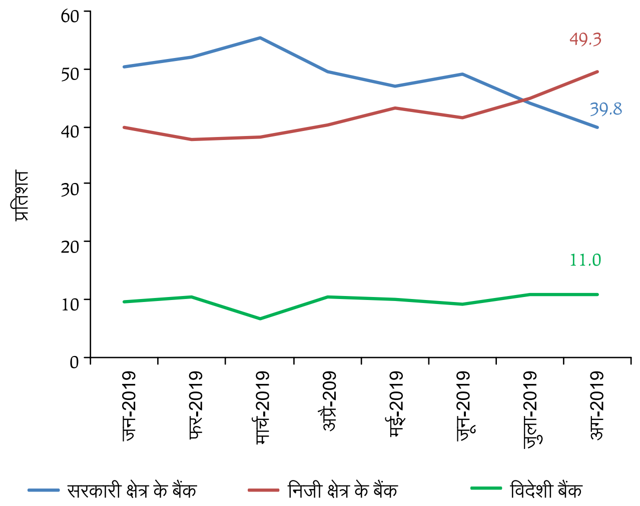

स्रोत : आरबीआई।

ब्याज़ दरों पर बैंक जमाओं की दीर्घावधि परिपक्वता प्रोफाइल को दर्शाता है।

फरवरी-अगस्त 2019 के दौरान बैंक समूहों में रुपए में दिए गए नए ऋणों पर डबल्यूएएलआर में गिरावट आई। यह गिरावट सबसे ज्यादा विदेशी बैंकों में देखी गई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे कम देखी गई (चार्ट IV.19)।

चूंकि अधिक एनपीए और निम्न पूंजी पर्याप्तता के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उधार देने संबंधी गतिविधि सीमित हो गई, अगस्त 2019 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रुपए में दिए गए नए ऋणों की तुलना में बढ़ गया (चार्ट IV.20)।

वास्तविक उधारी दरों में निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) और स्प्रेड शामिल है। बैंकों ने अगस्त 2019 के दौरान आवास ऋणों पर न्यूनतम स्प्रेड (1 वर्ष से अधिक की एमसीएलआर पर रुपए में दिए गए बकाया ऋणों पर डबल्यूएएलआर) लगाया जो कि (i) चूक की कम संभावना; (ii) अच्छे संपार्श्विक की उपलब्धता; तथा (iii) एनबीएफ़सी से प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है (चार्ट IV.21)। स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर 'अन्य व्यक्तिगत ऋणों' पर लगाया गया स्प्रेड सबसे अधिक था।

रुपए में दिए गए ऋणों/ रुपया बकाया ऋणों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफलों पर एमसीएलआर/डबल्यूएएलआर के बीच स्प्रेड 2019 में तेजी से बढ़ गया है जो ऋण बाज़ार में धीमे संचरण के विपरीत, बॉन्ड बाज़ार में नीतिगत दर के पूर्ण संचरण को दर्शाता है (चार्ट IV.22)।

मौद्रिक नीति के संचरण को बाधित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अल्प बचत योजनाओं पर नियंत्रित ब्याज दरें हैं। ये नियंत्रित ब्याज दरें समयान्तराल के साथ जी-सेक पर बाजार की ब्याज दरों से जुड़ी हुई हैं तथा इनको तुलनात्मक

चार्ट IV.21: क्षेत्रवार डब्ल्यूएएलआर और 1-वर्षीय माध्य एमसीएलआर - अगस्त 2019

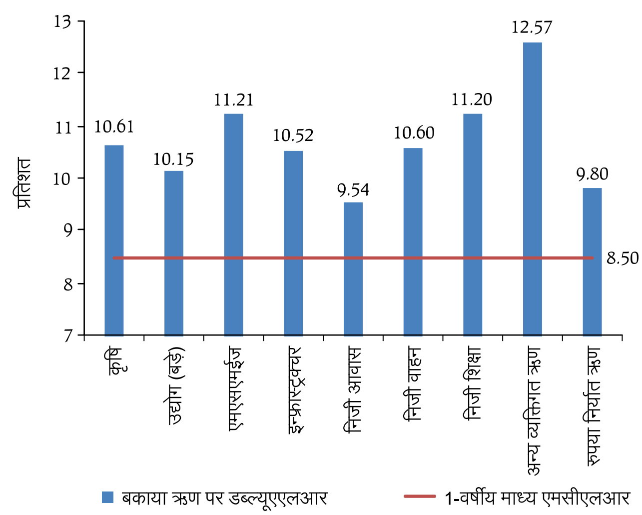

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.22: स्प्रेड्स - कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स पर उधार दरें

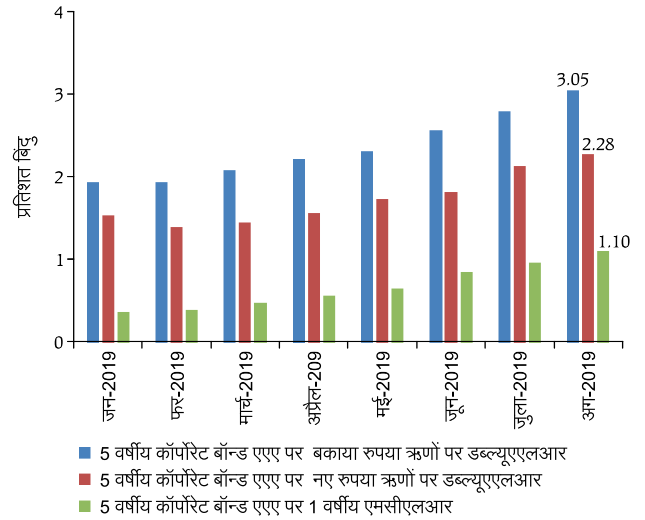

स्रोत : आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

परिपक्वताओं के जी-सेक दर के 0-100 आधार अंक से अधिक दरों के अंतर पर तिमाही आधार पर तय किया जाता है। 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को 28 जून 2019 को संशोधित किया गया, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी हुई, जिसके द्वारा सभी अल्प बचत योजनाओं (बचत जमा को छोड़कर) की ब्याज दरों में 10 आधार अंक की कटौती की गई। हालांकि, कटौती के बाद भी विभिन्न योजनाओं की अल्प बचत दरें 2019-20 की दूसरी तिमाही में फार्मूला-आधारित ब्याज़ दरों की तुलना में 18-62 आधार अंक उच्च बनी रहीं। इसके बाद की अवधि (जून-अगस्त 2019) में जी-सेक प्रतिफलों में गिरावट के बावजूद, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के सरकार के निर्णय से, विभिन्न योजनाओं पर वर्तमान अल्प बचत दरों और 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए फार्मूला-आधारित दरों के बीच का अंतर आगे चलकर 70-110 आधार अंक तक बढ़ गया (सारणी IV.5)।

ऋणों के कीमत निर्धारण की एमसीएलआर प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है क्योंकि यह हरेक बैंक का आंतरिक कार्य है और उधारकर्ताओं के पास यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि इसे किस प्रकार निर्धारित किया गया है। जहाँ नए उधारकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है क्योंकि वे सभी बैंकों की समग्र उधार दरों की तुलना कर सकते हैं और अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय ले सकते हैं, वहीं यह मौजूदा उधारकर्ताओं को प्रभावित करती है क्योंकि वे

सारणी IV.5: अल्प बचत लिखतों पर ब्याज दरें - तीसरी तिमाही : 2019-20

अल्प बचत योजना	परिपक्वता (वर्ष)	स्प्रेड (प्रतिशत अंक)$	संगत परिपक्वता का औसत जी-सेक यील्ड (प्रतिशत) (जून 2019 से अगस्त 2019)	फार्मूला- आधारित ब्याज दर(प्रतिशत) (अक्तूबर से दिसंबर 2019 के लिए लागू)	तीसरी तिमाही में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर(प्रतिशत)	अंतर (आधार अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6)-(5)
जमा बचत	-				4.00	-
सार्वजनिक भविष्य निधि	15	0.25	6.81	7.06	7.90	84
मियादी जमा						
1 वर्ष	1	0	5.85	5.85	6.90	105
2 वर्ष	2	0	6.01	6.01	6.90	89
3 वर्ष	3	0	6.18	6.18	6.90	72
5 वर्ष	5	0.25	6.50	6.75	7.70	95
पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा खाता	5	0	6.50	6.50	7.20	70
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना	5	0.25	6.47	6.72	7.60	88
किसान विकास पत्र	113 माह	0	6.81	6.81	7.60	79
एनएससी VIII इश्यु	5	0.25	6.66	6.91	7.90	99
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	6.50	7.50	8.60	110
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	6.81	7.56	8.40	84

$: 16 फरवरी 2016 की भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अल्प बचत दरों के निर्धारण के लिए स्प्रेड्स।
टिप्पणी : कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग-अलग लिखतों में भिन्न होती है।
स्रोत : भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उन कारकों को आसानी से नहीं जान सकते हैं जो एमसीएलआर में परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा, एमसीएलआर प्रणाली ने प्रभावी संचरण नहीं किया क्योंकि बैंक अपनी जमा ब्याज दरों को समायोजित करने में सुस्त रहे, जिसके फलस्वरूप उनकी उधार दरों पर इसका बोझ पड़ा।

इन चिंताओं के निराकरण के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक अध्ययन समूह (अध्यक्ष: डॉ. जनक राज)की सिफ़ारिशों के अनुसरण में यह आदेश दिया कि 01 अक्तूबर, 2019 से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)को सभी नए अस्थिर दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों और एमएसएमई को दिये गए अस्थिर दर वाले ऋणों को नीतिगत रेपो दर अथवा 3-माह वाले टी-बिल दर या 6-माह वाले ट्रेजरी बिल दर या एफ़बीआईएल द्वारा तय किए गए बेंचमार्क से लिंक करना होगा। बैंक बेंचमार्क दर के ऊपर अपना लाभांतर चुनने के लिय स्वतंत्र होंगे, बशर्ते ऋण जोखिम प्रीमियम में तभी परिवर्तन होगा जब उधारकर्ता के ऋण आकलन में उल्लेखनीय परिवर्तन होगा, जैसा कि ऋण करार में सहमति हुई है। बाहरी बेंचमार्क पारदर्शी होते हैं क्योंकि वे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं और इसलिए उधारकर्ता इसे आसानी से देख सकते हैं। बाह्य बेंचमार्क फ्रेमवर्क से संचरण में सुधार होगा क्योंकि बैंकों को निर्दिष्ट बेंचमार्क में परिवर्तन को लागू करना होगा, और इसलिए हरेक तीन महीने में ऋण को रीसेट करते समय उधार की ब्याज दर में तदनुसार परिवर्तन करना होगा।

IV.3 चलनिधि स्थितियां और मौद्रिक नीति की परिचालनगत प्रक्रिया

सन 2016 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन और उसमें समय-समय पर हुए परिवर्तन, यदि हों, से संबन्धित परिचालनगत प्रक्रिया को रिज़र्व बैंक द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, आरबीआई द्वारा किए गए चलनिधि परिचालन अक्तूबर 2018 और अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्टों में चर्चा किए गए विस्तृत फ्रेमवर्क के अनुसार किए गए थे। नियमित परिचालनों के अलावा, 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, आरबीआई ने परिवर्ती दर रेपो और रिवर्स रेपो नीलामियों को और सुकर और बेहतर बनाने की पहल की। नियमित 14-दिवसीय रेपो के माध्यम से 5,09,585 करोड़ रुपए की चलनिधि डाली गई, जबकि ओवरनाईट से लेकर 63-दिवस में परिपक्व होने वाले रिवर्स रेपो के माध्यम से 93,39,315 करोड़ रुपए की चलनिधि अवशोषित की गई। इसके अलावा, 1 से 3 दिवस में परिपक्व होने वाले परिवर्ती दर रेपो के माध्यम से कुल 47,128 करोड़ रुपए की चलनिधि डाली गई। सन 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, आरबीआई द्वारा चार मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामियाँ की गई और 5 बिलियन यूएस डॉलर का एक खरीद/बिक्री स्वैप किया गया। साथ ही, बैंकों को संरचनात्मक चलनिधि जुटाने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिसंबर 2018 में घोषित रोडमैप के अनुसार, पहली छमाही के दौरान, एसएलआर को 13 अप्रैल और 6 जुलाई को क्रमशः 25-25 बीपीएस घटाते हुए, कुल 50 बीपीएस घटाकर, बैंकों के एनडीटीएल का 18.75 प्रतिशत कर दिया गया।

चलनिधि के संचालक और प्रबंधन

आरबीआई द्वारा किए गए यूएस डॉलर 5 बिलियन खरीद/बिक्री स्वैप सहित विदेशी विनिमय परिचालन और निवल ओएमओ खरीद, 2019-20 की पहली छमाही में चलनिधि को बढ़ाने वाले के प्रमुख चालक रहे, जिसे आरबीआई द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत परिचालनों के माध्यम से अवशोषित किया गया। यह 2018-19 की दूसरी छमाही की स्थिति के विपरीत है, जब संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृहद विस्तार के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि का रिसाव हुआ, जिसे बड़े पैमाने के मुक्त बाजार खरीद परिचालन कर और एलएएफ़ के अंतर्गत चलनिधि डालकर फिर से भरा गया (चार्ट IV.23)।

चार्ट IV.23: चलनिधि के संचालक और प्रबंधन

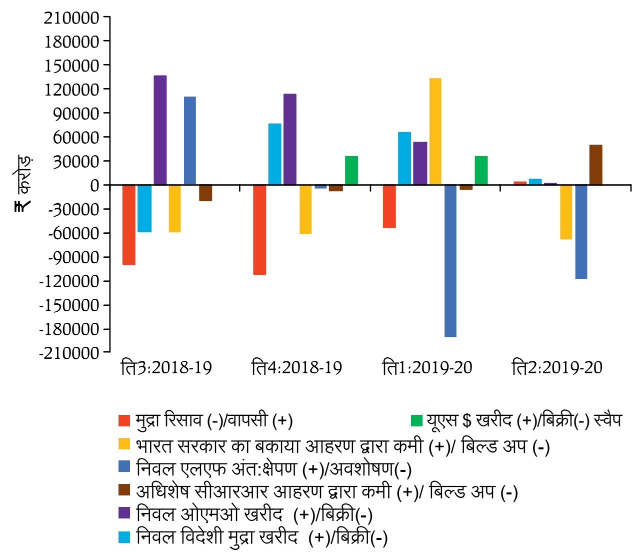

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.24: संचलन में मुद्रा

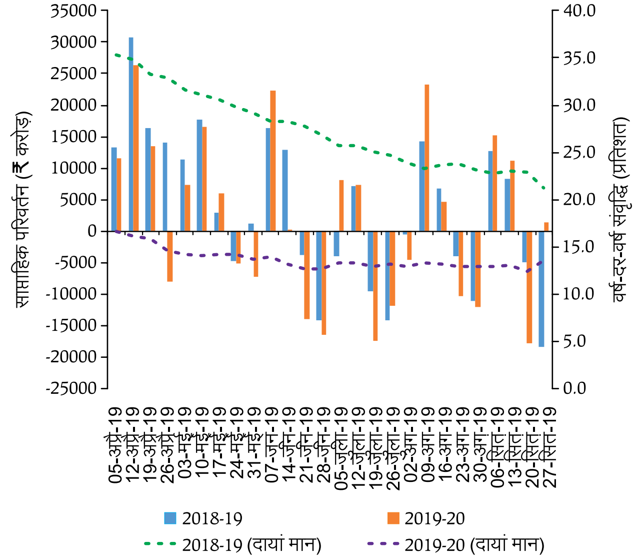

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.25: स्थायी चलनिधि डालना

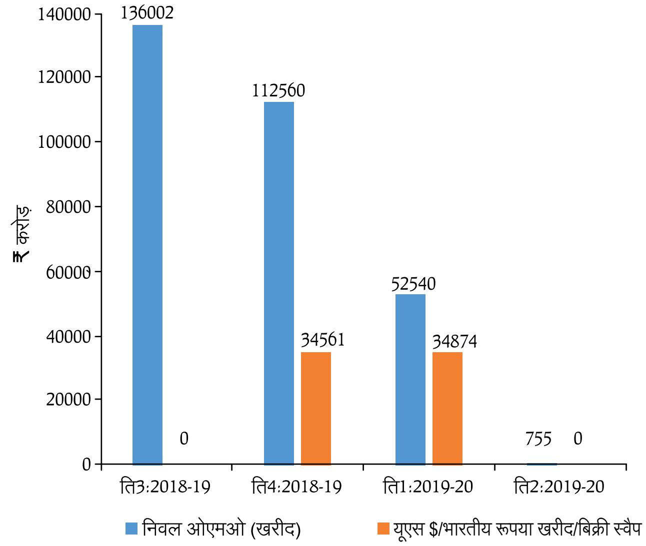

स्रोत : आरबीआई।

2019-20 की पहली छमाही के दौरान, सीआईसी में 49,378 करोड़ (2.3 प्रतिशत) की वृद्धि रही, जो 2018-19 की उसी अवधि के दौरान 95,896 करोड़ (5.2 प्रतिशत) की उल्लेखनीय रूप से उच्चतर वृद्धि की तुलना में धीमी थी। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में, सीआईसी में वृद्धि (वर्षानुवर्ष)लगातार धीमी रही (चार्ट IV.24)।

अप्रैल और मई में, नियंत्रित सरकारी खर्च तथा नकदी की भारी मांग की वजह से चलनिधि की कमी की स्थिति थी। भारत सरकार के द्वारा नकदी शेष को रिलीज करना प्रत्येक वर्ष अप्रैल की एक आम बात है – किन्तु चालू वर्ष में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकारी खर्च सीमित होने के कारण इसमें कमी रही। इसने मुद्रा की बढ़ती मांग के साथ मिलकर चलनिधि की तंगी उत्पन्न की किया। नतीजतन, रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में टिकाऊ चलनिधि मुहैया कराने के लिए अप्रैल में तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹34,874 करोड़) के क्रय/विक्रय के लिए स्वैप नीलामी की तथा प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए मई में ₹25,000 करोड़ की राशि के लिए दो ओएमओ खरीद नीलामी कीं। इसने इन दोनों माह के दौरान एलएएफ़ के तहत भी दैनिक औसत आधार पर ₹51,403 करोड़ की निवल चलनिधि मुहैया कराया।

जून में स्थिति तब बदल गई जब केंद्र में सरकार के गठन के पश्चात व्यय बढ़ने, रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की निवल खरीद किए जाने तथा चुनाव बीत जाने पर बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा की वापसी की वजह से चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बदल गई। रिज़र्व बैंक ने भी ₹27,500 करोड़ राशि की दो ओएमओ खरीद नीलामी कीं। नतीजतन, 2019-20 की पहली तिमाही में ओएमओ तथा अमरीकी डॉलर स्वैप दोनों के माध्यम से ₹87,414 करोड़ की टिकाऊ चलनिधि डाली गई (चार्ट IV.25)।[5] रिज़र्व बैंक ने जून में एलएएफ़ के तहत दैनिक निवल औसत के आधार पर ₹51,710 करोड़ की चलनिधि वापस ली।

जुलाई में (i) बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा की वापसी; तथा (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की निवल खरीददारी की वजह से चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बनी रही। हालांकि अगस्त में भी चलनिधि अधिशेष में ही रही पर उसके कारक बिलकुल भिन्न थे। पहला, मुद्रा विस्तार ने गति पकड़ी और प्रणालीगत चलनिधि का निकास हुआ। दूसरा, ईएमई में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, जिन्हें हांगकांग की राजनीतिक अशांति और अर्जेन्टीना के वित्तीय बाजार के धराशायी होने में देखा जा सकता है, के परिणामस्वरूप पूंजी का बहिर्वाह हुआ और जिससे विदेशी मुद्रा बाजार (बिक्री) में रिज़र्व बैंक

[5] ओएमओ में नीलामियों तथा तयशुदा सौदा प्रणाली आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफार्म दोनों के माध्यम से की गई खरीद शामिल है।

चार्ट IV.26: चलनिधि प्रबंधन

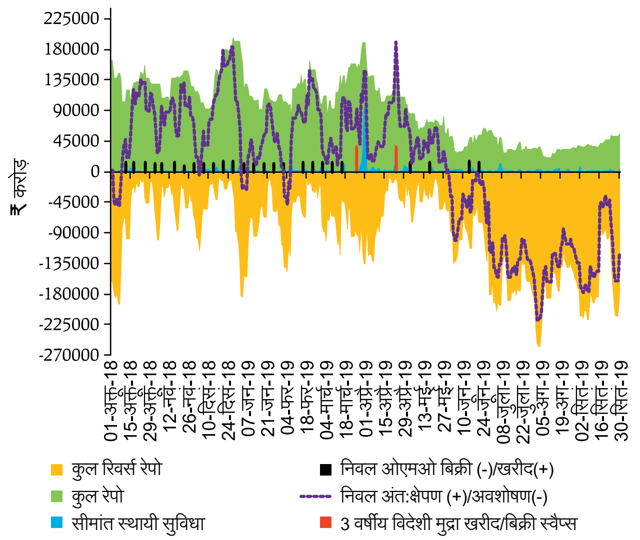

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.27: निवल एलएएफ और भारत सरकार का नकदी बकाया

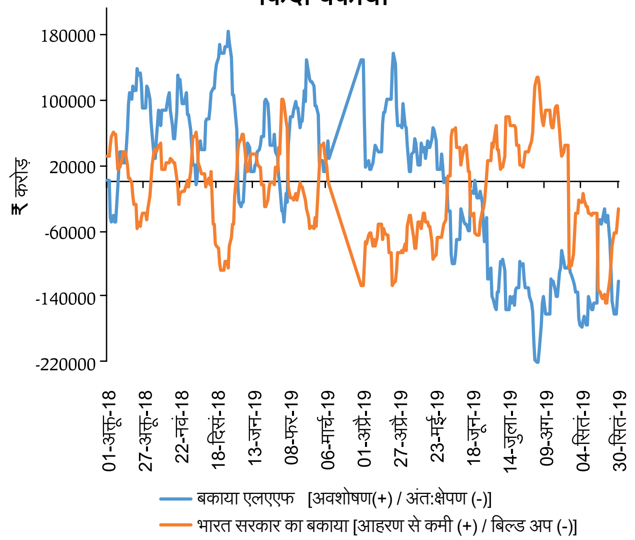

स्रोत : आरबीआई।

का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। हालांकि ये दवाब भारत सरकार के शेषों में से बड़े आहरणों में आई कमी और माह के अधिकांश भागों में केंद्र सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) का सहारा लिए जाने से भी अधिक थे। सितंबर में, 15 सितंबर के बाद विशेष रूप से अग्रिम करों की प्राप्ति से सरकारी नकदी शेष अधिक बढ़ जाने के कारण यह अधिशेष मामूली हो गया (चार्ट IV.26)। इसके बावजूद, पहली तिमाही में ₹17,409 करोड़ की राशि डाले जाने के विपरीत, 2019-20 की दूसरी तिमाही में एलएएफ़ के अंतर्गत दैनिक निवल औसत आधार पर चलनिधि का अवशोषण ₹1,31,370 करोड़ पर पहुँच गया। साथ ही,नियमित 14-दिन की सावधि रेपो के अतिरिक्त, अल्पावधि परिवर्ती दर रेपो (1-3 दिन) के माध्यम से अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया गया।

संक्षेपतः, 2019-20 की पहली छमाही में बैंकिंग व्यवस्था में टिकाऊ चलनिधि के प्रमुख कारक रिज़र्व बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा तथा नकदी विस्तार थे, जबकि प्रतिरोधात्मक चलनिधि उतार–चढ़ाव के प्रमुख कारक सरकारी व्यय थे। रिज़र्व बैंक द्वारा ओएमओ तथा अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया क्रय/विक्रय स्वैप के माध्यम से टिकाऊ चलनिधि डालने से निवल एलएएफ़ की स्थिति सरकारी नकदी शेष में उतार-चढ़ाव के रूप में प्रतिबिंबित हुई (चार्ट IV.27)। 2019-20 की पहली छमाही के दौरान सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को दो अवसरों पर 10-33 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले नकदी प्रबंधन बिलों के माध्यम से ₹50,000 करोड़ की सकल राशि जुटाकर अंशतः दूर किया गया।

2019-20 की पहली छमाही के दौरान परिवर्ती दर नीलामी के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन के परिचालनों को सुचारू रखना एक दूसरी विशेषता रही। ओवरनाइट से 14 दिनों तक की परिपक्वता अवधि वाले रेपो की नीलामी के माध्यम से चलनिधि डाली गई जबकि ओवरनाइट से 7 दिनों तक की परिपक्वता अवधि वाले रिवर्स रेपो के माध्यम से चलनिधि अवशोषित की गई (सारणी IV.6)।

सारणी IV.6: 2019-2020 की पहली छमाही में भिन्न दर नीलामी के माध्यम से फ़ाइन ट्यूनिंग परिचालन

परिचालन	**रेपो** (दिनों में परिपक्वता)				**रिवर्स रेपो** (दिनों में परिपक्वता)						
	1	**2**	**3**	**14***	**1**	**2**	**3**	**4**	**7**	**14**	**63**
फ्रिक्वेंसि (अवसरों की संख्या)	1	1	1	52	100	5	27	4	33	1	1
औसत मात्रा (₹ बिलियन)	8,825	25,003	13,300	5,09,585	65,62,076	3,65,300	16,88,773	2,90,358	4,31,458	550	800

*: नियमित 14-दिवसीय भिन्न दर रेपो परिचालन |

स्रोत : आरबीआई |

परिचालन लक्ष्य और नीतिगत दर

पहली छमाही के दौरान, डब्ल्यूएसीआर - जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है - मई-सितंबर के दौरान सामान्यतः रेपो दर के नीचे रहा (चार्ट IV.28)।

चार्ट IV.28: पॉलिसी कॉरीडोर तथा डब्ल्यूएसीआर

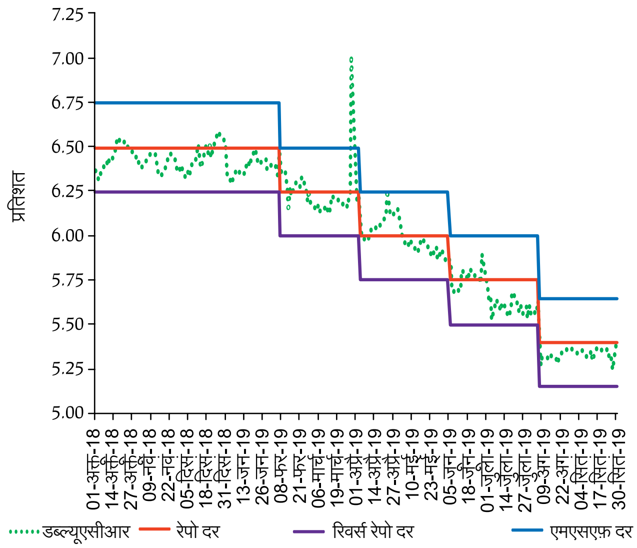

स्रोत : आरबीआई।

मौद्रिक नीति का उद्देश्य डब्ल्यूएसीआर को नीति रेपो दर के अनुरूप रखना तथा बाहरी आघातों से उत्पन्न अस्थिरता को निम्न (रिवर्स रेपो दर) और उच्च (सीमांत स्थायी सुविधा दर) सीमा द्वारा परिभाषित ब्याज दर कॉरिडॉर के भीतर रखना है। यद्यपि, ऐसे उदाहरण हैं जब डब्ल्यूएसीआर ने (i) चलनिधि स्थितियों की अनिश्चितताओं; (ii) बाजार के माइक्रोस्ट्रक्चर वाले मुद्दों जैसे कि तिमाही के अंत या वर्ष के अंत में चलनिधि की तंगी (अग्रिम कर भुगतान अथवा तुलन पत्र के कृत्रिम प्रबंधन की वजह से); (iii) मौद्रिक नीति क्रियान्वयन ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन (जैसे- टेपर टैंट्रम प्रकरण के बाद नीति रेपो दर को एमएसएफ़ दर से 300 आधार अंक ऊपर बढ़ाकर पॉलिसी कॉरिडॉर को गैर-सममित बनाना); तथा (iv) भावी ब्याज दरों के मामले में बैंकों की अपेक्षाओं के कारण, इस कॉरीडोर को तोड़ दिया। इस संदर्भ में, एक अनुभवजन्य प्रयोग वैसी घटनाओं के घटित होने में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करता है (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1: नीतिगत कॉरिडर का उल्लंघन करता डब्ल्यूएसीआर: कारक एवं निर्धारक

स्प्रेड के निर्धारक तत्वों (नीतिगत रेपो दर की तुलना में डब्ल्यूएसीआर) में बाज़ार अनुमान, जोखिम के उपाय, चलनिधि की स्थितियां तथा बाज़ार के लघु ढांचा चरांक शामिल हैं (सारणी IV.1.1)। चलनिधि स्थितियां औसत दैनिक सीआरआर आवश्यकता के अनुपात के रूप में किसी दिवस की निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) स्थिति के रूप में परिभाषित

सारणी IV.1.1: चरांकों का विवरण

चरांक	द्वारा मापित	अपेक्षित प्रभाव[6]
स्प्रेड अंतराल	स्प्रेड का पहला अंतराल (जहां स्प्रेड को भारित औसत मांग मुद्रा बाज़ार दर में से रेपो दर के घटाव के रूप में परिभाषित किया गया है)	वृद्धि
अपेक्षित अवधि के भीतर	14 दिवसीय मिबोर दर में से रेपो दर का घटाव	वृद्धि
चलनिधि अवस्थाएं	निवल एलएएफ की स्थिति/ औसत दैनिक नकद आरक्षित निधि अपेक्षा	वृद्धि
ब्याज दर अनिश्चितताएं	दो सप्ताह के नजरिया के अनुसार ब्याज दर के बारे में अनिश्चितता : गार्च (1,1) 14 दिवसीय मिबोर दर का सशर्त उतार-चढ़ाव	वृद्धि
चलनिधि अनिश्चितताएं	गार्च (1,1) आरक्षित निधि को पूरा करने संबंधी सशर्त उतार-चढ़ाव	वृद्धि
चलनिधि वितरण	एकदिवसीय बाज़ार में कुल वॉल्यूम की तुलना में मांग मुद्रा में वॉल्यूम का अनुपात	वृद्धि
कॉरिडर विड्थ डम्मी	डम्मी चरांक के रूप में कॉरिडर विड्थ - यह 0 (यदि कॉरिडर विड्थ = 100 आधार अंक अथवा इससे कम) अथवा 1 (यदि कॉरिडर विड्थ >100 आधार अंक हो) का मूल्य धारण करता है	वृद्धि
तिमाही डम्मी	तिमाही के अंत में परिणाम – तिमाही अंत के लिए मूल्य 1 होगा अन्यथा यह 0 होगा	वृद्धि

(जारी.)

[6] अपेक्षित प्रभाव असमानता के अनुपात में वृद्धि (कमी) के रूप में है। असमानता अनुपात को p/ (l-p) के रूप में परिभाषित किया गया है जहां p डब्ल्यूएसीआर द्वारा कॉरिडर नीति के उल्लंघन की संभावना को दर्शाता है।

की गई हैं। इस अनुपात में वृद्धि (कमी) चलनिधि स्थितियों में सख्ती (नरमी) को दर्शाएगा, जिसके परिणामस्वरूप घाटा वाली चलनिधि की अवस्थाओं के अधीन स्प्रेड में वृद्धि (कमी) होगी। अधिशेष चलनिधि वाली अवधियों के दौरान, इस अनुपात में वृद्धि (कमी) चलनिधि की अवस्थाओं में नरमी (सख्ती) दर्शाएगा जिसके परिणामस्वरूप स्प्रेड में कमी (वृद्धि) होगी। केंद्रीय बैंक की चलनिधि का बैंकों के बीच मनमाना वितरण डब्ल्यूएसीआर स्प्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जैसे चलनिधि के वितरण (कुछ भागीदार जो केंद्रीय बैंक की चलनिधि के अधिकांश भाग का एकाधिकारात्मक क्रय कर लेते है) में अधिक असमानता से मांग मुद्रा बाज़ार में निधियों की मांग तथा स्प्रेड में वृद्धि होने की संभावना है (लिंजर्ट एवं स्किम्ट, 2008; कुमार एवं अन्य, 2017)। इस चरांक को कुल एक-दिवसीय बाज़ार वॉल्यूम में मांग बाज़ार की लेनदेनों के हिस्सा द्वारा समीप ला दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नमूना अवधि के दौरान देखे गए विशेष प्रकृति के कारकों को ध्यान में रखते हुए, आनुभविक अभ्यास के लिए दो प्रतिरूपों का भी प्रयोग किया गया है। पहला, संबंधित अवधि हेतु चलनिधि प्रबंधन कार्यान्वयन ढांचा में बदलाव के लिए एक प्रतिरूप की शुरुआत की गई, जब टेपर-टैंट्रम के परिणामस्वरूप घरेलू वित्तीय बाज़ार में उथल-पुथल के प्रति नीतिगत जवाब के भाग के रूप में एमएसएफ दर को रेपो दर से 300 आधार अंक ऊपर तक बढ़ाया गया। तदनुसार, 17 जुलाई से 28 अक्तूबर 2013 तक के लिए प्रत्येक दिवस हेतु 1 का मूल्य ले लिया जाता है जो टेपर-टैंट्रम के बाद की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है अन्यथा 0 लिया जाता है। दूसरा, 09 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 की अवधि के लिए मूल्य 1 अन्यथा विमुद्रीकरण के बाद की अवधि के लिए 0 माना गया है जब बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी से बड़ी मात्रा में चलनिधि अधिशेष की स्थिति पैदा हुई एवं डब्ल्यूएसीआर ने कॉरिडर के निचले स्तर को पार किया, जो रिवर्स रेपो दर का नीचे गिरना है।

पूंजी प्रवाह संबंधी व्यवस्था में बदलाव पर साहित्य (फोर्ब्स और वारनॅक, 2012) में प्रयुक्त अनुभवजन्य रणनीति का अनुसरण करते हुए, मांग दर द्वारा ब्याज दर कॉरिडोर (प्रभु और भट्टाचार्य, 2019) के उल्लंघन की संभाव्यता के आकलन के लिए एक तार्किक प्रतिगमन विश्लेषण (बाइनरी लॉजिट मॉडल) किया गया।

निम्नलिखित लॉजिट मॉडल का प्रयोग किया गया :

$$L = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_o + \beta_1 X_1 + \ldots\ldots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

जहां p मांग मुद्रा दर द्वारा ब्याज दर कॉरिडोर के उल्लंघन की संभाव्यता को दर्शाता है। इसमें L लॉजिट फंक्शन है तथा X_k स्वतंत्र चरांकों के वेक्टर को दर्शाता है। इस मॉडल का आकलन मई 2011 से जून 2019 तक की अवधि में 1960 अवलोकनों को शामिल करते हुए दैनिक डेटा के आधार पर किया गया है (सारणी IV.1.2)।

परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि चलनिधि वितरण संबंधी दिशाहीनता में वृद्धि से मांग दर द्वारा ब्याज दर कॉरिडोर के उल्लंघन संबंधी असमानताओं में बढ़ोतरी होगी। उसी तरह, चलनिधि स्थितियों (बैंकों की सीआरआर अपेक्षाओं के सापेक्ष आरबीआई द्वारा अधिक प्रवाह) में वृद्धि तथा ब्याज दर अनिश्चितताओं में वृद्धि, ब्याज दर कॉरिडर के बाहर स्थित मांग दर की असमानताओं में भी बढ़ोतरी करती है।

सारणी IV.1.2: लॉजिट मॉडल – परिणाम

चरांक	असमानता अनुपात
1	2
स्प्रेड अंतराल	1.002 (0.587)
अपेक्षित अवधि के भीतर	1.001* (0.093)
चलनिधि अनिश्चितता	1.01 (0.856)
चलनिधि का वितरण	1.05*** (0.000)
ब्याज दर अनिश्चितता	1.01*** (0.005)
चलनिधि की अवस्थाएं	1.001** (0.042)
तिमाही डम्मी	3.25** (0.022)
टेपर-टैंट्रम के बाद डम्मी	5.10** (0.050)
कॉरिडोर विड्थ डम्मी	4.39*** (0.000)
विमुद्रीकरण डम्मी	0.301 (0.109)
स्थिरांक	0.01*** (0.000)
नैदानिक परीक्षण	
एलआर chi^2 परीक्षण	112.3 (0.00)
मैकफेडेन का R^2	0.140
अवलोकनों की संख्या	1960

*** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$.

नोट : कोष्ठकों में सामान्य त्रुटियाँ

(जारी.)

तिमाही डम्मी यह दर्शाता है कि जब सभी अन्य चरांकों को समान स्थिति में रखा जाए तो मांग दर तिमाही के अंत में कॉरिडोर के आगे रहने पर असमानताएं, गैर-तिमाही-अंत के दिनों की असमानताओं जैसी 3.25 गुना बड़ी हैं। उसी तरह से, टेपर-टैंट्रम के बाद डम्मी दर्शाती है कि उथल-पुथल के दिनों में टेपर-टैंट्रम के बाद, मांग दर द्वारा ब्याज दर कॉरिडोर के उल्लंघन संबंधी असमानताएं, वित्तीय बाज़ार में अशांति से प्रभावित नहीं रहने वाले दिनों की असमानताओं जैसी 5.1 गुना अधिक बड़ी हैं। अंत में, कॉरिडोर विड्थ डम्मी (कॉरिडर विड्थ ≥ 100 आधार अंक 1 है अन्यथा यह 0 है) दर्शाता है कि जब कॉरिडोर विड्थ 100 आधार अंक से अधिक हो तब मांग दर की ब्याज दर कॉरिडोर को पार करने संबंधी असमानताएं, कॉरिडोर कॉरिडर विड्थ के 100 आधार अंक कम रहने की स्थिति में विद्यमान असमानताओं जैसी 4.39 गुना बड़ी हैं।

नीति के दृष्टिकोण से, अनुभवजन्य अभ्यास केंद्रीय बैंक के चलनिधि प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि मनमाने चलनिधि वितरण के कारण डब्ल्यूसीएआर कॉरिडोर से विचलित हो सकता है। अतः, चलनिधि प्रबंधन संबंधी कार्यों एवं प्रथाओं को कतिपय बाज़ार भागीदारों के बीच चलनिधि संकेंद्रण को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसी तरह, उभरती चलनिधि की स्थितियों पर बेहतर सूचना के माध्यम से भावी मार्गदर्शन द्वारा बाज़ार की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है तथा स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। अंततः, चलनिधि पूर्वानुमान को, खास तौर पर संकीर्ण ब्याज दर कॉरीडोर व्यवस्था में, सटीक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि पूर्वानुमान की बड़ी त्रुटियाँ मांग दर द्वारा ब्याज दर कॉरीडोर को किसी भी दिशा में उल्लंघन किए जाने की संभावना बढ़ा देती हैं।

संदर्भ:

फोर्ब्स, के, जे. और एफ. ई वार्नोक (2012), "कैपिटल फ्लो वेव्स: सर्जेज, स्टॉप्स, फ्लाइट एंड रिट्रेंचमेंट", जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 88 (2), 235-251।

लिंजर्ट, टी., और एस. स्किम्ट (2011), "वॉट एक्सप्लेन्स द स्प्रेड बिटवीन द यूरो ओवरनाइट रेट एंड द ईसीबीज पॉलिसी रेट?", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 16 (3)।

कुमार, एस., प्रकाश, ए., और के. एम. कुशवाहा, (2017), " वॉट एक्सप्लेन्स कॉल मनी रेट स्प्रेड इन इंडिया?", आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज़, डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर): 07/2017।

प्रभु, ई., और आई. भट्टाचार्य (2019), "मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डब्ल्यूएसीआर स्प्रेड" मीमेयो।

चार्ट IV:29: रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड

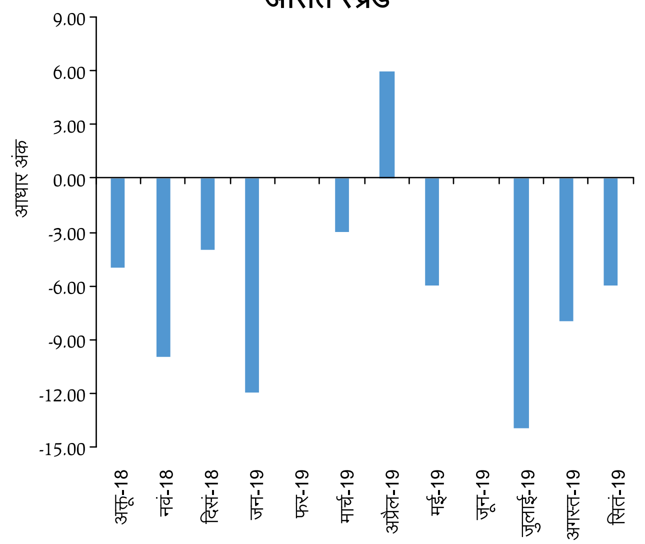

स्रोत : आरबीआई।

डब्ल्यूएसीआर अप्रैल में नीतिगत रेपो दर (औसतन) से 6 आधार अंक ऊपर रहा तथा समान अंतर के साथ मई में यह नीतिगत रेपो दर से कम रहा। तथापि, जून में यह नीतिगत रेपो दर के काफी नजदीक बना रहा (चार्ट IV.29)। आगे,डब्ल्यूएसीआर जुलाई में नीतिगत रेपो दर (औसतन) से 14 आधार अंक तक, अगस्त में 8 आधार अंक तक एवं सितंबर में 6 आधार अंक तक नीचे ट्रेड किया। समग्र रूप से, डब्ल्यूसीएआर वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के 6 आधार अंक की तुलना में, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में नीतिगत रेपो दर से 5 आधार अंक तक नीचे ट्रेड किया।

IV.4 निष्कर्ष

वैश्विक प्रतिकूलता और भू-राजनैतिक संशयों के प्रति घरेलू वित्तीय बाजारों में कमजोरी बनी रही। चुनाव-उपरांत बाहुल्य के बाद, वैश्विक गतिविधियों और आर्थिक क्रियाकलापों में मंदी की प्रतिक्रियास्वरूप,

इक्विटी बाजार जोखिम-विमुख बन गए। अगस्त में पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव रहा और इससे मुद्राओं पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ा। इसके विपरीत, बॉण्ड बाजार में उल्लेखनीय उछाल आया,बावजूद इसके कि हाल ही की अवधि में इसमें कुछ सुधार भी हुआ था। हालांकि क्रेडिट संवृद्धि में धीमापन रहा, जो मंद आर्थिक संभावनाओं को प्रकट करता है। आगे चलकर, चलनिधि स्थितियों का प्रबंध नीतिगत रेपो दर के साथ डब्लूएसीआर को संरेखित करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ चलनिधि जरूरतों को मौद्रिक नीति रुख के अनुरुप पर्याप्त रूप में पूरा किया जाए। बैंकों की ऋण ब्याज दरों में तीव्रतर मौद्रिक संचरण सुनिश्चित करना एक अहम प्राथमिकता बनी हुई है।

V. बाह्य परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक गतिविधियां धीमी बनी हुई हैं क्योंकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईज़) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) में गिरावट आई है। 2019 की दूसरी तिमाही में बढ़ती व्यापार और भू-राजनैतिक अनिश्चितताएं निकटतम अवधि परिदृश्य को धूमिल बना रही हैं। मामूली मुद्रास्फीति के चलते संवृद्धि संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए पूरे विश्व में मौद्रिक नीति को सुकर बनाया जा रहा है। ब्रेक्जिट के इर्द गिर्द अनिश्चितताओं और यूएस टेरिफ कार्रवाइयों के क्रम के अज्ञात परिणामों के मद्देनजर वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं।

अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) से वैश्विक गतिविधियां कमजोर हुई हैं और व्यापार एवं भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण निकट अवधि परिदृश्य धूमिल बना हुआ है। 2019 की दूसरी तिमाही में अधिकांश प्रमुख उन्नत अर्थव्यस्थाओं (एईज़) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) में गिरावट आई। मांग-आपूर्ति संतुलन बिगड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है जिसका प्रमुख कारण हाल में दूसरे सबसे बडे तेल निर्यातक- सऊदी अरब द्वारा आपूर्ति संबंधी बाधा थी जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 5 प्रतिशत है। वैश्विक मांग में कमी होने के कारण अन्य वैश्विक पण्यों की कीमतें नरम बनी रहीं। मामूली मुद्रास्फीति के चलते संवृद्धि संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए विश्व के सभी केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को सुकर बनाया है। 2019 के आरंभ से वैश्विक वित्तीय बाजार की विशेषता शांति थी, किन्तु वह व्यापार और भू-राजनैतिक तनावों के संयोग तथा बिगड़ते वैश्विक संवद्धि परिदृश्य से बढ़ी अस्थिरता के कारण मई 2019 के बाद से गायब हो गई।

V.1 वैश्विक आर्थिक स्थितियां

प्रमुख एईज़ और ईएमईज़ में आर्थिक गतिविधियां गति खोती जा रही हैं। यूएस में, निर्यात में कमी और कमजोर व्यापार निश्चित निवेश के कारण वास्तविक जीडीपी वृद्धि (ति-दर-ति, वार्षिकीकृत) 2019 की पहली तिमाही में बढ़ने के बावजूद दूसरी तिमाही में 2.0 प्रतिशत तक गिर गई (सारणी V.1)। प्राप्त हो रहे आंकड़ों से पता चलता है कि स्लोडाउन तीसरी तिमाही में भी जारी रहेगा, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन धीमा बना हुआ है और निर्यात घटना जारी है। आपूर्ति प्रबंधन संस्थान का विनिर्माण सूचकांक सितंबर में और अधिक गिरकर संकुचन जोन में पहुँच गया जो एक दशक में सबसे निम्नतम रीडिंग की ओर संकेत करता है। फिर भी, सुदृढ़ उपभोक्ता खर्च, जो बढ़ती खुदरा बिक्री में प्रदर्शित होता है, कुछ हद तक स्लोडाउन को कम करेगा।

यूरो क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि 2019 की दूसरी तिमाही में कम हो गई क्योंकि इसके प्रमुख घटक अर्थव्यवस्थाओं ने ब्रेक्जिट और व्यापार तनावों की अनिश्चितताओं के बीच अपनी गति खो दी। गिरते निर्यातों के बीच संघर्षरत वाहन उद्योग के कारण जर्मन अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में संकुचन हुआ; यह कमजोरी, तीसरी तिमाही में भी जारी रही क्योंकि सितंबर में विनिर्माण पीएमआई कमी वाले क्षेत्र में रही

सारणी V.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (तिमाही-दर-तिमाही, वार्षिकी)

(प्रतिशत)

देश	ति2-2018	ति3-2018	ति4-2018	ति1-2019	ति2-2019	2019 (पी)	2020 (पी)
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ							
कनाडा	2.5	2.1	0.3	0.5	3.7	1.8	1.7
यूरो क्षेत्र	1.6	0.8	1.2	1.6	0.8	1.6	1.5
जापान	1.9	-1.9	1.8	2.2	1.3	0.2	1.4
दक्षिण कोरिया	2.4	2.0	3.6	-1.6	4.0	2.6	2.8
यूके	2.0	2.4	1.2	2.4	-0.8	1.2	1.6
यूएस	3.5	2.9	1.1	3.1	2.0	2.3	1.9
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ							
ब्राज़ील	-0.4	2.0	0.4	-0.4	1.6	1.3	2.5
चीन	6.8	6.4	6.0	5.6	6.4	6.1	5.9
मलेशिया	2.4	6.0	5.2	4.4	4.0	4.6	4.8
मेक्सिको	-0.8	2.0	0.3	-1.0	0.1	1.3	1.6
रूस *	2.2	2.2	2.7	0.5	0.9	2.0	1.0
दक्षिण अफ्रीका	-0.5	2.6	1.4	-3.1	3.1	1.0	0.3
थाईलैंड	4.3	-0.9	3.6	4.1	2.4	3.9	3.7
मेमो:	**2018 (ई)**			**2019 (पी)**			**2020 (पी)**
विश्व उत्पादन	3.6			3.2			3.5
विश्व व्यापार मात्रा	3.7			2.5			3.7

ई: अनुमान, पी : पूर्वानुमान , *: वर्ष- दर- वर्ष संवृद्धि

स्रोत : ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ)।

जिससे लगातार नौंवे महीने में भी फैक्टरी गतिविधियों में संकुचन रहा। इटली में दूसरी तिमाही में जीडीपी संवृद्धि स्थिर रही क्योंकि सेवा क्षेत्र की तेजी ने उद्योग और कृषि गतिविधियों में आई कमी को समायोजित कर दिया, हालांकि ऋण संकट और इस समय चल रही राजनैतिक अनिश्चितताएं इसके नकारात्मक जोखिम हैं।

अमेरिका-चीन के बढ़ते व्यापार तनावों और सुस्त वैश्विक मांग से व्यापार व्यय में तेज निम्नगामी संशोधन के कारण जापानी अर्थव्यवस्था पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में धीमी गति से बढ़ी। इसने निर्धारित बिक्री कर में वृद्धि सहित 2019 की शेष अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। फिर भी , बिक्री कर में वृद्धि से पहले की त्वरित ख़रीदारी और राजकोषीय प्रोत्साहन से तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलने की उम्मीद है। ब्रेक्सिट अनिश्चितता के बाद अप्रैल में कार संयंत्रों की योजनाबद्ध तरीके से पूर्व बंदी किए जाने के कारण विनिर्माण गतिविधियों में आई गिरावट से दूसरी तिमाही के दौरान यूके की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में संकुचन आया। कठिन ब्रेक्सिट सौदे के संभावित जोखिमों और उभरते वैश्विक व्यापार की स्थितियों ने निकट- अवधि दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

वैश्विक आर्थिक स्थितियों के कमजोर होने से प्रमुख ईएमईज़ में आर्थिक गतिविधियां धीमी रहीं। अमेरिका के साथ लंबे और अनसुलझे व्यापार विवाद के प्रतिकूल असर और वैश्विक मांग के धीमेपन के प्रभाव से चीन की अर्थव्यवस्था में लगभग 27 वर्षों में सर्वाधिक कमजोर गति से दूसरी तिमाही में (वर्ष दर वर्ष) गिरावट दर्ज हुई। उपलब्ध उच्च आवृत्ति के संकेतक बतलाते हैं कि यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में जुलाई माह से गिरावट आई है जबकि कमजोर मांग के बीच विनिर्माण पीएमआई कम बनी रही। जबकि, बढ़ते आंतरिक और बाह्य प्रहार से समग्र जोखिम निम्नगामी बने रहे, राजकोषीय और मौद्रिक दोनों मोर्चों पर नीतिगत प्रोत्साहन से स्लोडाउन की गति में कमी आने की उम्मीद है।

ब्रिक्स की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच, रूसी अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में तीव्र गिरावट दर्ज करने के बाद पुनः गति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। जबकि आर्थिक गतिविधि में दूसरी तिमाही में थोड़ी वृद्धि देखी गई। आने वाले डेटा ने तीसरी तिमाही में कमजोरी के संकेत दिए हैं क्योंकि उपभोक्ता मांग धीमी बनी हुई है और जुलाई से औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में कमी आई है। फिर भी, भविष्य में राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं पर किए जा रहे उच्च राजकोषीय व्यय, कुल मांग को समर्थन कर सकते हैं।

ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष में सुस्त शुरूआत के बाद दूसरी तिमाही में गति हासिल की। दूसरी तिमाही में मजबूत मीयादी निवेश और निर्माण गतिविधियों के व्यापक तौर पर समर्थन से ब्राज़ील की आर्थिक स्थिति में पुनः सुधार आया। हालांकि, समायोजी मौद्रिक नीति के मद्देनज़र बढ़ी हुई मांग से विस्तार को बरकरार रखने की उम्मीद है, किन्तु घरेलू और बाहरी दोनों चुनौतियों के जोखिम इस गति को कम कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में, खनन और विनिर्माण में मजबूत वृद्धि के कारण आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, इससे पहली तिमाही में देखी गई उत्पादन की कमी में भरपाई हुई। हालाँकि, खपत प्रधान आर्थिक रिकवरी धीरे-धीरे होने की उम्मीद है क्योंकि अनिश्चित वैश्विक दृष्टिकोण और ऋण-ग्रस्त घरेलू बिजली उपयोगिताओं का अर्थव्यवस्था की समग्र संभावनाओं पर प्रभाव जारी रह सकता है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच, धीमे निवेश और निर्यात में गिरावट के कारण इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था 2019 की पहली दो तिमाहियों में 5.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक धीमी हो गई। थाईलैंड में स्लोडाउन, जो पहली तिमाही शुरू हुआ और दूसरी तिमाही (वर्ष दर वर्ष) तक जारी रहा, लगभग पाँच वर्षों में धीमी वृद्धि को दर्शाता है। संघर्षरत कृषि क्षेत्र, धीमे निर्यात और अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने के कारण स्लोडाउन आया। मुद्रा संकट के कारण पिछले साल की मंदी से उबरते हुए तुर्की अर्थव्यवस्था ने 2019 की पहली छमाही में सकारात्मक वृद्धि (ति-दर-ति) दर्ज की। अधिक सरकारी व्यय और ऋण विस्तार के माध्यम से पहली तिमाही में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से आर्थिक स्थिति के पुनः बहाली को समर्थन मिला।

जुलाई में मामूली वृद्धि दर्ज करने के बाद समग्र वैश्विक पीएमआई अगस्त में गिर गई, क्योंकि धीमा वैश्विक व्यापार समग्र निर्यात वृद्धि पर भारी पड़ा (चार्ट V.1 ए)। प्रमुख ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं

चार्ट V.1: सर्वेक्षण संकेत

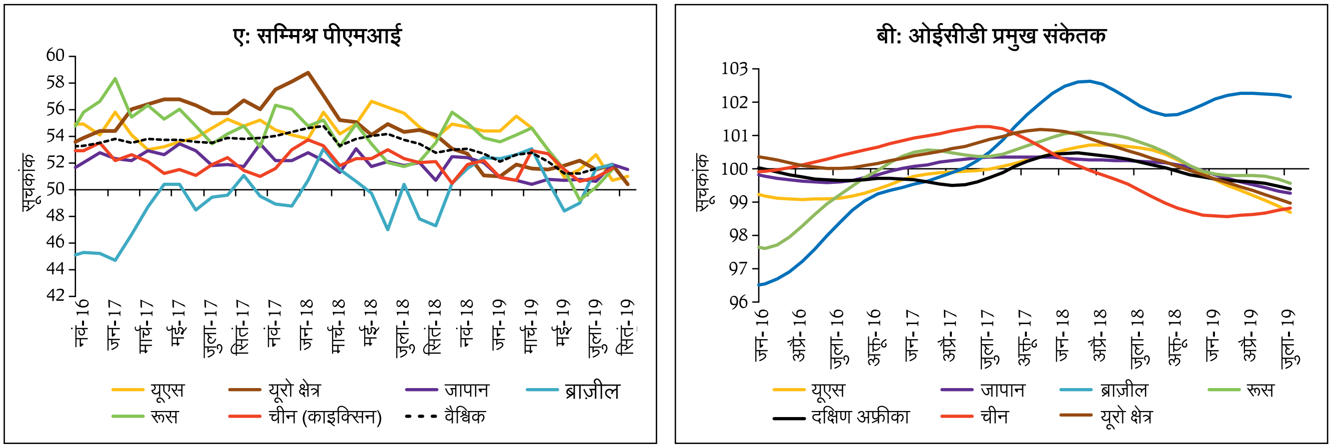

स्रोत : ब्लूमबर्ग; और आर्थिक सहकार्य एवं विकास संस्थान।

में, कम्पोजिट लीडिंग संकेतक (सीएलआई) ब्राजील को छोड़कर प्रमुख एईज़ और ईएमईज़ में संवृद्धि की गति को धीमी बतलाते हैं (चार्ट V.1बी)।

वैश्विक व्यापार में स्लोडाउन, जो 2018 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, 2019 में जारी रहा जिसमें 2019 में संकुचन में जाने वाली ईएमईज़ ने योगदान दिया (चार्ट V.2ए)। भावी संकेतकों से ज्ञात होता है कि विश्व व्यापार के 2019 में और धीमा होने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर[3] अपने रुझान स्तर से नीचे रहा जो अपने सभी घटक सूचकांकों विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई माल भाड़ा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑटोमोबाइल उत्पादन में सुस्त प्रदर्शन के कारण था। अन्य संकेतकों जैसे वालटिक ड्राइ इंडेक्स में हुए उतार-चढ़ाव बताते हैं कि विश्व व्यापार में स्लोडाउन बना रहेगा (चार्ट V.2बी)।

V.2 पण्य कीमतें और मुद्रास्फीति

व्यापार तनाव के बढ़ने से वैश्विक पण्य कीमतों में कमजोरी आयी। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में अप्रैल और सितंबर 2019 के बीच 4.1 फीसदी तक की गिरावट हुई।

अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन(एफ़एओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक खाद्य कीमतों में लगातार मई के पांचवें महीने में वृद्धि हुई जो निर्यात आपूर्ति कम होने के कारण डेयरी और मक्का की ऊंची कीमतों के चलते

चार्ट V.2: विश्व व्यापार मात्रा

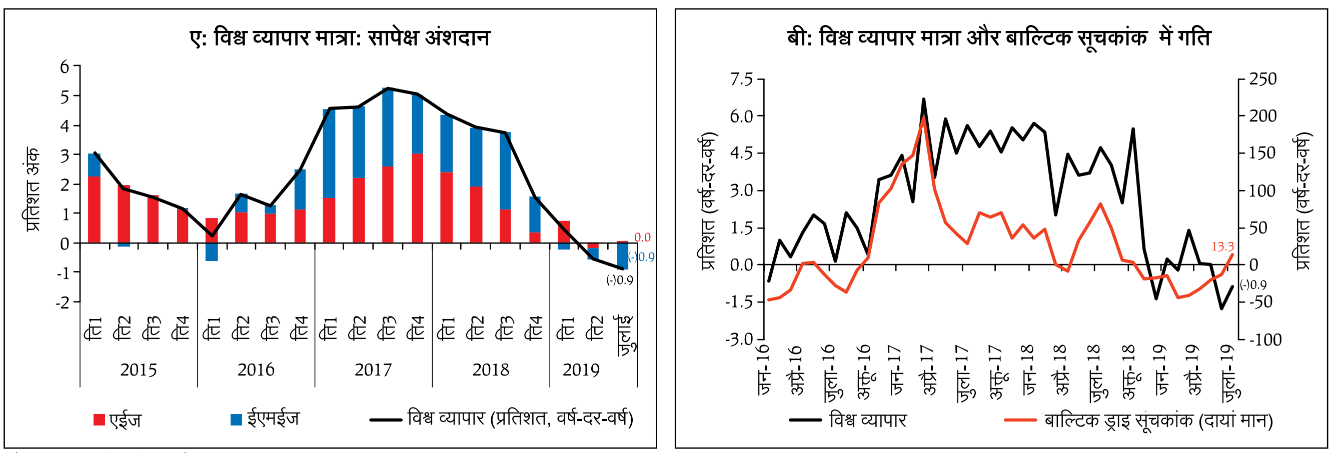

स्रोत : सीपीबी नेदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

[1] विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार आउटलुक संकेतक (डब्ल्यूटीओआई) को डब्ल्यूटीओ के माल व्यापार बैरोमीटर के साथ बदल दिया है।

चार्ट V.3: पण्य कीमतें

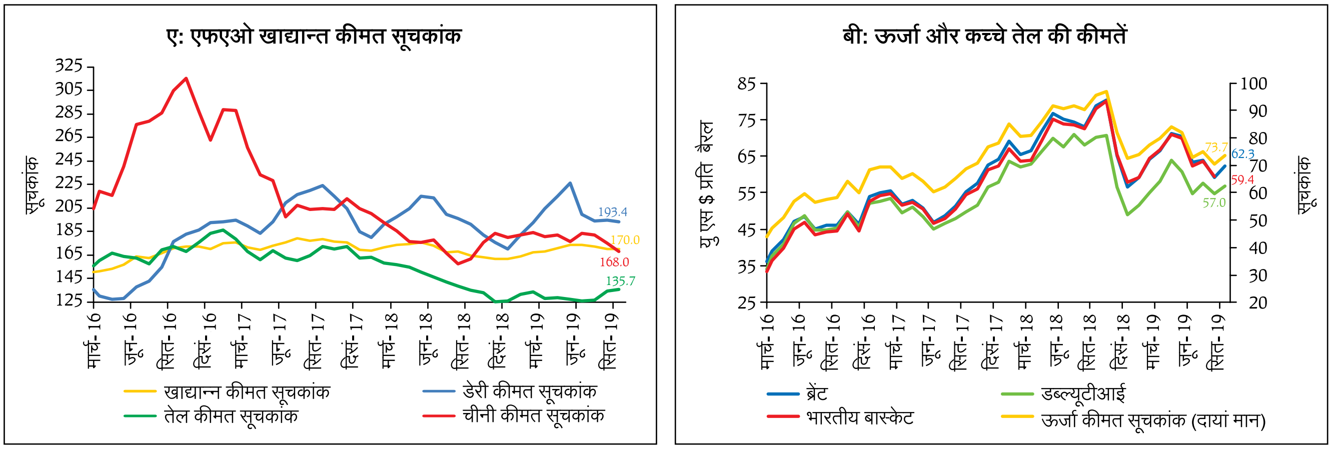

स्रोत : खाद्यान्न व कृषि संस्थान (एफएओ); और विश्व बैंक।

थी। हालांकि, इसमें जून-जुलाई में मामूली गिरावट आई क्योंकि कमजोर मांग के कारण डेयरी के मूल्य गिरे। अनाज और चीनी की कीमतों में तेज गिरावट के कारण अगस्त में वैश्विक खाद्य कीमतों में मामूली गिरावट आई। जबकि अनाज की कीमतें पर्याप्त निर्यात आपूर्ति के कारण गिर गईं, ब्राजील रियाल के कमजोर होने और भारत तथा मैक्सिको के द्वारा बड़े लदान की संभावनाओं ने चीनी की कीमतों को कम रखा (चार्ट V.3ए)। वैश्विक खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव ने ईएमईज़ में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाला है (बॉक्स V.1)।

अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध और प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा नौ महीने तक आपूर्ति कटौती को बढ़ाने के समझौते से मई की शुरुआत में तेल की कीमतें बढ़ गईं। हालांकि, सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बडी तेल प्रसंस्करण सुविधा से आपूर्ति में व्यवधानों के कारण, 16 सितंबर, 2019 को सबसे बड़े एक दिवसीय लाभ को हासिल करने से पहले, पर्याप्त आपूर्ति के बीच तेल की मांग में प्रत्याशित गिरावट ने बाजार की तंगी और कीमतों को कम कर दिया (चार्ट V.3बी)। इसके पश्चात आपूर्ति पुन: बहाल होने की प्रत्याशाओं से इसमें सुगमता आई(चार्ट V.3बी)।

अप्रैल-सितंबर 2019 के बीच, ब्लूमबर्ग बेस मेटल स्पॉट इंडेक्स द्वारा मापी गई आधार धातु की कीमतों में 9.0 प्रतिशत की गिरावट आई, जो संवृद्धि दृष्टिकोण संबंधी बढ़ी निराशा और लगातार व्यापार तनाव के चलते वैश्विक मांग के धीमी होने के कारण थी। लेकिन, प्रमुख निर्यातकों द्वारा लौह अयस्क और निकेल की आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण उनमें जुलाई में मामूली रूप से सुधार हुआ; तबसे इनका सीमित मात्रा में कारोबार हो रहा है क्योंकि बाज़ार को व्यापार के फ्रंट पर और गतिविधियों की प्रतीक्षा है। व्यापार अनिश्चितताओं के चलते घटती मांग के कारण तांबे की कीमतों में तेजी से गिरावट आई जिनमें चिली की खदानों में हड़ताल और चीन द्वारा शोधित तांबे के उत्पादन में कमी के कारण जून में छुटपुट रूप से बढ़ोतरी हुई। सुरक्षित निवेश ठिकानों की मांग के कारण स्वर्ण की कीमतें ऊंचाई पर बनी रहीं, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी हुई है (चार्ट V.4)।

एईज़ तथा ईएमईज़ में मुद्रास्फीति सौम्य रही। एईज़ के बीच, श्रम बाज़ार में कमी के बावजूद यूएस में सीपीआई मुद्रास्फीति शिथिल

चार्ट V.4: धातु कीमत सूचकांक

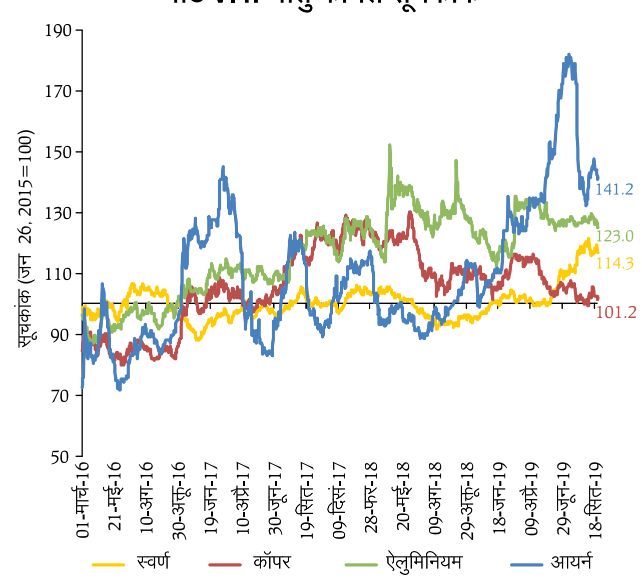

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

बॉक्स V.1 : अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतें – ईएमईज़ को अंतरण

कई ईएमईज़ में अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतें घरेलू खाद्य मूल्यों में अंतरों की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं क्योंकि इन देशों में घरेलू खर्च में भोजन की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। विश्व बैंक के खाद्य मूल्य सूचकांक में 2007 में 23.8 प्रतिशत, 2008 में 33.5 प्रतिशत और 2011 में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सभी खाद्य समूहों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। हालाँकि इन प्रसंगों में मूल्य वृद्धि की तादात लगभग समान थी, लेकिन प्रभावित वस्तुएं अलग-अलग थीं (चार्ट V.1.1)। जहां 2007-08 के दौरान चावल, गेहूं, तेल और अनाज की कीमतें बहुत अधिक रहीं, वहीं चीनी की कीमतें कम रहीं। चावल की कीमतें पहले प्रसंग के दौरान सबसे ज्यादा थीं लेकिन दूसरे प्रसंग के दौरान कई अन्य अनाज उत्पादों की तुलना में कम थीं।

एक मूल्य के नियम (एलओपी) (आर्डेनी, 1989; बाराहोना और चुलाफन, 2017) के अनुसार, परिवहन लागत या व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं मानते हुए, एकल समरूप वस्तु की कुशल बाजार में, एक आम मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को निम्नलिखित समीकरण के अनुसार समान रूप से दर्शाया गया है :

$$P_d = ER*P_w \qquad \ldots(1)$$

जहां ईआर विनिमय दर है [विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई घरेलू मुद्रा की इकाई(यों)], P_w वैश्विक(विदेशी) खाद्य कीमत है और P_d

चार्ट V.1.1: प्रमुख खाद्य वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्य

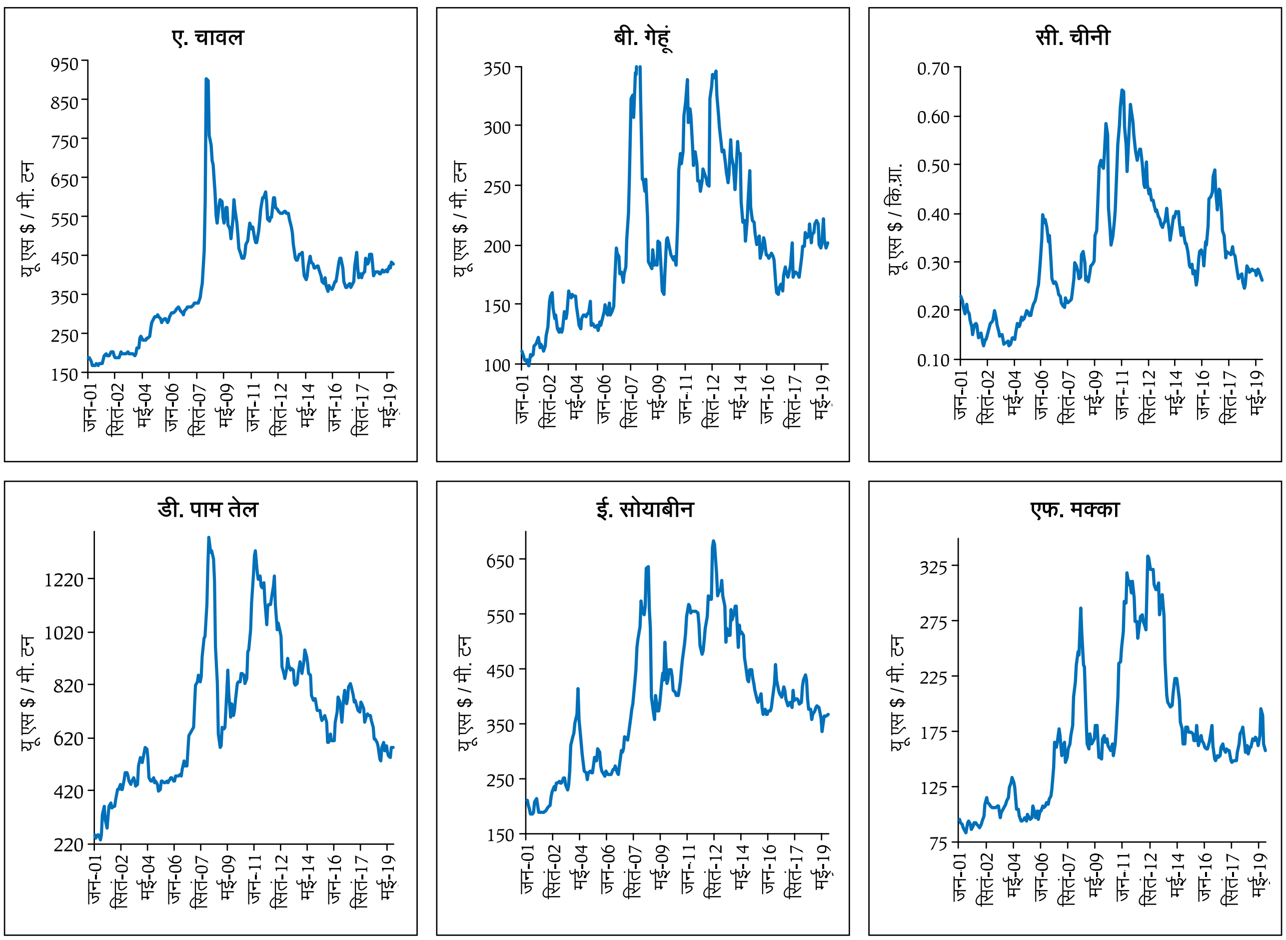

टिप्पणी : अंतिम डेटा बिंदु सितंबर 2019 के लिए है।
स्रोत : द वर्ल्ड बैंक पिंक शीट डेटावेस।

घरेलू खाद्य कीमत है। समीकरण (1) के अनुमानित वर्शन को एक कमजोर एलओपी परिकल्पना के रूप में संशोधित किया जा सकता है जो प्राकृतिक लघुगणक रूप में निम्नानुसार है :

$$\ln P_d = \alpha + \beta \ln P_w + \gamma \ln ER + e_t \quad \ldots(2)$$

ईआर को स्पष्ट रूप से एक बाह्य चर माना जाता है, क्योंकि ईएमईज़ आम तौर पर मूल्य लेने वाले होते हैं और β दीर्घावधि सम्बन्धों की उपस्थिति में दीर्घकालिक मूल्य संचरण प्रत्यास्थता है। निम्नलिखित प्रकार के त्रुटि सुधार मॉडल (ईसीएम) से अल्पकालिक मूल्य प्रत्यास्थता का अनुमान लगाया जा सकता है :

$$\Delta P_{d_t} = \delta + \sum_{i=1}^{k} \rho_i \Delta P_{d_{t-i}} + \sum_{i=1}^{l} \varphi_i \Delta P_{w_{t-i}} + \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \Delta ER_{t-i} + \theta ECT_{t-1} + \epsilon_t \quad \ldots(3)$$

जहां Δ पहला अंतर ऑपरेटर है, ECT त्रुटि सुधार शब्द है और φ अल्पकालिक मूल्य संचरण प्रत्यास्थता है। समीकरण (3) में ECM में एक गतिशील संबंध के रूप में घरेलू और विदेशी कीमतें निहित हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, विश्व खाद्य मूल्य में परिवर्तन के पासथ्रू (अंतरण) की घरेलू खाद्य मूल्य में छह ईएमईज़ अर्थात ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और तुर्की के संदर्भ में जांच की गई क्योंकि उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इन देशों के खाद्य पदार्थों का बहुत अधिक हिस्सा है (साहू एवं अन्य 2019)। जनवरी 2007 से जुलाई 2019 के मासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह पाया गया कि इनमें से प्रत्येक चर अर्थात वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक, देश-विशिष्ट खाद्य मूल्य सूचकांक और विनिमय दर क्रम एक अर्थात I (1) के साथ एकीकृत है। इसलिए, सहएकीकरण संबंध के अस्तित्व की जांच वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (वीईसीएम) के माध्यम से की गई थी। प्रत्येक मॉडल की अंतराल लंबाई अकाइके सूचना मानदंड (एआईसी) पर आधारित थी। अनुमानित वीईसीएम मॉडल पुष्टि करते हैं कि शेष क्रमिक रूप से सहसंबद्ध नहीं हैं।

अनुमानित अल्प-कालिक और दीर्घ-कालिक संचरण प्रत्यास्थता से पता चलता है कि विश्व खाद्य कीमतों से घरेलू खाद्य कीमतों में मूल्य संचरण का परिमाण भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग है

सारणी V.1.1: अनुमानित विश्व खाद्य मूल्य पासथ्रू गुणांक अंतरण

देश	दीर्घकालिक	अल्प-कालिक
ब्राज़ील	1.136***	0.024*
चीन	0.179**	0.029*
भारत	0.038***	0.054*
इंडोनेशिया	0.355***	0.082***
थाईलैंड	0.933***	0.040*
तुर्की	0.055***	0.130***

नोट : ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(सारणी V.1.1)। सभी संचरण प्रत्यास्थताएं सकारात्मक हैं और शून्य से अलग हैं तथा तुर्की और भारत को छोड़कर अल्प-कालिक प्रत्यास्थताएं दीर्घ-कालिक प्रत्यास्थताओं से कम हैं। भारत में खाद्य मूल्य के लिए अल्प-कालिक मूल्य संचरण प्रत्यास्थता 0.05 है, जिसका अर्थ है कि यदि विश्व खाद्य मूल्य में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो भारत में खाद्य सीपीआई में पांच आधार अंकों की वृद्धि होगी।

संक्षेप में, उच्च और अस्थिर खाद्य कीमतें दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती पेश करती हैं और उन ईएमईज़, विशेष रूप से जो बहुत ज्यादा खाद्य आयात करते हैं, के लिए घरेलू मुद्रास्फीति के निहितार्थ हैं।

संदर्भ :

आर्डेनी, पी. जी. (1989), “डज द लॉ ऑफ वन प्राइस रियली होल्ड फॉर कमोडिटी प्राइसेज ?”, अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, 71(3), भाग 71, नं. 3, पीपी 661-669।

बाराहोना, जे. एफ. एंड डब्ल्यू. चुलाफन (2017), “प्राइस ट्रांसमिशन बिटवीन वर्ल्ड फूड प्राइसेज एंड डिफरेंट कंज़्यूमर फूड प्राइस इंडाईसीस इन थाईलैंड”, कॉसेटसार्ट जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117300206?via%3Dihub.पर उपलब्ध है।

रही क्योंकि संसाधन के उपयोग के स्तर तक मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता निम्न रही। तथापि, ऊर्जा की कीमतों में सुधार होने से जुलाई माह में इसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई। मूलभूत निजी उपभोग व्यय (पीसीई), जो फेड का पसंदीदा मुद्रास्फीति मापक है,जून से बढ़ रह है लेकिन यह यूएस फेड के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। यूरो क्षेत्र में, ऊर्जा कीमतों में कमी तथा कमजोर होती संवृद्धि की वजह से मुद्रास्फीतिक दबावों में नरमी आई। जापान में, खाद्य, परिवहन एवं संचार की गिरती कीमतों के चलते सीपीआई मुद्रास्फीति धीमी रही। (चार्ट V.5 ए)।

कई ईएमईज़ में मुद्रास्फीति कम हो रही है। रूस में, उपभोक्ता मांग कम रहने की वजह से दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति कम रही, जबकि मजबूत फसल होने के चलते आसान आपूर्ति तथा रूबल की बढ़ती कीमतों ने अवस्फीति की स्थितियाँ पैदा कीं। बाजील में, साफ्ट फूड तथा ईंधन की कीमतों में नरमी की वजह से सीपीआई मुद्रास्फीति में अप्रैल माह से गिरावट हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में , मुद्रास्फीति ईंधन की गिरती कीमतों के कारण दूसरी तिमाही में स्थिर रहने के बाद जुलाई माह में कम हुई। तथापि, अगस्त माह में खाद्य सामग्री तथा आवास की कीमतों के बढ़ने से इसमें बढ़ोतरी हुई। तुर्की की मुद्रास्फीति जिसमें अप्रैल माह से गिरावट हो रही थी, जून माह में इसमें तेजी से गिरावट आई जो अनुकूल आधार प्रभाव तथा खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी के कारण थी। अगस्त माह में पुनः गिरावट की स्थिति में आने से पूर्व, म्यूनिसिपल कीमतों के बढ़ने के कारण उच्च स्तर की सेवा कीमतों में जुलाई माह में मामूली सी बढ़ोतरी हुई (चार्ट V.5बी)।

V.3 मौद्रिक नीति रुझान

प्रमुख एईज़ तथा ईएमईज़ में मौद्रिक नीति निभावकारी बनी रही। अमेरिकी फेड ने जारी व्यापार अनिश्चितताओं तथा कम मुद्रास्फीतिक दबावों की चिंताओं के मद्देनजर जुलाई 2019 से दो बार अपनी नीतिगत दरों में कटौती की (चार्ट V. 6 ए)। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अपनी जमा दरों को और घटाते हुए उन्हें ऋणात्मक क्षेत्र तक पहुंचा दिया, साथ ही नवंबर 2019 की शुरुआत से प्रति माह 20 बिलियन यूरो मूल्य के बॉण्डों की खरीद के रूप में मौद्रिक प्रोत्साहन के एक नए चक्र को मंजूरी दी। घटती मुद्रास्फीति, क्षीण होते व्यापार विश्वास और जर्मनी के मंदी में जाने के भय ने ईसीबी को प्रेरित किया कि वह मात्रात्मक सुलभता (क्वान्टिटेटिव ईजिंग) का एक चक्र और शुरू करे। ईसीबी ने इस बात के भी संकेत दिए कि दरें तब तक मौजूदा या निम्नतर स्तर पर रहेंगी जब तक कि मुद्रास्फीतिक परिदृश्य पर्याप्त स्तर के नजदीक नहीं पहुँच जाता लेकिन यह अनुमानित सीमा के भीतर 2 प्रतिशत के नीचे नहीं हो।

बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने अर्थव्यवस्था में निम्नगामी जोखिमों के बढ़ने के कारण अपनी मौद्रिक नीति को अत्यधिक नरम रखना जारी रखा और संकेत दिया है कि यदि वृद्धि की गति आगे और कम होती है तो प्रोत्साहन बढ़ा दिया जाएगा। यूके और कनाडा ने अपनी नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं, जबकि दक्षिण कोरिया ने धीमी संवृद्धि की चिंताओं के मद्देनजर जुलाई की बैठक में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद अगस्त में इसे अपरिवर्तित रखा।

ईएमईज़ के केंद्रीय बैंकों ने कम होती मुद्रास्फीतिक दशाओं और कमजोर होते आर्थिक परिदृश्य के कारण अपनी उन्नत

चार्ट V.5: चुनिन्दा अर्थव्यवस्थाओं में सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

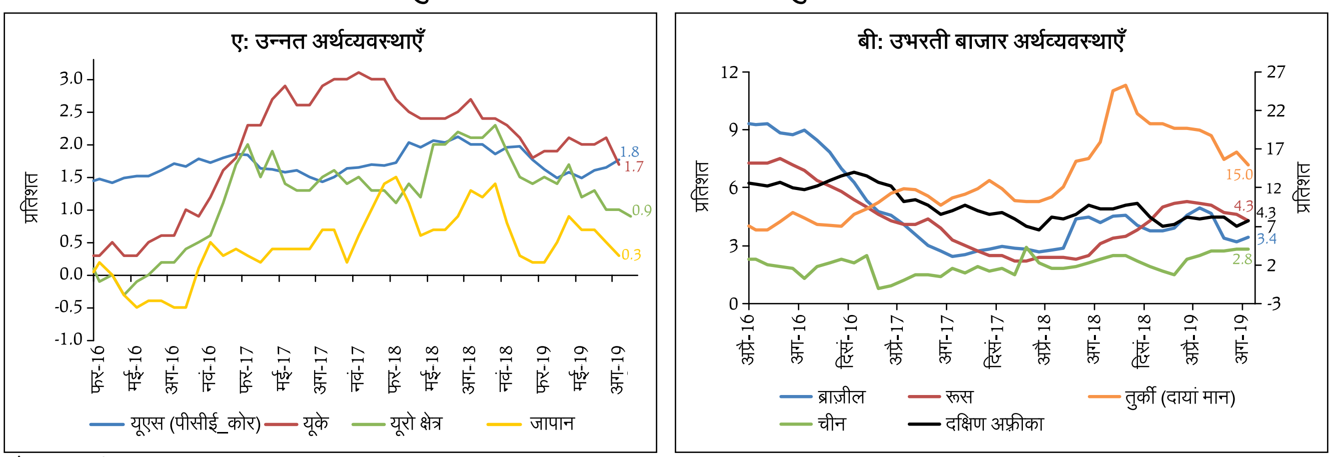

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट V.6: चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीति दर परिवर्तन

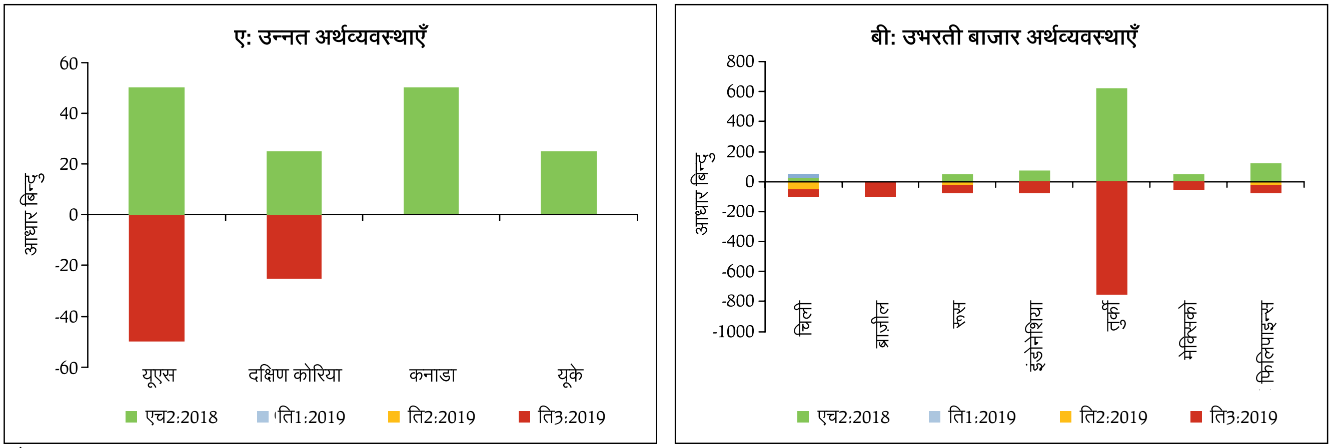

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

अर्थव्यवस्थाओं के समकक्षों के अनुरूप व्यापक रूप से डोविश रुख अपनाया। ब्रिक्स देशों के बीच, पीपुल बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अपनी नरम मौद्रिक नीति रुख जारी रखा, जबकि घरेलू स्थितियों की अपेक्षा के अनुरूप, भविष्य में संभावित नीतिगत सामंजस्य की ओर संकेत किया। इसके अलावा, प्रचुर चलनिधि दशाओं के जरिए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, पीबीओसी ने लघु एवं मध्यम आकार के बैंकों को जून में क्रमशः आरएमबी 200 बिलियन एवं आरएमबी 100 बिलियन के पुनर्भुनाई कोटा तथा स्थायी उधार सुविधा को बढ़ाकर चलनिधि सहायता मुहैया करायी। वास्तविक अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन देने तथा वित्तीयन लागत को कम करने के प्रयोजन से, पीबीओसी ने सितंबर 2019 में वित्तीय संस्थाओं (वित्तीय कंपनियों, वित्तीय पट्टादायी कंपनियों और ऑटो वित्त कंपनियों को छोड़कर) के लिए अपेक्षित आरक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कमी की। सूक्ष्म तथा लघु व्यवसायों को समर्थन बढ़ाने के प्रयासस्वरूप यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों, के लिए अपेक्षित आरक्षित अनुपात में 15 अक्तूबर तथा 15 नवंबर 2019 को प्रत्येक बार 50 आधार अंक की कमी की जाए, जो केवल प्रांतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में परिचालन करते हैं। इसके अलावा, सितंबर की अपनी बैठक में इसने एकवर्षीय परिपक्वता के लिए अपने ऋण मूल दर में 5 आधार अंकों की कटौती की।

ब्राजील ने कम होते मुद्रास्फीतिक दबावों तथा कमजोर होती आर्थिक गतिविधियों के कारण जुलाई से दो बार अपनी सेलीक दर में कटौती की। रूस ने गिरती मुद्रास्फीति और कमजोर मांग के मद्देनजर 2019 में तीन बार अपनी नीतिगत दरें घटायीं। दक्षिण अफ्रीका ने मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के कम होने के कारण जुलाई में अपनी नीतिगत दर घटाई और सितंबर में इसे फिर उसी स्तर पर बरकरार रखा। अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, तुर्की ने, बाजार की उम्मीदों से आगे बढ़ते हुए जुलाई तथा सितंबर में अपनी नीतिगत दरों में क्रमशः 425 आधार अंक 325 आधार अंक की कटौती की क्योंकि सुधरते मुद्रास्फीतिक परिदृश्य ने नीतिगत सुलभता के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान की। फिलिपीन्स ने व्यापार निवेश में फिर से जान फूंकने तथा धीमी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए अपनी नीतिगत दर को 2019 में सितंबर की अपनी बैठक में तीन बार घटाया। मेक्सिको के केंद्रीय बैंक ने सितंबर में अपनी नीतिगत दर घटाई, जो अगस्त से लगातार दूसरी कटौती है। चिली ने अपनी नीतिगत दर को जून से दो बार घटाया। इंडोनेशिया ने निम्न मुद्रास्फीतिक संभावनाओं के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के प्रयोजन से, सितंबर की बैठक में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, जो 2019 की तीसरी तिमाही में लगातार तीसरी कटौती थी(चार्ट V. 6बी)।

V.4 वैश्विक वित्तीय बाज़ार

वित्तीय बाजार में अस्थिरता बनी रही क्योंकि यूएस टैरिफ कार्रवाइयों के क्रम के अभी सामने आने तथा ब्रेक्सिट को लेकर जारी अनिश्चितताओं ने बाजार भाव को लगातार प्रभावित किया। वैश्विक इक्विटी बाज़ारों में मई में तेज बिकवाली देखी गई जिसने अप्रैल तक हुए लाभों को उलट दिया। तथापि, बाजार जून-जुलाई में अधिकांश हानियों से उबर गए क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों के डोविश दिशानिर्देशों तथा व्यापार संधि की नई आशाओं से बाजार मूल्यों में उछल आया, जबकि असुलझे तथा गहराते व्यापार विवाद से बाजार मूल्यों में आई कमी के चलते अगस्त माह में इनमें फिर गिरावट हुई। सितंबर में, व्यापार वार्ताओं में आए सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों की जोखिम

सहनशीलता को उच्च स्थिति में रखा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के लिए सुरक्षित ठिकानों की मांग के चलते बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई, जबकि मुद्रा बाजार अस्थिर बने रहे।

एईज़ के अंतर्गत, यूएस इक्विटी ने मई में सुधार के पश्चात जून-जुलाई में लाभ हासिल किए; ऐसा 2019 की पहली तिमाही के रेजिलिएंट कारपोरेट अर्जन डेटा और आगामी महीनों में फेड के द्वारा मौद्रिक नीति में सुगमता की बढ़ती प्रत्याशाओं के कारण संभव हुआ। अगस्त में, गहराते व्यापारिक तनावों और संवृद्धि संबंधी चिंताओं के बीच जोखिम न लेने की भावना यद्यपि भारी-बिकवाली की तरफ ले गई, तथापि व्यापार के फ्रंट पर सकारात्मक गतिविधियों ने सितंबर में बाजार के रुझान को बहाल कर दिया परिणामस्वरूप अगस्त में जो हानियाँ हुईं थी इक्विटी बाजार ने उनकी काफी भरपाई कर ली। तथापि, कमजोर आर्थिक डेटा के कारण अक्तूबर के प्रारम्भ में तेजी से बिकवाली देखी गई। यूरो क्षेत्र में, जर्मनी के कमजोर डेटा के फलस्वरूप मई माह के दौरान इक्विटी बाजार में गिरावट आई। तथापि, जून-जुलाई में इनमें कुछ स्थिरता बनी रही क्योंकि ईसीबी द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को आगे बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे थे और गैर वित्तीय निगमों की अर्जन प्रत्याशाओं में सकारात्मक गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। इसके बावजूद, बाज़ार में अगस्त माह के दौरान नरमी बनी रही क्योंकि जर्मनी के कमजोर डेटा और इटली में राजनीतिक उथल-पुथल ने संवृद्धि संबंधी चिंताओं को फिर पैदा कर दिया। मई में सुधार के बाद जून-जुलाई में जापानी इक्विटी बाज़ार में मजबूती आई। जुलाई में बाजार के ऊपर उठने की प्रवृत्ति कायम रखी क्योंकि व्यापारिक चिंताओं में कमी हुई, किन्तु माह के बीच में ये बाजार फिर से नीचे चले गए क्योंकि येन के मूल्य में वृद्धि हुई और कुछ निर्यात-प्रधान कंपनियों के कार्य निष्पादन में गिरावट आई। एईज़ के इक्विटी बाज़ारों ने सकारात्मक संकेत देते हुए सितंबर माह में प्रवेश किया क्योंकि हांगकांग में तनाव में कमी और व्यापारिक वार्ताओं में नई आशा के संचार ने वैश्विक निवेशकों के रुझान को ऊपर उठाया।

ईएमईज़ के स्टॉक बाज़ारों में गिरावट रही क्योंकि मजबूत अमरीकी डॉलर ने रोधक का काम किया जिसमेंपूंजी बहिवाह हुआ। जापान के साथ व्यापारिक संघर्ष के फलस्वरूप कमजोर दक्षिण कोरियाई ईक्विटीज़, हांगकांग में राजनैतिक अशांति, अर्जेन्टीना के वित्तीय बाज़ार में क्रैश और बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव ने अगस्त में ईएमईज़ शेयरों को और नीचे गिरा दिया। हालांकि, बाद में कुछ हानियों की भरपाई हो गई क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन के संकेतों और टैरिफ क्रियान्वयन के आस्थगन से बाजार भावों को बल मिला (चार्ट V.7)।

प्रमुख एईज़ और ईएमईज़ में बॉण्ड से होने वाले प्रतिफल में कमी आई क्योंकि जोखिम लेने की प्रवृत्ति के कम होने के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश स्थलों की ओर का रुख कर लिया। प्रथम तिमाही के बेहतर जीडीपी आंकड़ों के बलबूते अप्रैल में तेजी दिखाने के बाद मई में यूएस बॉण्ड के प्रतिफल में कमी आई। इसके बाद से ये तेजी से गिरते चले गए, बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव और यूएस फेड के डोविस रुख के बीच अगस्त में ये 2 प्रतिशत से भी नीचे चले गए। प्रतिफल में तीव्र गिरावट ने 10 वर्षीय और 3 माह के बीच वाली ट्रेजरी प्रतिभूतियों में ऋणात्मक प्रतिफल अंतराल बना दिया जैसा कि अध्याय 1 के बॉक्स 1.1 में व्याख्या की गई है।

यूरो क्षेत्र में, इसकी अधिकांश घटक अर्थव्यवस्थाओं में बॉण्ड से होने वाले प्रतिफल ऋणात्मक दायरे में चले गए क्योंकि यहाँ ईसीबी द्वारा

चार्ट V.7: इक्विटी बाजार

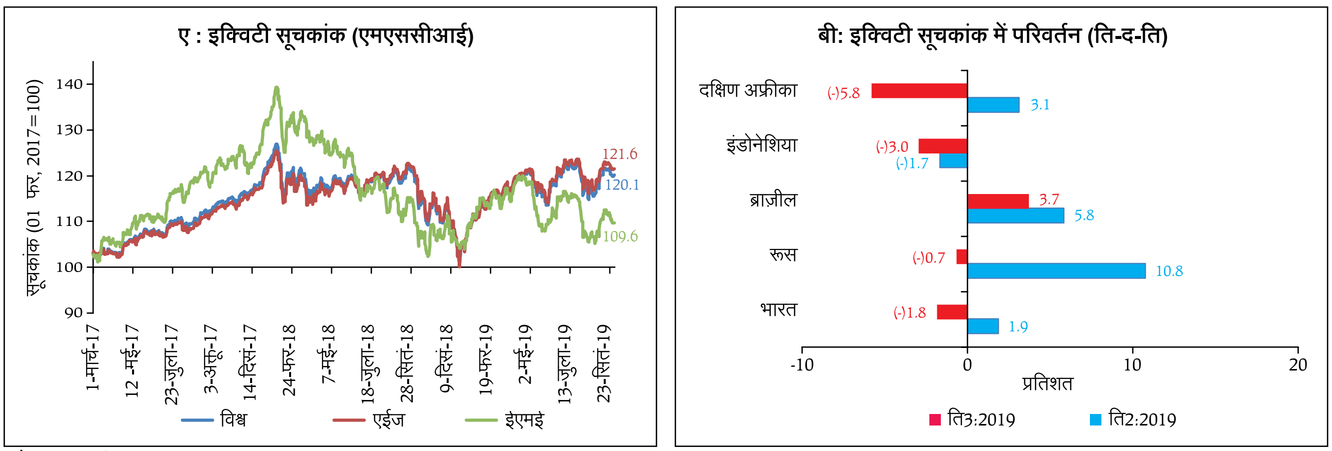

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट V.8: बांड प्रतिफल और मुद्रा उतार-चढ़ाव

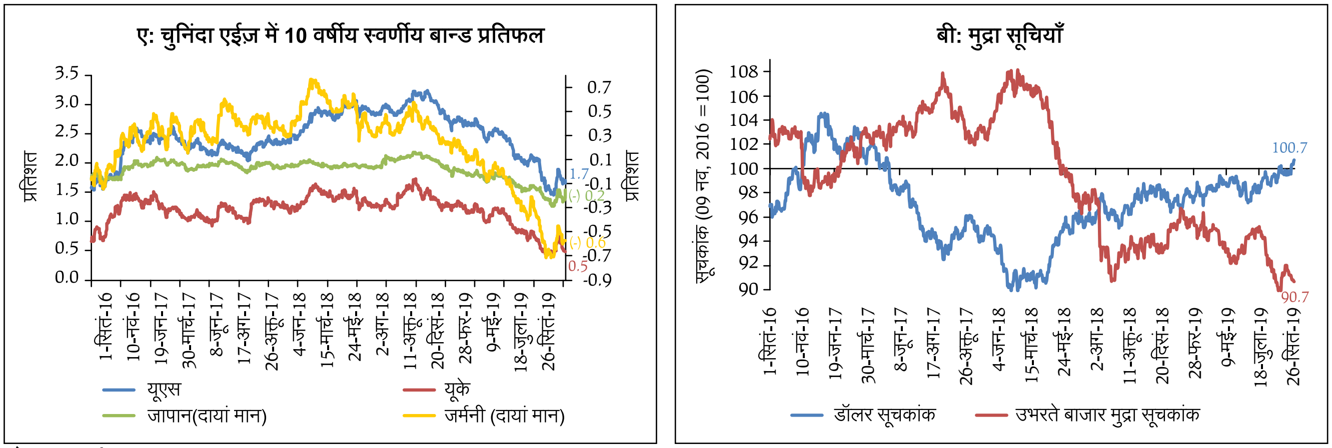

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

डोविस मौद्रिक नीति रुख अपनाए जाने की प्रत्याशा को बल मिला, साथ ही आर्थिक परिदृश्य भी कमजोर पड़ गया। जर्मनी के निराश करने वाले डेटा और इटली की राजनीतिक अनिश्चितताओं ने और अधिक निम्नगामी दबाव बना दिया। जापान में, जोखिम उठाने की कमजोर इच्छा के कारण बॉण्ड से होने वाले प्रतिफल ऋणात्मक दायरे में बने रहे। अधिकांश ईएमईज़ में बॉण्ड से होने वाले प्रतिफल कम हो रहे हैं और साथ ही केंद्रीय बैंक भी अत्यधिक समायोजनकारी बन रहे हैं क्योंकि मामूली मुद्रास्फीति ने गिरती हुई आर्थिक संवृद्धि को संबल देने के लिए नीतिगत गुंजाइश के लिए जगह बनाई है (चार्ट V.8ए)।

मुद्रा बाज़ारों में, यूएस फेड के डोविस दिशानिर्देशों के कारण जून में अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं की तुलना में कमजोर पड़ गया। लेकिन जुलाई में इसमें फिर से उछाल आया और इसने प्रथम तिमाही में हुई अधिकांश हानियों की भरपाई कर ली। अन्य एईज़ में कमजोर संवृद्धि संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षित निवेश स्थलों की मांग ने भी अमरीकी डॉलर को मजबूत किया। यूरो ने यूएस डॉलर की तुलना में अपना आधार गंवा दिया क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था में गतिहीनता रही, जबकि अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए ईसीबी की उच्च संभावना ने भी मुद्रा को और नीचे गिराया। जापानी येन ने प्रमुख मुद्राओं में से अधिकांश को पीछे छोड दिया क्योंकि व्यापार युद्ध से पैदा हुई अनिश्चितता के साथ ही, बदतर होती वैश्विक संवृद्धि स्थितियों से निवेशकों में जोखिम को हटाने की भावना बढ़ती गई। मजबूत अमरीकी डॉलर और व्यापारिक तनाव से आए स्पिल ओवर जोखिम के कारण अधिकांश ईएमईज़ की मुद्राओं को हानियां हुई। अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच एमएससीआई उभरते बाजार मुद्रा सूचकांक में 2.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई (V.8बी)

V.5 निष्कर्ष

संक्षेप में, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में लगातार गति कम रही है क्योंकि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से संबन्धित लंबे समय से चल रही अनिश्चितताओं ने आर्थिक भावों को प्रभावित किया। मुद्रास्फीतिक के दबावों के सौम्य रहने और बाजार भावों के अस्थिर रहने से वैश्विक आउटलुक के जोखिम निम्नगामी बने हुए हैं। फिर भी, दुनिया भर में मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन स्लोडाउन की गति को कम करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को रिकवरी के पथ पर लाने में मदद कर सकते हैं।

भाषण

भारत के बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता के आयाम
शक्तिकान्त दास

बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली संबंधी विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रत्याशाएं
एम. के. जैन

भारत के बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता के आयाम

शक्तिकान्त दास

अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है। वैश्विक विकास धीमा हो रहा है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सहज बनाकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं; लेकिन अभी तक कोई मंदी नहीं आई है। व्यापारिक युद्धों ने विश्व व्यापार को संकुचित कर दिया है और तकनीकी तथा मुद्रा युद्ध का रूप लेने का भय है किसी को भी कोई महत्वपूर्ण लाभ होने का प्रमाण नहीं है। निवल वस्तु आयातकों को संपार्श्विक लाभ और पण्य निर्यातकों के लिए व्यापार घाटे की शर्तों के साथ इस बीच वैश्विक पण्यों की कीमतें कम हो गई हैं। हालांकि सऊदी तेल पर ड्रोन हमलों के कारण परिणामी घटनाक्रम अभी भी उभर रहे हैं। सुरक्षा के छिटपुट उपाय पूंजी प्रवाह को उभरते हुए बाजारों से उन्नत अर्थव्यवस्था आस्तियों की तरफ ले जा रहे हैं; लेकिन निगेटिव यील्डिंग बॉन्ड का विस्तार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है जिससे वित्तीय स्थिरता को संभावित खतरा है।

शक्तियां और कमजोरियां

इस प्रतिकूल वातावरण में भारत के बाह्य क्षेत्र ने सुदृढ़ता और व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। चालू खाता घाटा औसतन पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत है और पोर्टफोलियो प्रवाह के लिए जोखिम-पर-जोखिम अस्थिरता प्रदान करने वाले वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद आसानी से वित्तपोषित है। 13 सितंबर 2019 को विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 429 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि आयात के 10 महीने के करीब या 1 साल तक के अवशिष्ट परिपक्वता के 21 महीने के ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त था। भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनी हुई है और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं # के लिए शीर्ष 10 स्थानों में एक है। नेट एफ़डीआई अप्रैल-जुलाई 2019 में 2018-19 की इसी अवधि में 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

1990 में सामने आई बाह्य भुगतान कठिनाइयों, जिसने व्यापक संरचनात्मक समायोजन और सुधारों को गति दी, के बाद से बाह्य ऋण प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जीडीपी के 19.7 प्रतिशत पर बाह्य ऋण का स्तर और ऋण सेवा अनुपात (वर्तमान आय के अनुपात के रूप में मूलधन भुगतान और ब्याज भुगतान) जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर उभरते हुए बाजारों में सबसे कम है। यह विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार दुनिया के बाह्य रूप से सबसे कम ऋणी देशों में भारत को रखता है। बाह्य देयताओं के व्यापक उपाय के संदर्भ में - निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति (एनआईआईपी) जिसमें ऋण और इक्विटी देयताएँ दोनों शामिल हैं, विदेशी आस्तियों का निवल - भारत का एक्सपोजर मार्च 2015 के अंत में 18.3 प्रतिशत के स्तर से घटकर मार्च 2019 के अंत में जीडीपी का 15.9 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में मार्च 2014 के अंत में, क्रमशः 68.2 प्रतिशत और 89.3 प्रतिशत से बढ़ कर मार्च 2019 के अंत में बाह्य ऋण का 76 प्रतिशत और एनआईआईपी का 94.6 प्रतिशत था। अवशिष्ट परिपक्वता के लघु अवधि के ऋण मार्च 2013 के अंत में 59 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर मार्च 2019 की समाप्ति पर में विदेशी मुद्रा भंडार के 57 प्रतिशत तक हुए। मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण कुल बाह्य ऋण का मुश्किल से 20 प्रतिशत है।

स्वस्थ विकास भारत की अंतर्निहित बुनियाद की सहज ताकत हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा जीडीपी के अनुपात से मापी जाने वाली अर्थव्यवस्था के खुलेपन का स्तर 1990 के दशक की पहली छमाही के 20 प्रतिशत से बढ़कर 2014-19 के पांच साल की नवीनतम अवधि में 44 प्रतिशत हो गई है। विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 1990 के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 1.7 प्रतिशत हो गया है।

घरेलू उत्पादन में सेवाओं के बढ़ते हुए योगदान के साथ भारत की सेवाओं का निर्यात पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। वास्तव में भारत की सेवाओं के निर्यात ने व्यापारिक निर्यातों की तुलना में वैश्विक आघातों के लिए उच्च स्तर की आघात सहनीयता दिखायी है। 81.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर निवल

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक 19 सितंबर 2019 को मुंबई में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2019 में।

स्रोत: एफडीआई रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, 2018.

सेवाओं की निर्यात ने 2018-19 में भारत के व्यापार घाटे के 45 प्रतिशत को वित्तपोषित किया है। व्यापार सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के सॉफ्टवेयर निर्यात के लगभग 12 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत सॉफ्टवेयर निर्यात और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं में विश्व में अग्रणी है। भारत का आईटी सेक्टर, जिसने 2018-19 में शुद्ध निर्यात के माध्यम से 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स सहित नई तकनीकों में छलांग लगा रहा है। भारतीय प्रवासी, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और इसे दर्शाते हुए भारत वर्तमान में विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से दुनिया में सबसे अधिक आवक प्रेषण प्राप्त करता है। इसके साथ-साथ गैर निवासी जमाराशियों में वृद्धि ने वर्षों में भुगतान संतुलन में स्थिर और विश्वसनीय सहायता प्रदान की है। सकल पूंजीगत अंतर्गत और आउटफ्लो और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से मापा जाने वाला वित्तीय खुलापन 1990 की पहली छमाही में 15 प्रतिशत से तीन गुना बढ़ कर 2014-19 के दौरान 45 प्रतिशत हो गया है।

इन उपलब्धियों के होते हुए भी ऐसी कई चिंताएँ हैं जिन्होने बाह्य क्षेत्र प्रबंधन के संचालन में महत्त्वपूर्ण स्थान लिया हुआ है। सबसे पहले विश्व व्यापार में मंदी के बोझ के कारण व्यापार निर्यात ने गति खो दी है। 2013-18 (UNCTAD, 2019) के दौरान निर्यात की मात्रा में औसतन 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत की निर्यात वृद्धि उसी अवधि में 2.2 प्रतिशत तक कमजोर हुई है – कई उभरती और उन्नत बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे ही - क्योंकि इकाई के मूल्य में गिरावट ने इसे दुष्प्रभावित किया है। वैश्विक माँग में मंदी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के हमारे निर्यात पर भी असर पड़ा है - वो कुल व्यापार निर्यात का 14 प्रतिशत है। दूसरा, घरेलू मांग में गिरावट ने आयातों, विशेष रूप से गैर-तेल गैर-सोने के आयातों को संकुचित किया है और इससे मध्यवर्ती, पूंजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का इनफ्लो कम हो गया है जो हमारी अवसंरचनाएँ और उद्योग के आधुनिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, पोर्टफोलियो प्रवाह, जो एक सामान्य वर्ष में बाह्य वित्तपोषण का लगभग औसतन 23 प्रतिशत रहता है, 2018-19 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल आउटफ्लो के साथ अत्यधिक अस्थिर हो गया है। 2019-20 के दौरान अब तक (13 सितंबर तक) पोर्टफोलियो इक्विटी आउटफ्लो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था लेकिन एक साल पहले इसी अवधि में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। हालांकि ऋण बाजार में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इनफ्लो ने राहत दी है। इसके अलावा, पोर्टफोलियो कैपिटल मूवमेंट वैश्विक स्पिलओवरों का माध्यम बन गया है जो कि घरेलू इक्विटी, ऋण और विदेशी मुद्रा बाजार, और आस्ति की कीमतों पर प्रभाव डालता है। फिर भी मैंने बतायीं सकारात्मक सुविधाओं से स्थिर भारत के बाह्य क्षेत्र के अंतर्निहित सुदृढ़ता ने इन आघातों को दूर से किया और घरेलू अर्थव्यवस्था को रोधक सुरक्षा प्रदान की।

बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन

इस पृष्ठभूमि में मैं भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा भारत की बाह्य स्थिति को मज़बूत करने हेतु और इस परीक्षा के समय में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में सुधार के प्रयोजन से किए गए कई हालिया पहलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

निर्यात

भुगतान संतुलन की स्थिति के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है। अंतिम विश्लेषण से पता चलता है कि, वस्तु और सेवा के निर्यात से मिलनेवाली विदेशी मुद्रा आय तथा ऐसी सेवाएं जिनके कारण देयताएं चूकाने की और आयात क्रय शक्ति मिलती है के लिए इक्विटी के साथ-साथ कर्ज के रूप में देयताएं पर्याप्त नहीं है। इन वर्षों में नीति का प्रयास उत्पादों और गंतव्यों, दोनों के संदर्भ में भारत के निर्यात प्रोफ़ाइल में व्यापक विविधीकरण को लाना है। विशेष रूप से, उत्पाद विविधीकरण ने भारत को ब्रिक्स साथियों के सापेक्ष अपनी निर्यात बास्केट को व्यापक बनाने और व्यापार के आघातों के लिए इसकी भेद्यता को कम करने में सक्षम बनाया है। विविधीकरण के अलावा भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उभरते हुए उत्पादों का निर्यात कर रहा है जिसके लिए वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के स्मार्ट फोन खंड में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम से मिली हुई गति से भारत ने एक आयातक की भूमिका से खुद को निर्यातक के रूप में बदल दिया है।

आगे बढ़ते हुए, कई पहल किए गए हैं और अन्य नियमित आधार पर शुरू हो रहे है ताकि निर्यात उद्योगों को उत्पादकता और अत्याधुनिक प्रतिस्पर्धा हासिल करने में सक्षम बनाया जा

सके। इनमें निर्यात सुविधाओं का उन्नयन, भारतीय किसानों और उनके उत्पादों का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और व्यापार सुविधा के उपाय भी शामिल हैं। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट की इलेक्ट्रॉनिक वापसी सहित करों और शुल्क (ड्यूटी) की प्रतिपूर्ति के प्रयास चल रहे हैं। फरवरी 2018 से आईटी, पर्यटन और आतिथ्य तथा चिकित्सा सेवाओं सहित 12 'चैंपियन' सेवा क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई है। रिज़र्व बैंक और सरकार सक्रिय रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के प्रचार में लगे हुए हैं जो कि व्यापार और सेवाओं, दोनों के निर्यात को बढ़ावा देंगे। ये सभी कदम निर्यात के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार करना चाहते हैं।

पूंजी प्रवाह

पूंजी प्रवाह के संबंध में भारत ने प्रगतिशील उदारीकरण का दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन वित्तीय बाजारों के विकास सहित घरेलू स्थिति की वास्तविकताओं के लिए अंशाकित दृष्टिकोण रखा है। एक विस्तारित निवेशक आधार के विनिमय दर जोखिम प्रबंधन के लिए लिखतों की एक विविध शृंखला सामने आयीं हैं। भारत की पदानुक्रमित नीति दृष्टिकोण - ऋण प्रवाह पर इक्विटी प्रवाह को प्राथमिकता देना, और इक्विटी प्रवाह के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रवाह पर एफडीआई प्रवाह को प्राथमिकता देना, और सकल ऋण प्रवाह के अंतर्गत अल्पकालिक प्रवाह पर दीर्घकालिक ऋण प्रवाह को प्राथमिकता देना- ने पूंजी प्रवाह की संरचना को प्रभावित किया है ।

इक्विटी प्रवाह की ओर मुड़ते हुए, भारत को एक आकर्षक निवेश स्थान बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एफ़डीआई नीति को लगातार उदार बनाया गया है। हाल के वर्षों में रक्षा, निर्माण विकास, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन, वित्तीय सेवाएं, आस्ति पुनर्निर्माण, प्रसारण और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को खोला गया हैं। बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी गई है। अगस्त 2019 में एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई मानदंडों को और अधिक उदार बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कोल माइनिंग में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के संबंध में, एक निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने और अधिक अनुमानित नीति वातावरण बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एफपीआई सीमा को अब मध्यम अवधि ढांचे के तहत छमाही आधार पर संशोधित किया जा रहा है। नगरपालिका बांड में राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए निर्धारित सीमा के भीतर एफपीआई की अनुमति दी गई है। एक स्वैच्छिक अवधारणा मार्ग (वीआरआर) के तहत एफपीआई को और ज़्यादा परिचालन सुदृढ़ता प्रदान की गयी है जो निवेशकों को उनकी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिमों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हुए जी-सेक, एसडीएल, ट्रेजरी बिल और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की सुविधा देता है। वीआरआर योजना के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। केंद्रीय बजट 2019-20 में एफ़पीआई के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड को आसान बनाने का और शेयर बाजारों में निर्बाध निवेश के लिए एफपीआई मार्ग के साथ गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) पोर्टफोलियो मार्ग को मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संस्थाओं को वैश्विक स्कैन और उपस्थिति देने के लिए बाह्य प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश को भी लगातार उदार बनाया गया है।

दो ट्रैक: विदेशी मुद्रा द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी); और रुपये द्वारा डेनोमिनेटेड ईसीबी के तहत बाह्य उधार मानदंडों को भी सरल बनाया गया है। एफ़डीआई प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं यथा समष्टि वित्त गतिविधियों में संलग्न पंजीकृत संस्थाएँ, पंजीकृत समितियां / ट्रस्ट / सहकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है। जीडीपी के 6.5 प्रतिशत पर ईसीबी के बकाया स्टॉक के लिए एक नियम-आधारित गतिशील सीमा लागू है। ईसीबी मार्ग के तहत रुपये मूल्यवर्ग वाले बांड या मसाला बॉन्ड घरेलू कंपनियों को विनिमय दर के जोखिम को हेजिंग की आवश्यकता के बिना अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं। स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या ईसीबी की अनुमति है। हाल ही में, ईसीबी से संबंधित अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और रुपया ऋणों

[1] केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों (जी-सेक), राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमाएं वर्तमान में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिभूतियों के संबंधित बकाया स्टॉक का 6 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 9 प्रतिशत निर्धारित हैं।

की चुकौती हेतु विशिष्ट पात्र उधारकर्ताओं के लिए भी छूट दी गई है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के ईसीबी के लिए अनिवार्य हेजिंग की आवश्यकता पहले के 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई थी। अप्रैल-जुलाई 2019 में ईसीबी का निवल संवितरण बढ़कर 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2018-19 की इसी अवधि में 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल चुकौती हुई थी।

विनिमय दर

निष्कर्ष देने से पूर्व रुपये की विनिमय दर के बारे में कुछ कहना उचित ही है। पिछले कुछ सालों में विनिमय दर में मुख्य रूप से वैश्विक स्पिलओवर द्वारा लगाए गए विचारणीय अस्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर दोतरफा हलचल देखी गई है। 2019-2020 में अभी तक रुपये ने एक संकीर्ण सीमा में कारोबार किया है जो पहली तिमाही में मामूली मूल्यवृद्धि के साथ अगस्त और सितंबर के पहले पखवाड़े में मूल्यह्रास की ओर संकेत करती है जिसका मुख्य कारण 14 सितंबर 2019 को सउदी तेल सुविधाओं पर ड्रोन आक्रमण रहा है। जुलाई 2019 की अपनी बाह्य क्षेत्रीय रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने मूल सिद्धांतों के साथ मुद्राओं के मेल का आकलन करने के लिए मॉडल का एक समूह बनाया । आईएमएफ आरईआर अंतर को रुपये के लिए, शून्य होने का अनुमान लगाता है, जो यह दर्शाता है कि मुद्रा काफी मूल्यवान है और मोटे तौर पर मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत की विनिमय दर व्यवस्था आघात सहनीय और बाजार संचालित है जिसमें विनिमय दर मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक के पास विनिमय दर के स्तर के लिए कोई लक्ष्य या बैंड नहीं है। हस्तक्षेपों का उद्देश्य अनुचित अस्थिरता का प्रबंधन करना है। यह पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित दो-पक्षीय हस्तक्षेपों में परिलक्षित होता है 2017-18 में निवल खरीद के बाद 2018-19 में निवल बिक्री। वास्तव में, यह इस सुदृढ़ता की मान्यता है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मुद्रा हेरफेर से संबंधित निगरानी से भारत को हटा दिया है।

निष्कर्ष

यद्यपि इस मोड़ पर कुछ नकारात्मक जोखिमें और बढ़ गयी हैं, कुल मिलाकर बाह्य क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण सतर्क आशावाद का है। उनमें से वैश्विक मंदी का गहरा होना और व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें भी व्यापार और प्रेषण चैनलों के माध्यम से चालू खाता शेष की व्यवहार्यता के लिए संभावित जोखिमों को बनाएँ रखती हैं। फिर भी ऐसी अंतर्निहित ताकतें हैं जो बाह्य क्षेत्रों को इन जोखिमों से बचाने के लिए बनाई जा सकती हैं। नए निर्यात मार्केट और नए क्षेत्रों की तलाश जारी रहनी चाहिए ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बदलती गतिशीलता के लाभ प्राप्त किए जा सके। भारतीय आईटी कंपनियों को अपने तुलनात्मक लाभ को सुधारने के लिए बाजार विविधीकरण में तेजी लाने और नए कौशल और प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है। रेमिटेंस और नॉन-रेजिडेंट डिपॉजिट मध्यम अवधि के लिए शॉक-एब्जॉर्बर बने रहने की संभावना है और इसे प्रेषित / जमा करने में आसानी और लेनदेन की लागत को कम करने सहित सफलतापूर्वक संवर्धित की जानी चाहिए।

अंततः बाह्य क्षेत्र की ताकत घरेलू मैक्रो-फंडामेंटल्स से प्राप्त होती है। निवेशकों और बाजारों को इन क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान देने के साथ विश्वसनीय रूप से आश्वस्त होना चाहिए ताकि समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके। साथ ही, हमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों को बरकरार रखना होगा। अति महत्त्वपूर्ण उद्देश्य द्वारा चालू खाता घाटे को स्थायी सीमा के भीतर रखना चाहिए और ऋण और इक्विटी प्रवाह के विवेकपूर्ण मिश्रण द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण है लेकिन यह अवसर भी प्रदान करता है। आईएमएफ के आकलन के अनुसार 2020 में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान छठवाँ रहेगा। व्यापार युद्ध नए व्यापार पुनर्वास के मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि भारत के लिए पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से अनुकूल प्रतीत होता है। भारतीय उद्यमशीलता, रुपया और हमारे लोग उत्तरोत्तर लेकिन अनवरत रूप से अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं। 2018 के बाद से भारत की कामकाजी जनसंख्या आयु निर्भर जनसंख्या से अधिक हो गई है, और यह जनसांख्यिकीय लाभ 2055 तक रहने की उम्मीद है। इस उपलब्धि में बाह्य अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर एक करीबी और निरंतर सतर्कता के साथ विवेकपूर्ण बाह्य क्षेत्र प्रबंधन महत्वपूर्ण बन जाता है और इसपर भारिबैं का विशेष ध्यान बना रहेगा।

धन्यवाद

बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली संबंधी विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रत्याशाएं*

एम. के. जैन

श्री सुनील मेहता, अध्यक्ष - इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और सहभागियो ! सभी को गुड ईवनिंग। यह सम्मेलन भारतीय बैंकिंग बिरादरी के और प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा अन्य सेवा प्रदाता क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है ताकि वे भारत में बैंकिंग क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों पर चर्चा कर सकें और भारत में व्यवसायरत बैंकों के लिए भावी कार्यनीति तैयार की जा सके। आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है।

भारत का बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ पूरे बैंकिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं जिससे वित्तीय प्रणाली के परिचालन के तौर-तरीके तथा वित्तीय संस्थानों के कामकाज के तरीके भी बदल गए हैं। वित्त और प्रौद्योगिकी के बीच गठजोड़ से बैंकिंग के कई पहलुओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी को एक ऐसे विघटनकारी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, कारोबारी मॉडल और बैंकिंग क्षेत्र की संरचना में आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेगा। इस आमूलचूल बदलाव ने बैंकों के साथ-साथ उनके विनियामकों के समक्ष भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर दी हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चुनौती अनुपालन की है, जो किसी भी बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आज इसी पहलू पर अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं।

अगर पारिभाषिक रूप में कहें तो विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और अनेक आचार संहिताओं, जिनमें कुछ स्वैच्छिक भी होती हैं, का पालन करना ही अनुपालन है। यद्यपि इनमें से अधिकांश के मूल में बाहरी अपेक्षाएं होती हैं, तथापि संगठन के लिए अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना और नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कारोबार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सशक्त अनुपालन संस्कृति वह होती है जिसमें समुचित आचार संहिताओं का पालन सुनिश्चित होता हो, हितों के टकराव का प्रबंधन किया जा सके और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार होता हो। इस प्रकार, अनुपालन के दायरे में केवल वह नहीं आता जो कानूनी रूप से बाध्यकरी हो, अपितु इसमें कारोबारी निष्ठा और नैतिक आचरण भी शामिल हैं।

अच्छी अनुपालन संस्कृति के लाभ

बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। खराब आचरण और भरोसा टूटने से होने वाली हानि से बचने के लिए बैंकों में ऐसी संस्कृति का होना महत्वपूर्ण है।

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों के लिए कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती है[1] यथा, i) संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम घटाने में; ii) प्रतिष्ठा जोखिम कम करने में; iii) नौकरी करते समय कर्मचारियों में झिझक कम करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में; iv) प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें संगठन में बनाए रखने में तथा कर्मचारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में; v) पारदर्शिता बढ़ाने में जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आ सके; vi) विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध बेहतर बनाने में और vii) निवेशकों के बीच हैसियत बढ़ाने में।

बैंकों द्वारा किए गए एक दबाव परीक्षण सर्वेक्षण में, यह देखा गया कि अनुपालन से कुछ व्यावसायिक लाभ भी हो सकते हैं। दबाव परीक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले बैंकरों में से एक तिहाई से अधिक ने इस ओर इशारा किया कि दबाव परीक्षण के सिद्धांतों के अनुपालन के सर्वप्रमुख फायदों में शामिल हैं-बेहतर जानकारी के आधार पर पूंजी नियोजन से जुड़े निर्णय लेना और संगठन के जोखिमों के बारे में एक दूरदर्शितापूर्ण नजरिया रखना।

इसलिए, यदि ग्राहक संतुष्टि चाहिए, जो तो हमें अनुपालन की संस्कृति को अपनाना होगा क्योंकि ग्राहक संतुष्टि ही इक्विटी पर प्रतिलाभ का मार्ग प्रशस्त करती है।

खराब अनुपालन संस्कृति के दुष्परिणाम

अनुपालन जोखिम कानूनी या विनियामकीय प्रतिबंधों, बड़े वित्तीय नुकसानों, या किसी बैंक की प्रतिष्ठा में गिरावट से जुड़ा

* 20 अगस्त 2019 को आईबीए तथा एफआईसीसीआई, मुंबई द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में वित्तीय संस्था बेंचमार्किंग और कैलिब्रेशन (एफआईबीएसी)-2019 विषय पर श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

[1] *https://www.pm360online.com/silver-linings-10-business-benefits-of-your-compliance-program/*

[2] *https://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2014/08/19/compliance-efforts-can-bring-business-benefits-for-banks/#2b5b69f6772c*

जोखिम है जो तब उत्पन्न हो जाता है जब कोई बैंक कानूनों, विनियमों, नियमों, संगठन द्वारा तैयार किए गए इनसे जुड़े स्व-विनियमन मानकों और आचार संहिताओं का अनुपालन नहीं करता। दूसरी ओर, एक प्रभावी अनुपालन व्यवस्था कारोबार के प्रत्येक क्षेत्र, उत्पाद और प्रक्रिया में निहित अनुपालन संबंधी जोखिमों की पहचान कर सकेगी और ऐसे जोखिमों को कम करने के तरीके विकसित करेगी। प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को विधिवत अभिलिखित किया जाना चाहिए और उसके साथ एक 'क्या करें' सूची और एक 'क्या न करें' सूची भी होनी चाहिए। उचित आचरण का पालन करने में विफलता के उदाहरणों को केस स्टडी के रूप में लेते हुए उनसे सभी स्टाफ को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे इनसे सबक ले सकें और अपने दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव ला सकें।

बैंकों को इस प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है कि अनुपालन खर्चीला होता है बल्कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उचित आचरण से हमारी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने पाती और साथ ही हम अर्थदण्ड से भी बचते हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप से हमें आय होती है जिसकी गणना बैंक नहीं करते और इसीलिए उन्हें यह आय मिल भी नहीं पाती। कमजोर अनुपालन संस्कृति से बैंकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वैश्विक रूप से देखें तो, वित्तीय संकट की शुरुआत से लेकर 2020 तक बैंकों पर जुर्माने और अर्थदण्ड की राशि 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गयी है। हाँगकॉग की एक वित्तीय सेवा परामर्शदाता कंपनी क्विनलान एंड एसोसिएट्स ने अनुमान लगाया कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद से खराब व्यवहार के कारण शीर्ष 50 वैश्विक बैंकों को होने वाले मुनाफे में 850 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो राइट-डाउन, ट्रेडिंग लॉस, जुर्माना और उच्च अनुपालन लागत के कारण हुआ था। जून 2018 से जुलाई 2019 के बीच 76 ऐसे मौके आये हैं जब रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है जिसकी कुल राशि ₹122.9 करोड़ रुपये है।

हालांकि, विनियमन का क्षेत्र जिस प्रकार विकसित हो रहा है, ऐसे में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जुर्माने और दंड का भय पर्याप्त नहीं है। लेकिन जिस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के अंतर्निहित उपाय मौजूद होते हैं, उसमें अनुपालन दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है जिससे संगठन की दक्षता बढ़ जाती है। इसके अलावा, एक सक्षम अभिशासन में अनुपालन, निष्ठा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और ये उस संस्था की कार्यसंस्कृति का अंग बन जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बैंक अपने पूरे संगठन को जिम्मेदारी के साथ काम करने हेतु सशक्त बना पाता है और निरंतर विकसित होते विनियमन और कारोबारी चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक लचीलापन भी संगठन में बना रहता है।

अनुपालन संस्कृति - भारतीय परिदृश्य

रिज़र्व बैंक ने बहुत पहले अगस्त 1992 में बैंकों में एक अनुपालन अधिकारी तैनात करने की प्रणाली प्रारंभ की थी जो बैंकों में धोखाधड़ी और कुप्रथाओं पर गठित समिति (घोष समिति) की सिफारिशों पर आधारित थी। अनुपालन अधिकारियों की भूमिका का महत्व 1995 में तेजी से बढ़ा जब लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन संबंधी क्रियाकलाप की जिम्मेदारी सौंपी गयी और उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वे आवधिक रूप से अनुपालन से जुड़े कार्यों की रिपोर्ट या प्रमाण सीधे मुख्य प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करें। हालांकि, धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि बैंकों में अनुपालन से जुड़े कार्यों की परिधि को न केवल बढ़ाना होगा, बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करना होगा, विशेषकर एक ऐसे परिदृश्य में जब बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत एक के बाद एक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों में अनुपालन से जुड़ी अनेकानेक कमियाँ उजागर हो रही हों। इसके बाद जब बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा अप्रैल 2005 में बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्यप्रणाली पर उच्च स्तरीय पेपर जारी किया गया तब अनुपालन कार्यप्रणाली की आवश्यकता और उसके महत्व को देखते हुए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों को और गति मिली। इन सिद्धांतों ने वर्ष 2007 में बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली को और सख्त बनाने के लिए हमें एक आधार दिया। वित्तीय संकट के बाद, खासकर व्यवहार, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल), और ग्राहकों के अलग-अलग वर्ग के लिए तैयार किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों की उपयुक्तता जैसे क्षेत्रों में अनुपालन पर जोर काफी बढ़ गया है।

इस संदर्भ में, एक अच्छी अनुपालन संस्कृति से होने वाले लाभों तथा खराब आचरण से होने वाले नुकसानों को पहचानते हुए भारतीय बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति विकसित करें। अपने पर्यवेक्षी दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों की अनुपालन संस्कृति में अनेक खामियाँ देखी हैं। इनमें से कुछ अनियमितताएं तो ऐसी हैं

[3] *https://in.reuters.com/article/banks-regulator-fines/u-s-eu-fines-on-banks-misconduct-to-top-400-billion-by-2020-report-idINKCN1C210D*

जो बार-बार सामने आती रही हैं, हालांकि बैंकों के प्रबंधतंत्रों द्वारा उनका अनुपालन कर लिए जाने की सूचना दी जाती रही है। मैं बैंकों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली में समग्र सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास करें।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अगर संबंधित बैंकों में एक अच्छी अनुपालन संस्कृति विकसित कर ली गयी होती, तो धोखाधड़ी के कारण बैंकों को होने वाले कुछ बड़े नुकसानों से बचा जा सकता था। जैसा कि पहले परिभाषित किया गया था, अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन भी शामिल होता है। धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में, एक सामान्य बात यह होती है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, इसमें फँसी धनराशि की मात्रा और धोखाधड़ी के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों की जटिलताओं ने बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर किया है।

साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुपालन जोखिम

एक बात और है जिस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। आम तौर पर, साइबर रेजिलिएंश फ्रेमवर्क का उद्देश्य तीन व्यापक मुद्दों से जुड़े खतरों से निपटना होता है - गोपनीयता भंग होना (गोपनीय डेटा चोरी होना), उपलब्धता समाप्त हो जाना (सिस्टम मौजूद है, लेकिन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं), और निष्ठा का भंग होना (डेटा या सिस्टम से जुड़ा भ्रष्टाचार जिससे सूचना और उसके संसाधन की प्रणाली में निष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है)। इन उल्लंघनों से संबंधित अनुपालन जोखिम का महत्व बढ़ता जा रहा है और इनसे प्राथमिकता के आधार पर निपटना जरूरी है।

अनुपालन संस्कृति संबंधी न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षा

अनुपालन की शुरुआत शीर्षस्तर से होती है। शायद आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में मैंने कुछ चुनिंदा बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बैंकों के निदेशक मंडल के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंध तंत्र से यह अपेक्षा है कि वे शीर्ष स्तर से पहल करते हुए एक मजबूत अनुपालन संस्कृति की शुरुआत करें। अनुपालन को संगठन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए; इसे केवल अनुपालन कार्य से जुड़े स्टाफ का कार्य नहीं माना जाना चाहिए। यह बैंक में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ सदस्य की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए और अनुपालन न होने की स्थिति में बैंक की प्रत्येक कारोबारी इकाई को समान रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कारोबार के दौरान बैंकों को उच्च मानक हासिल करने चाहिए और कानूनों का अनुपालन सही भावना से करना चाहिए। भले ही कोई कानून न तोड़ा गया हो, परंतु शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और बाजारों पर अपने क्रियाकलाप के प्रभाव को समझने में यदि भूल हुई तो इसके परिणाम गम्भीर दुष्प्रचार और प्रतिष्ठा जोखिम के रूप में देखने को मिल सकते हैं।

प्रभावी अनुपालन कार्यप्रणाली के लिए मजबूत अनुपालन संस्कृति एक अनिवार्य शर्त है।

अगर हम थोड़ा और गहन विश्लेषण करें तो पाएंगे कि किसी सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं-

शीर्षतंत्र की मंशा - क्या बोर्ड के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बताए गए संस्थागत मूल्य संस्था के कामकाज में परिलक्षित होते हैं। बोर्ड द्वारा की जाने वाली अनुपालन कार्यप्रणाली की निगरानी केवल नीतियाँ तैयार करने और इसकी आवधिक समीक्षा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बैंक की अनुपालन नीति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि निदेशक मंडल पूरे संगठन में ईमानदारी और निष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ावा नहीं देता। बोर्ड को एक गुणवत्ता गारंटी और सुधार कार्यक्रम तैयार करते हुए उसे निरंतर चलाना चाहिए जिसमें अनुपालन क्रियाकलाप के सभी पहलू शामिल हों।

उत्तरदायित्व : बैंक का वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि प्रबंध-तंत्र और कर्मचारियों द्वारा बैंक की अनुपालन नीति का पालन प्रभावी तरीके से किया जा रहा है; और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अनुपालन जोखिम कम से कम हो। स्वस्थ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने की संस्कृति; वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र, कार्यकारी प्रमुख और परिचालन प्रमुख के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन; प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कारोबारी इकाई की भूमिका और प्रतिरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में लेखापरीक्षा की भूमिका – इन सभी का अपना महत्व है।

वैचारिक आदान-प्रदान : आम तौर पर सभी स्टाफ सदस्यों और स्टाफ के विशिष्ट समूहों के लिए लागू सामान्य मानकों में अंतर करते हुए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रभावी अनुपालन संस्कृति के लिए यह अपेक्षित है कि पूरे बैंक में जोखिम और अनुपालन और प्रथाओं से संबंधित अपेक्षाओं की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की जाए; बोर्ड के मौजूदा और

नए सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए अनुपालन जागरूकता चैनल उपलब्ध हो; आचरण से जुड़े जोखिम को कम करने की प्रक्रिया मौजूद हो और ह्विसिल-ब्लोअर व्यवस्था लागू हो।

प्रोत्साहन संरचना : वांछित अनुपालन संस्कृति लागू करने के लिए बैंक के निर्णय लेने की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में एक समुचित प्रोत्साहन संरचना अंतर्निहित होनी चाहिए।

दूरदर्शी और अग्रसोची दृष्टिकोण : अनुपालन अन्य आश्वासन वाले कार्यों, यथा-जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा, से भिन्न है। अनुपालन कार्यप्रणाली निवारक अनुपालन पर केंद्रित होनी चाहिए। परिभाषा के अनुसार, निवारक अनुपालन पहले से ही बैंक की गतिविधियों का आकलन करके रखेगा और अनुपालन न करने वाली गतिविधियों / लेनदेन के घटित होने से पहले ही उन्हें रोक देगा। अनुपालन को दूरदर्शी और अग्रसोची गतिविधि बनाया जाना चाहिए।

अनुपालन का ढाँचा, प्राधिकार और संसाधन: किसी भी बैंक को अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली की संरचना स्वयं तैयार करनी चाहिए और अपने अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिकताएं इस प्रकार तय करनी चाहिए जो उसकी अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति और संरचना से मेल खाती हों। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक अपने परिचालन जोखिम क्रियाकलाप के भीतर ही अपने अनुपालन कार्यों को रखना चाहेंगे क्योंकि अनुपालन जोखिम और परिचालन जोखिम के कुछ पहलुओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरे बैंक अनुपालन और परिचालन जोखिम वाले कार्यों को अलग-अलग रखना पसंद कर सकते हैं लेकिन संभव है वे अनुपालन मामलों पर एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जिसमें इन दोनों कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अपेक्षा हो। बहरहाल, बैंक के भीतर अनुपालन कार्य चाहे किसी भी प्रणाली से किया जा रहा हो, यह समुचित रूप से अधिकार सम्पन्न, उच्च स्तरीय, स्वतंत्र, साधन-संपन्न होना चाहिए और इसकी बोर्ड तक पहुंच होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए, और इसकी गतिविधियों की आवधिक और स्वतंत्र समीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए। प्रबंधन को अनुपालन कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उसकी पूर्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हालांकि यह पुनरावृत्ति होगी तथापि, मैं पुन: जोर देकर कहना चाहता हूं कि अनुपालन बैंक के प्रत्येक स्टाफ की साझा जिम्मेदारी है।

कॉर्पोरेट अभिशासन का महत्व

सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति के विकास के लिए जहाँ फीडबैक प्रणाली का मौजूद होना महत्वपूर्ण है, वहीं, बैंक में ऐसा स्वस्थ वातावरण होना चाहिए जो मजबूत आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से ऐसी संस्कृति का पोषण करता हो और इसकी शुरुआत बैंक के बोर्ड स्तर से ही करनी होगी। बैंक को ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर कार्य की प्रेरणा पदानुक्रम में ऊपर से नीचे की ओर ही कार्य कर सकती है।

कॉर्पोरेट अभिशासन के तहत उन शक्तियों और उत्तरदायित्वों के आबंटन का कार्य किया जाता है जिनके आधार पर किसी भी बैंक का कारोबार उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र द्वारा चलाया जाता है जिसमें यह भी शामिल होता है कि वे कॉर्पोरेट संस्कृति, कॉर्पोरेट क्रियाकलापों का समन्वय किस प्रकार करें कि बैंक सुरक्षित और मजबूत तरीके से, कारोबारी निष्ठा के साथ और यथालागू कानूनों और नियमों का अनुपालन करते हुए अपना व्यवसाय कर सके। इस संदर्भ में, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोर्ड को प्रत्येक बैंक के आकार, उसके कारोबार की जटिलता, जोखिम लेने की क्षमता, उसके कारोबारी मॉडल और दर्शन के अनुसार नीतियों को अपनाना चाहिए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली नीतियों में इकाई विशेष से जुड़ी अनिश्चितताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, मात्र नीतियों को अपनाने से कोई समाधान नहीं निकलता। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि पूरी फर्म में उन नीतियों में अंतर्निहित सोच को प्रसारित किया जा सके। इसमें एक सशक्त अनुपालन संस्कृति की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है।

निष्कर्ष

पूरे बैंकिंग जगत में अनुपालन की संस्कृति में बहुत सारे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बैंकों के पर्यवेक्षक के तौर पर, रिज़र्व बैंक इस बात को लेकर बहुत गम्भीर है कि बैंकों में सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस और स्वस्थ अनुपालन संस्कृति हो क्योंकि ये बैंकों के सुरक्षित एवं अच्छे कारोबार के लिए अपरिहार्य हैं और यदि इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता, तो यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अच्छी तरह से अभिशासित बैंक कुशल और वहनीय लागत वाली पर्यवेक्षी प्रक्रिया तैयार करने में योगदान करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम ही पड़ती है। इस प्रकार की सुदृढ़ संस्कृति ऐसे संगठन तैयार करने में सहायक बनेगी जो

मजबूत होंगे, जिनमें वित्तीय आघातों को झेलने की क्षमता होगी, जिनमें अनुशासन होगा और जिनकी लाभप्रदता संधारणीय होगी तथा जिनमें ग्राहकों का विश्वास बना रहेगा। इसके लिए कई पर्यवेक्षी कदम भी उठाए जाने होंगे जिनके फलस्वरूप, यदि अनियमितताएं पायी जाती हैं तो, प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।

दुनिया भर में अनुपालन की भूमिका पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा रहा है और केंद्रीय बैंकों तथा बैंकरों द्वारा एकसमान रूप से यह स्वीकार किया गया है कि अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। विनियामकों, पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने वालों द्वारा इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लगा है कि तरह-तरह के नियमों और विनियमों को लागू करना तब तक एक निरर्थक कवायद साबित होती रहेगी जब तक विनियमित संस्थाएं इनका अनुपालन इनमें अंतर्निहित मूल भावना के अनुसार नहीं करेंगी।

यदि बैंकों में सशक्त कॉर्पोरेट अभिशासन और स्वस्थ अनुपालन संस्कृति होगी, तो पर्यवेक्षक के लिए उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर कर सकेंगे। इस संबंध में, पर्यवेक्षी अनुभव से भी यही बात निकलकर सामने आती है कि प्रत्येक बैंक के भीतर निदेशक मण्डल, वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र को प्रदत्त शक्तियों, जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों और जांच एवं संतुलन के साथ-साथ जोखिम, अनुपालन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से दिए जाने वाले आश्वासनों का विशेष महत्व है।

मुझे उम्मीद है कि बैंकिंग में उभरते रुझानों, वैश्विक विनियामकीय परिदृश्य, भारत में लागू हुए नई दीवाला व्यवस्था और बैंकों के कामकाज के तरीकों को प्रभावित करने वाले प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेषों पर पिछले दो दिनों से जो विचार-विमर्श चल रहा है उससे बैंकों को न केवल उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी बल्कि लेकिन देश में समावेशी और अनुपालन उन्मुख बैंकिंग के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए बैंकों को इस नए प्रतिमान द्वारा प्रदत्त अवसर का उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी।

संदर्भ

Bank of International Settlements (2005), 'Compliance and the compliance function in banks', *BIS*

Bank of International Settlements (2015), 'Corporate governance principles for banks – Guidelines', *BIS*

Flanner, Mark. J (2010), 'Market Discipline in Bank Supervision', *Chapter 15 of The Oxford Handbook of Banking, First Edition, OUP*

Hagendorff, Jens (2015), 'Corporate Governance in Banking', *Chapter 6 of The Oxford Handbook of Banking, Second Edition, OUP*

Mundra, S. S. (2014), 'Re-emphasizing the Role of Compliance Function In Banks', Speech delivered at the *CAFRAL Conference of Chief Compliance Officers in RBI, Mumbai*

Chakrabarthy, K. C. (2013), 'Compliance function in banks – back to the basics', Speech delivered at the launch of *Certificate Programmes on Compliance Function and Training, Mumbai*

Padmanabhan, G. (2015), 'Emerging Issues in Cyber Security in the Financial Sector', Speech delivered at the *Sri Chithira Thirunal Memorial Lecture Series organised by the State Bank of Travancore, Thiruvananthapuram*

लेख

भारत में आपूर्ति श्रृंखला गतिकी और खाद्य मुद्रास्फीति

पूर्वी भारत में सुदूर तक ऋण पहुंचाने के वाहक

*भारत में आपूर्ति श्रृंखला गतिकी और खाद्य मुद्रास्फीति**

यह आलेख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-सी) समूह में शामिल 16 प्रमुख खाद्य पदार्थों की फार्म गेट की कीमत और खुदरा कीमतों के अंतर के लिए कृषि बाजारों में विभिन्न मध्यस्थों द्वारा बढ़ाई गई कीमतों की क्या भूमिका है इसका परिक्षण करने के प्रयोजन से किसानों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए उपभोक्ता के रुपए में किसानों का औसत हिस्सा 28 प्रतिशत से 78 प्रतिशत के दायरे में पाया गया है। अनुभवआश्रित परिणाम बताते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सक्षम बनाने वाले कारक जैसे बेहतर रोड नेटवर्क, मंडी ढाँचा, सूचना के सुगम प्रवाह के लिए टेली-घनत्व, आपूर्ति अनिश्चितताओं को घटाने वाली सिंचाई सुविधाएं और देश में उपभोक्ता में जागरुकता बढ़ाने के लिए समग्र साक्षरता के स्तर में तरक्की, कीमतों में होनेवाली वृद्धि कम कर सकते हैं।

भूमिका

2014-15 से भारत में खाद्य कीमतों में तेज व लगातार कमी देखी गई है। सीपीआई-सी पर आधारित वार्षिक औसत खाद्य मुद्रास्फीति जो 2013-14 में 11.9 प्रतिशत थी, उत्तरोत्तर हर वर्ष घटते हुए 2018-19 में 1 प्रतिशत से कम पर आ गई। 2019-20 (अप्रैल-अगस्त) में खाद्य मुद्रास्फ़ीति 2.2 के औसत पर रही है (2018-19 की समान अवधि में 2.4 प्रतिशत)। भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण के तौर पर माँग के सापेक्ष अतिरिक्त आपूर्ति स्थिति को बताया गया है (आरबीआई 2019), आपूर्ति श्रृंखला गतिकी -चौड़ी सड़कों के नेटवर्क; कम कीमत पर मोबाईल फोन सेवाओं की उपलब्धता जिससे कमी व अधिशेष वाले केंद्रों के बीच सूचनाओं का सुगम प्रवाह; माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से साझा बाजार में पोतलदान की तीव्रतर आवाजाही; वित्तीय समावेश और सूक्ष्म-वित्त का विस्तार जिससे छोटे व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए कार्यशील पूँजी आसानी से उपलब्ध है – का भी योगदान इस गतिकी में हो सकता है।

यद्यपि कई अध्ययनों में उत्पादन लागत, अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों, उपभोक्ता के आहार-प्रकार और कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी नितियों तथा खाद्य मुद्रास्फीति गतिकी के अध्ययन में आपूर्ति प्रबंधन उपायों की जांच पड़ताल की गई है (गोकर्ण, 2011; गुलाटी और सैनी, 2013; बंदारा, 2013; भट्टाचार्य और सेनगुप्ता, 2017; आनंद व अन्य, 2016), हाल की अवधि में आपूर्ति श्रृंखला के विषयों के व्यापक आकलन परकोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। तथापि, फ़ार्म गेट से ख़ुदरा दुकानों तक विभिन्न स्तरों पर वृद्धि, उन वृद्धियों के घटकों तथा बाजार सहभागियों को शामिल करते हुए उत्पाद व फैक्टर मार्केट्स के बीचके अंतर्संबंधों को समझने के लिए कुछ अध्ययनों में प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित जानकारी का प्रयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता (बनर्जी और मीनाक्षी, 2004; चेंगप्पा व अन्य, 2012) को समझाया गया है। साहित्य में फ़ार्म गेट और खुदरा कीमतों के बीच वृद्धि के प्रभाव को दिखाते हुए भी खाद्य मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता(भट्टाचार्य, 2016) की व्याख्या दी गयी है। इसके अलावा और एक अध्ययन का निष्कर्ष था कि सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में, व्यापारी और बड़े खुदरा व्यापारी फायदा उठा सकते हैं तथा खाद्य आपूर्ति के ऋणात्मक आघात के स्फीतिकारी प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। (लाहिड़ी और घोष, 2014).

इस पृष्ठभूमि में, भारत में कृषि बाजारों के आपूर्ति श्रृंखला गतिकी में निहित मुद्दों का आकलन करने के लिए तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए, दिसंबर 2018[1] में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 16 राज्यों[2] की कृषि मंडियों से 16 प्रमुख खाद्य फ़सलों पर जानकारी माँगी गई। उत्पादन व उपभोग के अलग-अलग केंद्रों में फ़ैले किसान, व्यापारी और खुदरा व्यापारियों समेत सर्वेक्षण में लगभग 9400 लोगों की राय ली गई जिसमें प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रश्नावली रखी गई। यह आलेख सर्वेक्षण के प्रमुख परिणामों का विश्लेषण करता है तथा बहु-स्तरीय वृद्धि के स्वरूप

* यह लेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बिनोद बी. भोई, सुजाता कुंडू, विमल किशोर और डी. सुगन्थी द्वारा तैयार किया है और यह डीईपीआर, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी, एक बाहरी एजेंसी के सहयोग से सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिसे डीईपीआर के सहायक परामर्शदाता रमेश गोलाईत ने समन्वित किया था। सर्वेक्षण के दौरान अपने बहुमूल्य योगदान के लिए डीईपीआर क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के प्रति लेखक आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] यह किसानों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोजित एक बार का सर्वेक्षण था, जिन्होंने स्वेच्छा से सर्वेक्षण में भाग लिया था। इस लेख में बताए गए समेकित निष्कर्ष सर्वेक्षण के नमूना कवरेज और समय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

[2] सर्वेक्षण में 18 राज्यों को शामिल किया गया लेकिन नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में चुनिंदा फसलों के लिए मंडियों में किसानों की अनुपलब्धता के कारण, उन्हें किसानों से जुड़े कुछ विश्लेषणों में शामिल नहीं किया गया।

को समझाने में आपूर्ति श्रृंखला के कारकों को नापने का भी प्रयास करता है।

आलेख का शेष भाग छह भागों में विभाजित है। भाग II में हाल के वर्षों में खाद्य मुद्रा स्फीति में कमी के संदर्भ में वृद्धियों के बारे में शोधपरक तथ्य प्रस्तुत करता है। भाग III में भारत में कृषि बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला गतिकी पर चुनिंदा सैद्धांतिक व आनुभविक साहित्य की एक संक्षिप्त समीक्षा देता है जिसके बाद भाग IV में सर्वेक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं। भाग V सर्वेक्षण की पद्धति को निरुपित करता है। भाग VI में सर्वेक्षण के परिणाम और अनुभवआश्रित विश्लेषण दिया गया हैं। भाग VII निष्कर्षात्मक टिप्पणी देता है।

II. शोधपरक तथ्य

खुदरा कीमतें जो उपभोक्ता देता है और किसानों को प्राप्त होनेवाली मंडी कीमतें (मार्जिन या/वृद्धि) लेन-देन लागत, परिवहन लागत और और मार्ग में होने वाली फसलों की बरबादी जैसे विभिन्न कारणों से फसलवार अलग-अलग हो सकती है। फार्म उत्पादों की लागत, मंडी स्तरीय स्पर्धा, बुनियादी सुविधाएं और मंडी स्तरीय प्रभार (बाजार फीस, कमीशन प्रभार, भारांक प्रभार, श्रमिक प्रभार आदि) फार्म गेट कीमतों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारक हो सकते हैं। खाद्य कीमतों पर उपलब्ध द्वितीयक आँकड़े समय के साथ विभिन्न फसलों के मार्जिन में बड़ा अंतर दर्शाते हैं। (चार्ट 1).

चार्ट 1: मुख्य खाद्य पदार्थों की मंडी कीमत बनाम खुदरा कीमत

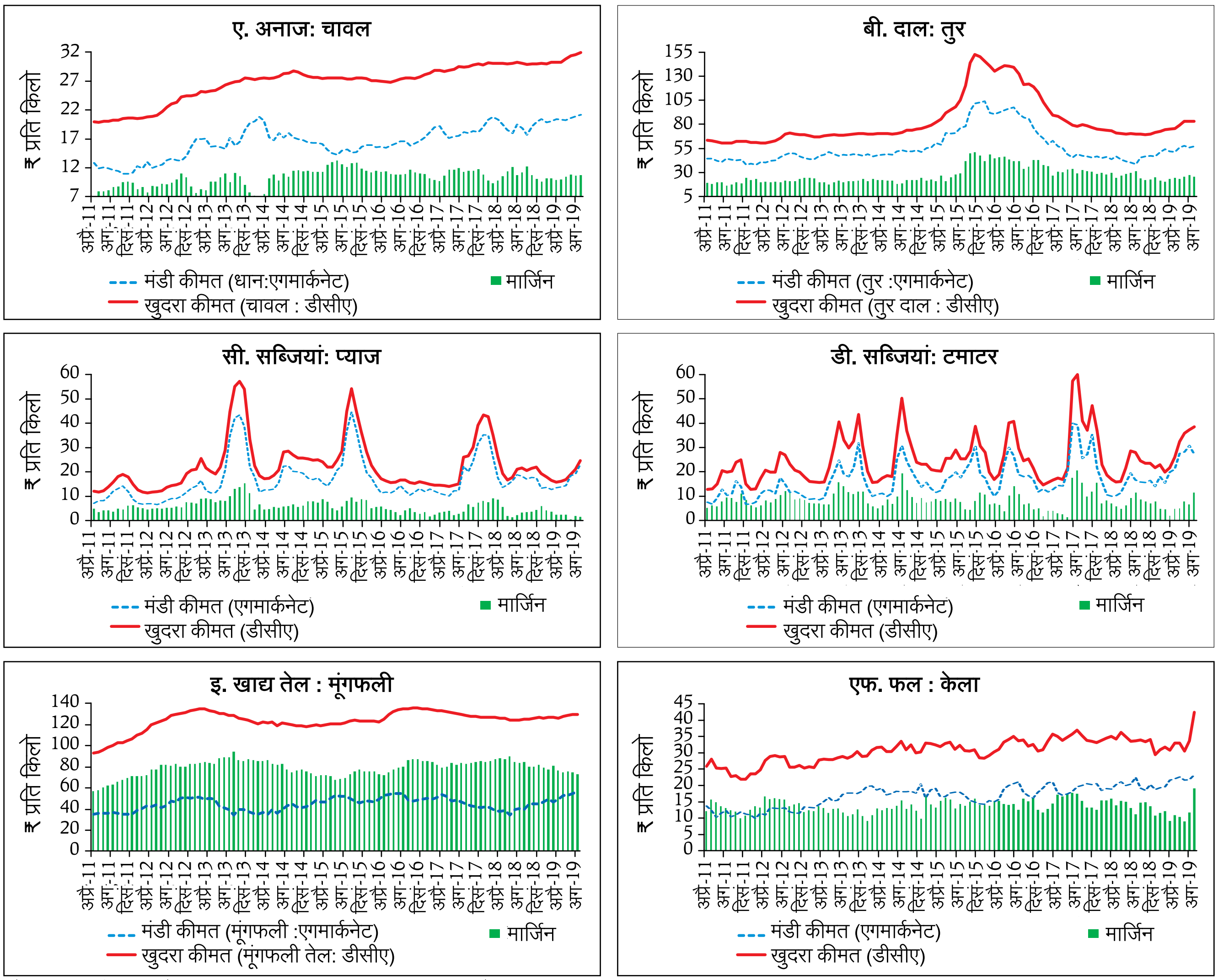

स्रोत: एगमार्कनेट; उपभोक्ता कार्य विभाग (डीसीए); राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी); तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2 : सीपीआई – खाद्य और पेय पदार्थ: मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अस्थिरता

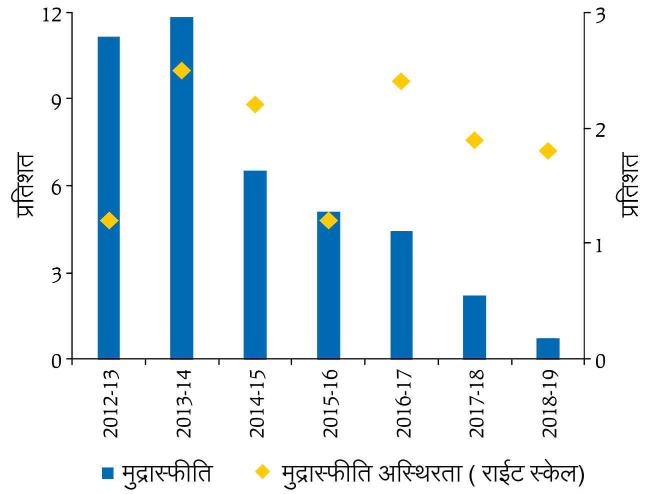

टिप्पणी: मानक विचलन का प्रयोग करते हुए मुद्रास्फीति अस्थिरता का आकलन किया गया है।
स्रोत : एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तथापि ये समग्र मार्जिन, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों (अर्थात् व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के मार्जिन) पर और उत्पादन केंद्रों व उपभोग केंद्रों के बीच मार्जिन की गतिकी को सही रूप में प्रतिबिंबित न करने के कारण फार्म गेट कीमतों से खुदरा कीमतों की वृद्धि का सही विश्लेषण नहीं हो पा रहा हैं। वृद्धि का स्वरूप विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में, औसत खाद्य मुद्रास्फ़ीति कम होने के बावजूद अत्यधिक अस्थिरता बनी हुई है (चार्ट 2)।

विभिन्न स्तरों पर, तस्वीर कुछ ज्यादा साफ़ होती है जिसमें विभिन्न खाद्य घटकों में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अस्थिरता में काफ़ी अंतर देखने मिलता है। (चार्ट 3)। उदाहरण के लिए, 2012-13 से 2015-16 की तुलना में 2016-17 से 2019-20 (अगस्त तक) में औसत मुद्रास्फीति में सर्वाधिक कमी देखने को मिली, स्फीतिकारी अस्थिरता उच्च बनी रही। इसके विपरीत, अनाजों, तेलों व वसा के मामले में, मुद्रास्फीति अस्थिरता काफी नीचे आ गई।

III. साहित्य समीक्षा

विषय पर उपलब्ध साहित्य के अनुसार, भारत में कृषि बाजार में अक्षमताएं भरी पड़ी हैं जैसा कि फार्म गेट कीमतों और उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाने वाली कीमतों में अंतर में देखने मिलता है। इस संदर्भ में, कुछ अध्ययन हैं जिनमें द्वितीयक व प्राथमिक दोनों डेटा का प्रयोग कर विभिन्न कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रीत किया गया है। . जैसे, मुंबई बाजार में अरहर के थोक व खुदरा कीमतों के बीच के अंतर पर अध्ययन में यह पाया गया कि 1999-00 और 2009-10 के बीच, किसानों को मिलने वाली कीमतों में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से कम वृद्धि हुई, जबकि इसकी थोक व खुदरा कीमतें 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ीं (चंद, 2012)। अध्ययन बताते हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत का नगण्य अंश ही किसान को मिलता है, जबकि कई मध्यस्थ उपभोक्ता के

चार्ट 3: सीपीआई – खाद्य और पेय पदार्थ के उप-समूह में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अस्थिरता

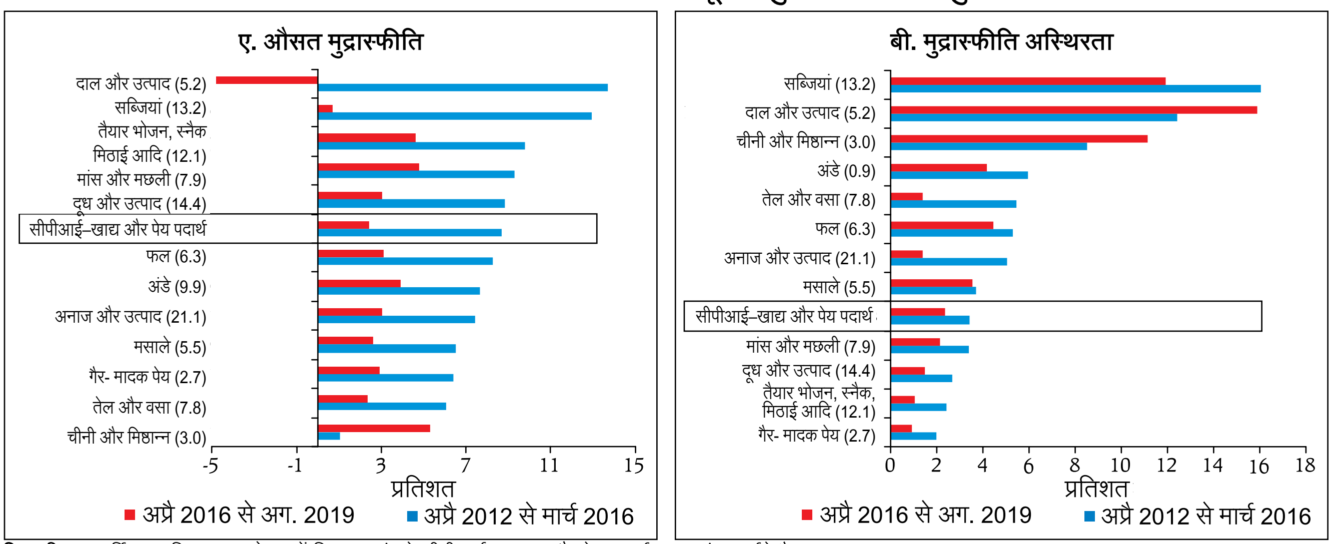

टिप्पणी : 1. वर्टिकल एक्सिस पर कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई – खाद्य और पेय पदार्थ का भारांक दर्शाते है।
2. मानक विचलन का प्रयोग करते हुए मुद्रास्फीति अस्थिरता का आकलन किया गया है।
स्रोत : एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

रुपए का एक बड़ा हिस्सा हासिल करते हैं। पिछले पाँच दशकों में, देश में विभिन्न फसलों में उपभोक्ता के रुपए में किसानों का हिस्सा 30 प्रतिशत से 89 प्रतिशत के दायरे में रहा है (पटेल, 1971; गाँधी और नंबूदिरी, 2002; सिंधू व अन्य, 2011; चेंगाप्पा व अन्य 2012; भारत सरकार, 2013) फलों व सब्जियों के मामले में उपभोक्ता के रुपए में किसानों का हिस्सा 32-68 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि खराब न होनेवाले खाद्यपदार्थों (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, तिलहन) के मामले में इसका दायरा 40 - 89 प्रतिशत रहा (भारत सरकार, 2013)। अन्य अध्ययन भी विभिन्न राज्यों व वस्तुओं में लगाई जानी वाली बाजार फीस और कमीशन एजेंट फीस में अंतर दर्शाते हैं, जो कि प्रमुख अनाजों की तुलना में खराब होनेवाली खाद्य वस्तुओं के मामले में उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा है। (गुलाटी, 2009; भारत सरकार, 2013)।

किसानों की उत्पादन लागत की फ़ार्म गेट कीमतों द्वारा भरपाई का अनुभवआश्रित वर्णन सामान्यत: न्यूनतम समर्थन कीमतों (एमएसपी) की तुलना में किसानों को प्राप्त कीमत पर ध्यान देता है (चटर्जी और कपूर, 2016; भारत सरकार, 2016; क्रिसिल, 2017) उदाहरण के लिए 2016-17 में दालों के मामले में किसानों का लाभ मार्जिन 30 प्रतिशत तक गिर गया है (क्रिसिल, 2017)। खेती से आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल के वर्षों में जैसे कई नीतिगत कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) जो कृषि वस्तुओं और बेहतर कीमत निर्धारण के लिए एकीकृत बाजार बनाने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एमएसपी को 2018-19 खरीफ फसलों के उत्पादन की लागत से 1.5 गुना बढ़ाना, और कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) मंडियों से फलों व सब्जियों को सूची से हटाना ई-नैम के कर्नाटक मॉडल, राष्ट्रीय ईमार्केट सेवा (आरईएमएस) पर एक अध्ययन में पता चला है कि 2013 और 2016 के दौरान कर्नाटक के किसानों को औसत कीमतों में 13 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई (चंद, 2017)। दूसरी तरफ़, कर्नाटक की मंडियों के प्राथमिक सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि बुनियादी ढाँचे के तौर पर केवल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के होने से किसानों को कोई खास मदद नहीं मिलेगी जब तक सभी हितधारकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर किसान – एजेंट-व्यापारी संबंधों को सुधारा नहीं जाता (अग्रवाल व अन्य, 2017)। एक और अध्ययन, जिसमें किसानों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को फलों और सब्जियों की बिक्री की जांच की गई (तामिलनाडू में उझावर संधाई और आंध्र प्रदेश में रायतू बाजार), जिसमें यह पाया गया कि किसानों को थोक कीमत की तुलना में 15-40 प्रतिशत अधिक कीमत मिलती है और उपभोक्ता को खुदरा कीमत की तुलना में 15-30 प्रतिशत का लाभ होता हैं। (भारत सरकार, 2011). मंडियों से फलों व सब्जियों को सूची से हटाने के बाद शहरी इलाकों में सीधे बिक्री की व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं।

IV. सर्वेक्षण के उद्देश्य

एक सामान्य कृषि बाजार आपूर्ति श्रृंखला किसानों, एग्रीगेटर्स, व्यापारियों/कमीशन एजेंटों, थोक व्यापारियों, प्रसंस्करण और खुदरा व्यापारियों जैसे विभिन्न मार्केट एजेंटों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में कार्य करती है। जानकारी साझा करने, लेनदेन की मात्रा प्रतिबद्धताओं या अंतर-व्यक्तिगत / अनौपचारिक क्रेडिट-संचालित संबंधो की व्यवस्था के आधार पर एजेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चार्ट 4 भारत में एक विशिष्ट कृषि आधारित वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के सरलीकृत संस्करण को दर्शाता है।

प्रतिनिधि कृषि आपूर्ति श्रृंखला की इस संरचना को ध्यान में रखते हुए, खाद्य पदार्थों में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया और फार्म गेट की कीमतों पर वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों, मंडियों में लेनदेन के तरीके तथा उपभोक्ताओं के लिए खाद्य मुद्रास्फीति को कम रखते हुए किसानों को अधिक पारिश्रमिक किमत सुनिश्चित

चार्ट 4: कृषि आधारित वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला

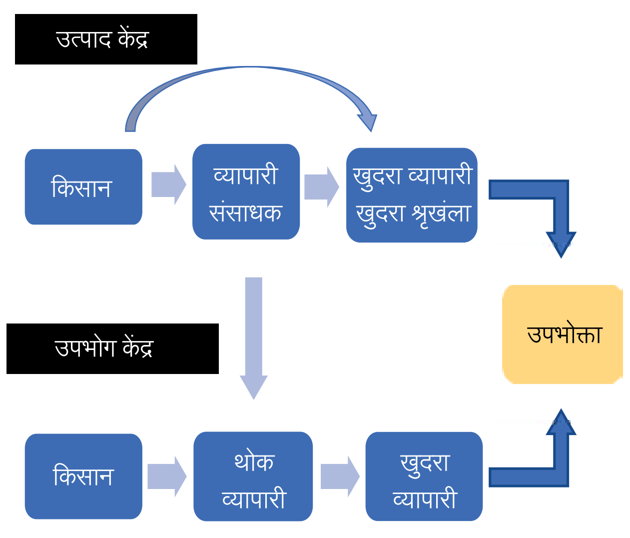

करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने में नीतिगत हस्तक्षेप की भूमिका समझने के लिए यह सर्वेक्षण (पहले उल्लेख किया गया) बनाया गया था। तदनुसार, सर्वेक्षण में निम्नलिखित पाँच व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे:

(i) खुदरा कीमतों में उत्पादकों (किसानों) का हिस्सा कितना है?

(ii) फार्म गेट की कीमतों में वृद्धि के लिए कौन से कारक प्रभावित करते हैं - परिवहन, श्रम और भंडारण लागत; करों / प्रभार; मध्यस्थों / मध्यस्थों की संख्या; और एजेंटों द्वारा लगाया गया कमीशन कितना है?

(iii) लेन-देन में प्रयुक्त विनिमय का मुख्य माध्यम क्या है - नकद, चेक, डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और / या व्यापार ऋण?

(iv) क्या फार्म गेट की कीमतें किसानों को उत्पादन की लागत की भरपाई करती हैं? तथा,

(v) किसानों के लिए बेहतर कीमत प्राप्ति और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमत में क्या और कौन सी सरकार की नीतियां बेहतर / सहायक होंगी?

जैसा कि आपूर्ति श्रृंखला गतिकी उत्पादन केंद्रों (चयनित वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक केंद्रों) कि तुलना में खपत केंद्रों (प्रमुख शहरों) में अलग-अलग होने की उम्मीद थी, सर्वेक्षण उत्पादन और उपभोग केंद्रों दोनों में अलग-अलग किया गया था।

V. सर्वेक्षण पद्धति

सर्वेक्षण में कुल 9,403 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिसमें किसान (2,811), व्यापारी (3,184) और खुदरा व्यापरी (3,408) उपभोग और उत्पादन केंद्रों (सारणी 1) में स्थित थे। 16 प्रमुख खाद्य फसलों (अनुबंध 1) में कीमत निर्धारण पर विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए 16 राज्यों में स्थित 85 मंडियों में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में किसानों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए अलग-अलग प्रश्नावली बनायी गयी थी, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रश्न शामिल थे और उसमें खरीद कीमत, बिक्री कीमत और मार्जिन पर जानकारी शामिल है।

केंद्र / राज्यों में उत्पादन, फसल की आवक, कीमतों और बाजार प्रथाओं में बड़ी विविधता के मद्देनजर विचलन को हटाने के लिए पूरे डेटासेट का शोधन किया गया। विचलन की छंटाई (प्रत्येक पक्ष पर प्राप्त कुल कोटेशन का 5 प्रतिशत) चरम मूल्यों को हटाने के लिए की गई थी। प्रत्येक समूह के लिए - किसान, व्यापारी और खुदरा व्यापारी - अलग-अलग [3] प्रति किलो की लागत के परिकलित मूल्यों, प्रति किलोग्राम मूल्य पर खरीद, प्रति किग्रा मूल्य और प्रति समूह के लिए लाभ मार्जिन प्रति किलोग्राम पर छंटाई की गयी थी।

VI. सर्वेक्षण निष्कर्ष और अनुभवआश्रित विश्लेषण

सर्वेक्षण निष्कर्ष

सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम कीमत में से किस अनुपात में कीमत मिलती है, अर्थात, प्रत्येक वस्तु के लिए व्यापारियों की कीमत निर्धारण प्रक्रिया में व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की तुलना में किसानों की मोल भाव करने की क्षमता। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि खुदरा कीमतों में किसानों की औसत हिस्सेदारी सर्वेक्षण में शामिल 14 फसलों[4] में 28-78 प्रतिशत के बीच अलग-अलग रही है – खराब होनेवाले खाद्य पदार्थों (विशेषकर, आलू और प्याज जैसी सब्जियां) के

सारणी 1 सर्वेक्षण की व्याप्ति

मंडी/केंद्र				समूह / वस्तुएं	
उत्तरदाता	उपभोग केंद्र	उत्पादन केंद्र	कुल	अनाज	धान/चावल
किसान	1,147	1,664	2,811	दाल	*तुर, मूंग, उडद,चना*
व्यापारी	2,176	1,008	3,184	तिलहन	मूंगफली, सोयाबीन
खुदरा व्यापारी	2,356	1,052	3,408	सब्जियां और फल	प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, सेब, केला, नारियल
कुल	**5,679**	**3,724**	**9,403**	मसाले	हलदी, लाल मिर्च

[3] डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा उत्तरदाताओं का टेलीफोन पर सत्यापन किया गया था।

[4] यहां खुदरा कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी केवल उन फसलों के लिए बताई गई है, जहां सर्वेक्षण के माध्यम से पर्याप्त डेटा एकत्र किया जा सकता है।

चार्ट 5: खुदरा कीमतों में किसानों का औसत भाग

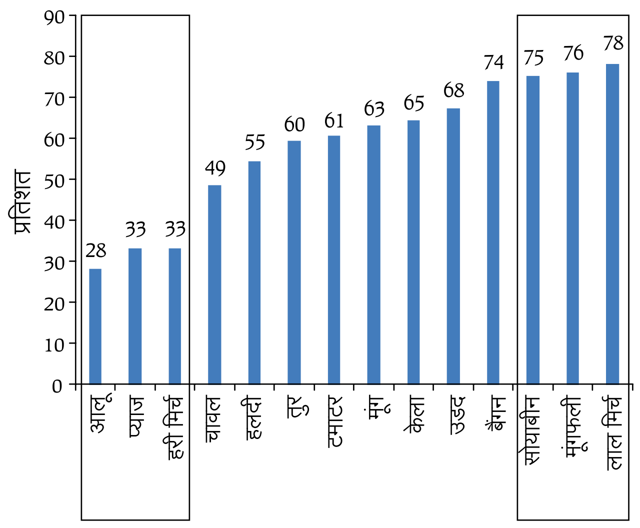

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मामले में कम हिस्सेदारी और न खराब होनेवाले खाद्य पदार्थ (जैसे, तिलहन और मसाले) (चार्ट 5) के लिए अधिक हिस्सेदारी के साथ ये निष्कर्ष मोटे तौर पर पटेल (1971), गांधी और नंबूदिरी (2002), और सिद्धू व अन्य द्वारा पहले किए गए अध्ययनों के अनुरूप हैं। (2011)। सर्वेक्षण के परिणामों की मजबूती के लिए इन निष्कर्षों / जांच को मान्य करने के लिए, अप्रैल 2019 में (यानी गर्मियों के मौसम में) एक और छोटा नमूना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 12 राज्यों में 197 किसानों, 321 खुदरा व्यापारियों और 434 व्यापारियों को शामिल किया गया था। फिर से किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष मोटे तौर पर इस लेख में विश्लेषण किए गए मुख्य सर्वेक्षण परिणामों के अनुरूप थे, जिसमें कुछ वस्तुओं मे विचलन था जिसका कारण मौसमी और छोटे नमूने कवरेज (अनुबंध 2) बताया गया।

सर्वेक्षण का दूसरा उद्देश्य कृषि माल कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज था, अर्थात् किसानों द्वारा प्राप्त बिक्री कीमत से लेकर खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को लगाए गए बिक्री कीमत तक। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला कि कीमते बढ़ाना कई कारकों से प्रभावित होता हैं - कमीशन और मंडी शुल्क; लदाई / उतराई शुल्क; पैकिंग, भारांक और परख शुल्क; यात्रा शुल्क; दुकान का किराया और स्थानीय कर; भंडारण लागत और सदस्यता शुल्क; और व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लाभ मार्जिन। इन कारकों की मार्क-अप की संवेदनशीलता अक्सर माल और क्षेत्र / राज्य विशिष्ट होती है, लेकिन सर्वेक्षण के निष्कर्ष (सारणी 2 में प्रस्तुत) मौजूदा साहित्य (गांधी और नंबूदरी, 2002; जीओआई; 2011; गुलाटी) के अनुरूप हैं। 2009; मिंटेन व अन्य।, 2012)।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए उत्पादन और उपभोग केंद्रों पर कीमतों में वृद्धि भिन्न था – वस्तुओं के लिए उपभोग केंद्रों में खुदरा व्यापारियों का मार्जिन आम तौर पर व्यापारियों के मार्जिन से अधिक था, संभवतः खुदरा स्तर पर विशेष रूप से खराब होने वाले खाद्य पदार्थो की हानि के कारण हो सकता है। हालांकि, उत्पादन केंद्रों (चार्ट 6) में ऐसा कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं देखा गया था।

तीसरा उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि मंडियों और खुदरा स्तर पर किए गए लेन-देन के लिए किस प्रकार -नकद, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, चेक, क्रेडिट से भुगतान किया जाता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों में वस्तुओं और राज्यों

सारणी 2: कीमतों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

किसान	व्यापारी	खुदरा व्यापारी
मंडी प्रभार: 0.8 प्रतिशत	सदस्यता शुल्क: ₹2412/वर्ष	दुकान का किराया: ₹4206/महिना
कमीशन: 1.3 प्रतिशत	दुकान का किराया: ₹5106/महिना	स्थानीय कर: 1.2 प्रतिशत
	सेस/कर: ₹0.7/कि.ग्रा.	
लदाई/उतराई: ₹0.4/कि.ग्रा.	श्रमिक प्रभार: ₹0.4/कि.ग्रा.	श्रमिक प्रभार: ₹.4/कि.ग्रा.
पैकिंग: ₹0.5/कि.ग्रा.	परिवहन लागत: ₹1.0/कि.ग्रा.	परिवहन लागत: खुदरा व्यापारियों की दायरा और प्रतिशत
भारांक: ₹0.3/कि.ग्रा.	भंडारण लागत: ₹1.0/कि.ग्रा.	0-5 प्रतिशत: 75 प्रतिशत
परख: ₹0.3/कि.ग्रा.		6-10 प्रतिशत: 21 प्रतिशत
		10 प्रतिशत से अधिक: 4 प्रतिशत

टिप्पणी : समाविष्ट की गई वस्तुओं और बाजारों के लिए नमूना औसत हैं।

चार्ट 6 : कीमत निर्धारण – मार्क-अप

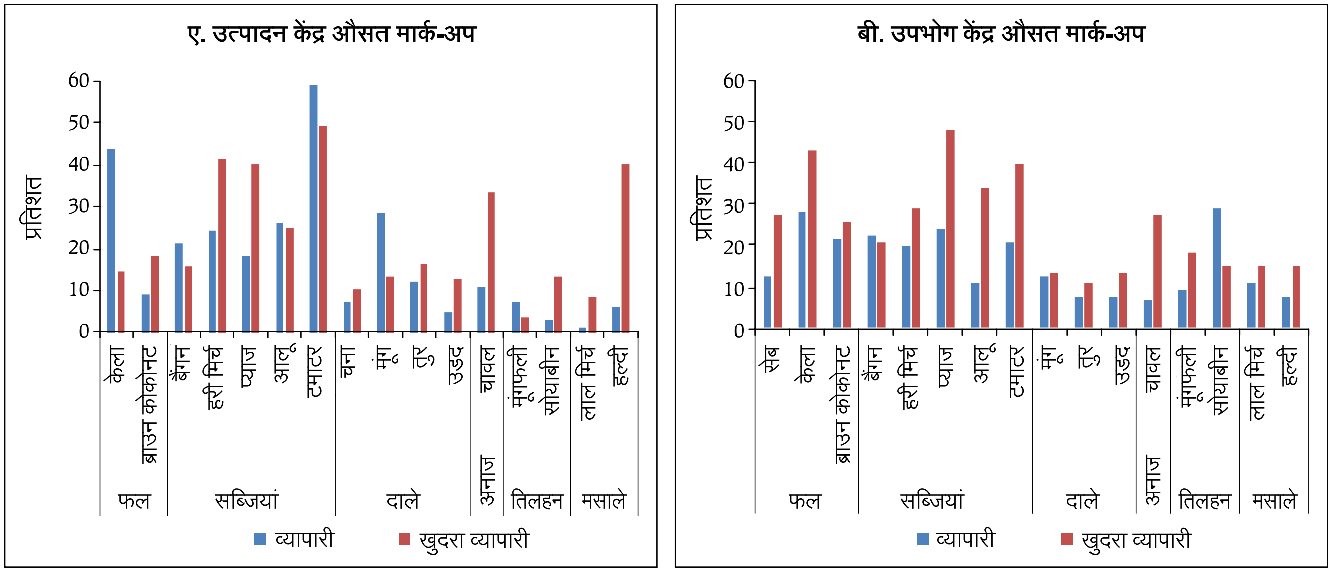

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

(चार्ट 7)[5] में समग्र स्तर पर मंडियों में मुख्य रूप से नकद भुगतान को अपनाया गया।

सर्वेक्षण के परिणामों ने सभी फसलों के भुगतान के लिए नकद के उपयोग में और काउंटर-पार्टियों (चार्ट 8) द्वारा भुगतान के तरीके में व्यापक भिन्नता दिखाई।

सर्वेक्षण में काउंटर-पार्टियों द्वारा भुगतान प्राप्त करने की अवधि के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि मंडियों में काउंटर-पार्टियों द्वारा भुगतान में कोई विशेष देरी नहीं हुई है क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वस्तुओं (चार्ट 9) के भौतिक लेनदेन पूरा होने के 2 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है।

किसानों के व्यवसाय की लाभप्रदता के बारे में उनके विचारों को जानने, अर्थात क्या वे अपने उत्पादन और विपणन लागत की

चार्ट 7 : भुगतान के प्रकार

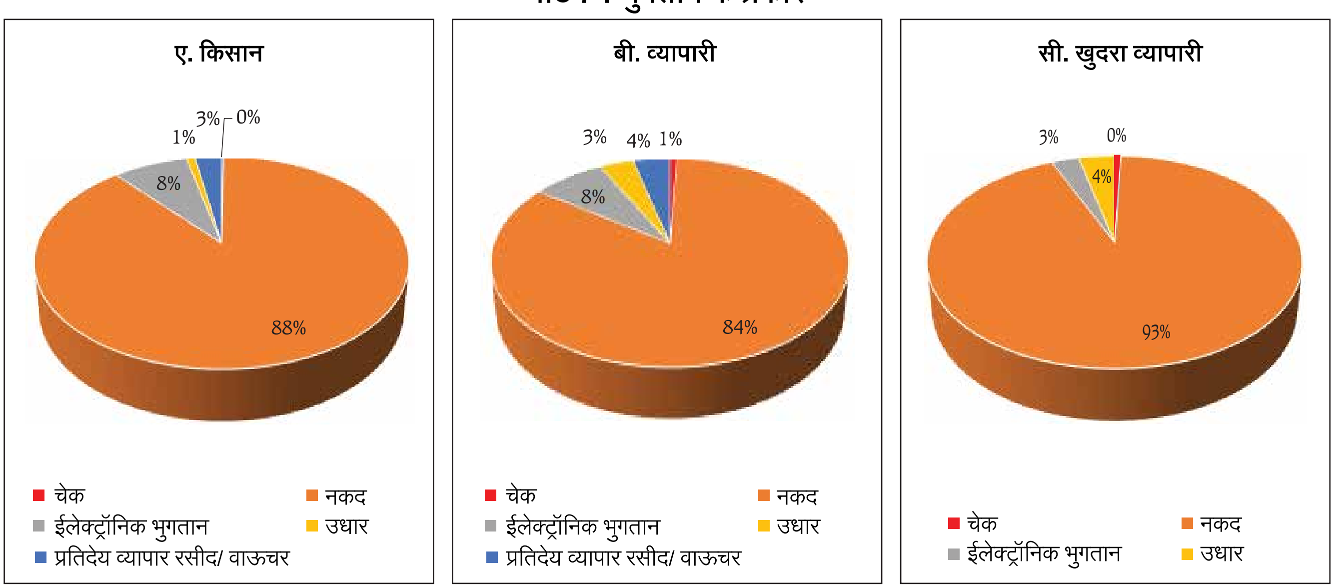

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

[5] अन्य अध्ययन जो ज्यादातर वस्तुओं को कवर करते हैं जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है और सरकारी खरीद होती है, हालांकि, पाया गया कि नकद भुगतान प्रमुख तरीका नहीं है (जीओआई, 2016)।

चार्ट 8: नकद लेन-देन का हिस्सा

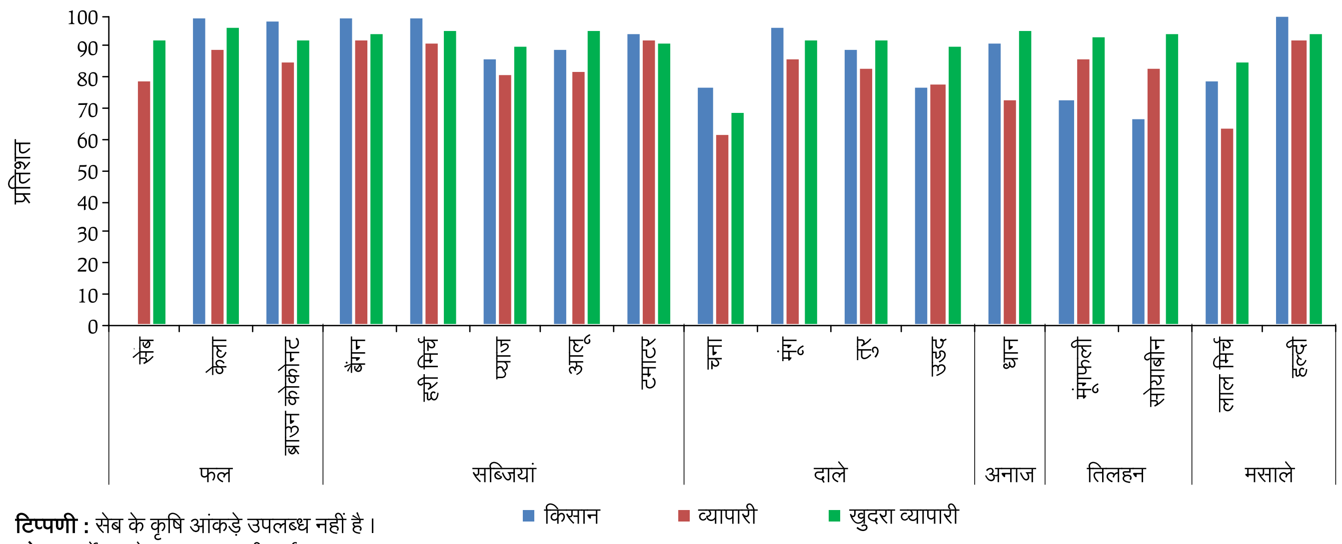

टिप्पणी : सेब के कृषि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वसूली करने में सक्षम हैं यह जानना चौथा उद्देश्य था। समग्र स्तर पर गुणात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुसार अधिकांश किसानों (यानी 62 प्रतिशत) ने यह स्पष्ट किया कि उनको लागत से बिक्री कीमत (चार्ट 10) अधिक मिलती है।

इसके अलावा, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि लागत की वसूली करने की उनकी क्षमता के बारे में किसानों की धारणा अलग-अलग वस्तुओं के लिए भिन्न है-अन्य खादय वस्तुओं (चार्ट 11) की तुलना में सब्जियों के लिए अपेक्षाकृत कम है।

पांचवां उद्देश्य उन सरकारी नीतियों पर किसानों, खुदरा व्यापारियों और व्यापारियों की प्रतिसूचना लेना था जिन्होंने उनकी मदद की है, या जो भविष्य में उनकी सहायता कर सकती हैं, यदि उन्हे लागू किया जाए। अधिकांश किसानों का मानना था कि फसलों के लिए एमएसपी और आसानी से उपलब्ध बाजार

चार्ट 9: भुगतान में विलंब

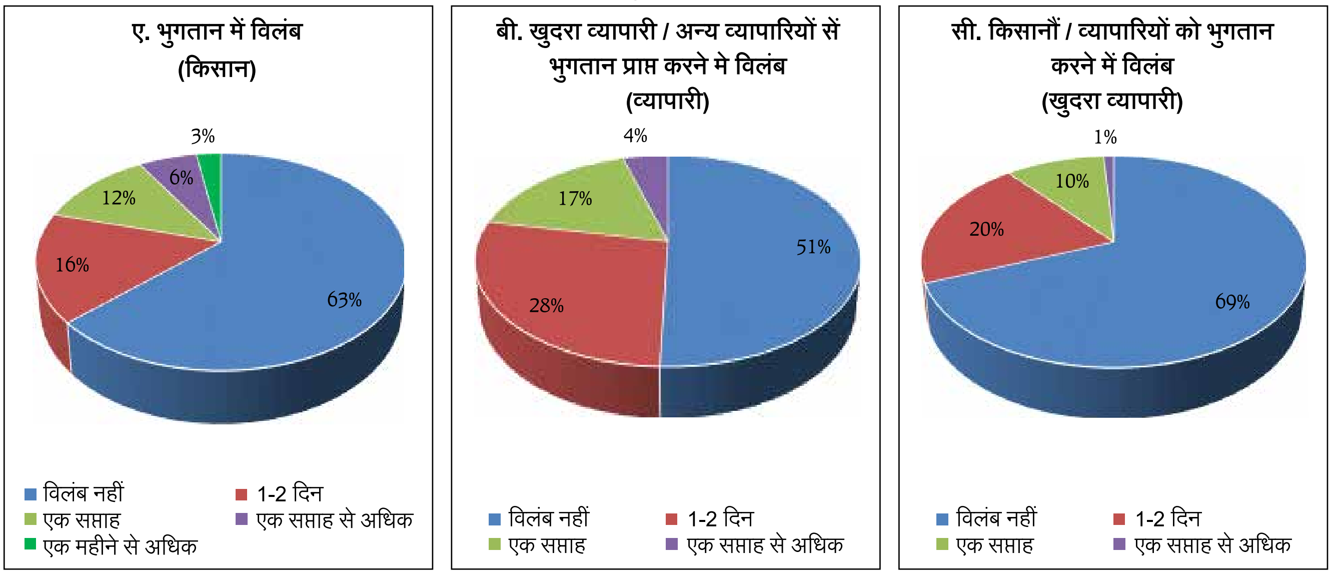

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 10: बिक्रि की कीमत बनाम लागत – समग्र स्तर

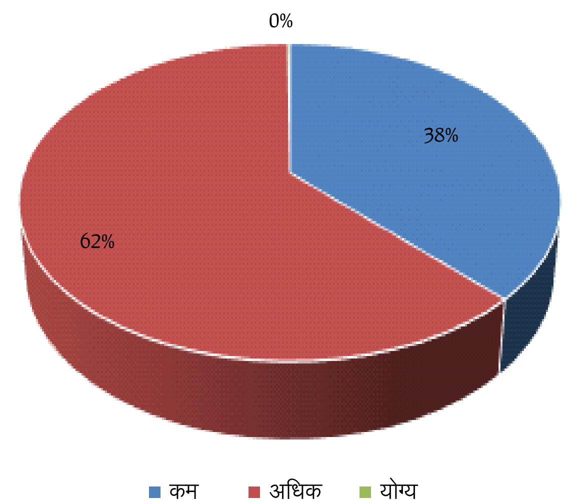

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 11: बिक्रि की कीमत बनाम लागत – सभी फसलें

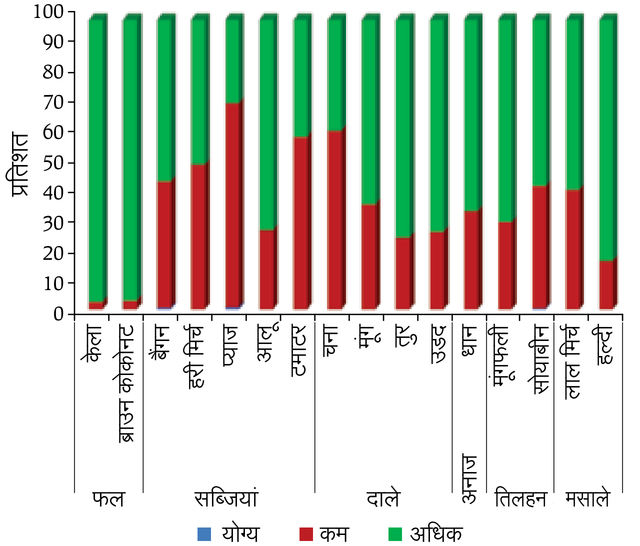

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

की जानकारी बेहतर कीमतों के लिए सहायक है। किसानों ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान, बेहतर भंडारण सुविधाएं और फसलों पर सरकारी सलाहकार उन्हें बेहतर फसल निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं (चार्ट 12)।

मंडियों में वस्तुओं के प्रचलित कीमतों की जानकारी ज्ञात होने के बारे में अधिकांश किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी उपज मंडियों में ले जाने से पहले कीमतों की जानकारी थी और इस जानकारी का प्रमुख स्रोत उनके संपर्क समूह के अन्य किसान और व्यापारी हैं। (चार्ट 13)

अधिकांश व्यापारियों ने बताया कि सरकार द्वारा एपीएमसी से उत्पादों की परख और कुछ उत्पादों की अधिसूचना रद्द करने से उनकी मदद हुई है और उनकी यह राय थी कि मंडी में भंडारण सुविधा में सुधार तथा मुक्त व्यापार की अनुमति से उन्हें और अधिक सहायता मिल सकती है। (चार्ट 14)

चार्ट 12: किसानों के लिए लाभकारी नीतियां – किसानों का दृष्टिकोण

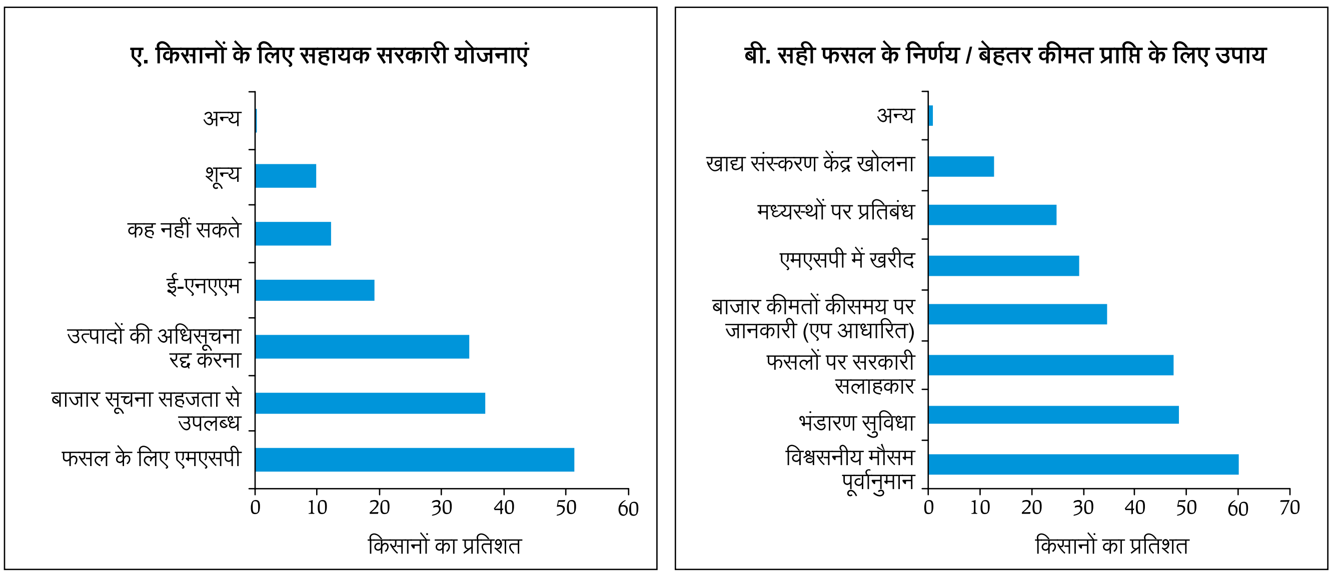

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 13: किसानों के बीच कीमत जागरूकता

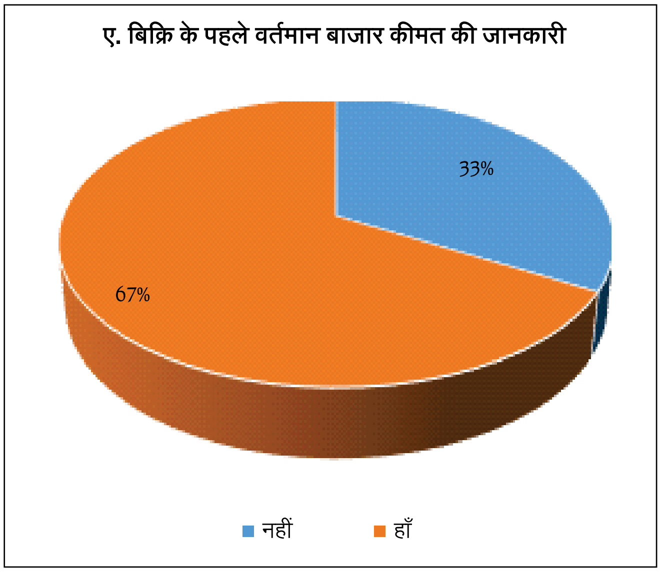

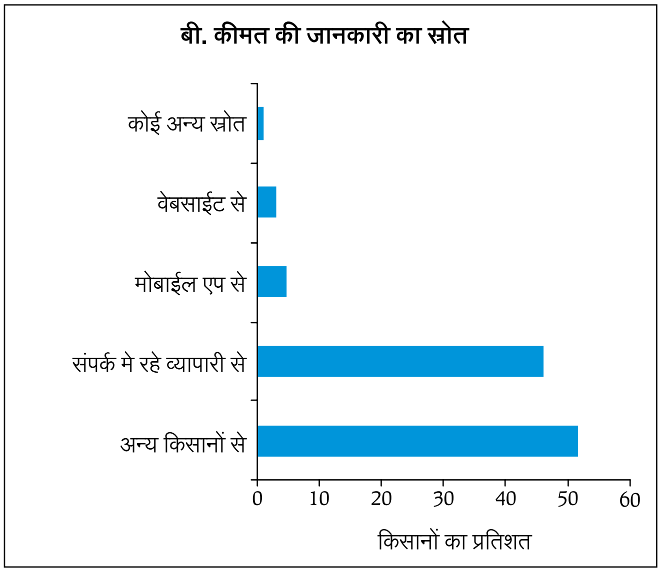

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सर्वेक्षण किए गए अधिकांश खुदरा व्यापारियों का मानना था कि भंडारण सुविधाओं में सुधार तथा सरकार के आपूर्ति प्रबंधन उपायों और बाजार में आपूर्ति की मांग की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी कीमत दबाव (चार्ट 15) को रोकने में सहायक हो सकती है।

खुदरा व्यापारियों ने आम तौर पर उनके लिए तथा साथ ही साथ उनके ग्राहकों के लिए सहायक नीतियों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपभोक्ताओं पर लगायी जानेवाली अंतिम बिक्री कीमत का निर्धारण करनेवाले कारकों पर भी अपनी राय प्रस्तुत की (चार्ट 16)। अधिकांश खुदरा व्यापारियों ने देखा कि मौजूदा बाजार कीमतें और किसानों/व्यापारियों से उत्पादों की खरीद/वितरण में होने वाली लागत उनकी बिक्री कीमतें निर्धारित करती है। इसके अलावा, अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बिक्री कीमतों में परिवर्तन करते समय भुगतान की गई कीमतें और खर्च की गई लागत इन दो प्रमुख कारकों को ध्यान में लिया जाता हैं।

चार्ट 14 : व्यापारियों के लिए लाभकारी नीतियां – व्यापारियों का दृष्टिकोण

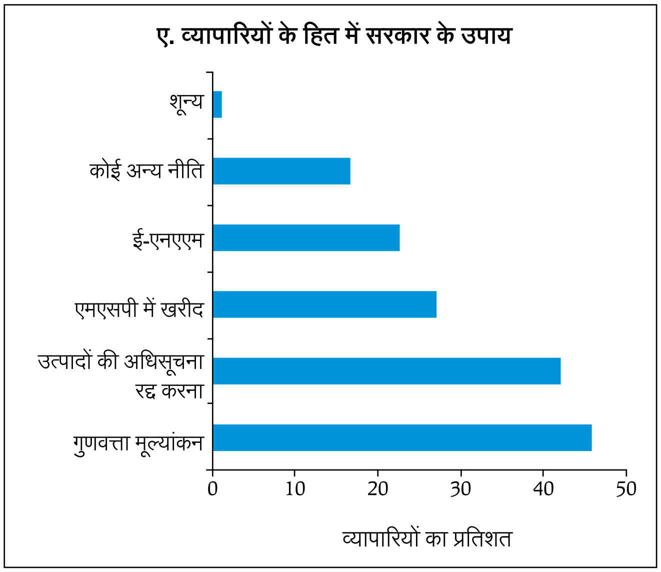

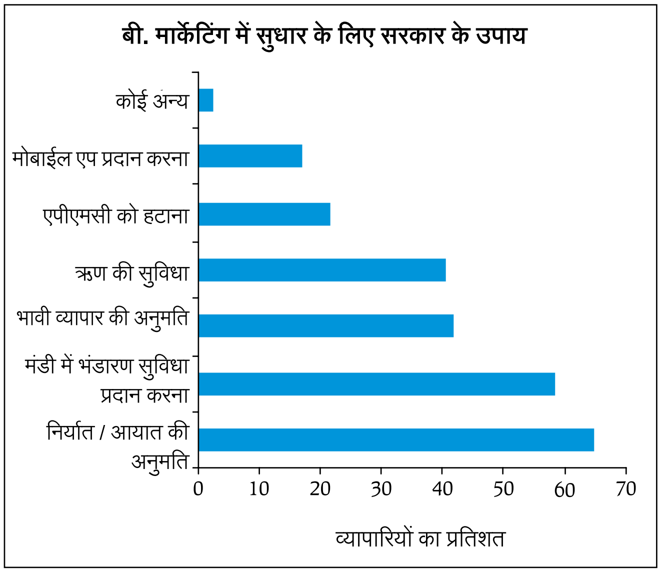

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 15: किमतों पर नियंत्रण रखने के लिए बनायी गयी नीतियां- खुदरा व्यापारियों का दृष्टिकोण

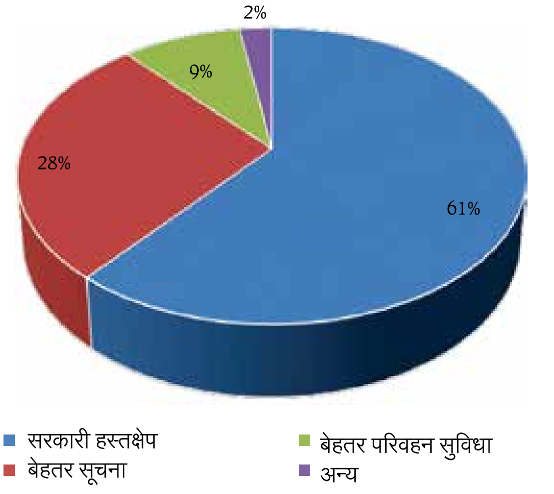

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अनुभवआश्रित विश्लेषण

संकलित सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के मार्क-अप को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए अनुभवआश्रित अभ्यास किया गया। साधारण कम वर्ग (ओएलएस) विधि का उपयोग कर के फसलों और राज्यों में डेटा पूलिंग करके निम्नलिखित बहुआयामी रिग्रेशन समीकरण का अनुमान लगाया गया:

$$M_{ic} = \alpha + \beta_1 I_i + \beta_2 SocioEco_i + \beta_3 Agri_i + \beta_4 C_c + \beta_5 S_i + \varepsilon_{ic}$$

जहां, आई और सी क्रमशः 'राज्य' और 'वस्तुओं' का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां, M_{ic} मार्क-अप है जिसे व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए बिक्रि कीमत से लागत घटाने पर लागत के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। I_i राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रति 100 व्यक्तियों का टेली-घनत्व, कुल सकल फसल क्षेत्र में कृषि मंडियों की संख्या का अनुपात, फलों और सब्जियों के क्षेत्र में उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज का अनुपात, कुल सकल फसली क्षेत्र तक सड़कों की लंबाई और ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या का अनुपात, शामिल है। $SocioEco_i$ राज्यों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को दर्शाता है जो साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। $Agri_i$ कृषि चर को दर्शाता है, जो कुल फसल क्षेत्र में सिंचिन क्षेत्र का प्रतिशत है और लंबी अवधि के लिए औसत वर्षा विचलन है (एलपीए) (छद्म चर मूल्य '1' नकारात्मक विचलन और अन्यथा शून्य विचलन है)। C_c और S_i क्रमशः फसल और राज्य डमी के वेक्टर हैं, और ε_{ic} अवशिष्ट है।

मुख्य मॉडल व्यापारी और खुदरा व्यापारियों के बुनियादी ढांचे, सामाजिक -आर्थिक और कृषि चर, फसल और राज्य डमी के लिए नियंत्रण पर मार्क-अप से पीछे हटता है। चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए कृषि व्यापार और मंडी शुल्क को नियंत्रित करने वाली नीतियां राज्यों में अलग-अलग होती हैं। अलगाव का स्रोत जानने के लिए राज्य डमी प्रस्तुत किए गए थे। इसके

चार्ट 16: बिक्री कीमतें प्रभावित करनेवाले कारक -व्यापारियों का दृष्टिकोण

ए. बिक्री कीमतें निर्धारित करने वाले कारक

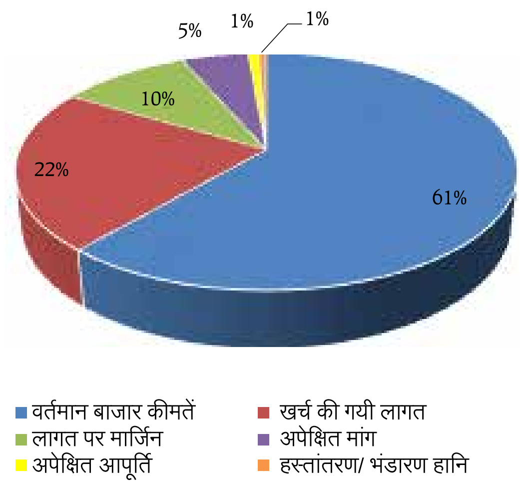

बी. बिक्री कीमतों को बदलनेवाले कारक

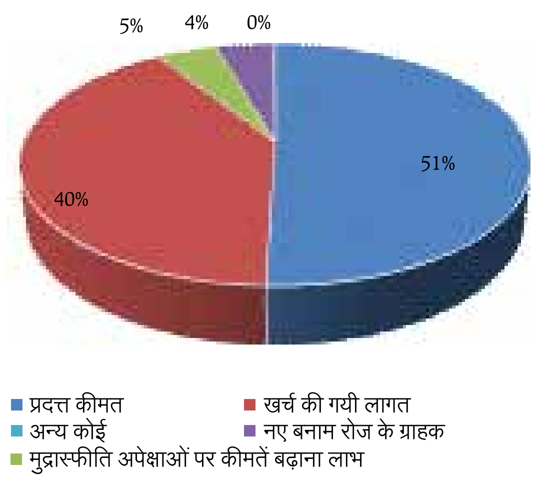

स्रोत : सर्वेक्षण डेटा; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 3: अर्थमितीय विश्लेषण के परिणाम

	व्यापारी			खुदरा व्यापारी		
आश्रित चर मार्क-अप	संपूर्ण नमूना	खराब होनेवाला	खराब न होनेवाला	संपूर्ण नमूना	खराब होनेवाला	खराब न होनेवाला
टेली घनत्व	-1.27*** (0.49)	-1.85** (0.81)	-0.81 (0.62)	-0.36* (0.29)	-0.75* (0.42)	-0.36 (0.30)
रोड घनत्व	-0.003* (0.002)	-0.006 (0.004)	-0.002 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.004*** (0.002)	-0.0007 (0.001)
मार्केट घनत्व	-0.167** (.079)	-0.26* (0.15)	-0.09 (0.09)	-0.095* (0.05)	-0.17 (0.34)	-0.10** (0.05)
प्रति व्यक्ति आय	0.63*** (0.18)	0.96*** (0.29)	0.38* (0.23)	0.08 (0.11)	0.32* (0.19)	0.05 (0.11)
वर्षा विचलन नकारात्मक स्थिति में डमी	10.3** (4.7)	19.83** (9.79)	3.74 (4.63)	1.97 (4.62)	5.8 (9.6)	6.78 (4.07)
सिंचन की तीव्रता	-1.21** (0.48)	-1.99** (0.94)	-0.63 (0.52)	-0.453 (0.31)	-0.55 (0.64)	0.37 (0.30)
साक्षरता दर	-0.74 (0.55)	-1.46 (1.01)	-0.28 (0.64)	-1.48*** (0.49)	-0.28 (0.83)	-1.74*** (0.45)
वस्तु डमी	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
राज्य डमी	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
आर-स्क्वेअर	0.42	0.38	0.39	0.54	0.28	0.31
टिप्पणियों की संख्या	199	79	120	206	78	128

***,** तथा * क्रमश: 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते है ।
नोट : कोष्टक में दिए गए आंकड़े रोबस्ट मानक विचलन दर्शाते है ।

अलावा, खराब होनेवाली और खराब न होनेवाली खाद्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग मॉडल का अनुमान लगाया गया था।

पूर्ण नमूने के लिए अनुभवआश्रित परिणामों से संकेत मिलता है कि बेहतर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे टेली-घनत्व, पक्की सड़कों और सकल फसली क्षेत्र के सापेक्ष बाजारों की संख्या व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों दोनों के मार्क-अप कम करती है (सारणी 3)। बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाएं न केवल किसानों को प्रत्यक्ष बाजार पहुंच प्रदान करती हैं बल्कि व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा की श्रेणी को भी बढ़ाती हैं, जिससे उनका मार्क-अप कम हो जाता है। वर्षा में कमी जैसे कृषि चर व्यापारीयों के मार्क-अप को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि सिंचाई की तीव्रता (यानी कुल फसली क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी) का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिंचाई के लिए कम पानी की उपलब्धता का उपज और उपज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों की मोल भाव करने की शक्ति कम हो जाती है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व्यापारियों के मार्क-अप को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, साक्षरता दर खुदरा व्यापारियों के मार्क-अप से नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। खुदरा व्यापारियों के मार्क-अप पर साक्षरता दर का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, संभवतः प्रचलित कीमतों और कई खुदरा दुकानों और ऑनलाइन किराना बाजारों जैसे वैकल्पिक खरीद विकल्पों के बारे में बढ़ी हुई उपभोक्ता जागरूकता है।

खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में, बुनियादी सुविधाओं, जैसे टेली-घनत्व, सभी मौसम सड़कों और सकल फसली क्षेत्र के लिए उपलब्ध बाजारों की संख्या व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों दोनों के कीमतें बढ़ाना को कम करती है। कृषि चर, वर्षा विचलन और सिंचाई की तीव्रता खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए व्यापारियों के मार्क-अप को प्रभावित करती है, न कि खराब न होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए इसका संभावित कारण मुख्य अनाज की सरकारी खरीद हो सकता है। इसके अतिरिक्त, खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के मामले में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों दोनों के मार्क-अप को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अनुसंधान से पता चला है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ने फल, सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पादों (राव व अन्य, 2006) जैसे उच्च कीमत वाली वस्तुओं की मांग बढ़ी। चावल और गेहूं (चटर्जी और कपूर, 2016) के मामले में किसानों की कीमतों की वसूली में सुधार

के पीछे परिवहन, बाजार बुनियादी ढांचे और संचार सुविधाओं तक बेहतर पहुंच को एक कारक के रूप में रेखांकित किया गया है; नेगी व अन्य., 2018; गोयल, 2010)। राज्यों में मंडी स्तर के आंकड़ों और जिला स्तरीय खरीद आंकड़ों का उपयोग करते हुए, एक अध्ययन से पता चला है कि भौगोलिक क्षेत्र जहां मंडी एकाग्रता अधिक है, किसानों को अधिक कीमतों का अनुभव होने की संभावना है (चटर्जी और कपूर, 2016)। एनएसएसओ 70 वें चरण और जनगणना 2011 डेटा 7 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह भी पाया गया कि सूचना और बेहतर परिवहन नेटवर्क तक पहुंच के परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है (नेगी व अन्य, 2018)।

VII. निष्कर्षात्मक टिप्पणी

2013-14 के बाद से भारत में औसत खाद्य मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति के कारकों पर उपलब्ध मैक्रो-लेवल डेटा-उत्पादन, आगमन, निर्यात/आयात, स्टॉक, एमएसपी, वर्षा/बुवाई पैटर्न, खपत पैटर्न और मांग, इनपुट लागत और वैश्विक खाद्य मूल्य प्रवृत्तियां-कई बार मंडियों/थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के बीच कीमतों के अंतर को समझाने में सहायता नहीं करते हैं, जो मार्क-अप के निर्धारकों को समझने के लिए आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता पर सर्वेक्षण आधारित सूचना संग्रह की आवश्यकता है, जो खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता दोनों तथा मार्क-अप को प्रभावित करता है।

किसानों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित इस लेख के अनुभवआश्रित निष्कर्ष भारत में कृषि बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला गतिकी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपयोगी दृष्टकोण प्रदान करते है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि खुदरा कीमतों में किसानों की औसत हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से 78 प्रतिशत के दायरे में अलग-अलग फसलों में भिन्न होती है। व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के मार्क-अप आम तौर पर खराब न होनेवाली खाद्य वस्तुओं की तुलना में खराब होनेवाले खाद्य वस्तुओं के लिए अधिक पाए गए। इसके अलावा, यह देखा गया कि व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए मार्जिन उत्पादन/उपभोग केंद्रों में भिन्न है, जिसमें खुदरा व्यापारियों का मार्जिन आम तौर पर खपत केंद्रों में व्यापारियों के मार्जिन से अधिक रहता है। खुदरा व्यापारियों के अत्यधिक मार्जिन आंशिक रूप से खुदरा विपणन चरणों में महत्वपूर्ण उत्पाद की हानि के कारण हो सकता है, विशेष रूप से खराब होनेवाली खाद्य वस्तुओं के लिए। इसके अलावा, मार्क-अप कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जो बाजार सहभागियों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कमीशन और मंडी प्रभारों में किसानों द्वारा वहन की जाने वाली लागतों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, अन्य मे लदाई /उतराई शुल्क और पैकिंग, भारांक और परख का शुल्क शामिल हैं। व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के लिए श्रमिक प्रभार, परिवहन लागत, दुकान किराया और स्थानीय कर कुछ प्रमुख लागत घटक हैं, साथ ही व्यापारियों के मामले में भंडारण लागत और सदस्यता शुल्क इसमें शामिल है। सर्वेक्षण के अनुसार मंडियों में भुगतान के प्रमुख साधन के रूप में नकदी का उपयोग किया जाता है। किसानों के अनुभव के संबंध में, 62 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनकी बिक्री कीमत उत्पादन लागत से अधिक है। इसके अलावा, सरकारी नीतियों के बारे में, किसानों ने कहा कि एमएसपी और आसानी से उपलब्ध बाजार जानकारी से उन्हें बेहतर कीमत मिलती है। किसानों ने यह भी बताया कि विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान, बेहतर भंडारण सुविधाएं और फसलों पर सरकारी सलाहकार उन्हें बेहतर फसल निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर, अधिकांश व्यापारियों ने देखा कि भंडारण सुविधा में सुधार और मुक्त व्यापार की अनुमति देना मददगार होगा, जबकि अधिकांश खुदरा व्यापारियों का मानना था कि सरकार के आपूर्ति प्रबंधन उपायों के साथ-साथ जानकारी की बेहतर उपलब्धता से खाद्य कीमतों का दबाव रोकने में सहायता मिलेगी।

अनुभवआश्रित परिणाम बताते हैं कि देश में सड़क नेटवर्क, बाजार घनत्व, टेली-घनत्व, सिंचाई सुविधाओं और समग्र साक्षरता दर जैसे आपूर्ति-पक्ष सुधार कीमतें कम करने में सहायता करते हैं, जबकि वर्षा की कमी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कीमतें बढ़ाती है। चूंकि फसलों में बहु-स्तर मार्क-अप खाद्य मुद्रास्फीति की वक्ररेखा और इसकी अस्थिरता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए विशेष रूप से आपूर्ति आघात /उपभोग पैटर्न में व्यवहारिक बदलावों की अवधि के दौरान एकत्र किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित आंकड़े खाद्य मुद्रास्फीति की गतिकी के आकलन में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं।

[6]6 एगमार्कनेट जिलों और राज्यों में विभिन्न वस्तुओं के लिए मंडी स्तर का डेटा प्रदान करता है।

7 कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण, एनएसएसओ 70 वां चरण, और जनगणना 2011 की ग्राम सुविधाएं आंकड़े।

संदर्भ

Aggarwal, N., S. Jain and S. Narayanan (2017), 'The Long Road to Transformation of Agricultural Markets in India: Lessons from Karnataka', *Economic & Political Weekly,* Vol. 52 (41), pp. 47-55.

Anand, R., N. Kumar and V. Tulin (2016), 'Understanding India's Food Inflation: The Role of Demand and Supply Factors', *IMF Working Paper*, WP/16/2.

Bandara, J.S. (2013), 'What is Driving India's Food Inflation? A Survey of Recent Evidence', *South Asia Economic Journal*, Vol. 14(1), pp. 127–156.

Banerji, A., and J.V. Meenakshi (2004), 'Buyer Collusion and Efficiency of Government Intervention in Wheat Markets in Northern India: An Asymmetric Structural Auctions Analysis', *American Journal of Agricultural Economics,* Vol. 86 (1), pp. 236–253.

Bhattacharya, R. (2016), 'How does Supply Chain Distortion Affect Food Inflation in India', *NIPFP Working Paper Series*, No. 173, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.

Bhattacharya, R., and A. Sen Gupta (2017), 'Drivers and Impact of Food Inflation in India', *MPRA Paper No. 88721.*

Chand, R. (2012), 'Development Policies and Agricultural Markets', *Economic & Political Weekly*, Vol. 47 (52), pp. 53-63.

Chand, R. (2017), 'Doubling Farmers' Income: Rationale, Strategy, Prospects and Action Plan', NITI Policy Paper No. 1, Government of India, New Delhi.

Chatterjee, S., and D. Kapur (2016), 'Understanding Price Variation in Agricultural Commodities in India: MSP, Government Procurement, and Agriculture Markets', India Policy Forum, National Council of Applied Economic Research, New Delhi.

Chengappa, P.G., A.V. Manjunatha, V. Dimble and K. Shah (2012), 'Competitive Assessment of Onion Markets in India', Report prepared for Competition Commission of India, Institute for Social and Economic Change, Bengaluru.

CRISIL (2017), 'Pulses and Rhythms - Analysing Volatility, Cyclicality and the Cobweb Phenomenon in Prices', Credit Rating Information Services of India Limited, Mumbai.

Gandhi, V.P., and N.V. Namboodiri (2002), 'Fruit and Vegetable Marketing and its Efficiency in India: A Study of Wholesale Markets in the Ahmedabad Area', Indian Institute of Management, Ahmedabad.

GoI (2011), 'Report of the Working Group on Agricultural Marketing Infrastructure, Secondary Agriculture and Policy Required for Internal and External Trade', Agriculture Division, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

GoI (2013), 'Final Report of Committee of State Ministers, In-charge of Agriculture Marketing to Promote Reforms', Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Government of India, New Delhi.

GoI (2016), 'Evaluation Study on Efficacy of Minimum Support Prices (MSP) on Farmers', NITI Aayog Report, Government of India, New Delhi.

Gokarn, S. (2011), 'The Price of Protein', *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, Vol. 4 (2), pp. 327-335.

Goyal, A. (2010), 'Information, Direct Access to Farmers, and Rural Market Performance in Central India', *American Economic Journal: Applied Economics,* Vol. 2 (3), pp. 22-45.

Gulati, A. (2009), 'Emerging Trends in Indian Agriculture: What Can We Learn from these?' *Agricultural Economics Research Review,* Vol. 22, pp. 171-184.

Gulati, A., and S. Saini (2013), 'Taming Food Inflation in India', *Discussion Paper No. 4*, Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture.

Lahiri, H., and A.N. Ghosh (2014), 'Government's Role in Controlling Food Inflation', in Ghosh, A., and A. Karmakar (eds.) *Analytical Issues in Trade, Development and Finance*, *India Studies in Business and Economics*, Springer India.

Minten, B., A. Vandeplas and J. Swinnen (2012), 'Regulations, Brokers, and Interlinkages: The Institutional Organisation of Wholesale Markets in India', *Journal of Development Studies*, Vol. 48 (7), pp. 864-886.

Negi, D.S, P.S. Birthal, D. Roy and M.T. Khan (2018), 'Farmers' Choice of Market Channels and Producer Prices in India: Role of Transportation and Communication Networks', *Food Policy*, Vol. 81, pp. 106-121.

Patel, B.B. (1971), 'Price Spread and Farmer's Share: Oil and Groundnut in Gujarat', *Economic & Political Weekly*, Vol. 6 (29), pp. 1435-1440.

Rao, P.P., P.S. Birthal and P.K. Joshi (2006), 'Diversification towards High Value Agriculture: Role of Urbanisation and Infrastructure', *Economic & Political Weekly*, Vol. 41(26), pp. 2747-2753

RBI (2019), 'Reserve Bank of India Annual Report 2018-19', Mumbai.

Sidhu, R.S., M.S. Sidhu and J.M. Singh (2011), 'Marketing Efficiency of Green Peas under Different Supply Chains in Punjab', *Agricultural Economics Research Review*, Vol. 24, pp. 267-273.

अनुबंध 1: राज्यों और केंद्रों की सूची

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	उपभोग केंद्र	उत्पादन केंद्र
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	गुंटूर, कडप्पा, कंदुकुरु, मदनपल्ली, विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी	बोको
बिहार	गया,पटना	बिहार शरीफ,पटना बाजार
गुजरात	अहमदाबाद,गांधीनगर	आनंद, बहादुरपुर, भरूच, देसा, जूनागढ़, महुवा, मेहसाणा
हिमाचलप्रदेश	-	शिमला
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	-
कर्नाटक	हुबली,बेंगलुरु	बीदर,बयादगी,चिंतामणि,चित्रदुर्ग, गदग, गुलबर्गा
केरल	कोची, तिरुवनंतपुरम	इडुक्की, कोल्लम, मल्लापुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर	छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, राजपुर
महाराष्ट्र	मुंबई, नागपुर, पुणे	जलगांव,कोल्हापुर, लासलगाँव, नेरी
नई दिल्ली	आज़ादपुर	-
उड़ीसा	भुवनेश्वर, राउरकेला	आनंदपुर, बलंगा, बारीपदा
पंजाब	अमृतसर, चंडीगढ़	जालंधर, संगरुर
राजस्थान	जयपुर,कोटा	भवानी,मेरटा
तमिलनाडू	चेन्नई,कोयम्बटूर	इरोड, तिरुचिरापल्ली, उलुंदुरपेट, वंदावसी
तेलंगना	हैदराबाद,इनुममूला	इनुममूला, करीमनगर,निजामाबाद
उत्तर प्रदेश	लखनऊ,वाराणसी	आग्रा, बांदा, ललितपुर, शजंहांपुर
पश्चिम बंगाल	असनसोल,कोलकाता	भागवांगोला, सिंगुर

टिप्पणी: हालांकि नमूने में 18 राज्य शामिल किए गए है, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में चुनिंदा मंडियों में किसानों की अनुपलब्धता के कारण, उन्हें उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी के विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया था।

अनुबंध 2: पुन:सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

चार्ट 1: उपभोक्ता मूल्य में कृषकों का औसत हिस्सा- मूल सर्वेक्षण बनाम पुनः सर्वेक्षण

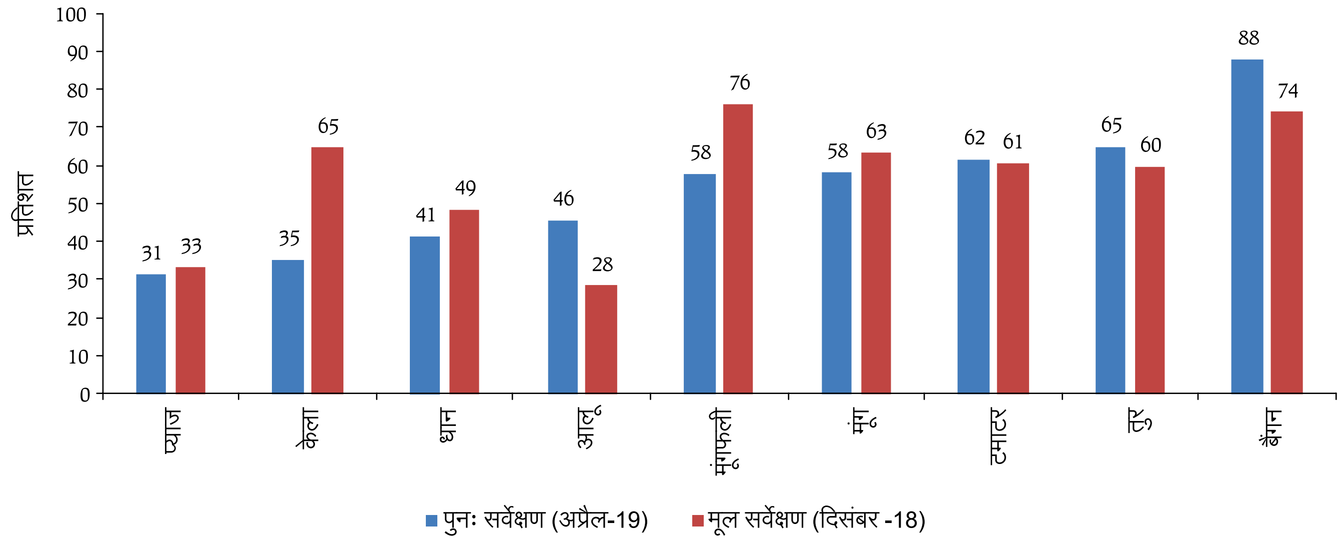

सारणी ए -1: मार्क-अप को प्रभावित करने वाले कारक

किसान	व्यापारी	खुदरा व्यापारी
मंडी प्रभार : रु 3.7/ कि.लो. कमीशन: रु.0.4/ कि.लो.	सदस्यता शुल्क: रु.1692/ वार्षिक दुकान का किराया :रु.8628/माह उपकर /कर : रु. 0.1/ कि.लो.	दुकान का किराया: रु.3791/माह स्थानीय कर रु. 0.5/ कि.लो.
लदाई /उतराई प्रभार: रु. 0.6/ कि.लो.	श्रमिक प्रभार : रु. 0.6/ कि.लो.	श्रमिक प्रभार : रु. 0.4/ कि.लो.
पैकिंग: रु.0.3/ कि.लो. भारांक: रु.0.2/ कि.लो. परखना : रु.0.1/ कि.लो.	परिवहन लागत :रु. 1.1/ कि.लो. भंडार लागत :रु. 0.1/ कि.लो.	परिवहन लागत :रु. 0.6/ कि.लो.

टिप्पणी: समाविष्ट की गई वस्तुओं और बाजारों के लिए नमूना औसत हैं।

चार्ट ए2: भुगतान के प्रकार

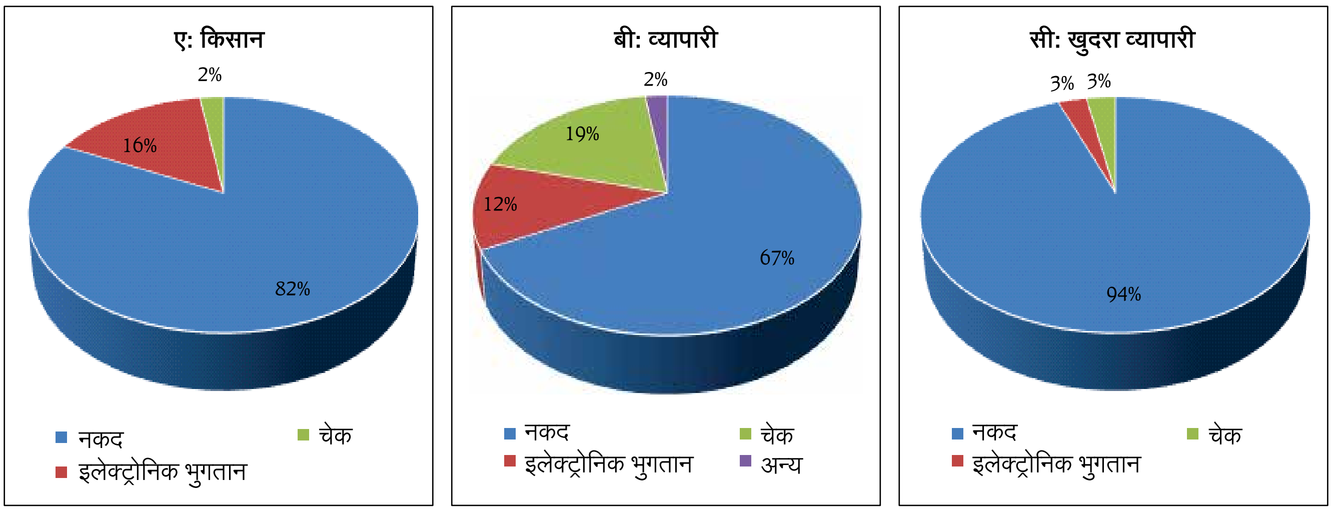

टिप्पणी : समाविष्ट की गई वस्तुओं और बाजारों के लिए नमूना औसत हैं।

*पूर्वी भारत में सुदूर तक ऋण पहुंचाने के वाहक**

यह लेख बताता है कि भारत का पूर्वी क्षेत्र संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में बैंक ऋण की संभावनाओं का दोहन करने में अन्य क्षेत्रों से पीछे है, भले ही इस क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सुदूर तक ऋण पहुंचाने को मजबूत करने के लिए ऋण की पहुंच बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष बताते हैं कि ऋण की मांग को प्रभावित करने वाले कारक - प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक गतिविधि का स्तर और सड़क नेटवर्क और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता - भी मायने रखती हैं।

परिचय

वित्तीय सेवाओं, विशेष रूप से ऋण तक पहुंच, आर्थिक समृद्धि की सुस्थापित सूचक है। हालांकि, भारत में उप-राष्ट्रीय स्तर पर, सुदूर तक ऋण पहुंचाने के संदर्भ में बैंकिंग आउटरीच काफी विषम है। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ऋण की अपेक्षाकृत गहरी पैठ देखी गई है, जिनमें क्रमशः जमा राशि में ऋण (सीडी) का अनुपात 93.2 प्रतिशत और 90 प्रतिशत है, जो कि मार्च 2018 की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिकीकरण के अपेक्षाकृत बेहतर स्तरों के साथ मेल खाता है। पूर्वी क्षेत्र (ईए)[1], विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, (क्रमशः 44.1 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के सीडी अनुपात के साथ) स्पष्ट रूप से पिछड़ जाता है, जो अपनी कम प्रति व्यक्ति आय और कमजोर औद्योगिक आधार के मुताबिक है।

ईए, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के संकीर्ण वित्तीय समावेशन ने लंबे समय से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित विभिन्न समितियों का ध्यान आकर्षित किया है [जैसे एनईआर के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना (2006); वित्तीय समावेशन संबंधी समिति (2008); छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा संबंधी समिति (2014); और वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (2015)]। शाखाओं की सुदूर पहुंच में सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति में ढील दी, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए, और घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएँ खोलने की अनुमति दी और इसके लिए प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है[2]। हालांकि इस नीतिगत कोशिश ने जमा सेवाओं, ऋण मध्यस्थता के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार लाया है, जो वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इस क्षेत्र में अपर्याप्त है।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख ईए में बैंकिंग आउटरीच को प्रभावित करने वाले कारकों को अनुभव के आधार पर परखने का प्रयास करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि ईए में अपेक्षाकृत ऋण की कमजोर पैठ उसकी प्रति व्यक्ति आय के स्तर, औद्योगिक गतिविधि के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के साथ मेल खाता है। अनुभवजन्य अनुमान से पता चलता है कि इन कारकों ने इस क्षेत्र में ऋण को सुदूर तक पहुंचाने में अड़चनें पैदा की हैं। यह आलेख सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समृद्ध डेटाबेस का उपयोग करता है। [3] खंड II में बताया गया है कि किस तरह क्षेत्र के बैंकिंग आउटरीच पैरामीटर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना करते हैं। खंड III अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए उपयोग किए गए डेटा का वर्णन करता है, जबकि खंड IV अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। खंड V में निष्कर्ष दिया गया है।

II. पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग आउटरीच

ईए में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और उपयोग देश की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र में उसके हिस्से के सापेक्ष अनुपातहीन दिखाई

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, कोलकाता के राज राजेश और अन्वेशा दास द्वारा तैयार किया गया है। श्री एस.सी.मुर्मू, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, कोलकाता ने जो हौसला दिया, प्रेरणा दी और बहुमूल्य सुझाव दिए उसके लिए लेखक उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आंकड़े संबंधी सहयोग के लिए सुभजित चौधरी एवं अनिन्दिता बौरी के प्रति आभार प्रकट किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार न होकर लेखकों के अपने विचार हैं।

[1] पूर्वी क्षेत्र (ईए) में 12 राज्य एवं एक संघ शासित प्रदेश आते हैं, जिन्हें दो क्षेत्रों, जैसे, पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं) तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम शामिल हैं) में विभाजित किए गए हैं।

[2] https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=5398&Mode=0

[3] कुमार (2013) ने अपने विश्लेषण में 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के डेटाबेस का उपयोग किया गया है ।

चार्ट 1: क्षेत्र-वार प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या

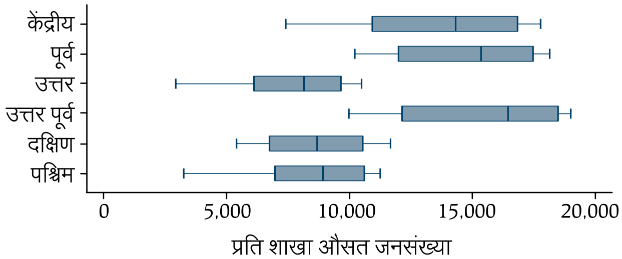

टिप्पणी : 1. विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है : केंद्रीय – छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड; पूर्व – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, एवं पश्चिम बंगाल; उत्तर पूर्व (एन.ई.) – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तथा त्रिपुरा; उत्तर – चंड़ीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, एवं राजस्थान; दक्षिण – आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी, और तमिलनाडु; एवं पश्चिम – गोवा, गुजरात, तथा महाराष्ट्र।
2. बॉक्स को विभाजित करने वाली ऊर्ध्व रेखा क्षेत्र के चर वितरण के मध्य का प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण वितरण में मूल्यों की श्रेणी को बाएं अंतिम बिंदु से दाएं टर्मिनल बिंदु तक दर्शाया गया है। बॉक्स के आयाम यह दर्शाते है कि माध्यिका के दोनों ओर किस प्रकार मूल्यों का प्रसार हुआ है।
स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियां, आरबीआई: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) एवं लेखकों की गणना।

देते हैं।[4] ईए में प्रति बैंक शाखा सेवा प्राप्त औसत जनसंख्या अधिक रहती है (चार्ट 1)।

2010 और 2017 के बीच, देश में ऋण और जमा खातों की कुल संख्या में ईए की हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है (चार्ट 2ए और 2बी)। वर्ष 2005 से प्रति 1,000 जनसंख्या पर जमा और ऋण खातों की संख्या के वितरण का विश्लेषण भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस अवधि के दौरान जमा और ऋण सेवाओं के उपयोग में अनंत विस्तार हुआ है। हालांकि, विश्लेषण से सुदूर तक बैंकिंग को पहुंचाने में क्षेत्रीय असमानता का पता चलता है। पूर्व और उत्तर-पूर्व क्षेत्र वित्तीय सेवाओं के औसत उपयोग (चार्ट 3ए और 3बी) के संदर्भ में दक्षिण, पश्चिम और उत्तर क्षेत्रों से पीछे हैं। इसकी विकासात्मक चुनौतियों को देखते हुए, देश में वित्तीय समावेशन के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि ईए पर समुचित ध्यान न दिया जाए।[6]

ईए की बैंकिंग गतिविधि में जमाराशि को जुटाने में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो ऋण संवितरण से कहीं ज्यादा है। जहां बकाया बैंक जमाराशियों में ईए का हिस्सा 15.1 प्रतिशत था, वहीं बैंक ऋण मार्च 2018 की समाप्ति पर कम था, अर्थात 8.1 प्रतिशत। तदनुसार, पूर्वी क्षेत्र में ऋण-मध्यस्थता (ऋण-जमा अनुपात) काफी कम रहा (चार्ट 4)। कृषि केंद्रित भू-भाग होने के

चार्ट 2: कुल जमा और ऋण खातों की संख्या में हिस्सेदारी (प्रतिशत)

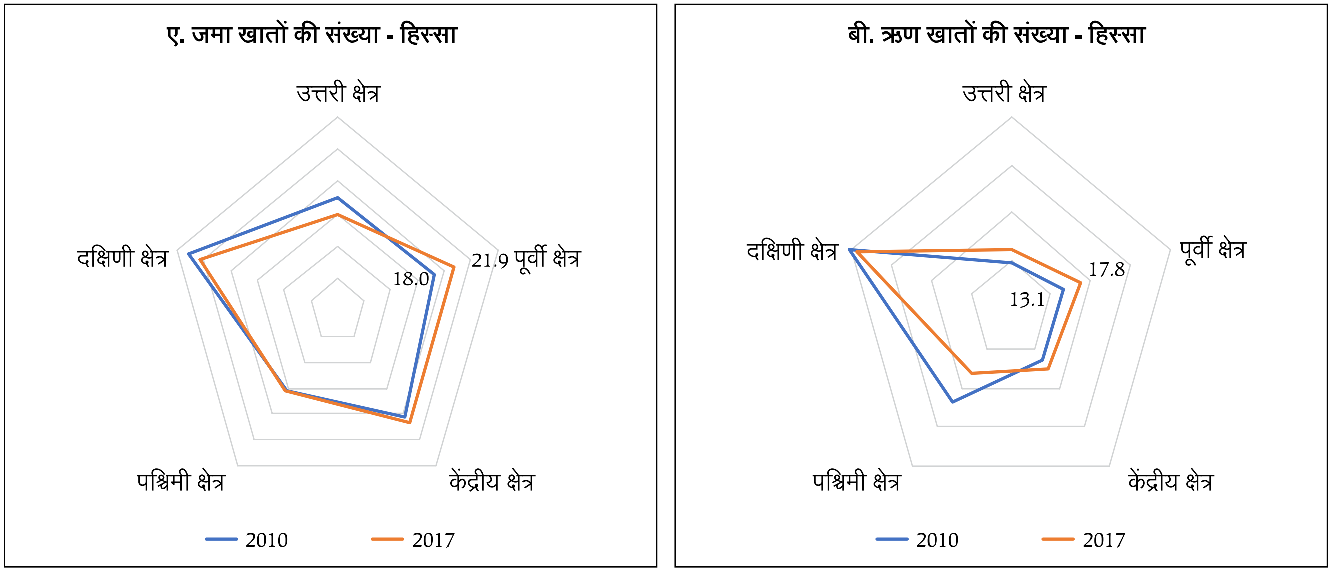

स्रोत : आरबीआई।

[4] पूर्वी क्षेत्र में क्रमशः देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हिस्सा है।
[5] आमतौर पर, जमा और ऋण खातों में बढ़ौती के रुझान देखने को मिलता है; इसलिए, चित्र में बॉक्स के विस्तार (बाएं छोर से दाएं) को विश्लेषण की अवधि के दौरान उनके अस्थायी संचलन का पर्याय माना जा सकता है।
[6] वित्तीय समावेशन में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित विभिन्न समितियों [जीओई (2008) और आरबीआई (2015)] ने देश के पूर्वी हिस्से में वित्तीय बहिष्कार की समस्या को उजागर किया है।

चार्ट 3: प्रति 1000 जनसंख्या पर जमा और ऋण खातों का क्षेत्रीय संवितरण (संख्या)

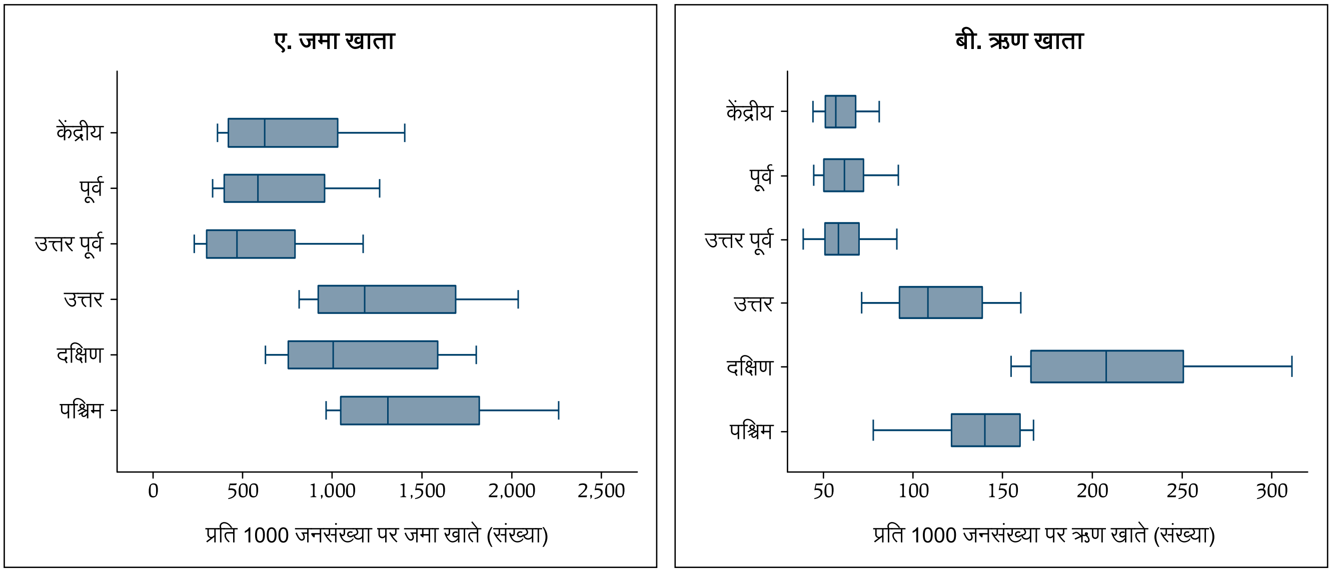

स्रोत : आरबीआई और एनएसओ।

बावजूद, न केवल इस क्षेत्र में कृषि ऋण संवितरण की हिस्सेदारी सबसे कम है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में एससीबी द्वारा कृषि ऋण देने की गति में भी कमी आई है।

वित्तीय विकास पर अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि जहां आपूर्ति-उन्मुख वित्तीय समावेशन नीतियां (जैसे सुदूर तक शाखा उपलब्ध कराना) वित्तीय सेवाओं (बर्गेस और पांडे, 2005) के वितरण को बढ़ावा देने में मदद करती हैं, वहीं मांग की गतिशीलता, बदले में, आर्थिक संवृद्धि (ज़ेंग और किम, 2007) से प्रभावित होती है। आर्थिक समृद्धि, विशेष रूप से औद्योगिक विकास, क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं (बेक, एवं अन्य, 2008; राजन और ज़िंगेल्स, 1998) के उपयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए, ईए के सभी राज्य, सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर, राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से नीचे हैं (चार्ट 5)। औद्योगिक विकास के

चार्ट 4: क्षेत्र-वार सीडी अनुपात (मार्च की समाप्ति पर) (प्रतिशत)*

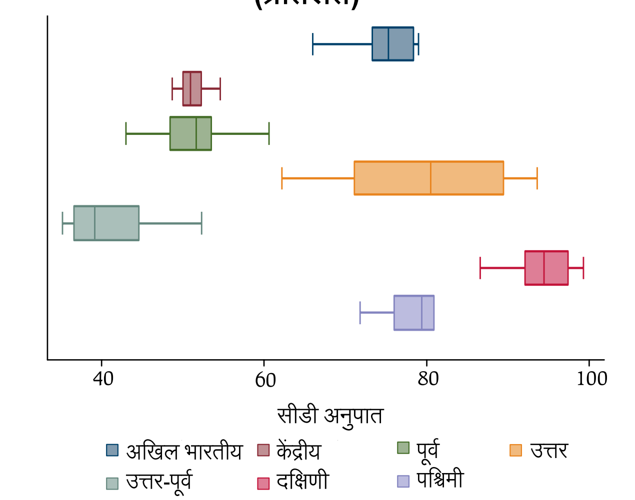

*: उपयोगिता के आधार पर।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 5: पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (2016-17)#

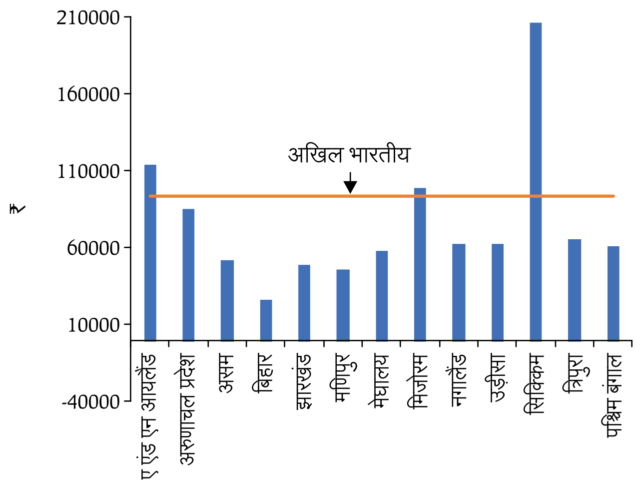

#: वर्ष 2017-18 हेतु असम, नगालैंड और ए एंड एन आयलैंड के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे एवं इसलिए, चार्ट में दिए गए आंकड़े वर्ष 2016-17 के हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट 6: प्रति 1000 जनसंख्या पर कारखानों की औसत संख्या@

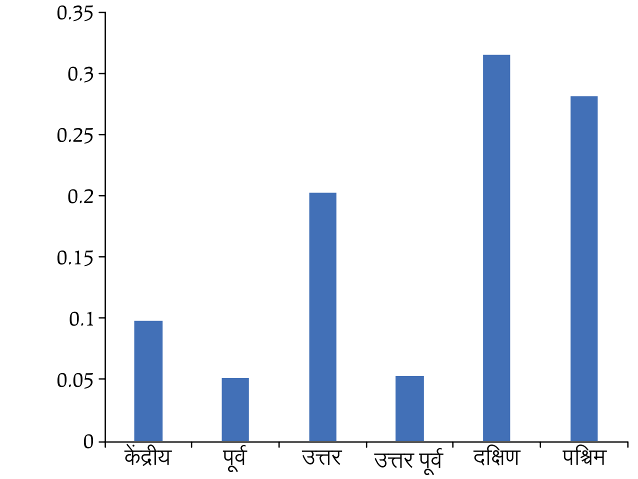

@: वर्ष 2005 से 2017 के औसत।
स्रोत : एनएसओ।

चार्ट 8: विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोवाट-घंटा)

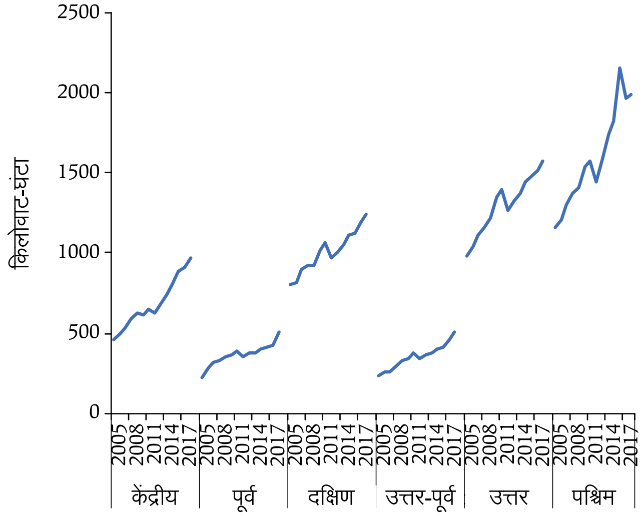

स्रोत : आरबीआई एवं केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए)।

संदर्भ में, पूर्वी क्षेत्र की प्रति 1,000 जनसंख्या पर कारखानों की संख्या के आंकड़ों का कम होना उस अंतर पर प्रकाश डालते हैं जिससे उन क्षेत्रों की बराबरी की जा सके जो एकदम आगे है (चार्ट 6)।

ईए का बैंकिंग आउटरीच सड़कों और बिजली जैसी भौतिक ढांचागत सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी कम हो सकता है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं और जिससे बैंकिंग सेवाओं की मांग में सुधार होता है। हालांकि सड़क नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, स्थिति संतोषजनक से कम है (चार्ट 7 और 8)

चार्ट 7: सड़क नेटवर्क में वृद्धि

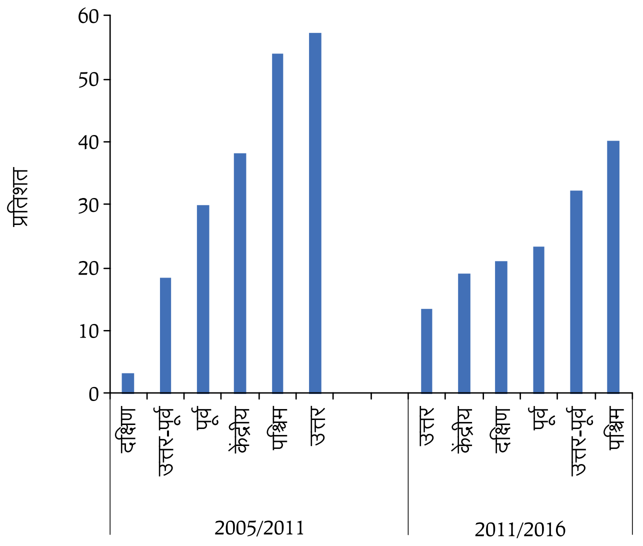

स्रोत : आरबीआई एवं एनएसओ।

III. डेटा विवरण

सुदूर तक बैंकिंग को पहुंचाने का मतलब मात्र यह नहीं है कि अधिक संख्या में बैंक शाखाएं उपलब्ध कराना, उसकी सेवाओं का उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाद वाला, जो अंततः संवृद्धि और विकास के संदर्भ में वांछित परिणाम देता है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से तात्पर्य सिर्फ उपलब्धता पहलू से है, जिसका आकलन एक संकेतक के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि प्रति हजार जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या। इसके विपरीत, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, प्रति 1000 जनसंख्या पर जमा और ऋण खातों की संख्या के माध्यम से देखा जा सकता है। इस आलेख में विश्लेषण के लिए, बैंकिंग सेवाओं के आकलन और उपयोग दोनों संकेतकों के डेटा का उपयोग किया गया है।

32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए एक समृद्ध उप-राष्ट्रीय वार्षिक डेटाबेस [लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव को छोड़कर] विभिन्न संकेतकों के लिए उपयोग किया गया है (सारणी 1)। चरों को समुचित रूप से सामान्य किया गया है। प्रति व्यक्ति आय राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के आर्थिक विकास के स्तर को प्रस्तुत करती है। यह उम्मीद

सारणी 1: चरों का विवरण

नोटेशन	चर	स्रोत
सीडीयू	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	आरबीआई
सीआरएसी	प्रति हजार जनसंख्या ऋण खातों की संख्या	आरबीआई एवं एनएसओ
डीपीएसी	प्रति हजार जनसंख्या जमा खातों की संख्या	आरबीआई एवं एनएसओ
एपीपीबी	प्रति शाखा औसत जनसंख्या	आरबीआई एवं एनएसओ
पीओडब्ल्यूईआर	प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता (किलोवाट-घंटा)	आरबीआई एवं सीईए
आरओएडी	सड़क की गहनता (प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर सड़क की लंबाई)	आरबीआई एवं एनएसओ
एलओजीपीसीआई	प्रति व्यक्ति आय का लॉगरिथम	आरबीआई
एफएसी	प्रति '000 जनसंख्या पर कारखानों की संख्या	एनएसओ
आईएनवीसीएपी	प्रति '000 जनसंख्या पर कारखानों में निवेश की गई पूंजी (रुपया)	एनएसओ
एजीसीआर	प्रति व्यक्ति कृषि ऋण (रुपया)	आरबीआई एवं एनएसओ

की जाती है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय बढ़ी बैंकिंग गतिविधि से सरोकार रखती है क्योंकि लोग वित्तीय लेनदेनों का तेजी से सहारा लेते हैं। प्रति बैंक शाखा (एपीपीबी) की औसत जनसंख्या संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में कुल शाखाओं की जनसंख्या का अनुपात है। उच्च एपीपीबी का मतलब है कि बैंक शाखाओं पर अधिक जनसंख्या का दबाव है।

प्रति हजार जनसंख्या (एफएसी) पर कारखानों की संख्या को औद्योगिक गतिविधि के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में माना जाता है। औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि से बैंकिंग लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि वेतन संवितरण, घरेलू बचत और ऋण संवितरण जमा / क्रेडिट खातों के माध्यम से किए जाते हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि विद्युत तक बेहतर पहुंच होने से कोर बैंकिंग के वर्तमान युग में न केवल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि यह औद्योगिकीकरण, आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी और जिससे वित्तीय सेवाओं की अधिक मांग पैदा होगी। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि भारत के प्रमुख राज्यों (घोष, 2015) में बैंकिंग आउटरीच को प्रभावित करने में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सड़क नेटवर्क जितना गहन होगा उतना ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और इस तरह आर्थिक गतिविधि, व्यक्तिगत आय स्तर और बैंकिंग गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। यह उम्मीद की जाती है कि कृषि ऋण में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और इंटर-लिंकेज के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में मांग को गति मिलती है और इस तरह बैंकिंग सेवाओं की मांग में सुदृढ़ता आती है।

IV. अनुभवजन्य निष्कर्ष

अनुमान में उपयोग किए गए चर के सारांश सांख्यिकी से पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का अखिल भारतीय आंकड़ों के समान सभी मापदंडों पर प्रदर्शन खराब रहा है (सारणी 2)। सीडी अनुपात बहुत कम रहता है। प्रति 1,000 आबादी पर क्रेडिट खातों और जमा खातों की संख्या विश्लेषण की अवधि के दौरान अखिल भारतीय औसत का लगभग 60 प्रतिशत है। नीति के दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से कारक ईए में बैंकिंग आउटरीच को प्रभावित करते हैं ताकि उचित नीतिगत हस्तक्षेप किया जा सके।

सारणी 2: चर की सारांश सांख्यिकी (2005 से 2018)

चर	क्षेत्र	औसत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम	निरीक्षण की संख्या
सीडीयू	संपूर्ण भारत	58.8	25.0	23.2	133.7	448
सीडीयू	पूर्वी क्षेत्र	42.2	13.3	23.2	113.9	182
सीडीयू	उत्तर-पूर्व	39.9	12.6	23.2	113.9	112
एपीपीबी	संपूर्ण भारत	11608.5	6259.6	0.0	34879.3	448
एपीपीबी	पूर्वी क्षेत्र	14759.8	6908.1	0.0	34879.3	182
एपीपीबी	उत्तर-पूर्व	14695.3	7904.8	0.0	34879.3	112
सीआरएसी	संपूर्ण भारत	104.7	74.5	20.3	522.0	432
सीआरएसी	पूर्वी क्षेत्र	62.0	25.3	20.3	205.3	174
सीआरएसी	उत्तर-पूर्व	60.5	27.2	20.3	205.3	105
डीपीएसी	संपूर्ण भारत	900.5	641.5	0.6	3805.8	432
डीपीएसी	पूर्वी क्षेत्र	541.9	342.8	0.6	1538.2	174
डीपीएसी	उत्तर-पूर्व	521.4	309.9	115.7	1538.2	105
बिजली	संपूर्ण भारत	825.0	578.8	78.0	3511.6	446
बिजली	पूर्वी क्षेत्र	358.3	172.3	78.0	798.1	180
बिजली	उत्तर-पूर्व	354.2	165.2	134.4	798.1	111
सड़क	संपूर्ण भारत	2.7	4.7	0.1	25.7	384
सड़क	पूर्वी क्षेत्र	1.4	1.2	0.2	4.2	156
सड़क	उत्तर-पूर्व	1.4	1.2	0.2	4.2	96
पीसीआई	संपूर्ण भारत	10.6	0.5	9.0	12.2	342
पीसीआई	पूर्वी क्षेत्र	10.4	0.5	9.0	11.6	138
पीसीआई	उत्तर-पूर्व	10.4	0.4	9.9	11.5	84
एजीसीआर	संपूर्ण भारत	5124.6	6805.4	177.8	55182.6	415
एजीसीआर	पूर्वी क्षेत्र	1488.4	1027.4	177.8	6787.3	157
एजीसीआर	उत्तर-पूर्व	1239.2	787.4	177.8	4380.3	95
एफएसी	संपूर्ण भारत	0.162	0.149	0.0	0.709	421
एफएसी	पूर्वी क्षेत्र	0.054	0.037	0.0	0.146	164
एफएसी	उत्तर-पूर्व	0.056	0.043	0.0	0.146	95
आईएनवीसीएपी	संपूर्ण भारत	19988.9	24503.0	0.0	134302.9	432
आईएनवीसीएपी	पूर्वी क्षेत्र	8763.6	17196.0	0.0	134302.9	172
आईएनवीसीएपी	उत्तर-पूर्व	6043.8	16358.4	0.0	134302.9	105

वर्ष 2005 से 2018 के लिए वार्षिक डेटा का उपयोग करते हुए, एक पैनल डेटा प्रतिगमन को अनुभवजन्य रूप से जांच करने के लिए नियोजित किया गया था, जो ब्याज के तीन चर के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये तीन चर हैं - प्रति 1,000 जनसंख्या पर जमा खाता, प्रति 1,000 जनसंख्या पर ऋण खाता और सीडी अनुपात। सम्पूर्ण भारत और ईए के लिए अलग-अलग अनुमान लगाए गए थे। व्याख्यात्मक चर शामिल थे; शाखा व्यापन, बुनियादी ढांचा, आर्थिक स्थिति, औद्योगिक गतिविधि का स्तर और अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्रों द्वारा ऋण अवशोषण। परीक्षण की जाने वाली परिकल्पना का महत्व प्रासंगिक साहित्य से है - आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता से संबंधित (रोसेनस्टीन- रोडन, 1943; नर्कसे, 1955; हिर्स्चमैन, 1958; रोस्टोव; 1965): और आर्थिक विकास को वित्त से जोड़ना (रॉबिन्सन, 1952)।

यह पाया गया कि हॉसमैन परीक्षण यादृच्छिक प्रभावों मॉडल के बनिस्पत निश्चित प्रभावों का समर्थन करता है। हालांकि, स्थिर नियत प्रभाव मॉडल, कारण और प्रभाव चर के संयुक्त निर्धारण की अंतर्जात समस्या से ग्रसित हो सकता है। यह उन अनुमानों को भी पूर्वाग्रहित करता है जब आर्थिक चर की गतिशील प्रकृति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) के अनुमानक ऐसी परिस्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल हैं (एरेलानो और बॉन्ड, 1991; आरिलानो और बोवर, 1995)। सिस्टम जीएमएम दृष्टिकोण को अंतर जीएमएम पद्धति के विपरीत लेख में लागू किया गया है क्योंकि पूर्व में अधिक कुशल और स्थिर अनुमानक होने की सूचना दी गई है जब आश्रित चर की स्वसमाश्रयी प्रक्रिया अत्यधिक स्थायी है (ब्लंडेल और बॉन्ड, 1998)। दो समीकरण – सिस्टम जीएमएम में – लेवल्स में और डिफरेंसेस में, नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it-1} + \beta_2 X_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (1)$$

$$\Delta Y_{it} = \beta_1 \Delta Y_{it-1} + \beta_2 \Delta X_{it} + \Delta\varepsilon_{it} \quad (2)$$

X_{it} अवधि में i^{th} राज्य के लिए जहां Y_{it} ब्याज के आश्रित चर को दर्शाता है, वहीं X_{it} व्याख्यात्मक चरों की मैट्रिक्स है (प्रति शाखा औसत जनसंख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति आय, प्रति 1,000 जनसंख्या पर कारखानों की संख्या और निवेशित पूंजी तथा कृषि ऋण अवशोषण), α_i राज्य की विशेष प्रकृति की विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए राज्य-विशिष्ट नियत प्रभाव मानदंड है और ε_{it} स्टोकेस्टिक डिसटरबेन्स शब्द है जिसे सामान्य रूप से माध्य 0 और वेरिएन्स σ^2 के साथ वितरित किया जाता है।

सिस्टम जीएमएम अनुमान (जो कि, 'छोटे T, बड़े N' 'पैनल के लिए उपयुक्त है) को क्रमशः विखंडित समयावधि 2005-10 और 2011-18 के लिए अलग-अलग किया गया था। अप्रैल 2010 में वित्तीय समावेशन योजना की शुरूआत के साथ-साथ चाउ ब्रेक-पॉइंट[8] परीक्षण द्वारा समय की अवधि को विखंडित किया गया था, जिसने एक महत्वपूर्ण संख्या में जमा और क्रेडिट खातों के सृजन के लिए नीतिगत बल दिया था। अनुमान के परिणाम इस प्रकार हैं।

ईए के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भी, प्रति 1,000 जनसंख्या पर जमा खातों की संख्या को बढ़ाने के लिए आय स्तर और औद्योगिक गतिविधि में सुधार पाया गया (सारणी 3)। एपीपीबी को सकारात्मक रूप से 2010 तक ईए और पूरे भारत दोनों के लिए जमा खातों की संख्या से संबंधित पाया जाता है।

सारणी 3: जमा खातों के लिए डाइनेमिक पैनल अनुमान
[आश्रित चर – जमा खाते (डीपीएसी)]

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ईए (2005-10)	संपूर्ण भारत (2005-10)	ईए (2011-18)	संपूर्ण भारत (2011-18)
$DPAC_{t-1}$	1.069^{***}	0.792^{***}	1.353^{***}	0.968^{***}
	(0.025)	(0.047)	(0.068)	(0.016)
$LOGPCI_{t-1}$	56.88^{***}	374.2^{***}		
	(15.66)	(32.85)		
ΔLOGPCI			1795.3^{***}	942.1^{***}
			(204.6)	(39.33)
$APPB_{t-1}$	0.003^{*}	0.008^{*}	0.008^{**}	-0.016^{***}
	(0.001)	(0.003)	(0.0025)	(0.002)
ΔFAC	592.1^{***}	274.7^{***}	2581.1^{***}	482.5^{***}
	(99.23)	(54.37)	(649.8)	(69.55)
constant	-627.9^{***}	-3849.2^{***}	-343.7^{***}	292.9^{***}
	(176.2)	(321.2)	(71.95)	(34.95)
Observations	60	155	43	114
AR(2) (p-value)	0.07	0.53	0.66	0.89
Sargan (p-value)	0.67	0.10	0.70	0.28

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।
2. $^{+}p< 0.10$, $^{*}p< 0.05$, $^{**}p< 0.01$, $^{***}p< 0.001$.

[7] अनुरोध पर उपलब्ध परिणाम, संक्षेप में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं ।

[8] परिणाम संक्षेप में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

2010 के बाद, हालांकि, अखिल भारतीय स्तर पर यह विपरीत रूप से संबंधित पाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर, 2017 में प्रति 1,000 आबादी पर जमा खातों की औसत संख्या 8,492 थी, जबकि पूर्वी क्षेत्र के लिए यह 2,418 थी। प्रौद्योगिकी व्यापन के पीछे बैंकों द्वारा शाखा युक्तिकरण की दिशा में हाल की पहल इस निष्कर्ष में वजन डाल देता है। पूर्वी क्षेत्र के लिए, इसके विपरीत, अल्पावधि में जमा खातों की संख्या पर एपीपीबी का सकारात्मक प्रभाव इस क्षेत्र में शाखा विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में सुझाव देता है।

जबकि वर्ष 2005-10 के दौरान पाया गया कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर प्रत्यक्ष रूप से जमा खातों की संख्या बढ़ गयी थी, आय में वृद्धि हाल के दिनों में इसका विस्तार करने के लिए मिली थी। संभवतः, वर्ष 2010-11 से बैंक जमाराशि आर्थिक गतिविधियों से अधिक निकटता से जुड़ी हैं (सक्सेना और श्रीजीत, 2018)। ऐसा पाया गया है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पूर्व के प्रति व्यक्ति आय स्तर को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर से ईए में प्रति 1,000 आबादी पर 1,000 प्रति व्यक्ति अधिक जमा खातों में रूपांतरित होता है। कारखानों की संख्या में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप उच्च आय सृजन क्षमता के कारण पूरे भारत में (अपेक्षाकृत कमोबेश) ईए की तुलना में अधिक जमा व्यापन होता है। उपरोक्त निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यदि औद्योगिक गतिविधि के रूप में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं तो वित्तीय समावेशन के प्रयास ईए के लिए लाभप्रद होंगे।

यह भी पाया गया है कि ईए में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ऋण खातों की संख्या को भी घनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र की कम ऋण अवशोषण क्षमता को दर्शाते हुए - इसके कृषि अभिविन्यास और कम औद्योगिक आधार को देखते हुए - ऋण खातों पर बढ़ती आय का प्रभाव वर्ष 2005-10 के दौरान सम्पूर्ण भारत के अनुमानों की तुलना में काफी कम पाया गया (सारणी 4)[9]। वर्ष 2011-18 के दौरान, आय में वृद्धि के कारण सम्पूर्ण भारत की तुलना में ईए में ऋण खातों की उच्च मांग का प्रसार हुआ।

[9]उद्योगों के स्थान के मामले में, सभी क्षेत्रों में देखें तो पूर्वी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर (2016-17 में) कारखानों की कुल संख्या का 10.4 प्रतिशत है जो सबसे कम हिस्सेदारी है।

सारणी 4: ऋण खातों के लिए डाइनेमिक पैनल अनुमान

[आश्रित चर – ऋण खाते (सीआरएसी)]

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ईए (2005-10)	संपूर्ण भारत (2005-10)	ईए (2011-18)	संपूर्ण भारत (2011-18)
$CRAC_{t-1}$	0.451^{***}	0.343^{***}	0.436^{***}	0.708^{***}
	(0.089)	(0.0162)	(0.108)	(0.0237)
$LOGPCI_{t-1}$	9.214^{+}	71.97^{***}	52.06^{**}	41.34^{***}
	(4.894)	(4.649)	(17.89)	(4.099)
$INVCAP_{t-1}$	0.00012	-0.00031^{***}	0.00076^{***}	-0.00047^{***}
	(0.0002)	(0.00005)	(0.0002)	(0.00004)
ΔAGCR	0.006^{***}		0.006^{***}	
	(0.0005)		(0.0008)	
$POWER_{t-1}$		0.018^{***}		0.0112^{***}
		(0.003)		(0.003)
constant	-65.73	-701.5^{***}	-514.3^{**}	-404.7^{***}
	(48.63)	(45.31)	(181.3)	(41.35)
Observations	54	158	55	150
AR(2) (p-value)	0.06	0.15	0.82	0.35
Sargan (p-value)	0.99	0.22	0.73	0.29

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।
2. $^{+}p< 0.10$, $^{*}p< 0.05$, $^{**}p< 0.01$, $^{***}p< 0.001$.

यह पाया गया है कि ईए में ऋण खातों की संख्या में वृद्धि से ऋण जमा-अनुपात को उल्लेखनीय रूप से और सम्पूर्ण भारत की तुलना में बड़े पैमाने पर बल मिला है (सारणी 5)। ईए में वर्ष

सारणी 5: सीडी अनुपात के लिए डाइनेमिक पैनल अनुमान

[आश्रित चर – सीडी अनुपात (सीडीयू)]

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ईए (2005-10)	संपूर्ण भारत (2005-10)	ईए (2011-18)	संपूर्ण भारत (2011-18)
CDU_{t-1}	0.789^{***}	0.262^{***}	-0.129^{***}	0.421^{***}
	(0.096)	(0.067)	(0.035)	(0.007)
$DPAC_{t-1}$	-0.064^{***}	-0.018^{*}	-0.017^{***}	-0.004^{***}
	(0.013)	(0.008)	(0.003)	(0.0004)
$POWER_{t-1}$	0.051^{*}	0.010^{*}	0.0429^{***}	0.003^{***}
	(0.021)	(0.005)	(0.009)	(0.0005)
ΔCRAC	1.847^{***}	0.174^{***}	0.136^{**}	0.033^{***}
	(0.554)	(0.0488)	(0.0418)	(0.003)
$ROAD_{t-1}$		2.301^{**}	4.295^{**}	1.642^{***}
		(0.722)	(1.509)	(0.055)
constant	12.71^{+}	38.89^{***}	31.98^{***}	30.24^{***}
	(7.257)	(3.123)	(4.329)	(1.179)
Observations	63	158	77	191
AR(2) (p-value)	0.47	0.65	0.27	0.28
Sargan (p-value)	0.69	0.18	0.91	0.51

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।
2. $^{+}p< 0.10$, $^{*}p< 0.05$, $^{**}p< 0.01$, $^{***}p< 0.001$.

चार्ट 9: पूर्वी क्षेत्र में सड़क घनत्व और बिजली के लिए स्कैटर प्लॉट

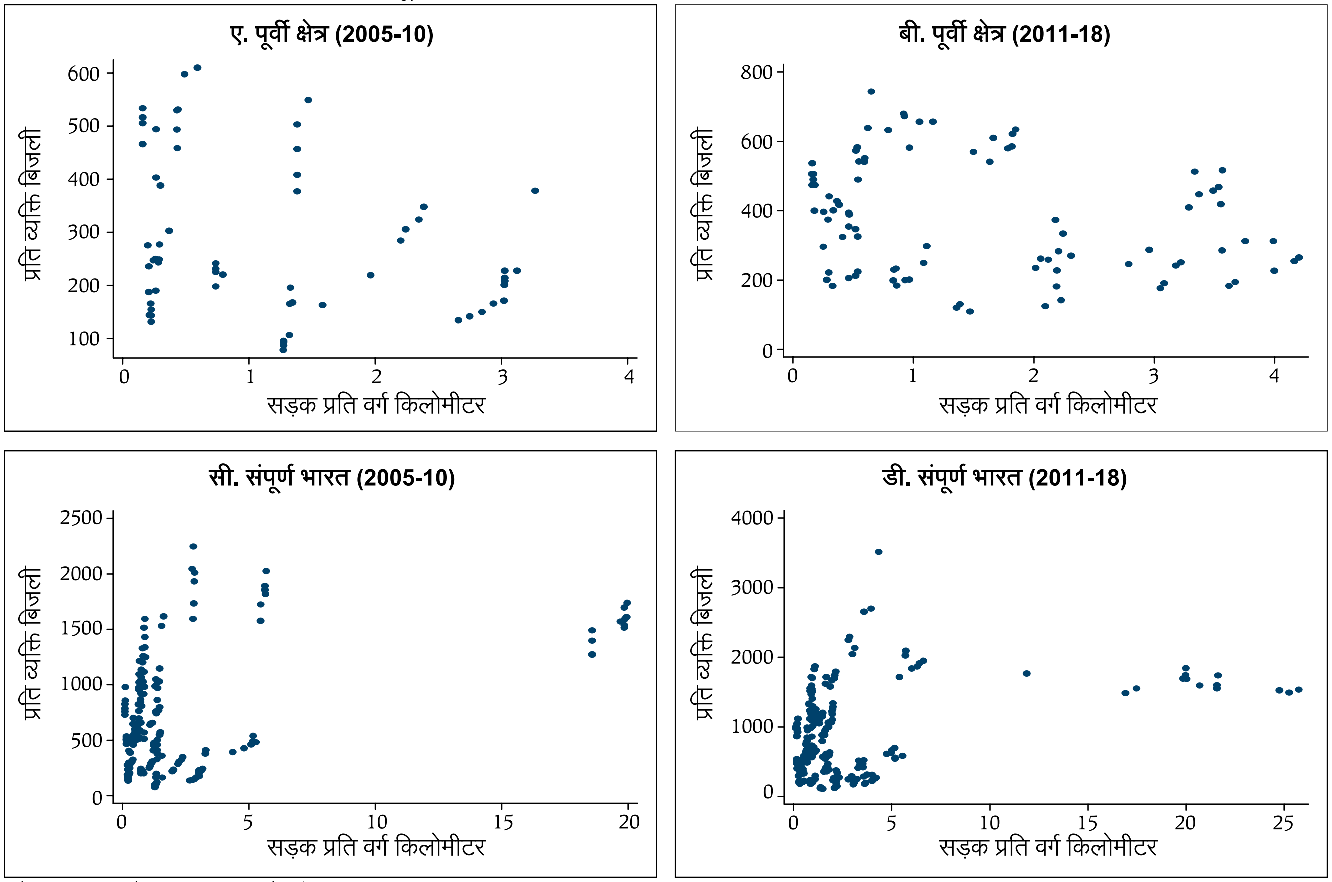

स्रोत : एनएसओ, आरबीआई और लेखक की गणना।

2005-10 के दौरान सीडी अनुपात की उच्च संवेदनशीलता इस अवधि के दौरान दर्ज की गई उच्च ऋण वृद्धि को दर्शा सकती है। हालांकि, ईए में वर्ष 2011-18 के दौरान प्रति 1,000 आबादी पर ऋण खातों की संख्या के तुलना में सीडी अनुपात की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। सीआरआईएसआईएल के अनुसार (2018), भारत में प्रति 1,000 आबादी पर ऋण खातों की औसत संख्या 2011-18 के दौरान तेजी से बढ़ी, क्योंकि जन धन योजना (जेडीवाई) के बाद पूर्वी क्षेत्र में ऋण खातों का प्रसार हुआ। यह ऋण की वास्तविक मांग की तुलना में पहुंच के प्रयास को दर्शाता है। अखिल भारतीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति बिजली की अधिक उपलब्धता और अधिक सड़क घनत्व के कारण जमा की प्रति यूनिट के हिसाब से उपयोग किए गए ऋण की मात्रा पर अच्छा-खासा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईए में, वर्ष 2005-10 के दौरान बिजली और सड़कों की प्रगति साथ-साथ नहीं हुई (चार्ट 9 ए)। फिर भी, जब 2011-18 के दौरान बिजली और सड़क दोनों में सुधार हुआ, तो ईए में सीडी अनुपात पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा (चार्ट 9 बी)। संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास में पूरकता की कमी उनके व्यक्तिगत कार्यसाधकता में बाधा उत्पन्न कर सकती है (मार्कर्ड और हॉफमैन, 2016; ओईसीडी, 2007)।

V. निष्कर्ष

देश के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की सीमित पहुँच को देखते हुए, वित्तीय क्षेत्र के लिए विकास और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए एक अहम गुंजाइश अभी भी है। आय स्तर में वृद्धि, एक मजबूत औद्योगिक आधार और बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाओं (जैसे कि बिजली की उपलब्धता और सड़क का नेटवर्क) के कारण अधिक से अधिक ऋण व्यापन में सहूलियत मिलेगी। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में पूरक को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे ऋण की मांग बढ़ती है।

हालांकि, जहां हाल ही में जेडीवाई जैसी वित्तीय समावेशन की पहल ने पूरे देश में परिवारों को नो फ्रिल्स अकाउंट्स / 'मूलभूत बचत बैंक जमा खाता' उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल की है, वहीं प्रति 1,000 आबादी पर केवल जमा खातों में बढ़ोतरी आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन के संभावित योगदान को भुनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुमान परिणाम से पता चलता है कि ऐसे बैंक खातों को ऋण के साथ जोड़ना समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो सीडी अनुपात को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। भूभाग में विशिष्ट विविधता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, कृषि-जलवायु क्षेत्रों, मानव संसाधनों की उपलब्धता और अवसंरचनात्मक स्थिति को देखते हुए, वित्तीय प्रसार संबंधी किए जाने वाले प्रयासों के सफल होने के लिए पूर्वी क्षेत्र के हरेक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयोजन-विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है।

संदर्भ

Arellano, M. and O. Bover (1995), 'Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models', *Journal of Econometrics*, 68: 29-51.

Arellano, M. and S. Bond (1991), 'Some tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations', *Review of Economic Studies*, 58: 277-297.

Beck, Thorsten, Erik Feyen, Alain Ize, and Florencia Moizeszowicz (2008), 'Benchmarking Financial Development', *World Bank Policy Research Working Paper*, WPS4638.

Blundell, R. and S. Bond (1998), 'Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models', *Journal of Econometrics*, 87:11-143.

Burgess, Robin and Rohini Pande (2005), 'Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment', *American Economic Review*, 95(3), 780-795.

CRISIL (2018), 'Financial inclusion surges, driven by Jan-Dhan Yojana', Vol. 4, February. Available [Online] *https://www.crisil.com/en/home/our-analysis/reports/2018/02/crisil-inclusix-financial-inclusion-surges-driven-by-Jan-Dhan-yojana.html* (Accessed on June 21, 2019)

Ghosh, Saibal (2012), 'Determinants of banking outreach: An empirical assessment of Indian states', Journal of Developing Areas, 46(2): 269-295. Available [Online] *https://mpra.ub.uni-muenchen.de/38650* (Accessed on June 20, 2019)

Government of India (2008), 'Report of the Committee on Financial Inclusion in India'.

Hirschman, A.O. (1958), '*The Strategy of Economic Development*', New havens: Yale University Press.

Kumar, Nitin (2013), 'Financial inclusion and its determinants: evidence from India', *Journal of Financial Economic Policy*, 5(1): 4-19. Available [Online] *https://doi.org/10.1108/17576381311317754* (Accessed on April 05, 2019)

Markard, Jochen and Hoffmann, Volker H. (2016), 'Analysis of complementarities: Framework and examples from the energy transition', *Technological Forecasting and Social Change, Elsevier*, Vol. 111(C), pp. 63-75.

Nurkse, R. (1955), *'Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries'*, Basil Blackwell: Oxford.

OECD (2007), 'Infrastructure to 2030', Volume 2, Mapping Policy for Electricity, Water and Transport, June.

Rajan, R. G. and Zingales, L. (1998), 'Financial dependence and growth', *American Economic Review*, 88, 559–86.

Reserve Bank of India (2015), 'Report of the Committee on Medium-term Path on Financial Inclusion', December.

Robinson, J. (1952), '*The Generalization of The General Theory, in The Rate of Interest and Other Essays'*, MacMillan, London.

Rosenstein-Rodan, P. (1943), 'Problems of Industrialization of Eastern and South-eastern Europe', *Economic Journal*, 53: 202–211.

Rostow, W.W. (1965), '*The Economics of Take-Off into Self – Sustained Growth*', New York: St. Martin's Press.

Saxena, T. K. and Thoppil Bhargavan Sreejith (2018), 'Post-Demonetisation Patterns of Deposits with Scheduled Commercial Banks: 2016-17 and 2017-18', RBI Bulletin, December.

Zang, H. and Kim, Y. C. (2007), 'Does Financial Development Precede Growth? Robinson and Lucas Might Be Right', *Applied Economics Letters*, 14:15-19.

वर्किंग पेपर की प्रेस प्रकाशनी

भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान: क्या मशीन लर्निंग के पास बेहतर पूर्वानुमान की कुंजी है?

भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान: क्या मशीन लर्निंग के पास बेहतर पूर्वानुमान की कुंजी है?

यह पेपर मशीनी अध्ययन (एमएल) के प्रतिमान की समीक्षा करता है और इसे भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए लागू किया जाता है। इस अध्ययन में विभिन्न मशीन लर्निंग कलन विधि (अल्गोरिद्म) को केंद्र में रखा गया है और हेडलाइन, भोजन, ईंधन मुद्रास्फीति की स्थिति और प्रमुख उपायों के पूर्वानुमान में मानक सांख्यिकीय मॉडल के परिप्रेक्ष में उनका परीक्षण किया गया है। पेपर के मुख्य निष्कर्ष से पता चलता है कि आम तौर पर एमएल कार्यप्रणालियाँ मानक सांख्यिकीय मॉडल से बेहतर हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि साधारण औसत-आधारित पूर्वानुमान संयोजन आमतौर पर सभी व्यक्तिगत मॉडलों से बेहतर होते हैं। सरल भार योजना भी जटिल भार विधि को बेहतर बनाती है। इष्टतम संयोजन पद्धति पर बहस के बावजूद, ये परिणाम बताते हैं कि बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमान संयोजन एक अच्छा अभ्यास है। यह पेपर अपने हेडलाइन मुद्रास्फीति के सीधे पूर्वानुमानों की तुलना अलग से पूर्वानुमानित इसके घटकों से करता है, और हेडलाइन मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए उनका संयोजन करता है। इस दूसरे दृष्टिकोण का उपयोग करके सटीकता का पूर्वानुमान लगाने में कोई सार्थक लाभ नहीं हो पाता है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मशीन लर्निंग का क्षेत्र नए आकड़ों को शामिल करने के लिए साधन और कार्यप्रणालियों के एक नए प्रतिमान के साथ-साथ नीतिनिर्माताओं के पूर्वानुमान टूलकिट में अधिक जटिल पद्धति प्रदान करता है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	127
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	128
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	129
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	130
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	131
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	131
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	132
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	133
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	134
9	कुल चलनिधि राशियां	134
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	135
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	135
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	136
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	136
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	137
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	138
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	139
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	140
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	141
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	141
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	141
21	थोक मूल्य सूचकांक	142
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	145
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	145
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	146
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	146
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	147
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	148
28	वाणिज्यिक पत्र	148
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	148
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	149

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	150
32	विदेशी मुद्रा भंडार	150
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	150
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	151
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	151
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	152
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण	152
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	153
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	154
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	155
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹ में)	156
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	157
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	158
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	159
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	160
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	161
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	162
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	163
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	164

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2017-18	2018-19		2019-20
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.9	7.7	5.7	4.9
1.1.1 कृषि	2.9	6.5	5.1	-0.1	2.0
1.1.2 उद्योग	6.2	8.6	9.9	3.4	1.7
1.1.3 सेवाएं	7.7	8.0	7.5	8.2	6.7
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	10.4	7.2	8.1	4.1
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	11.8	13.3	3.6	4.0
	2018-19	2018		2019	
		जुलाई	अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.80	6.5	4.8	4.3	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	8.7	8.9	9.6	9.7
2.1.2 ऋण	13.3	12.3	13.4	12.1	10.2
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	12.5	13.5	12.1	10.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	6.8	5.1	1.3	2.1
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	20.6	19.0	12.9	13.1
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	9.9	10.8	10.6	9.8
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	18.75	18.75
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.7	4.7	4.8	4.9
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	74.7	75.4	76.5	75.7
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	-8.9	70.5	-186.1	-44.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	30.0	30.1	27.7	28.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	136.9	84.4	207.1	96.5
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.25	6.50	5.75	5.40
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.00	6.25	5.50	5.15
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.50	6.75	6.00	5.65
4.4 बैंक दर	6.50	6.50	6.75	6.00	5.65
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.75/9.45	8.75/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.90/8.05	7.90/8.05	8.00/8.40	7.90/8.40
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.00	6.25/7.25	6.25/7.30	6.35/7.10
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.21	6.36	5.59	5.36
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.69	6.81	5.65	5.41
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.97	7.02	5.88	5.63
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	7.27	7.33	5.94	5.72
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.76	7.95	6.47	6.70
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	68.70	70.93	69.06	71.76
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	79.78	82.84	76.94	79.24
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर 1-माह (%)	6.07	4.37	4.40	4.00	3.85
3-माह (%)	4.80	4.37	4.34	4.09	4.18
6-माह (%)	4.16	4.40	4.22	4.31	4.24
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	4.2	3.7	3.2	3.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.6	5.6	6.0	6.3
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	5.3	4.6	1.1	1.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	2.0	-0.1	5.0	6.4
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	18.1	17.7	-3.6	-4.0
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	4.5	4.4	0.3	0.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	29.7	26.8	-10.4	-13.4
7.2 निर्यात	8.7	16.1	19.7	2.0	-6.0

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
		सितंबर	अगस्त 30	सितंबर 6	सितंबर 13	सितंबर 20	सितंबर 27
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	1899547	2150382	2165588	2176743	2158831	2160124
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	11	13	10	11	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**2113775**	**1899560**	**2150393**	**2165601**	**2176754**	**2158842**	**2160137**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	72080	93095	92651	90984	90211	89945
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	1826575	2056512	2072173	2084996	2067861	2069429
1.2.3 रुपया सिक्का	735	905	785	777	774	770	763
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	806012	721022	838350	829279	817017	845225	882826
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	101	100	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	43	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	565707	505127	538143	527551	519670	550002	532442
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3576	4190	4172	4250	4307	4199
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	2136	2651	2754	2791	2824	2743
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	28571	30810	30546	30619	30656	30680
2.1.1.8 अन्य	199734	180020	262413	261208	258140	256241	311557
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	700	1449		2904	1404	1054	1061
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1129472	1104241	1114369	1083622	1085475	1064818
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**1893698**	**1850494**	**1942591**	**1943648**	**1900638**	**1930701**	**1947644**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	11	13	10	11	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	927652	797721	797661	756128	775489	789658
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	245	606	421	1462	64	459
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	180688	179616	31140	34701	33667	44656	47478
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		35	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	13463	5824	5633	5581	5673	6081	6139
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700	1449		5	5	720	5
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	923080	655879	1000909	999237	999268	1000064	1000116
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	79781	106571	106028	104425	103615	103776
2.2.6.1 सोना	87169	72726	103784	103289	101430	100569	100272

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अग. 1, 2019	3508	19673	-	141067	250	-	-	-	-	-156982
अग. 2, 2019	3508	31601	2550	160775	2505	-	-	-	-	-183813
अग. 3, 2019	3800	5950	-	-	500	-	-	-	-	-1650
अग. 5, 2019	3539	21272	-	165491	375	-	-	-	-	-182849
अग. 6, 2019	6430	19750	2510	151611	1350	-	-	-	-	-161071
अग. 7, 2019	3504	8863	-	138003	50	-	-	-	-	-143312
अग. 8, 2019	5444	10101	-	140022	1900	-	-	-	-	-142779
अग. 9, 2019	3779	12908	8855	171524	1500	-	-	-	-	-170298
अग. 13, 2019	4054	16432	8650	128874	-	-135	-	-	-	-132737
अग. 14, 2019	3507	16885	-	131769	2325	135	-	-	-	-142687
अग. 16, 2019	4080	26924	7550	139289	3611	–	-	-	-	-150972
अग. 17, 2019	-	7609	-	-	304	–	-	-	-	-7305
अग. 19, 2019	3819	23937	-	116237	-	–	-	-	-	-136355
अग. 20, 2019	3754	13757	3000	124110	475	-200	-	-	-	-130838
अग. 21, 2019	3815	10389	-	104552	601	-190	-	-	-	-110715
अग. 22, 2019	5154	13364	-	116034	1	190	-	-	-	-124053
अग. 23, 2019	3769	11368	9730	128775	2250	–	-	-	-	-124394
अग. 26, 2019	4354	20296	-	112122	55	-339	-	-	-	-128348
अग. 27, 2019	3854	14067	10375	129325	2	81	-	-	-	-129080
अग. 28, 2019	5132	17108	-	130158	8	–	-	-	-	-142126
अग. 29, 2019	3849	19336	-	135069	67	–	-	-	-	-150489
अग. 30, 2019	3834	41664	7900	118834	55	–	-	-	-	-148709
अग. 31, 2019	2815	11329	-	-	445	0	-	-	-	-8069

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15377	-2323	-93	-4072
1.1 क्रय (+)	40804	3680	1592	615
1.2 विक्रय (-)	56181	6003	1685	4687
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	-17023	-1379	-29493
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15377	-18631	9809	5737
(करोड़ ₹)	-111945	-128243	64906	35413
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13774	5730	-8609	-7848

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	1350	327	1521
1.2 विक्रय (-)	13935	1350	327	1521
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0	-1135	249	-475

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	31 अगस्त 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	295	660	-365
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	300	630	-330
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	6177	3805	2372
4. 1 वर्ष से अधिक	890	10415	-9525
कुल (1+2+3+4)	**7662**	**15510**	**-7848**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद		नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019					
		सितंबर 28	अप्रैल 26	मई 24	जून 21	जुलाई 19	अगस्त 30	सितंबर 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	4200	998	1615	1400	1151	55	48
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पूर्नवित्त								
2.1 सीमा	–	–	-	-	-	-	-	–
2.2 बकाया	–	–	-	-	-	-	-	–
3 पीडी के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3.2 बकाया	2678	1900	2348	2762	2453	2356	1879	2372
4 अन्य								
4.1 सीमा	–	–	-	-	-	-	-	–
4.2 बकाया	–	–	-	-	-	-	-	–
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	6100	3346	4377	3853	3507	1934	2420

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052234	1846844	2098713	2106299	2082639
1.1 संचलन में नोट	2110883	1901937	2161526	2172899	2150382
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	24954	25241	25258	25258
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84536	80790	88797	92600	93744
2 जनता की जमाराशियां	1658051	1366714	1475859	1460925	1511661
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626309	1342044	1439850	1430405	1480679
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	24670	36009	30520	30982
3 एम$_1$ (1+2)	**3710285**	**3213558**	**3574573**	**3567224**	**3594300**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	120658	140599	140599	140599
5 एम$_2$ (3+4)	**3850884**	**3334216**	**3715172**	**3707823**	**3734899**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11720589	11057850	11993212	12031914	12082792
7 एम$_3$ (3+6)	**15430874**	**14271408**	**15567784**	**15599138**	**15677092**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	326675	367287	367287	367287
9 एम$_4$ (7+8)	**15798161**	**14598083**	**15935071**	**15966425**	**16044379**

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**4387788**	**4394706**	**4746771**	**4850296**	**4720649**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	683456	1054649	1089465	934922
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	683598	1054791	1089607	1000337
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	683153	1051651	1088008	999731
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	445	3140	1599	606
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	127735	142	142	142	65415
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	100	100	100	65373
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3585837	3711250	3692122	3760831	3785727
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**10380180**	**9368994**	**10270651**	**10295103**	**10289165**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	9537	7951	7805	7597
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10364817	9359457	10262700	10287298	10281568
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9769185	8780753	9658374	9682985	9680162
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	570157	590851	590196	590119
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9701	8547	13475	14117	11288
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**3070841**	**2957420**	**3172049**	**3270041**	**3273156**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2833717	2949795	3047788	3050903
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2833931	2950003	3047997	3051112
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	214	208	209	209
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	123702	222254	222254	222254
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**25887**	**25697**	**25984**	**26001**	**26001**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**2433823**	**2475408**	**2647671**	**2842302**	**2631880**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1060678	1108128	1237463	1106106
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1375028	1414730	1539543	1604839	1525774
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**15430874**	**14271408**	**15567784**	**15599138**	**15677092**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710285	3213558	3574572	3567224	3594300
एन एम$_2$ (एन एम$_1$ + 1.2.2.1)	8910877	8116004	8894300	8902098	8951944
एन एम$_3$ (एन एम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	15645209	14470203	15748004	15779633	15844365
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052234	1846844	2098713	2106299	2082639
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13183179	12236369	13261467	13285680	13386556
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626309	1342044	1439850	1430405	1480679
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11556870	10894325	11821617	11855275	11905877
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5200592	4902446	5319728	5334874	5357644
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	168856	217697	182499	174259
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356279	5991879	6501889	6520401	6548232
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	24670	36009	30520	30982
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378054	362320	351815	357133	344189
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15656096	14623927	15914427	16028135	15887013
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4387788	4394706	4746771	4850296	4720649
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	683456	1054649	1089465	934922
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3585837	3711250	3692122	3760831	3785727
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11268307	10229221	11167656	11177839	11166363
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	9537	7951	7805	7597
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11252944	10219684	11159705	11170034	11158766
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	851073	889164	873456	868005
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	25984	26001	26001
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2707106	2899819	2976414	3018164
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2833717	2949795	3047788	3050903
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-126611	-49975	-71374	-32739
2.4 पूंजी खाता	2346743	2331824	2386574	2474953	2419473
2.5 अन्य मदें (निवल)	491757	554704	705652	775964	667339

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2018	2019		
		अगस्त	जून	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**15645209**	**14470202**	**15601556**	**15748004**	**15844365**
2 डाकघर जमाराशियां	367287	326675	367287	367287	367287
3 एल$_1$ (1 + 2)	**16012496**	**14796877**	**15968843**	**16115291**	**16211652**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	2932	2932	2932
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	2656	2656	2656
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	31	31	31
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	245	245	245
5 एल$_2$ (3 + 4)	**16015428**	**14799809**	**15971775**	**16118223**	**16214584**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	31905	..	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**16047333**	..	**16003680**	..	..

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1927634	2187510	2198900	2176383
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	601969	508658	570316	568915	575794
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	558496	475461	533013	531335	538143
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	24670	36009	30520	30982
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2460962	2793835	2798334	2783158
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	662226	926184	962009	812361
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	683456	1054649	1089465	934922
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	683053	1051551	1087908	934358
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	43992	65729	88332	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	638238	985102	998882	998945
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	638238	985102	998882	998945
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	923	820	794	786
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	127693	100	100	100	65373
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	403	3098	1557	564
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	-30767	-136416	-135261	-130158
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	-30802	-136416	-135261	-130158
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	9537	7951	7805	7597
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	2388	2356	2337	1879
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	25984	26001	26001
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2833717	2949795	3047788	3050903
2.3.1 सोना	159585	143002	167502	192691	196879
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2690733	2782310	2855114	2854041
2.4 पूंजी खाता	970265	1041550	956127	1049728	992582
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	19128	152001	187735	113524

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2018	2019				
		अगस्त 31	अगस्त 2	अगस्त 9	अगस्त 16	अगस्त 23	अगस्त 30
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2460962	2757039	2772422	2798334	2776198	2783158
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1927634	2170944	2194302	2198900	2188501	2176383
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	601969	508658	555627	547573	568915	556860	575794
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	24670	30469	30548	30520	30838	30982
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	801951	683456	1118383	1089146	1089465	1044878	934922
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	-30767	-220744	-166172	-135261	-109748	-130158
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	9537	7809	7805	7805	7856	7597
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2833717	2970775	3032149	3047788	3065400	3050903
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26001	26001	26001	26001	26001
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1060678	1145184	1216506	1237463	1258188	1106106

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12408835	11482991	12478990	12503370	12603278
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511084	1229034	1324903	1315942	1365634
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10897751	10253957	11154087	11187428	11237644
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4903988	4614280	5019339	5034343	5056940
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	168856	217697	182499	174259
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5993763	5639676	6134748	6153086	6180704
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378054	362320	351815	357133	344189
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14028966	13136978	14039414	14117177	14129733
2.1.1 सरकार को ऋण	3378300	3503463	3487418	3554068	3578217
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10650666	9633515	10551996	10563109	10551516
2.1.2.1 बैंक ऋण	9769185	8780753	9658374	9682985	9680162
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9727575	8731899	9592372	9617765	9617770
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	9418	8103	9543	9456
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2053	1234	5317	6087	2855
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	842111	880202	864493	859043
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-126611	-49975	-71374	-32739
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	164536	262389	236891	277568
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	163525	171595	176639	176916
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	127622	140770	131626	133392
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538079	577232	748448	749332	752190
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	475461	533013	531335	538143
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74852	70969	79019	82736	83889
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	-30802	-136416	-135261	-130158
2.4 पूंजी खाता	1352307	1266103	1406277	1401054	1402720
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	380987	476185	500805	533578	498996
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	397976	392929	358680	383697	398200
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-48452	-43288	-52866	-46808	-54049

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3504696	3492737	3560158	3581075
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	128771	94922	98242	95964
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11372	12040	11974	11951
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	72650	67170	66043	66396
3.3 अन्य	6379	6133	5606	5586	5582
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	127044	129883	126458	125821
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	224696	256179	249163	247318
4.3 अन्य	170047	119658	163168	161902	162734
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	70812	60018	55891	52891
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	81582	90896	89235	90387

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		अगस्त	जुलाई	अगस्त		अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	222	223	215	218	147	149	139	142
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**276350**	**240678**	**263876**	**271324**	**271426**	**234936**	**258259**	**266046**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	153154	185400	185890	176828	148495	180398	180832
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	71789	67474	72190	79459	70873	67025	72092
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	15734	11002	13244	15139	15569	10836	13122
2 अन्य के प्रति देयताएं	**13835976**	**12843432**	**13842551**	**14012441**	**13495672**	**12529386**	**13489748**	**13655976**
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	11945888	12974287	13123280	12573772	11646516	12633527	12780195
2.1.1 मांग	1542554	1257331	1330254	1396129	1511287	1229034	1300077	1365634
2.1.2 मीयादी	11359025	10688557	11644033	11727151	11062484	10417481	11333450	11414560
2.2 उधार	381864	367173	356127	347776	378254	362320	352570	344189
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	530372	512137	541385	543646	520551	503652	531592
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**180688**	**61696**	**29570**	**31140**	**180688**	**61661**	**29570**	**31140**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	180688	61696	29570	31140	180688	61661	29570	31140
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	657555	560596	621410	637528	640584	546430	606416	622032
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	72806	82242	85737	74877	70969	80508	83889
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	581001	487790	539168	551791	565707	475461	525908	538143
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**372670**	**322707**	**366497**	**381547**	**327814**	**287642**	**315319**	**329551**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	212867	260055	262276	223048	195828	236186	237150
5.1.1 चालू खाते में	17216	12000	20795	17223	13329	9640	18253	14736
5.1.2 अन्य खातों में	228663	200867	239261	245053	209719	186188	217933	222414
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	45911	28498	39789	32252	31478	11892	26827
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	34258	30160	30958	29635	33949	26892	25311
5.4 अन्य आस्तियां	46793	29672	47784	48524	42879	26388	40349	40263
6 निवेश	**3475607**	**3599169**	**3600192**	**3676380**	**3381056**	**3504696**	**3506704**	**3581072**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3592553	3590252	3667033	3379001	3503463	3502765	3578217
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6616	9940	9347	2055	1234	3938	2855
7 बैंक ऋण	**10047125**	**9039378**	**9944498**	**9962773**	**9771722**	**8780753**	**9660517**	**9680162**
7क खाद्यान्न ऋण	64636	71881	88137	89424	41610	48854	61104	62392
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	8819546	9723456	9745356	9521994	8565701	9443639	9466749
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	21441	25697	24827	26223	19864	24687	23884
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	138432	136518	135742	158296	135992	134252	133580
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	24352	23895	24132	24588	24135	23583	23823
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	35607	34932	32716	40622	35062	34356	32126

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 30	2019-20	2019
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	**8674892**	**7819134**	**8561546**	**8594549**	**-0.9**	**9.9**
1.1 खाद्यान्न ऋण	**41474**	**48754**	**65787**	**62182**	**49.9**	**27.5**
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	**8633418**	**7770380**	**8495759**	**8532367**	**–1.2**	**9.8**
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1111300**	**1041879**	**1108988**	**1113027**	**0.2**	**6.8**
1.2.2 उद्योग	**2885778**	**2662066**	**2798360**	**2765215**	**–4.2**	**3.9**
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	366411	361608	358885	–4.4	-2.1
1.2.2.2 मझौले	106395	105261	105214	104436	–1.8	-0.8
1.2.2.3 बड़े	2403878	2190394	2331538	2301894	–4.2	5.1
1.2.3 सेवाएं	**2415609**	**2074013**	**2312871**	**2350198**	**–2.7**	**13.3**
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	125613	140947	141245	2.0	12.4
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	18332	18212	18761	1.2	2.3
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	36994	39899	40221	3.1	8.7
1.2.3.4 नौवहन	7748	6781	5879	5955	–23.1	-12.2
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	158591	166562	169097	–1.4	6.6
1.2.3.6 व्यापार	528158	475076	513452	504278	–4.5	6.1
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	210472	229764	221053	–11.8	5.0
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	264604	283688	283225	2.0	7.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	187220	208627	216388	7.0	15.6
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	641208	490160	636733	680360	6.1	38.8
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	575246	582558	573894	–14.2	-0.2
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	**2220732**	**1992422**	**2275540**	**2303930**	**3.7**	**15.6**
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	3193	5623	5484	–12.9	71.8
1.2.4.2 आवास	1160111	1041857	1199806	1214773	4.7	16.6
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	82873	66825	64901	62607	–24.5	-6.3
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	5843	5396	5087	–18.8	-12.9
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	78499	93974	97650	10.6	24.4
1.2.4.6 शिक्षा	67988	69766	67665	68457	0.7	-1.9
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	195499	201318	202662	0.3	3.7
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	530940	636857	647211	6.7	21.9
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**2739021**	**2563310**	**2716953**	**2721947**	**–0.6**	**6.2**
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1035940	1102240	1105805	0.1	6.7
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	988106	1047483	1048364	–1.8	6.1
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	366411	361608	358884	–4.4	-2.1
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	621695	685875	689479	–0.3	10.9
1.2अ.3 आवास	432703	393556	441976	444823	2.8	13.0
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	21155	31593	31376	30.2	48.3
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	57766	53659	53983	0.1	-6.5
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	349	385	402	1.3	15.2
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	587136	678242	682231	3.0	16.2
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	20518	14155	13139	–15.6	-36.0

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 30	2019-20	2019
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	**2885778**	**2662066**	**2798360**	**2765215**	**–4.2**	**3.9**
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	**41752**	**41417**	**40563**	**40938**	**–1.9**	**–1.2**
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	**157058**	**142661**	**150077**	**145210**	**–7.5**	**1.8**
1.2.1 चीनी	29705	26063	28582	27889	–6.1	7.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	20594	19475	18929	–11.3	–8.1
1.2.3 चाय	4966	5269	5200	5356	7.9	1.7
1.2.4 अन्य	101044	90735	96820	93036	–7.9	2.5
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	**14662**	**12949**	**14440**	**13857**	**–5.5**	**7.0**
1.4 वस्त्र	**203549**	**198059**	**191284**	**186307**	**–8.5**	**–5.9**
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	98152	90087	84473	–13.6	–13.9
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	1935	2110	2117	–0.1	9.4
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	26748	23789	25452	25423	–5.0	6.9
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	74183	73635	74294	–3.5	0.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	**11071**	**11295**	**11211**	**11051**	**–0.2**	**–2.2**
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	**11968**	**11203**	**11701**	**11881**	**–0.7**	**6.1**
1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	**30319**	**29847**	**29760**	**29864**	**–1.5**	**0.1**
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	**63136**	**53809**	**53085**	**51976**	**–17.7**	**–3.4**
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	**191484**	**167292**	**173212**	**177006**	**–7.6**	**5.8**
1.9.1 उवर्रक	40043	29200	34419	35572	–11.2	21.8
1.9.2 औषधि और दवाइयां	50500	51105	48195	48566	–3.8	–5.0
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	36809	37900	39987	–14.4	8.6
1.9.4 अन्य	54224	50178	52698	52881	–2.5	5.4
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**45803**	**42978**	**45843**	**46501**	**1.5**	**8.2**
1.11 कांच और कांच के सामान	**9887**	**10003**	**9652**	**9942**	**0.6**	**–0.6**
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	**55683**	**51351**	**57539**	**59223**	**6.4**	**15.3**
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	**371564**	**384036**	**347995**	**348467**	**–6.2**	**–9.3**
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	294673	265912	266309	–5.9	–9.6
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	89363	82083	82158	–7.4	–8.1
1.14 सभी अभियांत्रिकी	**168621**	**154691**	**165038**	**166488**	**–1.3**	**7.6**
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	37856	35083	37367	37284	–1.5	6.3
1.14.2 अन्य	130765	119608	127671	129204	–1.2	8.0
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	**79859**	**75444**	**82728**	**83022**	**4.0**	**10.0**
1.16 रत्न और आभूषण	**72014**	**69189**	**66066**	**66361**	**–7.8**	**–4.1**
1.17 निर्माण	**99473**	**87842**	**95384**	**95990**	**–3.5**	**9.3**
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	**1055921**	**923695**	**1034716**	**1004811**	**–4.8**	**8.8**
1.18.1 पावर	568966	529938	568247	558892	–1.8	5.5
1.18.2 दूरसंचार	115585	90652	112215	109761	–5.0	21.1
1.18.3 सड़क	186852	171222	188386	190895	2.2	11.5
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	131883	165868	145263	–21.3	10.1
1.19 अन्य उद्योग	**201954**	**194303**	**218066**	**216319**	**7.1**	**11.3**

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबधं में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018	2019						
		जुलाई, 27	मई, 31	जून, 07	जून, 21	जून, 28	जुलाई, 05	जुलाई, 19	जुलाई, 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	31	31	31	31	31	31	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**62003.4**	**54157.8**	**62344.8**	**61829.6**	**61051.4**	**63649.9**	**63016.6**	**63709.3**	**63046.8**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**18241.3**	**16895.3**	**17715.9**	**18400.1**	**18111.8**	**20235.9**	**18887.7**	**18049.0**	**18127.7**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	4754.6	4866.0	5838.0	5924.6	5967.4	5764.0	5231.8	5530.1
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	8832.8	9906.2	9627.3	8976.4	10064.2	10036.7	9671.7	9777.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	371.9	70.0	0.0	0.0	1255.3	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2936.0	2873.8	2934.8	3210.8	2949.1	3087.0	3145.4	2820.3
2.2 मीयादी देयताएं	**98531.4**	**87100.7**	**99343.7**	**99374.6**	**100475.8**	**104584.1**	**102902.8**	**103751.6**	**105734.7**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	41046.1	46246.8	46503.5	47744.6	47559.4	49264.0	49066.4	51637.1
2.2.1.2 अन्य	52194.8	45325.0	52438.6	52202.4	52074.9	53585.7	52979.9	54037.6	53269.4
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1265.3	0.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	729.1	658.3	668.7	656.3	2173.6	659.0	647.5	828.2
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	43429.5	47096.2	46448.0	45612.6	45914.7	45329.2	45658.8	44603.4
4.1 मांग	16826.7	15715.8	14109.5	13706.0	13356.7	13687.7	13837.5	14211.5	14152.3
4.2 मीयादी	33548.7	27713.6	32986.7	32741.9	32255.9	32227.0	31491.7	31447.3	30451.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**5721.0**	**4548.6**	**4846.3**	**5096.3**	**5080.5**	**5290.0**	**5334.2**	**5181.0**	**5408.2**
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	294.6	339.2	289.9	310.9	334.7	291.7	322.5	302.6
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4254.0	4507.1	4806.5	4769.6	4955.4	5042.5	4858.5	5105.6
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1543.2**	**856.0**	**960.1**	**853.5**	**796.5**	**2213.6**	**862.7**	**839.9**	**936.2**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**30885.3**	**53078.0**	**31103.6**	**30826.2**	**30656.7**	**30634.4**	**30542.5**	**30157.6**	**30332.3**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**16190.2**	**17355.3**	**15001.4**	**15802.0**	**16143.7**	**17580.3**	**17705.1**	**22900.7**	**19088.4**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**60089.8**	**54190.2**	**62530.9**	**63753.8**	**63824.0**	**63419.8**	**63812.5**	**63536.6**	**62462.4**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**60086.2**	**54187.8**	**62530.3**	**63753.2**	**63823.4**	**63419.3**	**63811.9**	**63536.1**	**62461.9**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	82610.9	69278.4	78346.8	77644.7	77866.6	77817.4	77563.1	77832.9	77427.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	2.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अगस्त 18	जुलाई 19	अगस्त 19	अगस्त 18	जुलाई 19	अगस्त 19	अगस्त 18	जुलाई 19	अगस्त 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**139.5**	**138.4**	**139.1**	**142.7**	**143.0**	**144.0**	**140.1**	**147.7**	**149.1**	**141.7**	**144.7**	**145.9**
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	139.2	138.4	139.2	136.5	141.4	142.1	138.3	139.3	140.1
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	148.8	164.0	161.9	146.4	160.2	158.3	148.0	162.7	160.6
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	139.1	138.4	137.1	136.6	142.5	140.8	138.1	140.0	138.5
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	143.5	143.9	144.5	141.2	144.1	144.8	142.6	144.0	144.6
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	125.0	124.4	124.8	117.4	119.3	119.9	122.2	122.5	123.0
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	154.4	146.4	145.6	146.3	154.7	153.9	150.6	150.3	149.5
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	156.3	150.1	156.1	157.3	180.1	189.3	156.6	160.3	167.4
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	126.8	130.6	131.5	113.6	128.9	129.8	122.4	130.0	130.9
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	115.4	110.8	111.7	113.3	111.8	112.7	114.7	111.1	112.0
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	138.6	141.7	142.8	141.1	141.6	142.5	139.4	141.7	142.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	133.8	138.5	138.5	127.4	129.5	129.8	131.1	134.7	134.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	155.2	156.7	156.9	150.4	155.6	156.2	153.0	156.2	156.6
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**159.4**	**162.9**	**160.4**	**156.4**	**164.5**	**165.1**	**162.1**	**167.2**	**167.9**	**157.9**	**165.2**	**165.8**
3 कपड़ा और जूते	**150.3**	**139.3**	**145.9**	**151.3**	**150.9**	**151.1**	**138.3**	**142.7**	**143.0**	**146.1**	**147.6**	**147.9**
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	152.1	151.6	151.8	140.0	144.7	145.0	147.3	148.9	149.1
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	145.8	146.6	146.6	129.0	131.9	132.2	138.8	140.5	140.6
4 आवास	**--**	**145.6**	**145.6**	**--**	**--**	**--**	**144.6**	**150.6**	**151.6**	**144.6**	**150.6**	**151.6**
5 ईंधन और लाइट	**147.0**	**129.3**	**140.3**	**147.7**	**146.8**	**146.4**	**129.8**	**127.0**	**125.5**	**140.9**	**139.3**	**138.5**
6 विविध	**138.6**	**131.1**	**134.9**	**136.6**	**144.2**	**144.9**	**131.0**	**134.5**	**135.3**	**133.9**	**139.5**	**140.2**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	143.8	150.0	150.2	134.4	137.7	138.1	139.4	144.2	144.5
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	139.4	152.2	152.7	134.9	140.8	141.5	137.7	147.9	148.5
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	128.3	131.2	131.4	120.7	120.6	120.8	124.3	125.6	125.8
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	138.6	147.5	148.1	129.8	135.0	135.5	133.6	140.5	141.0
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	146.9	159.1	159.7	145.3	150.4	151.5	146.0	154.0	154.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	131.3	136.1	138.7	128.3	135.1	137.9	130.1	135.7	138.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**141.3**	**137.7**	**139.6**	**142.5**	**144.9**	**145.6**	**138.0**	**143.3**	**144.2**	**140.4**	**144.2**	**144.9**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018	2019	
				अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	301	319	320
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	907	958	965
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	915	915	965	972

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018	2019	
		अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31,193	29,644	34,522	37,356
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38,404	37,374	39,099	43,747

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			अगस्त	जून	जुलाई (अ)	अगस्त (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**119.8**	**120.1**	**121.5**	**121.2**	**121.4**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**134.2**	**135.2**	**141.0**	**142.1**	**143.9**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**143.7**	**144.8**	**152.2**	**153.7**	**155.9**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	145.1	155.4	157.4	159.2
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	155.8	166.8	175.6	180.2
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	143.7	145.5	143.6	145.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	134.9	146.0	143.7	143.8
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	131.3	133.9	136.0	141.5
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	141.3	144.2	142.6	142.8
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**123.1**	**124.0**	**128.7**	**128.8**	**129.9**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	130.8	133.9	132.2	130.1
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	140.1	150.0	150.1	151.7
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	108.7	106.1	106.6	105.8
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	155.3	208.3	211.8	241.0
1.1.3 खनिज	**0.833**	**136.5**	**129.4**	**153.4**	**153.4**	**153.4**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	114.1	146.8	147.5	146.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	183.2	176.6	174.0	176.6
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**92.4**	**95.4**	**87.2**	**86.9**	**88.1**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**104.1**	**104.9**	**102.2**	**100.6**	**100.7**
1.2.1 कोल	**2.138**	**123.3**	**123.0**	**124.0**	**124.0**	**124.0**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	132.0	133.9	133.9	133.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	129.9	129.9	129.9
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**96.7**	**98.3**	**94.0**	**91.4**	**91.5**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**109.6**	**109.4**	**108.3**	**108.3**	**108.3**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**117.9**	**117.8**	**118.5**	**118.1**	**117.8**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**128.6**	**129.6**	**130.8**	**130.9**	**132.4**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	137.5	140.5	140.2	137.3
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	137.9	132.3	132.6	134.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.9	115.6	113.9	114.4
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	118.8	112.4	112.3	113.7
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	136.1	139.8	140.7	142.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	141.8	145.0	145.2	146.4
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	110.6	136.0	136.8	137.3
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	129.1	132.2	132.4	132.4
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	114.2	117.3	116.8	119.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	127.7	128.4	128.3	129.1
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	133.3	133.7	132.8	131.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	141.9	145.8	145.9	143.2
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	121.9	124.8	125.9	130.2
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	126.5	131.6	131.5	130.2
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	141.2	154.5	155.7	162.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	158.0	172.1	174.6	176.9
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**120.7**	**120.0**	**123.3**	**123.2**	**124.0**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	113.8	112.9	116.4	116.5	117.9
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	121.3	124.8	126.9	126.6
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	129.5	132.5	129.9	130.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**150.4**	**150.2**	**154.0**	**153.6**	**153.9**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	150.2	154.0	153.6	153.9
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**117.9**	**118.3**	**119.4**	**119.3**	**118.3**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	111.4	110.7	110.5	109.5
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	126.7	130.7	130.7	129.2
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	115.0	115.0	116.4	115.9
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	131.3	135.2	134.9	135.3
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	138.0	139.4	140.3	140.4
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	117.8	118.2	117.3	116.1
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**138.8**	**138.8**	**138.0**	**137.1**	**136.3**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.6	139.3	137.7	136.7
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	137.0	136.7	134.6	135.4	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			अगस्त	जून	जुलाई (अ)	अगस्त (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**121.8**	**121.5**	**118.6**	**118.3**	**119.3**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.0	109.8	106.2	106.1	108.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	134.6	136.4	136.2	136.6
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	123.5	123.6	120.0	119.5	119.8
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**133.5**	**133.3**	**134.5**	**134.2**	**134.1**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	122.7	126.2	125.2	120.1
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.3	136.8	134.9	134.5	136.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	158.7	156.5	175.5	175.5	174.9
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	122.6	129.2	129.5	128.4
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**123.3**	**122.3**	**122.5**	**122.3**	**121.5**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	129.3	127.7	127.2	126.7	125.7
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	116.2	115.1	115.5	115.2
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	119.8	122.6	122.3	121.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**146.6**	**148.7**	**148.0**	**150.1**	**151.0**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	148.7	148.0	150.1	151.0
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**119.1**	**118.8**	**119.0**	**118.8**	**118.3**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	124.7	123.4	122.2	121.4
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	120.0	123.4	123.1	123.0
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	118.7	114.5	113.5	114.4
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	119.1	121.9	125.0	123.6
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	111.4	116.4	116.1	115.1
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	116.4	119.5	119.6	118.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	117.2	114.6	114.8	113.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	104.4	100.3	100.0	99.1
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**123.5**	**123.0**	**125.7**	**126.2**	**125.4**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	123.0	125.7	126.2	125.4
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**109.6**	**109.5**	**109.3**	**109.2**	**108.2**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.0	99.3	99.3	99.5
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	92.0	94.2	93.1	94.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	117.3	116.5	116.5	114.7
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**115.9**	**115.8**	**118.3**	**117.5**	**117.5**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	121.1	125.7	124.9	127.1
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	110.2	109.4	110.4	109.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	100.2	100.7	102.5	101.9
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.3	114.5	114.5	114.5
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	113.1	121.8	120.4	119.7
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	122.7	121.0	120.9	121.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	120.0	119.7	121.5	122.7
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	138.8	94.6	90.0	90.4
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**112.2**	**111.6**	**108.7**	**107.3**	**104.8**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	112.6	105.0	100.9	96.9
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.8	117.3	113.5	112.6	104.7
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	99.5	96.2	95.0	93.7
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	108.2	108.4	106.5	104.9
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	119.8	113.7	111.6	108.4
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	112.8	107.4	105.7	100.7
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	113.2	106.3	101.4	98.4
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	125.8	129.7	127.3	125.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	112.1	106.9	107.6	107.4
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	109.5	113.5	115.6	113.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	115.1	143.5	145.6	146.9
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**115.1**	**115.4**	**116.2**	**114.8**	**114.1**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	114.2	114.7	114.2	113.7
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	129.0	124.4	119.2	120.1
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	105.9	107.1	102.6	100.9	100.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	95.2	101.2	100.3	100.2
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.7	100.2	100.2	100.2
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	121.6	126.1	126.3	123.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**111.8**	**112.8**	**111.4**	**111.4**	**111.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	101.8	97.4	97.9	98.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.1	135.0	135.0	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			अगस्त	जून	जुलाई (अ)	अगस्त (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.2	116.7	116.9	117.2
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	103.8	105.4	102.2	102.2	101.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	109.8	112.5	112.5	110.8
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	137.9	137.4	138.7	136.6	138.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	101.5	104.2	104.2	100.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.5	109.5	109.5	109.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**111.7**	**111.8**	**110.9**	**111.3**	**111.1**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	107.9	107.5	108.7	107.9
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	117.7	118.5	117.6	117.5	117.2
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	127.0	113.6	118.4	109.5
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	111.2	110.0	109.3	108.8	110.1
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	108.7	111.4	107.6	112.2
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	121.8	120.4	120.5	120.5
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.1	108.9	109.6	109.3
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**111.3**	**111.2**	**113.2**	**113.5**	**113.1**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	103.2	104.7	105.0	105.2
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	118.7	119.3	119.6	120.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	107.1	111.6	112.2	110.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	112.9	110.2	110.5	112.3
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	77.4	79.3	79.3	79.8
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	110.2	110.6	110.6	110.6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	130.2	133.7	132.2	132.3
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	116.7	119.7	120.0	120.6
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	102.5	107.4	108.2	108.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.8	74.5	76.6	74.5
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	121.3	125.3	125.3	122.6
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	120.8	120.8	121.8	118.7
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	124.2	126.8	126.9	126.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	66.6	66.6	66.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**112.8**	**113.3**	**114.7**	**114.0**	**113.5**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	113.9	115.7	115.2	114.1
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	112.5	113.5	112.7	112.7
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**111.7**	**110.9**	**117.0**	**116.4**	**117.6**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.7	103.9	106.6	106.7	106.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	105.6	113.0	112.3	113.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	127.8	127.9	128.7	128.4	128.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	123.9	125.1	125.6	124.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**127.3**	**125.3**	**132.1**	**128.7**	**131.4**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	125.3	132.1	128.7	131.4
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**107.0**	**100.6**	**108.7**	**108.3**	**110.3**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	97.3	105.6	105.2	107.4
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	174.3	177.2	175.9	173.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	127.4	128.1	128.5	128.7
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	132.2	137.7	136.4	136.7
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	155.1	161.1	161.0	161.0
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**138.1**	**139.1**	**144.2**	**145.2**	**147.1**

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औदयोगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2017-18	2018-19	अप्रैल-जुलाई		जुलाई	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	126.4	130.6	125.7	131.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	104.9	107.9	102.7	106.2	95.5	100.2
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	127.4	131.0	127.6	132.9
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	160.1	170.6	162.0	169.7
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	124.9	128.3	123.6	127.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	103.0	98.6	98.7	91.7
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	121.7	134.9	121.4	138.3
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	138.8	139.3	136.1	139.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	131.3	127.7	133.5	129.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	133.8	143.4	135.1	146.3

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - अगस्त			
	2019-20 (बज़ट अनुमान)	2019-20 (वर्तमान)	2018-19 (वर्तमान)	बज़ट अनुमान का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**1962761**	**603201**	**464548**	**30.7**	**26.9**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1649582	404580	366216	24.5	24.7
1.2 करेतर राजस्व	313179	198621	98332	63.4	40.1
2 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**119828**	**18260**	**15020**	**15.2**	**16.3**
2.1 ऋण की वसूली	14828	5902	5596	39.8	45.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	105000	12358	9424	11.8	11.8
3 कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) (1+2)	**2082589**	**621461**	**479568**	**29.8**	**26.4**
4 राजस्व व्यय	2447780	1039125	938641	42.5	43.8
4.1 ब्याज भुगतान	660471	219026	219111	33.2	38.1
5 पूंजी व्यय	338569	136176	132218	40.2	44.0
6 कुल व्यय (4+5)	**2786349**	**1175301**	**1070859**	**42.2**	**43.8**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**485019**	**435924**	**474093**	**89.9**	**114.0**
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	**703760**	**553840**	**591291**	**78.7**	**94.7**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**43289**	**334814**	**372180**	**773.4**	**767.7**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनियन बज़ट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018	2019					
		अगस्त 31	जुलाई 26	अगस्त 2	अगस्त 9	अगस्त 16	अगस्त 23	अगस्त 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	40183	24102	22039	19676	20291	19702	19939
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	20952	10211	8377	8030	8694	7287	7196
1.3 राज्य सरकारें	26999	66535	44396	47146	50146	41646	53146	54141
1.4 अन्य	27747	69949	87786	89656	90464	87195	87650	85510
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	39358	55667	56979	62264	61894	64548	64410
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	33855	53898	54118	49798	49556	45203	46639
2.3 राज्य सरकारें	28036	33382	4504	2254	2340	2492	2492	2667
2.4 अन्य	18567	26013	25847	26199	27089	29424	33191	33619
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	37554	51756	53239	59979	61806	60856	59867
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	74249	80333	78133	69970	67909	67475	68176
3.3 राज्य सरकारें	18892	15792	17200	17200	17615	17615	17065	17745
3.4 अन्य	62393	55373	52741	53496	54828	55014	56781	57147
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	136153	115097	94450	78070	81157	138375	177224
4.4 अन्य	252	440	215	162	147	396	167	677
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	513195	508440	508838	512198	503532	515394	517055

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जुलाई 31	7000	58	70201	5250	16	7000	5250	12250	98.61	5.6539
अगस्त 7	7000	60	61631	12393	8	6997	12393	19390	98.66	5.4477
अगस्त 14	7000	52	33390	2301	30	6999	2301	9300	98.65	5.4889
अगस्त 21	7000	65	79641	19533	28	6997	19533	26530	98.66	5.4477
अगस्त 28	7000	59	94060	4002	32	6998	4002	11000	98.67	5.4065
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जुलाई 31	5000	76	28869	0	17	5000	0	5000	97.15	5.8833
अगस्त 7	5000	59	22632	0	14	5000	0	5000	97.24	5.6923
अगस्त 14	5000	64	18399	1	25	4999	1	5000	97.26	5.6499
अगस्त 21	5000	63	19917	8	29	4992	8	5000	97.27	5.6287
अगस्त 28	5000	72	18372	0	40	5000	0	5000	97.27	5.6287
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जुलाई 31	4000	72	15529	0	23	4000	0	4000	94.41	5.9372
अगस्त 7	4000	60	12916	500	34	4000	500	4500	94.49	5.8473
अगस्त 14	4000	89	13908	0	28	4000	0	4000	94.56	5.7688
अगस्त 21	4000	80	18415	305	26	3995	305	4300	94.59	5.7351
अगस्त 28	4000	73	12442	850	37	4000	850	4850	94.60	5.7239

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
	1	2
अगस्त 1, 2019	4.40-5.75	5.56
अगस्त 2, 2019	4.40-5.80	5.59
अगस्त 3, 2019	4.00-5.75	5.39
अगस्त 5, 2019	4.40-5.80	5.56
अगस्त 6, 2019	4.40-5.80	5.63
अगस्त 7, 2019	4.40-5.75	5.50
अगस्त 8, 2019	4.10-5.65	5.27
अगस्त 9, 2019	4.10-5.50	5.32
अगस्त 13, 2019	4.10-5.50	5.31
अगस्त 14, 2019	4.10-5.50	5.33
अगस्त 16, 2019	4.00-5.40	5.31
अगस्त 19, 2019	4.00-5.45	5.30
अगस्त 20, 2019	4.00-5.42	5.28
अगस्त 21, 2019	4.10-5.40	5.32
अगस्त 22, 2019	4.10-5.45	5.33
अगस्त 23, 2019	4.00-5.65	5.34
अगस्त 26, 2019	4.00-5.45	5.36
अगस्त 27, 2019	4.00-5.45	5.35
अगस्त 28, 2019	4.10-5.45	5.36
अगस्त 29, 2019	3.90-5.45	5.36
अगस्त 30, 2019	4.10-5.50	5.36
अगस्त 31, 2019	4.20-5.45	5.31
सितंबर 3, 2019	4.10-5.45	5.34
सितंबर 4, 2019	4.10-5.50	5.35
सितंबर 5, 2019	4.10-5.50	5.35
सितंबर 6, 2019	4.10-5.50	5.35
सितंबर 7, 2019	3.90-5.40	5.23
सितंबर 9, 2019	4.10-5.45	5.32
सितंबर 11, 2019	4.00-5.50	5.32
सितंबर 12, 2019	4.00-5.45	5.35
सितंबर 13, 2019	4.00-5.45	5.29

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2018	2019			
	अगस्त 31	जुलाई 19	अगस्त 2	अगस्त 16	अगस्त 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	163975.02	224039.00	198141.00	178635.00	179455.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	24130.54	10406.96	13107.14	16349.46	15568.45
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.95-8.90	5.86-7.36	5.66-7.09	5.43-7.19	5.40-7.22

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	जुलाई 31	जुलाई 15	जुलाई 30	अगस्त 15	अगस्त 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	632296.01	544981.40	509412.80	516900.55	497176.75
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	156116.00	81216.10	119806.65	123734.95	77603.30
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.44-10.40	5.81-13.19	5.69-14.47	5.38-13.99	5.37-13.39

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018	2019					
		अगस्त 24	जुलाई 26	अगस्त 2	अगस्त 9	अगस्त 16	अगस्त 23	अगस्त 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	25444	24991	18197	23748	37362	36111	35391
2 नोटिस मुद्रा	4930	274	294	6450	314	348	428	10155
3 मीयादी मुद्रा	740	854	570	792	608	900	695	697
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	228992	253638	269919	242494	296266	315753	309833
5 बाजार रिपो	200970	169760	165619	194213	193189	229721	211641	203504
6 कार्पोरेट बांड में रिपो		613	120	1363	750	920	2376	1809
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	68761	59156	71600	72485	67446	67473	78536
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	46319	106224	106743	135451	71713	106854	94875
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	2879	6809	7328	8317	3624	4684	6356
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	4687	3734	2158	797	2769	2798	2604
10.2 182-दिवसीय	1450	826	2022	3901	4724	2626	4597	1735
10.3 364-दिवसीय	1620	252	4225	3892	9540	2772	3017	2665
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400	2400			10036	7689	565	66
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	57364	123015	124022	168864	91194	122515	108301
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	17	5	145	49	371	96	98

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(करोड़ ₹)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रैल-अगस्त)		2019-20 (अप्रैल-अगस्त)*		अगस्त 2018		अगस्त 2019*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**129**	**16754**	**68**	**11568**	**38**	**59140**	**11**	**1254**	**5**	**4149**
1ए प्रीमियम	124	16083	66	11243	38	37667	10	1197	5	4118
1.1 पब्लिक	119	14606	64	10440	29	7955	11	1254	4	4047
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	62	10194	29	7834	10	1197	4	4029
1.2 राइट्स	10	2149	4	1128	9	51185	–	–	1	102
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	4	1049	9	29833	–	–	1	89
2 अधिमान शेयर	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**25**	**36680**	**7**	**21048**	**14**	**6970**	**–**	**–**	**3**	**2794**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	7	21048	14	6970	–	–	3	2794
3.2.1 पब्लिक	25	36680	7	21048	14	6970	–	–	3	2794
3.2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**154**	**53434**	**75**	**32616**	**52**	**66110**	**11**	**1254**	**8**	**6943**
4.1 पब्लिक	144	51284	71	31488	43	14925	11	1254	7	6841
4.2 राइट्स	10	2149	4	1128	9	51185	–	–	1	102

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018	2019				
			अगस्त	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2307726	193397	180584	208548	173529	181114	185881
	अमेरिकी मिलियन डालर	330078	27808	26011	29889	24990	26321	26127
1.1 तेल	करोड़ ₹	325929	25836	24689	34780	18378	25052	23596
	अमेरिकी मिलियन डालर	46554	3715	3556	4985	2647	3641	3317
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1981797	167561	155896	173768	155151	156062	162285
	अमेरिकी मिलियन डालर	283525	24093	22454	24905	22344	22681	22810
2 आयात	करोड़ ₹	3585672	318044	293936	325136	284114	273582	281606
	अमेरिकी मिलियन डालर	512793	45731	41416	45358	40334	39760	39582
2.1 तेल	करोड़ ₹	986275	83032	80108	87788	77363	66057	77380
	अमेरिकी मिलियन डालर	140921	11939	11448	12478	11071	9600	10876
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2599397	235012	213828	237348	206751	207525	204226
	अमेरिकी मिलियन डालर	371872	33792	29967	32880	29263	30160	28705
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1277945	-124647	-113351	-116588	-110585	-92468	-95725
	अमेरिकी मिलियन डालर	-182714	-17923	-15405	-15468	-15344	-13439	-13455
3.1 तेल	करोड़ ₹	-660346	-57196	-55419	-53007	-58984	-41005	-53785
	अमेरिकी मिलियन डालर	-94367	-8224	-7892	-7493	-8424	-5959	-7560
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-617599	-67451	-57932	-63581	-51600	-51463	-41940
	अमेरिकी मिलियन डालर	-88347	-9699	-7513	-7975	-6920	-7479	-5895

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019					
		सितंबर 21	अगस्त 16	अगस्त 23	अगस्त 30	सितंबर 6	सितंबर 13	सितंबर 20
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड़ ₹**	**2883110**	**3059903**	**3078248**	**3063055**	**3077688**	**3045361**	**3045895**
	अमेरिकी मिलियन डालर	**401790**	**430501**	**429051**	**428604**	**429608**	**428960**	**428572**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	2709820	2831145	2849226	2829979	2845520	2817033	2819216
	अमेरिकी मिलियन डालर	377413	398327	397129	396005	397205	396795	396670
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	144810	192691	192762	196880	195940	192414	190780
	अमेरिकी मिलियन डालर	20414	27111	26867	27550	27351	27103	26843
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1054	1046	1046	1046	1046	1046	1046
	करोड़ ₹	10640	10221	10285	10242	10270	10167	10196
	अमेरिकी मिलियन डालर	1481	1438	1434	1433	1434	1432	1435
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	17840	25846	25975	25954	25958	25748	25703
	अमेरिकी मिलियन डालर	2483	3626	3621	3617	3619	3630	3623

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		अगस्त	जुलाई	अगस्त	अप्रैल-अगस्त	अप्रैल-अगस्त
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**130,423**	**123,028**	**133,125**	**130,513**	**5,702**	**4,042**
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,623	23,975	23,895	597	725
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	86,507	93,211	91,136	4,119	2,496
1.3 एनआरओ	15,236	13,899	15,938	15,482	986	820

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-अगस्त	अप्रैल-अगस्त	अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**30,712**	**13,368**	**19,388**	**1,987**	**3,673**	**1,824**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**43,302**	**18,476**	**24,155**	**2,544**	**4,570**	**2,732**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**62,001**	**25,013**	**30,809**	**3,896**	**5,923**	**4,056**
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,055	18,304	23,630	2,564	4,529	2,609
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	1,558	2,809	14	50	43
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36,315	14,198	17,957	2,182	3,761	2,004
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	2,272	2,589	311	661	506
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	275	275	56	56	56
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,672	5,457	5,422	1,115	1,115	1,115
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,274	1,252	1,757	217	280	332
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**18,699**	**6,537**	**6,654**	**1,352**	**1,353**	**1,324**
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18,452	6,417	6,621	1,298	1,341	1,323
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	120	33	54	12	2
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**12,590**	**5,108**	**4,767**	**557**	**896**	**908**
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7,201	3,219	2,265	259	437	492
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,032	1,264	1,276	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,202	1,401	1,783	296	334	209
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2,845	776	557	250	127	45
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**–618**	**–6,144**	**2,995**	**–2,831**	**–1,313**	**–534**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	1,820	–	1,820	–	–
1.2.2 एफआईआई	–2,225	–9,446	3,847	–4,911	–708	–601
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	–1,482	852	–261	605	–67
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**30,094**	**7,224**	**22,383**	**–844**	**2,360**	**1,290**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		अगस्त	जून	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**13,787.6**	**1,426.9**	**1,407.5**	**1,691.6**	**1,875.8**
1.1 जमाराशियां	455.9	32.2	37.4	49.6	33.7
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	6.6	3.9	6.5	6.8
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	47.2	28.6	30.1	25.5
1.4 उपहार	1,370.2	116.3	130.9	151.2	177.2
1.5 दान	8.7	2.4	0.9	1.1	10.3
1.6 यात्रा	4,803.8	533.6	595.9	653.5	784.7
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	241.2	230.2	292.8	281.6
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	1.7	2.2	3.1	2.7
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	419.1	353.9	477.6	531.2
1.10 अन्य	242.2	26.7	23.5	26.2	22.2

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	70.94	73.33	73.22
1.2 रीर	119.71	114.01	111.31	115.74	115.57
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	72.32	74.68	74.52
2.2 रीर	121.94	116.32	113.38	118.30	118.05
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	61.35	63.67	63.80
1.2 रीर	129.19	121.70	118.69	124.91	125.20
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	90.34	93.76	93.95
2.2 रीर	100.00	94.20	91.88	96.69	96.92

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि मिलियन अमरिकी डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	90	90	115
1.2 राशि	28387	3685	3418	3167
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	4	3	1
2.2 राशि	13537	1141	1563	150
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1020	94	93	116
3.2 राशि	41924	4827	4981	3317
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5	5	6	5
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	0.94	1.38	1.43
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.00-12.00	0.00-11.20	0.00-10.59

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**286992**	**298331**	**-11338**	**302166**	**288182**	**13984**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**155749**	**171552**	**-15803**	**160686**	**175031**	**-14345**
1.1 पण्य	**83389**	**129140**	**-45751**	**82729**	**128941**	**-46212**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**72360**	**42413**	**29947**	**77957**	**46091**	**31867**
1.2.1 सेवाएं	48200	29524	18676	52197	32166	20031
1.2.1.1 यात्रा	6448	5914	534	6950	6203	747
1.2.1.2 परिवहन	4863	4776	87	5344	6104	-760
1.2.1.3 बीमा	606	373	233	588	409	179
1.2.1.4 जीएनआईई	170	278	-108	151	307	-155
1.2.1.5 विविध	36114	18183	17930	39164	19143	20021
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	20121	1516	18605	22811	1812	20998
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9436	9479	-43	11475	11715	-239
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1111	744	367	1287	519	769
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	522	232	290	700	284	415
1.2.2 अंतरण	18803	1772	17031	19963	2012	17951
1.2.2.1 आधिकारिक	41	225	-184	35	307	-272
1.2.2.2 निजी	18763	1547	17216	19928	1705	18224
1.2.3 आय	5356	11117	-5760	5797	11913	-6116
1.2.3.1 निवेश आय	4213	10514	-6301	4446	11274	-6829
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1144	603	541	1352	639	713
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**131243**	**126456**	**4787**	**141032**	**113150**	**27882**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**77688**	**76261**	**1427**	**88393**	**69659**	**18734**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	17235	7663	9573	21215	7323	13891
2.1.1.1 भारत में	16960	3834	13126	20830	3976	16854
2.1.1.1.1 इक्विटी	12914	3821	9093	16492	3957	12535
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3228		3228	3193		3193
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	817	12	805	1145	19	1126
2.1.1.2 विदेश में	276	3829	-3554	384	3347	-2963
2.1.1.2.1 इक्विटी	276	2326	-2050	384	1336	-952
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	770	-770
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	745	-745	0	1241	-1241
2.1.2 संविभाग निवेश	60453	68598	-8145	67178	62335	4843
2.1.2.1 भारत में	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
2.1.2.1.1 एफआईआई	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	49357	52107	-2749	50491	47378	3112
2.1.2.1.1.2 ऋण	9781	16137	-6356	16582	14538	2044
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1315	354	961	105	419	-314
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**18774**	**23046**	**-4272**	**22450**	**12597**	**9853**
2.2.1 बाह्य सहायता	1876	1350	526	3021	1551	1470
2.2.1.1 भारत द्वारा	12	31	-19	5	30	-25
2.2.1.2 भारत को	1864	1319	545	3016	1521	1495
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	4749	6057	-1308	10001	3608	6393
2.2.2.1 भारत द्वारा	1718	1519	199	881	742	140
2.2.2.2 भारत को	3031	4538	-1507	9119	2866	6253
2.2.3 भारत को अल्पावधि	12149	15639	-3490	9428	7438	1990
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	5613	15639	-10026	8028	7438	590
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6536	0	6536	1400	0	1400
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**28806**	**18745**	**10061**	**16877**	**20761**	**-3884**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	28806	18231	10575	16877	20378	-3501
2.3.1.1 आस्तियां	11158	5690	5468	5503	10076	-4573
2.3.1.2 देयताएं	17648	12541	5106	11375	10302	1072
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	15578	12067	3512	10780	8026	2754
2.3.2 अन्य	0	513	-513	0	383	-383
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	23	-23	0	60	-60
2.5 अन्य पूंजी	5975	8381	-2406	13312	10073	3239
3 भूल-चूक		**322**	**-322**	**447**	0	**447**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**11338**	0	**11338**	0	**13984**	**-13984**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	11338	0	11338		13984	-13984

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
मद	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**1922549**	**1998504**	**-75956**	**2101454**	**2004201**	**97254**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1043356**	**1149222**	**-105867**	**1117517**	**1217281**	**-99764**
1.1 पण्य	**558619**	**865100**	**-306482**	**575351**	**896736**	**-321385**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**484737**	**284122**	**200615**	**542166**	**320545**	**221621**
1.2.1 सेवाएं	322893	197782	125111	363010	223703	139307
1.2.1.1 यात्रा	43194	39615	3579	48335	43139	5196
1.2.1.2 परिवहन	32574	31994	581	37162	42451	-5289
1.2.1.3 बीमा	4060	2497	1563	4089	2846	1243
1.2.1.4 जीएनआईई	1138	1865	-727	1052	2133	-1081
1.2.1.5 विविध	241926	121810	120116	272372	133133	139238
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	134790	10153	124636	158640	12604	146036
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	63210	63496	-286	79808	81470	-1663
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7446	4986	2460	8953	3608	5346
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	3496	1556	1940	4865	1976	2889
1.2.2 अंतरण	125962	11871	114092	138837	13991	124846
1.2.2.1 आधिकारिक	273	1508	-1235	242	2136	-1894
1.2.2.2 निजी	125689	10363	115326	138595	11855	126740
1.2.3 आय	35882	74470	-38588	40319	82851	-42532
1.2.3.1 निवेश आय	28220	70433	-42213	30918	78408	-47490
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7662	4037	3625	9401	4443	4958
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**879193**	**847122**	**32071**	**980828**	**786920**	**193908**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	520428	510868	9561	614739	484452	130287
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	115458	51333	64126	147540	50932	96608
2.1.1.1 भारत में	113612	25681	87931	144867	27655	117212
2.1.1.1.1 इक्विटी	86514	25598	60915	114698	27522	87176
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	21623	0	21623	22208	0	22208
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5475	83	5392	7961	133	7828
2.1.1.2 विदेश में	1847	25652	-23805	2673	23277	-20604
2.1.1.2.1 इक्विटी	1847	15580	-13734	2673	9291	-6618
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5078	-5078	0	5357	-5357
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	4993	-4993	0	8628	-8628
2.1.2 संविभाग निवेश	404970	459535	-54565	467199	433520	33679
2.1.2.1 भारत में	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
2.1.2.1.1 एफआईआई	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	330642	349060	-18419	351144	329501	21644
2.1.2.1.1.2 ऋण	65520	108102	-42582	115323	101107	14216
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8809	2374	6435	732	2913	-2181
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**125766**	**154384**	**-28619**	**156133**	**87608**	**68525**
2.2.1 बाह्य सहायता	12567	9043	3524	21010	10790	10221
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	36	211	-174
2.2.1.2 भारत को	12486	8834	3652	20974	10579	10395
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	31814	40576	-8762	69552	25089	44463
2.2.2.1 भारत द्वारा	11511	10176	1335	6131	5157	974
2.2.2.2 भारत को	20303	30400	-10097	63421	19932	43489
2.2.3 भारत को अल्पावधि	81385	104766	-23381	65571	51730	13841
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	37600	104766	-67165	55835	51730	4105
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	43784	0	43784	9737	0	9737
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**192971**	**125569**	**67401**	**117376**	**144387**	**-27011**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	192971	122132	70839	117376	141724	-24348
2.3.1.1 आस्तियां	74749	38118	36631	38270	70077	-31806
2.3.1.2 देयताएं	118221	84013	34208	79106	71648	7458
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	104358	80835	23523	74973	55820	19153
2.3.2 अन्य	0	3438	-3438	0	2662	-2662
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	154	-154	0	418	-418
2.5 अन्य पूंजी	40028	56146	-16118	92580	70054	22525
3 भूल-चूक	0	**2160**	**-2160**	**3109**	0	**3109**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**75956**	0	**75956**	0	**97254**	**-97254**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	75956	0	75956	0	97254	-97254

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर))

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**155748**	**171530**	**-15782**	**160686**	**175002**	**-14316**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**131589**	**158664**	**-27074**	**134926**	**161107**	**-26181**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**83389**	**129140**	**-45751**	**82729**	**128941**	**-46212**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	84567	120697	-36129	82205	117492	-35287
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-1178	0	-1178	524	0	524
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		8443	-8443		11449	-11449
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**48200**	**29524**	**18676**	**52197**	**32166**	**20031**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	25	10	15	33	18	14
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	40	207	-167	45	413	-368
1.अ.ख.3 परिवहन	4863	4776	87	5344	6104	-760
1.अ.ख.4 यात्रा	6448	5914	534	6950	6203	747
1.अ.ख.5 निर्माण	1010	649	361	754	754	0
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	606	373	233	588	409	179
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1111	744	367	1287	519	769
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	228	2087	-1859	319	2091	-1771
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20746	1882	18864	23604	2207	21397
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9436	9479	-43	11475	11715	-239
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	496	565	-69	532	631	-99
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	170	278	-108	151	307	-155
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	3021	2561	461	1114	796	318
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**5356**	**11117**	**-5760**	**5797**	**11913**	**-6116**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1144	603	541	1352	639	713
1.आ.2 निवेश आय	3563	10337	-6774	3230	11074	-7844
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1789	4391	-2602	1590	4634	-3044
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	34	2361	-2326	46	2503	-2457
1.आ.2.3 अन्य निवेश	210	3574	-3363	163	3922	-3758
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1530	12	1518	1431	15	1415
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	650	177	472	1216	200	1016
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**18803**	**1750**	**17053**	**19963**	**1982**	**17981**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18763	1547	17216	19928	1705	18224
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	18172	1141	17031	19303	1217	18086
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	591	406	184	625	487	138
1.इ.2 सामान्य सरकार	40	203	-163	34	278	-243
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**111**	**94**	**17**	**87**	**910**	**-824**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	66	16	51	11	824	-813
2.2 पूँजी अंतरण	45	78	-33	76	86	-10
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**142471**	**126384**	**16087**	**140946**	**126253**	**14692**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**17235**	**7663**	**9573**	**21215**	**7323**	**13891**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	16960	3834	13126	20830	3976	16854
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	16142	3821	12321	19685	3957	15728
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	12914	3821	9093	16492	3957	12535
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3228		3228	3193		3193
3.1.अ.2 ऋण लिखत	817	12	805	1145	19	1126
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	817	12	805	1145	19	1126
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	276	3829	-3554	384	3347	-2963
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	276	3084	-2808	384	2106	-1722
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	276	2326	-2050	384	1336	-952
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		770	-770
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	745	-745	0	1241	-1241
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		745	-745		1241	-1241
3.2 संविभाग निवेश	**60453**	**68598**	**-8145**	**67178**	**62335**	**4843**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	49357	52107	-2749	50491	47378	3112
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	9781	16137	-6356	16582	14538	2044
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1315	354	961	105	419	-314
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**3631**	**5113**	**-1482**	**6703**	**5182**	**1521**
3.4 अन्य निवेश	**49813**	**45010**	**4803**	**45850**	**37429**	**8421**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	15578	12580	2998	10780	8409	2371
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	513	-513	0	383	-383
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	15578	12067	3512	10780	8026	2754
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	19853	13572	6281	19119	17511	1608
3.4.3अ भारत को ऋण	18122	12021	6101	18232	16739	1493
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1730	1550	180	887	772	115
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	102	635	-533	46	176	-131
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	12149	15639	-3490	9428	7438	1990
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य /देय-अन्य	2132	2585	-453	6477	3894	2582
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार						
3.5 आरक्षित आस्तियां	**11338**	0	**11338**	0	**13984**	**-13984**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	11338	0	11338	0	13984	-13984
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**142471**	**126384**	**16087**	**140946**	**126253**	**14692**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	70823	65114	5709	77415	59219	18196
4.2 ऋण लिखत	58178	58685	-507	57054	49156	7898
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	13470	2585	10885	6477	17878	-11402
5. निवल भूल-चूक		**322**	**-322**	**447**		**447**

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**1043352**	**1149073**	**-105721**	**1117515**	**1217075**	**-99561**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**881511**	**1062882**	**-181371**	**938361**	**1120439**	**-182078**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**558619**	**865100**	**-306482**	**575351**	**896736**	**-321385**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	566511	808541	-242030	571705	817114	-245409
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-7893	0	-7893	3646	0	3646
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	56559	-56559	0	79622	-79622
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**322893**	**197782**	**125111**	**363010**	**223703**	**139307**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	165	67	98	227	127	100
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	270	1385	-1116	312	2872	-2560
1.अ.ख.3 परिवहन	32574	31994	581	37162	42451	-5289
1.अ.ख.4 यात्रा	43194	39616	3579	48335	43139	5196
1.अ.ख.5 निर्माण	6767	4346	2421	5245	5244	1
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4060	2497	1563	4089	2846	1243
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7446	4986	2460	8953	3608	5346
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1528	13981	-12453	2221	14539	-12318
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	138980	12609	126370	164159	15349	148809
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	63210	63496	-286	79808	81470	-1663
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3322	3786	-465	3700	4390	-690
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1138	1865	-727	1052	2133	-1081
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	20239	17153	3086	7746	5534	2213
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**35882**	**74470**	**-38588**	**40319**	**82851**	**-42532**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7662	4037	3625	9401	4443	4958
1.आ.2 निवेश आय	23869	69247	-45378	22464	77019	-54555
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	11985	29417	-17433	11059	32231	-21172
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	229	15813	-15585	321	17407	-17086
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1408	23939	-22531	1136	27274	-26138
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	10248	78	10170	9949	107	9842
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	4351	1186	3165	8454	1389	7065
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**125959**	**11722**	**114237**	**138835**	**13785**	**125049**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	125689	10363	115326	138595	11855	126740
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	121733	7642	114090	134248	8465	125782
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	3957	2721	1236	4347	3390	957
1.इ.2 सामान्य सरकार	270	1359	-1089	239	1930	-1691
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**746**	**629**	**117**	**603**	**6331**	**-5728**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	444	104	340	76	5731	-5655
2.2 पूँजी अंतरण	302	525	-224	527	600	-72
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**954406**	**846641**	**107765**	**980227**	**878048**	**102179**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**115458**	**51333**	**64126**	**147540**	**50932**	**96608**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	113612	25681	87931	144867	27655	117212
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	108137	25598	82538	136906	27522	109384
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	86514	25598	60915	114698	27522	87176
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	21623	0	21623	22208	0	22208
3.1.अ.2 ऋण लिखत	5475	83	5392	7961	133	7828
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	5475	83	5392	7961	133	7828
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1847	25652	-23805	2673	23277	-20604
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1847	20659	-18812	2673	14649	-11976
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1847	15580	-13734	2673	9291	-6618
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5078	-5078	0	5357	-5357
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	4993	-4993	0	8628	-8628
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	4993	-4993	0	8628	-8628
3.2 संविभाग निवेश	**404970**	**459535**	**-54565**	**467199**	**433520**	**33679**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	330642	349060	-18419	351144	329501	21644
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	65520	108102	-42582	115323	101107	14216
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8809	2374	6435	732	2913	-2181
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**24326**	**34253**	**-9927**	**46618**	**36037**	**10581**
3.4 अन्य निवेश	**333696**	**301521**	**32176**	**318871**	**260305**	**58565**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	104358	84273	20086	74973	58482	16490
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	3438	-3438	0	2662	-2662
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	104358	80835	23523	74973	55820	19153
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	132993	90915	42078	132966	121783	11183
3.4.3अ भारत को ऋण	121401	80531	40870	126799	116416	10383
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	11592	10385	1208	6167	5367	799
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	681	4252	-3571	318	1226	-908
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	81385	104766	-23381	65571	51730	13841
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	14279	17315	-3036	45043	27084	17959
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**75956**	**0**	**75956**	**0**	**97254**	**-97254**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	75956	0	75956	0	97254	-97254
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**954406**	**846641**	**107765**	**980227**	**878048**	**102179**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	474441	436196	38245	538390	411846	126544
4.2 ऋण लिखत	389731	393130	-3399	396793	341864	54930
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	90235	17315	72920	45043	124338	-79295
5. निवल भूल-चूक	**0**	**2160**	**-2160**	**3109**	**0**	**3109**

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399218	160927	372276	169964	399218	172926	417272
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	106542	356524	111122	382105	112844	399381
1.2 अन्य पूंजी	58841	17113	54385	15752	58841	17113	60082	17891
2 संविभाग निवेश	4699	260313	3070	254254	4699	260313	5012	267073
2.1 इक्विटी	590	147479	1941	144433	590	147479	1806	151162
2.2 ऋण	4109	112834	1129	109821	4109	112834	3206	115912
3 अन्य निवेश	54538	419296	41343	391991	54538	419296	54511	429581
3.1 व्यापार ऋण	924	105191	1357	99584	924	105191	2140	107224
3.2 ऋण	9884	168129	7034	156573	9884	168129	9765	173982
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	16294	124506	25158	130644	24169	133846
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	16658	11328	18574	15332	18437	14529
4 रिज़र्व्स	412871		405740		412871		429837	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078827	611079	1018521	642072	1078827	662287	1113926
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436755		-407441		-436755		-451640

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़ ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		जून	जुलाई	अगस्त		जून	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	**1366.30**	**118.26**	**127.45**	**118.79**	**171552061**	**15299131**	**16004194**	**14842138**
1.1 ग्राहक लेनदेन	1332.96	115.99	125.07	116.56	118436812	10177608	10886126	9829147
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	33.07	2.24	2.35	2.21	17251375	1824135	1690930	1694482
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.267	0.024	0.027	0.024	35863874	3297389	3427138	3318509
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	**36.17**	**3.10**	**3.62**	**3.34**	**116551038**	**10918363**	**11683806**	**10510799**
2.1 सीबीएलओ	1.30	–	–	–	18140463	–	–	–
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	11.11	1.48	1.78	1.30	50931587	6828452	7518962	6471125
2.2.1 एकमुश्त	8.06	1.11	1.36	0.93	9355007	1507446	1766292	1292195
2.2.2 रिपो	2.162	0.205	0.229	0.186	27124989	2441204	2562517	2162777
2.2.3 त्रिपक्षीय रिपो	0.89	0.17	0.19	0.18	14451590	2879802	3190152	3016154
2.3 विदेशी समाशोधन	23.76	1.62	1.84	2.05	47478988	4089910	4164844	4039674
3 पेपर समाशोधन	**11237.61**	**839.64**	**937.63**	**878.22**	**8246065**	**635798**	**687403**	**637093**
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	11116.69	836.46	934.80	875.55	8153592	633018	685224	635055
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2.2 अन्य केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	120.92	3.18	2.83	2.67	92473	2781	2179	2039
4 खुदरा इलेक्ट्रानिक समाशोधन	**71132.50**	**6436.48**	**6887.21**	**7297.54**	**25874543**	**2058081**	**2114124**	**2136636**
4.1 ईसीएस नामे	9.25	0.27	0.22	0.04	1258	9	4	7
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	53.57	3.30	2.82	3.38	13235	924	968	914
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	23188.87	1991.40	2194.19	2212.60	22793608	1749645	1784264	1796153
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	17529.09	1713.25	1892.76	2001.40	1590257	173019	182021	188886
4.5 राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	30351.71	2728.27	2797.21	3080.12	1476184	134484	146867	150676
5 कार्ड	**160462.56**	**13760.24**	**14203.09**	**14234.95**	**4512210**	**398120**	**400652**	**405503**
5.1 क्रेडिट कार्ड	17723.61	1640.46	1792.82	1804.31	607946	57317	60025	60011
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	97.71	8.12	8.66	8.58	4533	388	409	410
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	17625.90	1632.33	1784.16	1795.73	603413	56928	59616	59601
5.2 डेबिट कार्ड	142738.96	12119.79	12410.27	12430.65	3904264	340803	340626	345492
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	98596.15	8004.84	8160.15	8142.95	3310789	283403	282133	287452
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	44142.81	4114.94	4250.12	4287.70	593475	57400	58494	58040
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	**46072.29**	**3898.19**	**4075.89**	**4070.66**	**213324**	**17764**	**18437**	**18324**
6.1 एम-वॉलेट	41419.42	3347.01	3471.32	3493.36	183902	15471	15949	15693
6.2 पीपीआई कार्ड	4652.33	551.17	604.57	577.31	29335	2293	2488	2631
6.3 पेपर वाउचर	0.54	0.00	0.00	0.00	87	–	–	–
7 मोबाइल बैंकिंग	**62003.19**	**8486.06**	**9111.82**	**10157.79**	**2958407**	**497543**	**563140**	**328043**
8 कार्ड बकाया	**9717.19**	**8865.40**	**8908.80**	**9033.26**	–	–	–	–
8.1 क्रेडिट कार्ड	470.89	496.48	502.64	517.65	–	–	–	–
8.2 डेबिट कार्ड	9246.30	8368.92	8406.16	8515.60	–	–	–	–
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	**221703**	**226839**	**227629**	**228170**	–	–	–	–
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	**3722229**	**4068954**	**4252850**	**4409250**	–	–	–	–
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	**290307.16**	**25055.89**	**26234.87**	**26603.49**	**291085366**	**26029868**	**27481479**	**25231983**

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्युरिटीज़ सेगमेन्ट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2017-18	2018		2019	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**72,898.00**	**5,921.00**	**10,415.00**	**8,567.00**	**9,839.00**
	बकाया	**803,971.00**	**791,997.00**	**880,698.00**	**889,396.00**	**899,191.00**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**58,332.00**	**4,620.00**	**8,579.00**	**6,358.00**	**7,130.00**
	बकाया	**527,310.00**	**519,772.00**	**593,432.00**	**599,790.00**	**606,920.00**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17,145.00	1,511.00	2,915.00	2,318.00	2,360.00
	बकाया	109,210.00	106,694.00	130,185.00	132,503.00	134,863.00
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	–162.00	–19.00	–30.00	–21.00	–19.00
	बकाया	3,138.00	3,032.00	2,917.00	2,896.00	2,877.00
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	5.00	–68.00	–1.00	4.00	0.00
	बकाया	–43.00	–46.00	–12.00	–8.00	–8.00
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	1,625.00	527.00	1,036.00	966.00	928.00
	बकाया	181,691.00	180,801.00	189,759.00	190,725.00	191,653.00
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	12,264.00	1,039.00	1,232.00	1,190.00	1,184.00
	बकाया	41,718.00	40,590.00	52,072.00	53,262.00	54,446.00
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	19,633.00	1,500.00	2,317.00	2,508.00	2,451.00
	बकाया	99,292.00	97,390.00	116,728.00	119,236.00	121,687.00
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	59,818.00	59,068.00	67,662.00	68,920.00	70,179.00
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	4,597.00	4,559.00	5,617.00	5,734.00	5,824.00
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6,140.00	6,036.00	6,860.00	6,888.00	6,910.00
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	28,737.00	27,727.00	36,589.00	37,694.00	38,774.00
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	7,868.00	130.00	1,110.00	–607.00	215.00
	बकाया	92,320.00	91,357.00	101,799.00	101,192.00	101,407.00
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	–45.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	बकाया	–37.00	–68.00	–37.00	–37.00	–26.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	–1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	21.00	22.00	21.00	21.00	21.00
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**7,943.00**	**790.00**	**1,500.00**	**1,623.00**	**1,732.00**
	बकाया	**206,676.00**	**205,953.00**	**215,815.00**	**217,569.00**	**219,257.00**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	–65.00	583.00	1,124.00	1,159.00	1,262.00
	बकाया	87,174.00	86,205.00	92,374.00	93,533.00	94,795.00
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	–956.00	–1.00	5.00	9.00	3.00
	बकाया	–71.00	1,104.00	288.00	297.00	300.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	–15,592.00	–1,280.00	–1,895.00	–1,655.00	–1,609.00
	बकाया	37,981.00	38,877.00	24,496.00	22,841.00	21,232.00
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	24,588	1,489	2,259	2,095	2,065
	बकाया	70,612	68,783.00	87,154.00	89,249.00	91,314.00
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	–29.00	0.00	7.00	15.00	12.00
	बकाया	–140.00	–145.00	–74.00	–59.00	–47.00
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	–3.00	–1.00	0.00	0.00	–1.00
	बकाया	–64.00	–64.00	–81.00	–81.00	–82.00
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	11,184.00	11,193.00	11,658.00	11,789.00	11,745.00
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**6,623.00**	**511.00**	**336.00**	**586.00**	**977.00**
	बकाया	**69,985.00**	**66,272.00**	**71,451.00**	**72,037.00**	**73,014.00**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर हैं।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018			2019	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**5455681**	**5602830**	**5758103**	**5921026**	**6072243**
1. वाणिज्यिक बैंक	41.84	41.41	40.51	40.28	39.05
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.33	0.37	0.33	0.31	0.36
3. बीमाकृत कंपनियां	24.24	24.61	24.57	24.34	24.88
4. म्यूच्युअल फंड	1.13	1.41	0.64	0.35	0.64
5. सहकारी बैंक	2.59	2.51	2.38	2.29	2.17
6. वित्तीय संस्थाएं	0.93	0.97	1.01	1.05	1.05
7. कॉरपोरेट	1.09	1.01	1.05	0.97	0.99
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.84	3.65	3.60	3.22	3.27
9. भविष्य निधियां	5.79	5.71	5.54	5.47	5.35
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	11.63	11.76	13.81	15.27	15.67
11. अन्य	6.58	6.58	6.55	6.46	6.57
11.1 राज्य सरकार	1.97	1.99	1.97	2.00	2.02

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018			2019	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**2495461**	**2566833**	**2669393**	**2777229**	**2826935**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.02	34.66	34.00	33.87	32.57
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.75	0.58	0.60	0.58	0.75
3. बीमाकृत कंपनियां	34.24	33.74	33.90	33.04	33.94
4. म्यूच्युअल फंड	1.20	1.05	1.23	1.20	1.24
5. सहकारी बैंक	4.79	4.75	4.67	4.55	4.65
6. वित्तीय संस्थाएं	0.35	0.43	0.37	0.42	0.44
7. कॉरपोरेट	0.16	0.17	0.22	0.29	0.32
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.15	0.10	0.09	0.09	0.08
9. भविष्य निधियां	20.34	21.04	21.29	22.15	21.88
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
11. अन्य	2.99	3.48	3.64	3.81	4.08
11.1 राज्य सरकार	0.06	0.07	0.07	0.11	0.14

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2018			2019	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**528007**	**565750**	**529826**	**412704**	**524618**
1. वाणिज्यिक बैंक	55.30	47.84	53.76	57.56	53.60
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.41	1.86	2.06	2.68	1.85
3. बीमाकृत कंपनियां	3.66	4.55	4.74	6.61	5.13
4. म्यूच्युअल फंड	7.03	10.69	5.65	2.78	13.00
5. सहकारी बैंक	1.29	1.20	1.21	2.48	2.54
6. वित्तीय संस्थाएं	2.36	1.67	1.88	2.49	2.14
7. कॉरपोरेट	1.88	6.67	1.86	2.23	1.67
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.21	0.01	0.02	0.08	0.07
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	26.87	25.50	28.72	23.10	19.99
11.1 राज्य सरकार	23.11	21.36	24.04	17.91	15.59

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (स.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**3285210**	**3760611**	**4265969**	**4515946**	**5516932**	**6071777**
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	**3189737**	**3778049**	**4288432**	**4528422**	**5364245**	**6003162**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**836563**	**952410**	**1064704**	**997097**	**1174823**	**1247962**
3क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*26.3*	*27.3*	*27.8*	*26.4*	*29.0*	*28.8*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*25.6*	*27.4*	*27.9*	*26.5*	*28.2*	*28.5*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.2*	*20.0*	*20.4*	*19.8*	*22.1*	*22.1*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*16.2*	*16.7*	*17.1*	*17.4*	*18.5*	*18.5*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.7*	*6.9*	*6.9*	*5.8*	*6.2*	*5.9*

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अगस्त 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	629	4	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	72	11	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	524	16	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	248	12	377	10	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	86	17	74	11	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	133	7	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	104	19	427	16	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	851	20	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	248	21	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	1087	11	-	-	-	-

टिप्पणी : 1. राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3. राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4. प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5. -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अगस्त 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7692	759	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1090	1	--	0
3	असम	3940	48	--	4000
4	बिहार	6563	--	--	16600
5	छत्तीसगढ़	3969	--	1	0
6	गोवा	554	278	--	0
7	गुजरात	12668	445	--	0
8	हरियाणा	1931	1109	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	3917	--	--	1500
13	केरल	1990	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	858	--	0
15	महाराष्ट्र	36296	275	--	19000
16	मणिपुर	350	93	--	0
17	मेघालय	569	28	9	0
18	मिज़ोरम	512	30	--	0
19	नगालैंड	1447	31	--	0
20	उड़ीसा	12420	1346	78	18895
21	पुदुचेरी	298	--	--	925
22	पंजाब	223	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6157	--	45	11833
25	तेलंगाना	5177	1055	1	0
26	त्रिपुरा	305	5	--	0
27	उत्तरप्रदेश	2786	73	--	0
28	उत्तराखंड	--	--	180	0
29	पश्चिम बंगाल	10249	493	214	0
	कुल	**121101**	**6925**	**666**	**74552**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						जून		जुलाई		अगस्त			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	3104	2521	2974	1808	3000	1834	16078	11062
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	261	261	-	-	-	-	472	472
3	असम	7760	6797	10595	8089	-	-	500	500	1200	1200	1700	1700
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	-	-1000	3600	3600	4000	4000	7600	6600
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	200	100	200	200	300	100	900	600
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	2000	1000	3700	2200	2300	600	13300	9100
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	-	-700	3501	3501	3000	3000	8501	7801
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	-	-	500	500	500	500	1600	1600
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	249	249	1000	1000	400	400	2749	2210
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	1500	1500	-	-	-	-474	1500	508
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	-	-	2000	1000	2000	1000	4000	2000
13	केरल	20500	16203	19500	14784	729	129	3000	3000	2453	2453	11682	11082
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	2000	2000	1000	1000	1000	1000	6000	6000
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	2000	2000	4500	1500	-	-2000	12500	7500
16	मणिपुर	525	278	970	667	400	400	-	-	200	200	803	803
17	मेघालय	1116	920	1122	863	-	-50	200	200	150	150	350	300
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	-	-	-	-	100	100	258	258
19	नगालैंड	1135	766	822	355	-	-	-	-	-	-	100	-160
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	-	-	1000	1000	-	-	2000	2000
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	1900	1400	3420	2120	2200	900	10820	6620
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	5995	3183	2387	1887	2000	1000	15882	11070
24	सिक्कीम	995	745	1088	795	213	213	-	-	-	-	213	213
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	4000	4000	4615	4615	4000	4000	19615	19615
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	3300	2883	3000	2166	2500	1666	12800	9216
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	-	-	-	-	450	450	450	450
28	उत्तरप्रदेश	41600	37178	46000	33307	-	-500	4000	2500	7000	5500	11000	6000
29	उत्तराखंड	6660	5830	6300	5289	-	-	500	200	300	300	1300	700
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	2000	2000	5010	3010	4500	2500	11510	1510
	कुल	419100	340281	478323	348643	29851	21589	50606	37506	44553	31379	176682	127830

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित *जैसे* - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय,182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा (https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक)** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 का बज़ट अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40. सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलबध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंज़िल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं.........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**